राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ३ तृतीय विधान सभा के तृतीय सत्र, १९६३ का ३४ वां दिवस संख्या १७

बुधवार, दिनांक २० मार्च, १९६३

विधान सभा की बैठक म. पू. ११-०६ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[**यातायात, चिकित्सा, कृषि, स्वायत्त शासन, गृह, सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण एवं विद्युत**—विभाग]

प्रश्न संख्या ४७३

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानचन्द मोदी ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखें)

श्रीमती गौरी पूनिया ।

हास्पिटल विजीटर्स कमेटियां-जोधपुर डिवीजन

४७४. **श्रीमती गौरी पूनिया** (डंगाना): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जोधपुर डिवीजन के किस-किस जिले की हास्पिटल विजीटर्स कमेटियां बन चुकी हैं ? कृपया सदस्यों की सूचियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(२) किस किस जिले की हास्पिटल विजीटर्स कमेटियां अब तक नहीं बन पायी हैं, और क्यों ? कारणों सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उप-मंत्री स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (१) यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

(२) कमेटियां शीघ्र ही बना दी जायेंगी ।

श्रीमती गौरी पूनिया: यह विचाराधीन कब से है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा: यह प्रश्न थोड़े समय पहले असेम्बली में आया था उस समय भी मैंने उत्तर दिया था और आशा है इस सत्र की अवधि तक ही यह प्रश्न हल हो जायेगा ।

Page No 2

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या यह सच है कि पहले हास्पिटल एडवाइजरी कमेटियां बनाई गई थीं और बाद में बन्द कर दी गयीं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह तो समय समय पर रिवाइज होती रहती हैं। वे दुबारा रिवाइज नहीं की गयीं ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : रिवाइज हो सकती हैं, लेकिन ऐसी जानकारी मिली है कि सरकार ने रूल्स बना कर यह बन्द कर दी हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : बन्द नहीं की हैं। अवधि होती है उसके बाद में यह समाप्त हो जाती है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उसके बाद दूसरी बना तो देते हैं ।

श्री अध्यक्ष : कह दिया आपने कि बन रही हैं ।

श्रीमती गौरी पूनिया : राज्य भर में कहीं नहीं बनी हैं या जोधपुर डिवीजन में की विचाराधीन है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : करीब करीब सभी जगह हैं। कुछ जगह की बनी हैं लेकिन उनको अभी डिक्लेयर नहीं किया है ।

श्रीमती गौरी पूनिया : ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से नहीं बन पायीं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : आपको कहा कि इस सत्र के अन्त तक बन जायेंगी।

श्री मानिक चन्द सुराणा (कोलायत) : यह सब जगह बन जायेंगी या केवल जोधपुर में ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : सब जगह ।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : जो बनी हैं उनको डिक्लेयर क्यों नहीं किया जाता है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : सबको एक साथ ही करेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : फिर बनाने से क्या मतलब हुआ ?

श्री भीमसेन (लूण करणसर) : बीकानेर में तो बनी हैं और चल भी रही हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री भैरोंसिंह. ।

सरकारी फार्मों पर बुल्स की खरीद

४७५. **श्री भैरोंसिह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् ६१-६२ व ६२-६३ में अब तक किस किस सरकारी फार्म पर कब कब कितने कितने बुल्स किस किस उम्र के व कुल कितनी कीमत के खरीदे गये ?

(२) इन बुल्स के खरीदने में क्या प्रक्रिया अपनाई गई ?

(३) क्या यह सही है कि सरकारी आज्ञा के अनुसार सर्विसेबल बुल्स खरीदे जाने थे, फिर भी छोटी उम्र के खरीदे गये ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) क्या इन बुल्स की पैडिग्री मालूम की जाकर उनकी हिस्ट्री मेन्टेन की गई है तथा जनता द्वारा खरीदे जाने पर

Page No 3

(श्री भैरोंसिह)
इन बुल्स की यह हिस्ट्री बताई जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, कृषि (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) सन् ६१–६२ के वर्ष में ५८ बछड़े १ साल से २ साल की उम्र के बुल रियरिंग फ़ार्म नोहर के लिए ३५,०१० रु० के खरीदे गये । सन् ६२-६३ में कोई सांड नहीं खरीदे गये ।

(२) इस कार्य हेतु नियुक्त कमेटी द्वारा यह ख़रीद की गई थी ।

(३) जी नहीं ।

(४) ऐसी व्यवस्था है ।

श्री भैरोंसिह : आपने यह बताया, क्या यह सही है कि सरकार ने यह आर्डर्स दिये थे कि जो बुल्स खरीदे जायें वे सर्विसेबल होने चाहिए ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जी नहीं, यह रियरिंग फ़ार्म है, इसलिए सर्विसेबल बुल्स का सवाल नहीं खड़ा होता ।

श्री भैरोंसिह : क्या ये जयपुर-बस्सी फार्म के लिए नहीं खरीदे गए थे ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जी नहीं ।

श्री भैरोंसिह : इसको मैं कैसे मानू ? मैं खुद देख कर आया हूं और मैंने खुद ने एक बछड़ा खरीदा है और आप कहती हैं कि नहीं खरीदा गया ।

श्री अध्यक्ष : फ़ार्म के बछड़े भी तो हो सकते हैं ।

श्री भैरोंसिह : यह लोगों को सप्लाई करने के लिए खरीदे गए हैं और मैं खुद एक बछडा खरीद कर लाया हूं ।

कृषि-मंत्री, (श्री नाथूराम मिर्धा) : आप साफ बता दीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिह : आप यह कह रही है कि नहीं खरीदे गये, तो यह कैसे हो सकता है जब कि मैं खुद देख कर आया हूं और खरीद कर लाया हूं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने जो खरीदे हैं, यह नया फार्म बनाया गया है नोहर में उसके होंगे । फिर जो अच्छे बछडे हैं और एक से दो साल के बीच की उम्र के हैं लोगों से खरीद लेते हैं ।

श्री भरोंसिह : लेकिन बस्सी फार्म पर कहां से आ गये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बस्सी फ़ार्म पर कोई बछड़ा नहीं खरीदा ।

श्री भैरोंसिह : बछड़े हरियाणा से ख़रीदे हैं और दूसरी जगह से खरीदे हैं और उनको ६ महीने अपने यहां रखा है और बेचा है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा है कि हमारी बुल्स प्रोग्राम स्कीम चार तरह की होती हैं । एक तो स्वंय बछड़ा तैयार करते हैं वह सांड के रूप में मुफ्त में देते हैं । दूसरी योजना में बुल रियरिंग फ़ार्म में प्राईवेट लोगों से बछड़े खरीद कर फार्म में पालते है । तीसरी योजना में जो अच्छे प्रकार के सलेक्टेड बुल्स हैं यानी जो बछड़े

(श्री नाथूराम मिर्धा)

अच्छे बुल बनने वाले हैं और वे ब्रीडर्स के पास मौजूद हैं वे जब तक २।। साल के न हो जायें तब तक १० रुपये के हिसाब से सब्सिडी देते हैं और चौथी योजना यह है कि जो अच्छे बल सर्विस के लायक हो गये हैं या होने वाले हैं उनको जो पंचायतें खरीदना चाहती हैं जिस गाव के लिए उनको हम २००, रु० तक सब्सिडी के रूप में देते हैं और ज्यादा पैसा देना होता है तो गांव वाले उस पर खर्च सकते हैं। ये ४ स्कीम्स हैं जिनके तहत हम बुल्स खरीद कर गांवों में बांटते हैं ।

श्री भैरोंसिह : तो क्या यह माना जाये कि इसके अन्तर्गत वस्सी फार्म में १९६१-६२ और ६२-६३ में कोई बछड़े नहीं खरीदे गये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह अलग प्रश्न है ।

श्री भैरोंसिह : अलग प्रश्न कैसे है ? मेरा प्रश्न स्पष्ट है कि सन् ६१–६२ व ६२-६३ में अब तक किस किस सरकारी फार्म पर कब कब कितने कितने बुल्स किस किस उम्र के व कुल कितनी कीमत के खरीदे गये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नोहर के फार्म से कुछ बछड़े यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लाए गये हैं यह सूचना मुझे दी गई है ।

श्री भैरोंसिह : मैं कहता हूं कि फिर सूचना सही नहीं दी गई है । बस्सी फार्म के लिए खरीद कर बछड़े लाये गये हैं, नोहर से नहीं आये हैं । यहां की कमेटी गई और वह खरीद कर लाई है। कौन सा बल अच्छा हो सकता है, उसकी हिस्ट्री पूछी तो मालूम नहीं, उसकी पेडीग्री मालूम नहीं है तो फिर पूछा कि कैसे खरीदे गये तो कहा गया कि जो अच्छे समझे गये वही खरीद लिये ।

श्री नाथूराम मिर्धा: जो जानकारी मिली है वह यही है कि नोहर फार्म में जो इस स्टेज पर थे कि जल्दी ही तैयार होकर दूसरे इलाके में बांटे जा सकते थे ऐसे बछड़ों को तैयार करने के लिए बस्सी में ले आये थे for distribution.

श्री भैरोंसिह : माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर गलत इनफॉर्मेशन दी जा रही है। ८-९ महीने के बछड़े थे और दो-तीन वर्ष के बछड़े खरीद लिये और मैं खुद १।। वर्ष का खरीद कर लाया हूं ।

गृह मंत्री (**श्री मथुरादास माथुर**) : आपके लिए स्पेशयली मंगवा लिया होगा ।

श्री भैरोंसिह : स्पेशयली मंगवाने का प्रश्न नहीं है । आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से खरीदे हैं, किस तरह से आये हैं । बिल्कुल गलत जवाब दिया जा रहा है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : जो पुख्ता इनफार्मेशन है वह दे रहा हूं । बस्सी फार्म के लिए आये बछड़े नहीं खरीदे गये और जो बछड़े नोहर में खरीदे गये उनको डिस्ट्रीब्यूट करना था ।

श्री भैरोंसिह : आप बता सकते हैं कि नोहर से कितने डिस्ट्रीब्यूशन के लिये आये थे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह एग्ज़ेक्ट तादाद मालूम नहीं है ।

Page No 5

श्री भैरोंसिह: क्या बस्सी फार्म के लिए डाइरेक्टर ने पर्चेज करके यहां बुल्स नहीं बेचे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं ।

श्री भैरोंसिह : मैं बता देना चाहता हूं कि बिल्कुल गलत इनफार्मेशन है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह ठीक है। आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): हम तो चुपचाप बैठे रहते हैं, इसलिए कौनसा सही है और कौनसा गलत है–इसका पता नहीं चलता है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): आप इधर आकर बैठिये, उधर तो चुपचाप ही रहेंगे ।

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय, आज्ञा हो तो ज्वाला प्रसाद जी को ले जाकर बता लाऊं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मुझे ऐसे कामों की फुर्सत नहीं है, आप बैलों मे घूमते रहें ।

श्री भैरोंसिह: आप तो बैलों की पूजा करते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आप जैसे आदमी वहां जाते है । कमाल की बात है ।

श्री अध्यक्ष: श्री जयसिंह ।

मालपुरा जल योजना

४७६ **श्री जयसिंह** (मालपुरा): क्या स्वायत्तशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा मालपुरा की पानी योजना के लिये अभी तक कोई कदम नहीं उठाये गये हैं !

(२) यदि हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) यह सही नहीं है ।

(२) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या सही नहीं है ?

श्री दौलतराम सारण : जो आपने प्रश्न में कहा है वह ।

श्री जयनारायण सालोदिया : मालपुरा में नल-योजना के लिये सरकार कोई विचार नहीं रखती है।

श्री दौलतराम सारण : सरकार का विचार है, मैं तो कह रहा हूं। आपने पूछा था––क्या सरकार का विचार नहीं है, इसका जवाब मैंनें दिया कि यह सही नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री दौलतराम सारण : प्रयास किया जायगा तीसरी योजना में पूरा हो।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : सही यह है कि कदम उठाया गया । हल्ले सवाल का जवाब है––यह सही नहीं है। यदि कदम उठाया गया तो क्या क्या उठाया गया ?

श्री दौलतराम सारण: योजना बनी, सर्वे की गयी, मंजूरी दी गयी, सामान के लिये इन्डेन्ट किया गया ।

श्री दुर्गालाल बादशाह : अध्यक्ष महोदय, यह हो रहा है कि कागज की कार्यवाही हुई, सैंक्शन मिल गई, इन्विटेशन दे दिया गया जीमने के लिये लेकिन जीमन का सामान तैयार नहीं है।

गृह मंत्री (श्री मथुरादासमाथुर) : मीनू बना है।

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया कि योजना का ऐस्टीमेट तैयार किया गया, स्वीकार किया गया, सामान के लिये इन्डेन्ट दिया गया। सामान आयेगा तब कार्यवाही चालू हो जायगी।

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसीन्द) : क्या इस योजना में फ़ाइनेन्स मिनिस्टर की तरफ़ से कट नहीं लगा?

प्रश्न संख्या ४७७

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४७८

श्री मथुरेशबिहारी।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४७९

श्री जुझार सिंह।

(अनुपस्थित)

चेचक के टीके–भीम व देवगढ तहसील

४८०. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि रूस से भारी संख्या में चेचक (Lymphs) के टीके की दवा आई है जिससे राजस्थान भर में समस्त आबाल वृद्धों के टीके लगाये जायेंगे?

(२) क्या यह सही है कि इस बड़ी योजना को कार्यान्वित करने के लिये सारी पंचायतों के अध्यापकों की सेवायें ली जा रही हैं?

(३) क्या भीम व देवगढ तहसीलों में टीके लगने आरम्भ हो गये हैं? यदि हां, तो यह काम कब तक समाप्त हो जाने की योजना है? आबादी कितनी है और टीके कितनों के लग चुके है?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (१) जी हां।

(२) चेचक की बीमारी की रोक-थाम के लिये पंचायत समितियों को भी निवेदन किया गया है कि वे मास-वेक्सीनेशन के कार्य में अपने स्टाफ द्वारा उचित सहयोग दें।

(३) जी हां। भीम और देवगढ पंचायत समितियों में मास वेक्सीनेशन का कार्य शुरू हो गया है जिनकी आबादी करीब २ निम्न प्रकार है:–

भीम	६७,०००
देवगढ	४७,०००

भीम में कुल ३५,००० माता के टीके लग चुके हैं एवं वहां मास-वेक्सीनेशन का कार्य चल रहा है।

देवगढ में मास वेक्सीनेशन का कार्य दिनांक २५-२-६३ से शुरू हो गया है और अभी कार्य चालू है। अनुमानतः कार्य लगभग दो मास में पूरा होने की आशा है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या यह सही है कि ग्राउट ग्रॉफ डेट लिम्फ्स लगाये जाते हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : ग्रापकी इन्फोर्मेशन शायद गलत है, क्योंकि दो-दो बार टीके लगाते हैं। फिर भी माता निकल जाती हैं इसका क्या कारण है ?

श्री रामकिशन (वैर) : इसका जवाब ग्राना जरूरी है। चार चार बार टीके लगा देते हैं फिर भी माता निकल जाती है

श्री भैरोंसिंह : बार बार टीके लगाते है फिर भी माता निकल जाती है इसका क्या कारण है ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : भीमगढ़ में चेचक से कितने बच्चों की मृत्यु हुई?

श्रीमती प्रभा मिश्रा: यह अलग प्रश्न है, आप अलग से पूछें।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : राजस्थान भर में माता का प्रकोप है, टीकों का कोई असर नहीं है।

श्रीमती प्रभा मिश्रा: यह नहीं कहा जा सकता कि टीके का कोई ग्रसर नहीं है क्योंकि जिस तरह यह एपेडेमिक दूसरे राज्यों में फैलो हैं वहां कंट्रोल किया गया है। राजस्थान मे इसके फीगर्स कम्पेरेटिवली बहुत कम हैं। इसलिये यह कहना कि इसक असर नहीं होता, ठीक नहीं है। हो सकता है कि टीके लगने के बाद चेचक निकली हो। इसका कारण यह हो सकता है कि सुचारु रूप से टीकों की देखभाल न रखी हो, खुला रखा हो, या धो दिया हो ग्रौर उससे टीके का ग्रसर मिट गया है। इसके अलावा ग्रौर कोई कारण नहीं है।

श्री दलपत सिंह (ग्राबू) : काफी ज्यादा तादाद में बच्चें मर चुके है। ग्रापने पहले इसका एक्सपेरीमेंट किया नहीं है। सिरोही ग्रौर जालोर मे काफी टीके लगाने के बाद भी बच्चे मर चुके हैं।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्रीमती प्रभा मिश्रा : माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं उसकी इन्क्वायरी करके जो उचित कार्यवाही होगी वह की जायेगी।

ग्राम भिरानी, डाबड़ी तथा सीधमुख क्षेत्र में भाखरा नहर से सिंचाई

४८१. **श्री हरदत्त सिंह** (नोहर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि सरकार तहसील भादरा के भिरानी, डाबडी आदि गांवों से होकर तहसील राजगढ़ के सीधमुख गांव तक के क्षेत्र के लिये भाखरा नहर से सिंचाई के लिये किसी नई नहर के निर्माण की योजना बना रही है ?

(ख) अगर हां, तो उसकी अब क्या स्टेज है और उसका कार्य कब ग्रारम्भ किया जावेगा ?

(ग) क्या यह भी सही है कि जिला गंगानगर के नहर विभाग के उच्चाधिकारियों की सम्मति के ग्रनुसार भाखरा नहर की अमरसिंह ब्रान्च की जोगीवाला डिस्टीब्यूट्री का कोर्स सही न होने से पूरा पानी नही लगता ग्रौर उसका कोर्स (बहाव का रास्ता) बदलने की योजना नहर विभाग के विचाराधीन है ?

उप मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण):

(१) जी हां।

(२) इस योजना की प्रारम्भिक सर्वे करली है, तखमीना तैयार कर लिया है उसकी

(श्री दौलतराम सारण)
जांच की कार्यवाही की जा रही है। तखमीना स्वीकार करने के बाद कार्य प्रारम्भ होगा।

(ग) जी, नहीं।

श्री हरदत्त सिंह: यह नहर कहां से निकालने का विचार है?

श्री दौलतराम सारण: दुबारा फरमावें।

श्री हरदत्त सिंह: यह जो नहर निकाल रहे हैं उसका क्या नामकरण होगा और उसका हैड कहां होगा?

श्री दौलतराम सारण: किशनगढ़ ब्रान्च से लाई जायगी और सीधमुख में हैड होगा।

श्री हरदत्त सिंह: क्या आप यह बता सकते हैं कि कितने एकड़ भूमि को यह इरिगेट करेगी?

श्री दौलतराम सारण: अभी पूरा नही कहा जा सकता, लेकिन फिर भी ४५,००० एकड़ फलो इरिगेशन और ८६ हजार एकड़ लिफ्ट इरिगेशन होगा।

श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत): ये तखमीने कौनसे अधिकारी कनाल विभाग के बनाते हैं और कौन इसकी जांच करते हैं क्योंकि आपने कहा है कि तखमीना आ चुका है और जांच हो रही है!

श्री दौलतराम सारण: पहले सर्वे करते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर देखते है, फिर चीफ इंजीनियर देखते है।

श्री मानिकचन्द सुराणा: आपने तखमीना बनाया....

श्री दौलतराम सारण: आप मेरी बात सुन लीजिये। आप मुझे डांट रहे है ख्वाम-ख्वाह।

श्री मानिकचन्द सुराणा: डाटने की आदत नहीं है मुझमे अब तक, मैं डांट नही रहा हूं। आपने यह कहा है कि एस्टीमेट्स बन चुके हैं तखमीने की जांच की जा रही है। प्रश्न सीधा सा यह है कि कौन से अधिकारी एस्टीमेट्स बनाते हैं और कौनसे अधिकारी उसकी जांच करते है?

श्री दौलतराम सारण: मैंने निवेदन किया कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर उनकी जांच करते हैं। एस्टिमेट्स बन चुके है और चीफ इंजीनियर के पास आ गये हैं और उनकी जांच की जा रही है।

श्री हरदत्त सिंह: ये चीफ इंजीनियर के पास कब आये?

श्री अध्यक्ष: श्री रघुवीर सिंह।

बाड़ी में नल-योजना

४८२. **श्री रघुवीरसिंह** (बाड़ी): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

क्या बाड़ी प्रोपर, जिला भरतपुर में नल लगाये जाने की योजना सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुकी है तथा इसके लिये रुपया भी मंजूर हो चुका है? यदि हां, तो फिर इस योजना को कार्यान्वित नहीं करने के क्या कारण हैं?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण): जी नहीं।

श्री रामकिशन (वैर) : आपने प्रावधान किया है कि १० हजार के नीचे की आबादी वालों के लिए तीसरी योजना में पानी की व्यवस्था नहीं की जायगी लेकिन जहां ज्यादा आबादी है उनके लिए भी व्यवस्था नहीं की गई है–इसका क्या कारण है ?

श्री दौलतराम सारण : अर्थाभाव के कारण नहीं की गई।

श्री रामकिशन (वैर) : केवल धौलपुर के लिये ही यह अर्थाभाव है या दूसरों के लिये भी ?

श्री दौलतराम सारण : सबके लिये समान कार्यवाही होगी।

श्री रामकिशन : आपने बताया था कि ५९ में कार्यवाही चलाई और इतनी पूरी हो गई, फिर यह ६२-६३ तक पूरी कैसे नहीं हुई ?

श्री दौलतराम सारण : इसमें दिया है वह भी ठीक है और उत्तर दिया है वह भी ठीक है।

श्री रामकिशन : या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही गलत हैं ?

श्री दौलतराम सारण : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : बजट में इस हैड के नीचे कुछ कटौती की गई है क्या ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्रीजी से पूछें।

श्री भैरोंसिह : प्लान एलोकेशन थे उनमें कुछ कटौती की गई है ?

श्री अध्यक्ष : आज इसी मांग पर बहस होगी, उस समय विस्तार से आप पूछ लें।

श्री रघुवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, पंचवर्षीय योजना के जो इनके टार्गेट्स थे उसमें इन्होंने रखा है कि दस हजार की आबादी के प्रत्येक शहर या कस्बे को पानी देंगे। यह फिजिकल टार्गेट रखने के बावजूद भी पानी नहीं दे पा रहे हैं, इसका कारण क्या है ?

श्री अध्यक्ष : आज इस मांग पर बहस होगी, उस समय और भी शंकाओं का निवारण कर देंगे।

श्री भैरोंसिंह : अगर अभी बतला दें तो बहस फालतू नहीं होगी।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : क्या बाडी में कोई सर्वे कराया गया या इसके बारे में ?

श्री रघुवीर सिंह : क्या बाडी में सर्वे कराया गया था ?

श्री दौलतराम सारण : सर्वे किया गया था, लेकिन धनाभाव के कारण नहीं ली जा सकी।

श्री रामकिशन : सर्वे कब हुआ था ?

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह (श्री राम किशन से) उनको प्रश्न पूछने दें।

श्री रघुवीर सिंह : कितनी धन–राशि की मंजूरी हुई इसके लिए ?

श्री अध्यक्ष : सर्वे के बाद कोई धन-राशि मंजूर की गई ?

श्री दौलतराम सारण : मंजूर नहीं की गई। अगर मंजूर होती तो कार्यवाही की जाती।

श्री रघुबीर सिंह : तखमीना कितने का था ?

श्री दौलतराम सारण : ५,४९,१००) रु का है।

श्री रघुबीर सिंह : इस योजना के चालू होने की कब तक उम्मीद की जाय ?

(अल्प विराम के अन्तर)

श्री अध्यक्ष : (उप-मंत्री महोदय से) उसमें (कागजों में) कुछ नहीं लिखा है।

श्री दौलतराम सारण : क्या पूछ रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : कब तक बनने की उम्मीद है ?

श्री दौलतराम सारण : अभी निकट भविष्य में तो आशा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

डकैती एवं लूटमार की घटनाएं, जिला बीकानेर।

४८३. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बीकानेर जिले में माह फरवरी, ६२ से जनवरी, ६३ तक कहां कहां डकैती एवं लूटमार की घटनायें घटी ? उक्त घटनाओं में से कौन सी घटनाओं के सम्बन्ध में पुलिस को सूचना मिल गई थी तथा पुलिस ने उस सूचना पर क्या कार्यवाही की ? डकैतों का किस हद तक पीछा किया गया और यदि पीछा नहीं किया गया था तो ऐसा न करने के क्या कारण थे ?

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : इस काल में कुल क्रमशः ९ व २६ स्थानों पर डकैती व लूट की घटनाएं होने की सूचना पुलिस को मिली। घटनास्थलों की सूचना संलग्न है। सूचना मिलते ही फौरन पुलिस मुकदमा कायम कर घटनास्थल पर पहुंची और डाकुओं का पाक हिन्द सरहद तक पीछा किया। जिन घटनाओं में पीछा नहीं किया गया उनमें या तो पुलिस को सूचना देर से मिली और डाकू भाग निकलने में सफल हुए। या वे असत्य व टेक्नीकल नेचर की घटनायें थीं।

(कृपया परिशिष्टी देखिये)

श्री भीमसेन : ये डाकू पाक सीमा में चले जाते हैं उसके बाद क्या भारत सरकार से कार्यवाही करा रहे हैं, जिससे जो डाकू वहां पाक सीमा में शरण लेते हैं वे सरेन्डर कर दें ?

श्री मथुरादास माथुर : जो पाक-सीमा म डाकू निकल जाते हैं उनके लिए भारत सरकार और पाकिस्तान के बीच लिखा-पढ़ी होती है और यहां के इन्सपेक्टर जनरल पुलिस, डी. आई. जी. डी, एस. पी. लेवल पर पाकिस्तान की ऑथोरिटीज और हमारी आथोरिटीज की मीटिंग होती है। उस वक्त जो सवालात होते हैं, उनको वहां रैज करते हैं और उन पर डिस्कशन होता है। उनसे जितना सहयोग मिलता है, उतनी ही कामयाबी हो सकती है।

Page No 11

श्री भीमसेन : जो कॉन्फ्रेन्सेज या मीटिंग होती हैं, इनमें वे क्या कहते हैं, क्या वे स्वीकार करते हैं और सरेन्डर कराते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : स्वीकार क्यों नहीं करते। वे इन्कार नहीं कर सकते क्योंकि जो डाकू या मवेशी पाकिस्तान में चले जाते हैं तो पाकिस्तान की नियरेस्ट पोस्ट से आदमी बुलाकर रसीद लेते हैं। वे इन्कार नहीं कर सकते क्योंकि रसीद होती है। वे कहते हैं कि वे सरेन्डर कराने में सहयोग करेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : उनकी तरफ से ज्यादा रेस्पोन्स नहीं है तो प्रयत्न करने में फायदा क्या ? उसके बाद सरकार को और दूसरे कदम उठाने चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री केसरीसिंह।

श्री भीमसेन : एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं, बीकानेर में जो लूट की घटनायें हुई हैं, जो लिस्ट में दी हैं, उसमें से किसी में माल बरामद हुआ है ?

श्री मथुरादास माथुर : क्या हुआ, किसमें हुआ, किसमें नहीं हुआ, **चौबीस घटनायें हुई हैं, इसलिए नहीं बता सकता।**

श्री भीमसेन : एक घटना भी बता दीजिये, जिसमें हुआ है ?

श्री मथुरादास माथुर : आगे प्रश्न पूछा जा चुका है।

अध्यक्ष : श्री केसरी सिंह।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): वह कौनसी डकैती थी जिसमें डाकू डी. आई. जी. के आंसू पोंछने के लिए रुमाल छोड़ गये थे–यह मैं जानना चाहती हूं ?

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न पूछ लिया गया है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : डी. आई. जी. के आंसू पोंछने के लिए डाकू माल छोड़ गये थे, वह कौनसी डकैती हुई है बीकानेर में ?

श्री अध्यक्ष : यह दूसरा प्रश्न है। श्री केसरीसिंह।

म्युनिसिपल बोर्ड, पाली की आडिट रिपोर्ट

४८४. **श्री केसरीसिंह** (पाली) :Will the Minister for Municipalities be pleased to state:—

(1) Whether in accordance with sub-section (1) of section 277 of the Rajasthan Municipalities Act, 1959 the quarterly reports of the accounts have been regularly laid before the present Municipal Board, Pali? If so, a copy of each of the reports so furnished may please be laid on the Table of the House.

(2) Whether the annual Audit Reports have been duly placed before the members of the Municipal Board, Pali, and the audit comments duly complied with.

A copy of the latest Audit Report may please be laid on the Table of the House along with the compliance report of the Board.

Page No 12

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलत राम सारण): (१) जी नहीं। प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(२) जी हां। आडिट रिपोर्ट व अनुपालन रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(कृपया उक्त रिपोर्ट की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में देखें)

श्री केसरीसिंह : यह क्वाटरली रिपोर्ट और सालाना रिपोर्ट पेश की जानी चाहिए थी वह नहीं की गई है, इसके लिए क्या एक्शन लिया है ?

श्री दौलतराम सारण : आपके प्रश्न से यह हमारे ध्यान में आया और इस पर जो भी नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए वह की गई है।

श्री केसरीसिंह : क्या यह सही नहीं है कि बोर्ड के मेम्बर ने दस्तखत करके चेयरमैन महोदय को भी आब्जेक्शन्स के रूप में लिख कर दिया था और काम्पीटेंट आथोरिटी को रिप्रजेंटेशन लिख कर दिया है कि हिसाब नहीं बताया गया ?

श्री दौलतराम सारण : यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री केसरी सिंह : यह आडिट रिपोर्ट की जो अनुपालन रिपोर्ट आई है, क्या इससे आप पूर्ण रूप से संतुष्ट है; जो आडिट आब्जेक्शन्स किये गये उनका ठीक तरह से निराकरण कर दिया है ?

श्री दौलतराम सारण : आपने प्रश्न में जो जानकारी चाही है, वह दे दी है। अब हम संतुष्ट हैं या नहीं हैं, यह राय का सवाल है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इस आडिट रिपोर्ट के साथ में कम्प्लायेन्स रिपोर्ट है या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : यह निवेदन कर चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढदार।

स्टेन्डर्ड मीटर्स

४८५. **श्री दुर्गालाल बाढदार** (हवामहल, जयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सत्य है कि पानी का कनेक्शन लेने वाले व्यक्तियों को मीटर नियमानुसार सरकार को सप्लाई करना चाहिए ?

(२) क्या यह सत्य है कि जो स्टेन्डर्ड मीटर्स सरकार ने मान रखे हैं उनके अभाव में पार्टीज को स्वयं मीटर की व्यवस्था करनी पड़ती है ?

(३) क्या जलदाय विभाग स्टेन्डर्ड मीटर्स के अतिरिक्त भी किसी भी प्रकार का मीटर पास कर देता है ?

(४) जलदाय विभाग स्टेन्डर्ड मीटर किस किस प्रकार के मीटरों को मानता है। उनका विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(५) सन् १९५५ से १९६० तक राज्य सरकार के जलदाय विभाग ने कुल कितने स्टेन्डर्ड मीटर्स खरीदे और कितने आम लोगों को सप्लाई किए ?

(६) सन् १९५५ से १९६० तक कुल कितने नए कनेक्शन्स दिये गए जिनमें प्राइवेट पार्टीज ने स्टेन्डर्ड मीटर्स अपनी ओर से

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

जलदाय विभाग को दिए और जलदाय विभाग ने कितने मीटरों की व्यवस्था की ?

उप मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री-भवानी शंकर नंदवाना) : (१) जी नहीं।

(२) जी हां।

(३) जलदाय विभाग उसी मीटर को पास करता है जो सही रीडिंग दे।

(४) जलदाय विभाग केवल उसी मीटर को स्टेन्डर्ड मानता है जो आई. एस. आई. द्वारा प्रमाणित हो या उसके बराबर हो।

(५) सन् १९५५ से ६० तक जलदाय विभाग ने कुल १८,६६४ मीटर खरीदे। और आम लोगों को कनेक्शन के लिए १३,८१६ मीटर दिये गये।

(६) सन १९५५ से ६० तक १८,५४२ नये कनेक्शन दिये गये जिनमें से सरकार ने १३,८१६ मीटरों की व्यवस्था की व प्राइवेट पार्टीज ने ४,७२६ मीटरों की व्यवस्था की।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : प्राइवेट पार्टीज मीटर प्रोवाइड करती हैं सरकार को और सरकार की ओर से जलदाय विभाग द्वारा कहा जाता है कि मीटर हमारे पास नहीं है, तो आखिर फिर ये कहां से मिल जाते हैं ? यह क्या राज्य सरकार को मालूम है कि ब्लैक मार्केट से मीटर खरीदे जाते हैं। आप कोई व्यवस्था कर दें, यह आप स्वयं विचार कीजिये।

श्री भवानी शंकर नंदवाना : मीटर अवेलेबल हैं नहीं। कोटा से मिलते हैं, जितनी मिक्दार आती वह दे देते हैं। अगर मीटर नहीं मिलते हैं, तो फ्लेट रेट पर कनेक्शन दे देते हैं। सरकार जो मीटर खरीद कर देती है, उस पर किराया एक रुपया प्रति माह लेंगे और वे खुद खरीद कर लायें तो दस आना लेते हैं। यह उनको रियायत दी है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मेरा निवेदन है कि कोटा से मिलने वाले सरकार को तो मिलते नहीं है लेकिन प्राइवेट बिजनेसमैन, व्यापारी को मिल जाते हैं, इस ओर सरकार ध्यान दे।

श्री भवानी शंकर नंदवाना : इस ओर तो सरकार क्या ध्यान देगी ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अगर राज्य सरकार ध्यान नहीं देगी तो क्या पब्लिक खुद ध्यान दिया करे और अपना इन्तजाम खुद किया करे ?

गृह मंत्री श्री मथुरादास माथुर : इन्तजाम कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन !

कृषि सलाहकार

४८६. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे :–

(१) क्या सरकार ने राजकीय सचिवालय, जयपुर में किसी कृषि सलाहकार की नियुक्ति कर रखी है ? यदि हां, तो कब से और किस ग्रेड म ?

(२) इस सलाहकार की कृषि सम्बन्धी क्या योग्यताएं हैं ?

(३) इस सलाहकार के सुझावों से कृषि सम्बन्धी मामलों मे सरकार को क्या लाभ हुआ है ?

(श्री रामकिशन)

(४) सलाहकार कार्यालय का सालाना खर्चा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा): (१) जी हां । कृषि सलाहकार की नियुक्ति अप्रेल सन् १९५८ से की गई है । इनको कोई वेतन नहीं दिया जाता है ।

(२) कृषि सलाहकार एक प्रगतिशील और अनुभवी किसान है और इनको कृषि सम्बन्धी अच्छी जानकारी है ।

(३) समय समय पर ये सलाह देते रहते हैं जो कि बहुत ही उपयुक्त साबित हुई है ।

(४) कृषि सलाहकार के कार्यालय का सालाना खर्चा लगभग ८,२३८.९४ रुपये है ।

श्री रामकिशन: अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री जी ने उत्तर दिया है मैं समझता हूं कि वे खुद अपने मन में असंतुष्ट हैं । उन्होंने कहा कि वे प्रगतिशील, होशियार और अनुभवी काश्तकार हैं और उनकी सलाह से लाभ मिल रहा है । मैंने खास तौर पर यह पूछा था कि उनकी योग्यता क्या है ? इससे जाहिर है कि वे खुद असन्तुष्ट हैं । अस्पष्ट जवाब नहीं दें, स्पष्ट जवाब दें । वे जो जवाब देते हैं उसका कोई मतलब नहीं निकलता है ।

श्री नाथूराम मिर्धा: मेरा ख्याल है कि बहुत मतलब निकलता है जो मैंने बताया है उससे ।

श्री राम किशन: आप कन्विन्स्ड हैं, संतुष्ट हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा: बहुत कन्विन्स्ड हूं, कन्विन्स होकर जवाब देते हैं ?

श्री रामकिशन: उनकी सलाह से कितना फिजिकल लाभ पहुंचा है ? उनकी कोई योग्यता नहीं है, फिर कैसे मालूम हुआ कि वे प्रगतिशील किसान हैं ? वे कहां खेती करते हैं ? कहां फार्म है ? उसमें कितने पेड़ हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा: आप मुझसे अलग से पूछते तो मैं आपको सब बता देता—कितना लम्बा-चौड़ा फार्म है, उसमें कितने पेड़ लगाये हैं, उनकी क्या योग्यता है । आप कहें तो मैं उसकी घंटे भर तक चर्चा कर सकता हूं ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): कौन साहब है ?

श्री नाथूराम मिर्धा: रामजी काक हैं है ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): किस-किस मामले में क्या क्या सलाह दी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा: क्या क्या सलाह दी है, उसका तो बहुत लम्बा विवरण होगा ।

श्री रामकिशन: खास खास बता दें ।

श्री नाथूराम मिर्धा: खास खास क्या, जो वे काम कर रहे हैं, उसका बहुत लम्बा विवरण होगा । इसके बारे में चर्चा करेंगे तो बहुत लम्बा समय लगेगा ।

श्री रामकिशन: बहुत सलाह दी है, यह तो ठीक है, लेकिन दो-तीन बातें सलाह वाली बता दें जिससे मालूम हो जाय कि किस तरह की सलाह दी है और उससे कितना

(श्री रामकिशन)

लाभ हुआ है । इस मामले को दबायें नहीं, यह बहुत गम्भीर मामला है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : वे बहुत अच्छे प्रगतिशील किसान हैं, जिनका खुद का फार्म है, इसमें सब तरह के पेड़ लगाते हैं, कपास लगाते हैं और बेस करके किसानों को मार्गदर्शन देते हैं, वे सब तरह के काम करते हैं। यह बहुत अच्छा फार्म है । वे खुद प्रेक्टीकली हाथ से काम करते हैं । और रिसर्च लेबोरेट्री से जो सीख कर आते हैं उसके अनुसार अपने फार्म पर एक्सपेरीमेंट करते हैं और अगर सफल होते हैं तो उसे किसानों तक पहुंचाते हैं । एक अच्छे किसान को जो बात करनी चाहिएं और जाननी चाहिए, वे सब करते हैं और जानते है ।

श्री मोतीलाल चौधरी : क्या यह सही है कि वर्तमान सलाहकार हैं वे आल इंडिया बेसिस पर भेड़-पालन, फ्रूट्स आदि के कम्पीटीशन में बराबर फर्स्ट आते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वे कई बार आये हैं ।

श्री रामकिशन : क्या जिस वक्त प्रगतिशील किसान की नियुक्ति की थी, तो राजस्थान में और जो किसान प्रगतिशील हैं, उनकी जानकारी नहीं की थी? उनको किस आधार पर प्रगतिशील किसान माना है और उनकी क्या योग्यता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे को राजस्थान के किसानों की तो क्या सारे हिन्दुस्तान के किसानों की जानकारी है और मैं कह सकता हूं कि उनमें से रामजी काक एक बहुत अच्छे किसान हैं ।

(बहुत से माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

(शोर-गुल)

श्री अध्यक्ष : Order, Order !

श्री रामकिशन: जब आपने यह कहा कि योग्यता का आधार नहीं था, प्रगतिशीलता का आधार था तो दूसरे प्रगतिशील किसानों में से आपने किन किन को बुलाया था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं बुलाऊं क्यों ? मैं तो एक-एक को अच्छी तरह से जानता हूं ।

श्री रामकिशन : आप किन-किन बातों को जानते हैं उनमें से एक दो के नाम तो बतावें ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्व का प्रश्न है। जिस समय टैक्स सरकार लगा रही है

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उनकी नियुक्ति के पूर्व उन्होंने कितनी कॉम्पीटीशन्स में भाग लिया है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

(विराम)

Next question has been asked. Please don't argue. आपने पूछा कि आप किन को जानते हैं, तो बता दिया कि वे व्यक्तिगत जानकारी रखते हैं ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : क्या उन्होंने हाथ से काम किया है ?

श्री अध्यक्ष : वे कह चुके हैं कि उनका खुद का फार्म है और काम किया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : उन्होंने खुद ने काम किया है। वे हल चला सकते हैं, खुरपी चला सकते हैं और उनके हाथों में फाले पड़े हैं।

श्री रामकिशन : आप कहते हैं कि उनको अनुभव है और उनके खुद के फार्म हैं तो आप बतावें कि कितने प्राइवेट फार्म वाले हैं उनको भी अनुभव है, उनको क्यों नहीं लिया गया? इनको ही क्यों लिया गया?

श्री अध्यक्ष : यह दूसरा प्रश्न है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : कृषि के मामले में उनको कोई अनुभव नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४८७.

श्री सतीश-चन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

राजस्थान मे कृषि उत्पादन

४८८. **श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर)**:

Will the Agriculture Minister be pleased to state:

1 What has been the percentage increase in the agricultural production in Rajasthan :

(i) during the First Five Year Plan,

(ii) during the Second Five Year Plan, and

(iii) during the first two years of the Third Plan?

2. What percentage of additional area has been brought under cultivation in Rajasthan:-

(i) during the First Five Year Plan,

(ii) during the Second Five Year Plan, and

(iii) during the first two years of the Third Plan?

3. What increase in the productivity per acre of agricultural production has been achieved in Rajasthan —

(i) during the First Five Year Plan,

(ii) during the Second Five Year Plan, and

(iii) during the first two years of the Third Plan.

उप-मंत्री, कृषि (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१,२,३,) सदस्य महोदय द्वारा चाही गई विस्तृत जानकारी सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने इसे देखा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप देख लें, फिर सप्लीमेंन्ट्री पूछें।

(अनुपूरक प्रश्नोत्तरों के लिये कृपया आगे देखिये)

भावरा हिसार वाया डावड़ी रूट के लिए आवेदन-पत्र

४८९. **श्री मोहन लाल सारस्वत** (रतनगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) बीकानेर रीजन के भादरा हिसार वाया डावडी बस रूट के लिये आवेदन-पत्र कब मांगे थे और कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ?

(२) अभी तक उक्त रूट पर परमिट क्यों नहीं स्वीकार किये गये ?

यातायात मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) :
(१) अभी तक आवेदन-पत्र नहीं मांगे गये हैं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री मोहन लाल सारस्वत : ये प्रार्थना-पत्र कई दफे मांगे जा चुके है। आप कह रहे हैं कि मांगे ही नहीं गये ।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने कहा कि अभी रिसेन्टली २३.१. को यह तय हुआ है। कार्यवाही कलेक्टर के विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

रूरल वाटर सप्लाई स्कीम के स्वीकृत धनराशी

४९०. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) इस वर्ष रूरल वाटर सप्लाई स्कीम के अन्तर्गत कितनी धनराशी की योजनाएं सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हैं ?

(२) जिन-जिन गांवों की योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं उनकी जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(३) बीकानेर जिले के किन किन गांवों को पिछले तीन वर्षों में इस स्कीम में शामिल किया जा चुका है ?

उप मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) इस वर्ष रूरल वाटर सप्लाई के अन्तर्गत कोई भी योजना सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं की गई है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(३) बीकानेर जिले के निम्नलिखित गांवों को पिछले तीन वर्षों से इस स्कीम में शामिल किया जा चुका है :

(१) बेरासर

(२) पांचू

(३) सारून्डा

(४) लूणकरणसर

(५) जसरासर

(६) बादरा

(७) कालू

(८) राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट ऐरिया में डिग्गियों का निर्माण कार्य ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : यह लूणकरणसर में नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : यह योजना में शामिल है। वहां बोरिंग किया गया है।

Page No 18

श्री मानिकचन्द सुराणा : कोलायत में भी इस प्रकार की कोई योजना है क्या ? जैसा अभी भीमसेनजी ने पूछा और आपने कहा उसी तरह कोलायत भी बीकानेर में हैं।

श्री दौलतराम सारण : आपने यह पूछा है कि बीकानेर जिले के किन किन गांवों को पिछले तीन वर्षों में इस स्कीम में शामिल किया जा चुका है ? मैंने गांवों के नाम निवेदन कर दिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा: मैंने सुना नहीं। आप दुबारा पढ़ दें।

श्री दौलतराम सारण : में पढ देता हूं :

बीकानेर जिले के निम्नलिखित गांवों को पिछले तीन वर्षों से इस स्कीम में शामिल किया जा चुका है :—

(१) बैरासर (२) पांचू (३) सारूण्डा (४) लूनकरणसर (५) जेसरासर (६) बादरा (७) कालू (८) राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट ऐरिया में डिग्गियों का निर्माण कार्य।

श्री मानिक चन्द सुराणा : जैसरासर और कालू में कोई काम हुआ है, इस योजना के अनुसार ?

श्री दौलतराम सारण : जैसरासर में ३० हजार ८८४ रुपये अब तक खर्च किये जा चुके है और कालू में अभी खर्च नहीं हुआ है। अभी पानी की जांच की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४९१

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा
(अनुपस्थित)

श्री नत्थीसिंह

नगरपालिका सदस्यों के विरुद्ध जिलाधीश, [भरत]पुर के द्वारा शिकायत

४९२. **श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि जिलाधीश, भरतपुर द्वारा नगरपालिका के कई सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये राज्य सरकार को रिपोर्ट की गई थी ? यदि हां, तो कितने सदस्यों के विरुद्ध ऐसी रिपोर्ट की गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त सदस्यों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि उक्त सदस्यों के अलावा चेयरमैन नगरपालिका के सम्बन्ध में भी रिपोर्ट की गई थी और उन्हें निलम्बित कर दिया गया है ?

उप मंत्री स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां। भूतपूर्व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व १२ सदस्यों के विरुद्ध।

(२) सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही जारी है। यह सही है कि चेयरमैन को निलम्बित कर दिया गया है।

श्री नत्थीसिंह : सदस्यों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री दौलतराम सरण : कलेक्टर ने रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक उत्तर दिया है।

श्री रामकिशन : यह रिपोर्ट कब दी ?

श्री दौलतराम सारण : ७-४-६२ को।

श्री रामकिशन : माननीय सदस्यों के खिलाफ भी कलेक्टर ने शिकायत की थी और चेयरमैन के खिलाफ भी की थी। आपने चेयरमैन को तो निलम्बित कर दिया है और दूसरों को क्यों नहीं किया ?

Page No 19

श्री दौलतराम सारण : जांच पड़ताल करके चार्जसीट दी जा रही है।

श्री रामकिशन : चैयरमैन के खिलाफ कार्यवाही की गई मगर दूसरे सदस्यों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही क्यों नही की गई ?

श्री दौलतराम सारण : अब जल्दी कर रहे है।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बरकतुल्लाखां): अब तक विलम्ब हुआ है, मैं इसको स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री भैरोंसिंह : (किशनपोल, जयपुर): कलेक्टर की रिपोर्ट सदस्यों और चैयरमैन सब के खिलाफ थी। आप एक पार्ट को तो सजा देते हैं और बुरा मानते है और दूसरों के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रहे है, इसकी क्या वजह है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बरकतुल्लाखां): चैयरमैन के खिलाफ एलिगेशन्स थे। हाई कोर्ट में सब पेपर्स चले गये थे।

भैरोंसिंह : पेपर्स के आधार पर कलेक्टर ने काफी समय पहले रिपोट देदी थी, उसमें देर क्यों हुई ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री इस बात को स्वीकार कर चुके है कि देरी हुई है।

श्री रामकिशन : देरी का ही तो, अध्यक्ष महोदय, प्रश्न है। देरी क्यों हुई ?

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य ने यह रिफ्लेक्शन किया है कि उन्होंने पक्षपात किया है।

श्री बरकतुल्लाखां : कोई पक्षपात नहीं किया गया है। The Chairman was head of the institution, charges against him were serious; therefor action was taken first against him. There were less serious charges against the Members....

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कलेक्टर ने सदस्यों और चैयरमैन, दोनों को, दोषी माना था ?

श्री नत्थीसिंह : क्या यह सही है कि बजाय सदस्यों को दोषी मानते आपने चैअरमैन को निलम्बित किया है और उनके खिलाफ एक्शन नही लिया ?

श्री बरकतुल्लाखां : The matter went to the High Court and stay orders were granted by the High Court. उनका केस तो हाई कोर्ट में गया था और फैसला चैयरमैन के खिलाफ हुआ।

श्री रामकिशन : हाई कोर्ट को तो यह कहा गया था कि हमने बोर्ड को सुपरसीड कर दिया है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि हाई कोर्ट में रिट चैयरमैन ने की थी ?

एक माननीय सदस्य : क्या यह बोर्ड सुपरसीड हो चुका है और इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): जिसके खिलाफ़ चार्ज था उसको आपने ओफिशियटिंग चैयरमैन बना दिया।

श्री रामकिशन : इसका कारण तो आप बता दें ?

श्री अध्यक्ष : वह तो स्पष्ट हो गया होगा।

श्री रामकिशन : अगर इसमें भी टेलीफोन वाली बात कहें तो हम संतुष्ट हो जावेंगे।

श्री अध्यक्ष: इसमें, कहने की क्या बात है।

(विराम)

next : श्री श्योपतसिंह।

भाखरा नांगल योजना पर खर्चा

४९३. श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) भाखरा नांगल योजना पर कुल कितना खर्चा होने का अनुमान है और इसमें से राजस्थान सरकार के हिस्से में कितना रुपया पड़ेगा ?

(२) इस योजना की सिंचाई योजनाओं व बिजली योजनाओं पर कितना खर्चा होगा ? अलग-अलग बताया जावे।

उप-मंत्री सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) भाखरा नांगल प्रोजेक्ट की सिंचाई क्षेत्र पर खर्च की अनुमानित लागत १२०.०० करोड़ रुपये है। राजस्थान सरकार के हिस्से में इसका अनुमानित खर्चा २३.८५ करोड़ रुपया पड़ेगा, और अब तक १९.९६ करोड़ रुपया हिस्से में आया है।

(२) इस योजना की सिंचाई परियोजनाओं पर १२०.०० करोड़ व बिजली योजनाओं पर ५३.५३ करोड़ रुपये-कुल १७३.५३ करोड़ रु० की लागत लगने का अनुमान था लेकिन अनुमानतः योजना पर कुल खर्च २३३ करोड़ रु० आवेगा, जिस में से ३३.६ करोड़ रु० ब्याज के हैं।

लोन और सहायता, नगरपालिका रतनगढ़

४९४. श्री मोहरसिंह राठौड़ (चूरू) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) नगरपालिका रतनगढ को राज्य सरकार की ओर से कौन-कौन से साल में कितना-कितना लोन और सहायता मिली ?

(२) उक्त लोन और सहायता की शर्तों के अनुसार आज तक कार्य सम्पन्न हुए या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या कार्य सम्पन्न नहीं हुए तो उक्त रकम अभी तक नगरपालिका के कोष में जमा है ?

(४) यदि जमा नहीं है तो उक्त राशि किस अधिकारी ने अनुचित रूप से व्यय करें

(श्री मोहरसिंह राठौड़)
दी तथा उस अधिकारी के विरुद्ध राज्य सरकार ने क्या एक्शन लिया ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण): (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) उक्त लोन और सहायता कर्मचारियों के वेतन आदि में खर्च किए जाने से कार्य सम्पन्न नहीं हो सके।

(३) जी नहीं।

(४) इसकी जांच की जा रही है। जांच समाप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी।

(**कृपया परिशिष्ट ३ देखिये**)

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : कर्मचारियों के वेतन के लिये खर्च कर दी तो जो सब्सिडी और लोन जिस काम के लिए दिया था उसमें नहीं लगा कर कर्मचारियों को वेतन आदि चुकाने में खर्च कर दिया, इसके लिए एक्शन क्यों नहीं लिया गया ?

श्री दौलतराम सारण : मेरे उत्तर में स्पष्ट कह चुका हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहारी बाजार, जयपुर) : इस रकम को कर्मचारियों की तनख्वाह में खर्च कर देना, यही एक चीज नगरपालिका को सुपरसीड करने के लिए पर्याप्त नहीं है ?

श्री दौलतराम सारण : म्युनिसिपेलिटी तो सुपरसीड किये हुए हैं। जिन्होंने की उनके खिलाफ जांच करके आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

श्री मोहनलाल सारस्वत : ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिट विभाग ६ महिने पहले निश्चित कर चुका है कि जिन्होंने खर्च किया है उनसे वसूल की जाय।

प्रश्न संख्या ४९५

श्री अध्यक्ष : श्री गणपतिलाल वर्मा।

श्री गणपतिलाल वर्मा (माण्डलगढ़) : माननीय अध्यक्ष, इस प्रश्न का उत्तर मुझे पिछली बार मिल चुका है इसलिए मैं यह प्रश्न नहीं पूछना चाहता।

प्रश्न संख्या ४९६

श्री अध्यक्ष : श्री हरिराम चौहान।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४९७।

श्री गोविन्द सहाय

(अनुपस्थित)

श्री महेन्द्रसिंह

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : On a point of order, Sir, अध्यक्ष महोदय, किसी प्रश्न के छपने पर वह हाउस की प्रोपर्टी है। उस सम्बन्ध में आने वाला उत्तर प्राप्त करने के इस सदन को अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। किसी मेम्बर को डायरेक्ट उत्तर दे दिया जाय तो यह सदन की परम्परा के विरुद्ध है। इस प्रकार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। जवाब तो दिया ही जाना चाहिये। सप्लीमेन्टी न करना चाहें तो वे न करें।

श्री गणपतिलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार का प्रश्न इसी सत्र में पिछली

(श्री गणपतिलाल वर्मा)
बार मैंने पूछा था, उसका उत्तर मुझे इसी सत्र में मिल चुका है। इसलिये मैंने इस प्रश्न को नहीं पूछा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : दुबारा खर्चा हुआ, वह किससे वसूल किया जायगा ?

गृह-मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : If the hon'ble Member does not want to put the question he cannot be compelled by other hon'ble Members to ask it. परम्परा यह है कि यदि कोई माननीय सदस्य सदन में प्रश्न पूछते हैं और नहीं पूछना चाहें तो दूसरे माननीय सदस्य पूछने के लिये कम्पेल नहीं कर सकते।

श्री भैरोंसिंह : विथड्रा नहीं कर सकते। अगर मेम्बर गैर-हाजिर है और दूसरे को आथोरिटी नहीं दे दे तब तक तो नहीं पूछा जाय। पर प्रश्न यहां रखने पर विथड्रा नहीं कर सकते। यह मोशन नहीं है, क्वेश्चन है।

श्री मथुरादास माथुर : मेम्बर नहीं पूछना चाहें तो कम्पेल नहीं किया जा सकता है। वे तो प्रेजेन्ट हैं।

श्री रामकिशन : इसमें तो पूछ लिया गया है।

एक माननीय सदस्य : नहीं पूछा है।

अध्यक्ष : श्री महेन्द्रसिंह

खरंजे पर चिकनाहट

४९४. **कुंवर श्री महेन्द्रसिंह** (दीगोद): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि कोटा इटावा रोड पर ग्राम ताथेड, जिला कोटा के पास व ग्राम मारवाडा चौकी रेल्वे लाइन के नीचे दो नाले अलग-अलग उक्त दोनों स्थानों पर सडक को क्रोस करते हैं ?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों नाले नहर के कारण बारहों मास बहते रहते हैं, जिससे खरंजे पर काफी चिकनाहट जम गई है ?

(३) क्या यह भी सही है कि खरंजे पर चिकनाहट होने के कारण बैलगाडी, मवेशी व लोगों को निकलने में काफी तकलीफ रहती है ? यदि हां, तो इसके लिये सरकार क्या करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानी-शंकर नन्दवाना) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां, पुलिया निर्माण के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

श्री महेन्द्रसिंह : क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इस पर यह कार्यवाही कर रहे हैं कि चम्बल की नहर की वजह से दिन-रात पानी बहता है तो इर्रिगेशन विभाग को लिखा है कि आप की वजह से लोगों को पुलिये के अभाव में दिक्कत हो रही है। एस्टीमेट्स वगैरह तैयार किये जा रहे हैं, इर्रिगेशन विभाग को पैसे देने पडेंगे।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (मंडावर) : वहां दूसरे ही ढंग से दूसरे ही कारणों से पानी बहता है, नहर नहीं है······

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : उत्तर बहुत स्पष्ट है ।

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदसिंह ।

काकेज व थरपारकर नस्ल की गायें

४९९. **श्री उम्मेद सिंह** (बाड़मेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सही है कि काकेज व थरपारकर नस्ल की गायें बाड़मेर जिले में राजस्थान के अन्य सब जिलों से सब से ज्यादा संख्या में प्राप्त है ?

(ख) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त नस्लें भारत की प्रमुख नस्लों में से हैं ?

(ग) क्या मद्रास, मैसूर व मध्यप्रदेश आदि प्रांत थरपारकर नस्ल की गायों के विशेष खरीददार हैं और उनसे राजस्थान को अच्छी आमदनी होती हैं ?

(घ) अगर हां, तो सरकार इन नस्लों की गायों व उनको रखने वालों को क्या प्रोत्साहन देती है या देने की कार्यवाही कर रही है ?

उप-मंत्री कृषि (श्रीमती कमला बेनीवाल): (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) केवल मध्यप्रदेश प्रांत ने अभी कुछ गाये खरीदी है ।

(घ) इन नस्लों की गायें पालने वालों को ऋण दिया जाता है तथा पशु पालन विभाग द्वारा इनके बुल्स निःशुल्क वितरित किये जाते है । निःशुल्क चिकित्सा एवं उन्नत पशुओं को इनाम देने की भी व्यवस्था है ।

श्री उम्मेदसिंह: क्या यह बताने की कृपा करेंगें कि राजस्थान की प्रमुख ब्रीड्स में से यें दोनों है इनके लिये सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नही है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : २ नं० में मैंने यह स्वीकार किया हैं कि प्रमुख नस्लों मे से हैं और तरक्की के लिये जो कार्यवाही की जा रही है उसका विवरण दिया है ।

श्रीउम्मेदसिंह : तरक्की का विवरण दिया, मैं मान गया; पर यह सफिसियेंट नहीं है इसलिये सरकार से रिक्वेस्ट है कि सरकारी फार्म खोल कर प्रोत्साहन दे ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : जिस जिस तरह साधन बढ़ते जायेंगे, उत्तम व्यवस्था की जायगी

श्री उम्मेदसिंह : इन साधनों की बाड़मेर और जसलमेर के लिए ही कमी है क्या ?

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल !

मऊ इब्राहिमपुर ग्राम को बिजली

५००. **श्री श्रवण लाल** (हिन्डोन): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि हिन्डोन से बिजली हिन्डोन स्टेशन तक पहुंच चुकी है।

Page No 24

(श्री श्रवण लाल)

(२) क्या यह भी सच है कि हिन्डौन स्टेशन से मऊ इब्राहिमपुर ग्राम करीब ४ मील दूर रह जाता है और उसकी जनसंख्या ५ हज़ार के करीब तथा एक व्यापारिक कस्बा है और जयपुर से करौली जाने वाली सड़क पर स्थित है ? क्या सरकार यहां पर बिजली लाने की योजना बना रही है ? यदि हां तो यहां, कब तक बिजली पहुंच जावेगी ?

उपमंत्री सामान्य प्रशासन (श्री परस राम मदेरणा) : (१) जी हां ।

(२) जी हां । पर जनसंख्या १९५१ की जनगणना के अनुसार केवल ९६३ है और जयपुर से करौली जाने वाली सड़क पर स्थित है । यहां बिजली लाने की कोई योजना नहीं है ।

श्री श्रवणलाल : मन्त्री महोदय ने ९६३ जनसंख्या बताई पर मैं निश्चय के साथ कहना चाहता हूं कि वहां की जनसंख्या ५००० से कुछ ही कम हैं।

श्री परसराम मदेरणा : १९५१ की जनसंख्या के अनुसार ९६३ ही जनसंख्या है और १९५१ की जनगणना के अनुसार ११५२ है आप ५००० की कह रहे हैं और सेंसस रिपोर्ट यह कह रही है ।

श्री रामकिशन : (वैर) जनसंख्या बता रहे हैं या जनसंघियों की संख्या बता रहे हैं ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : कांग्रेस मेम्बर्स कितने है, यह संख्या बता रहे हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया ५००० या ५००० से ऊपर की जनसंख्या के गांवों में बिजली देने की सरकार की योजना है, यह गांव उनमें नहीं आता है । इसके बाद भी इलेक्ट्रिक प्रोग्राम में शामिल किया जाना इस बात पर निर्भर करता है कि रेमुनरिटी होगी या नहीं, धन उपलब्ध होगा कि नहीं । ६३ के लोकल इलेक्ट्रिक डिस्ट्रिब्यूशन में यह नहीं लिया गया है, आगे लेना धन की उपलब्धि, रेमुनरिटी होगी या नहीं इन सब आधारों पर मुनस्सर होगा ।

श्री भैंरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा): अन्य उत्पादन के लिए कुओं में बिजली लेने के लिए किसानों ने मांग की, उनको क्यों नहीं दी गई ।

श्री परसराम मदेरणा : किसानों ने मांग की है या नहीं, इसकी मेरे पास सूचना नहीं पर लोकल डिस्ट्रिब्यूशन में यह गांव आता नहीं ।

श्री भैंरवलाल 'कालाबादल' : कुओं के लिए किसान बिजली लेना चाहते हैं उनको कब देंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल ।

श्री भैंरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : एक प्रश्न । यह आपने जो जन-संख्या बतायी है वह रेवेन्यू विलेज की है, या आबादी है विलेज की ?

श्री परसराम मदेरणा : विलेज की का आबादी का सवाल रेवेन्यू विलेज से ही होता है जिसमें ढानी वगैरह इन्क्ल्यूड होते हैं, सर्किल इन्क्ल्यूड होते हैं । एक पोर्शन तो होता नहीं है ।

Page No 25

श्री भैरोंसिह : रेवेन्यू विलेज में ढाणियां होती हैं वह हम भी जानते हैं ।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, वहां पर इस तरह तीन मोहल्ले हैं–मऊ इब्राहिमपुर, इब्राहिमपुर कलां और मऊ इब्राहिमपुर खास । वहां की जो जनसंख्या बतायी गई है वह बिलकुल गलत है ।

श्री परसराम मदेरणा : आपने तीनों के बारे में नहीं पूछा है । आपने तो मऊ इब्राहिमपुर के बारे में पूछा है उसी के लिए मेरा उत्तर है ।

श्री अध्यक्ष : ये बिजली चाहते हैं, आबादी नहीं चाहते हैं ।

प्रश्न संख्या ५०१

श्री मुक्तिलाल मोदी ।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द चौधरी ।

सड़क निर्माण योजना, तहसील दौसा

५०२. श्री **मूलचन्द चौधरी** (दौसा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या तहसील दौसा में ग्राम हिंगोदिया के पास से होती हुई बनीबाण ग्राम होकर लवाण जाने वाली सड़क के निर्माण की योजना सरकार ने मंजूर की थी ?

(२) क्या इसके लिए सरकार द्वारा रोड बाउन्ड्री स्टोन्स गाढ़ दिये गये थे ?

(३) क्या अब उस सड़क का काम बन्द है ? यदि हां, तो सरकार उपरोक्त सड़क का कार्य कब से शुरू करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नंदवाना) : (१) दौसा से लूमां वाया लवाण रोड की स्वीकृति दी गई है ।

(२) जी नहीं ।

(३) जी हां । आशा है कि कुछ दिनों में काम शुरू हो जावेगा ।

श्री मूलचन्द चौधरी : कब तक हो जावेगा ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : कुछ ही दिनों में ।

श्री मूलचन्द चौधरी : इस साल हो जायेगा ।

श्री भवानीशंकर नंदवाना : कुछ ही दिनों में, मैंने कहा ।

श्री दुर्गालाल बारदार (हवामहल, जयपुर): सीमा को परिसीमित तो करें । 'जल्दी' इतना वेग (Vague) टर्म है कि इससे कुछ काम होता है नहीं ।

श्री अध्यक्ष : इस समय तो कुछ दिनों को कहा है । तीसरी योजना नहीं कहा ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): कुछ दिनों का अर्थ तो एक महीने से कम होना चाहिये । तो एक महिने से कम है या ज्यादा?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : २० दिन में शुरू हो जावेगी ।

श्री अध्यक्ष : आपका इन्टरप्रिटेशन मंजूर है उनको ।

Page No 26

(श्री अध्यक्ष)
प्रश्न संख्या ५०३

श्री गोपीलाल गोठवाल।

(अनुपस्थित)

श्री मानसिंह महार (आमेर) : प्रश्न संख्या ५०३।

श्री अध्यक्ष : आप थोड़े ही हैं गोपीलाल गोठवाल।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : बनने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री मानसिंह महार : उन्होंने मुझे कहा है।

श्री अध्यक्ष : मुझे तो नहीं कहा।

(विराम)

श्री भगराज।

भूमि का कटाव, रानीवाड़ा पंचायत समिति

५०४. **श्री भगराज चौधरी** (रानीवाड़ा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पिछले वर्षों में अत्यधिक वृष्टि के कारण रानीवाड़ा पंचायत समिति में हजारों एकड़ भूमि का कटाव (Soil Erosion) हो गया है जिससे वह भूमि काश्त के काबिल नहीं रही?

(२) यदि हां, तो उस भूमि को वापिस खेती लायक बनाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

(३) यदि नहीं, तो क्यों नहीं तथा क्या सरकार निकट भविष्य में ऐसा कोई संतोष-जनक कदम उठाने का विचार रखती है?

उप-मंत्री, कृषि (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) पिछले वर्षों में अधिक वर्षा से इन क्षेत्रों में भूमि का कटाव तो नहीं हुआ, किन्तु जेतपुरा नदी में बाढ़ आने के कारण बालू रेत उपजाऊ भूमि पर जमा हो गई है, जिससे भूमि काश्त के काबिल नहीं रही है।

(२) इस समस्या की जांच-पड़ताल करा ली गई है और इसकी रोक थाम करने के लिये योजना भी बनाई जा रही है। भूमि संरक्षण कार्य के लिये भारत सरकार से अधिक धनराशि उपलब्ध होने की आशा है। यदि यह धनराशि मिल गई तो अगले साल जालोर जिले को भी इस प्रोग्राम में शामिल करने की योजना है।

(३) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री भगराज चौधरी : कितनी एकड़ जमीन ऐसी है जिस पर रेत फिर जाने से काबिल-काश्त नहीं रही है?

श्रीमती कमला बेनीवाल : दो-तीन हजार एकड़।

श्री भगराज चौधरी : दस-बारह वर्षों से अधिक वर्षा होने के कारण इस नदी की रेत फिर गई है जिससे वह जमीन काश्त के कारण जमीन में नहीं हो रही है सरकार को शीघ्र से शीघ्र इस ओर कुछ कार्यवाही करनी चाहिये, ताकि जमीन में काश्त हो सके।

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण

श्री दलपतसिंह (ग्राबू) : अध्यक्ष महोदय, एक इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, नदी के कटाव से कुओं का पानी काफी गहरा चला गया है । काश्तकार बिल्कुल प्रॉडक्शन कम करते हैं और इससे काश्तकार बर्बाद हो रहे हैं । इसलिए मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस ग्रोर शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करें ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने निवेदन किया कि जल्दी से जल्दी इसको करने के लिये योजना बना ली गई है ।

श्री दलपत सिंह : जल्दी से जल्दी तो पांच वर्ष हो गये कहते कहते । कोई कार्यवाही नहीं हुई । ऐसी कट्स बना कर करें, जिससे कूओं का पानी ऊपर आये । योजना तो कागजों में न रह जाय ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : योजना प्रारम्भ होने की स्टेज पर आ गई है और अब इसमें देर नहीं है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (ग्रासीन्द): सरकार ने रेत हटाने की क्या व्यवस्था की है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री जयनारायण सालोदिया ।

किसानों को बिजली, तहसील निवाई

५०५. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) क्या यह सच है कि चम्बल योजना की बिजली की लाइन तहसील निवाई के बीच से गई है ?

(२) क्या चम्बल योजना की बिजली सरकार किसानों को खेती कार्य के लिए देने का विचार रखती है ?

(३) क्या निवाई तहसील क्षेत्रों के किसानों ने अपने कुओं में सिंचाई के लिए बिजली के पम्प लगाने के कई प्रार्थना-पत्र दिए हैं ?

(४) क्या यह सच है कि इस क्षेत्र में कई जगह सर्वे भी हो गया है ? यदि हां, तो सरकार इस क्षेत्र के किसानों को कब तक बिजली देने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां ।

(२) जी हां ।

(३) मेयोलाई ग्राम के २० किसानों से प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं ।

(४) जी हां । सर्वे हो चुका है और इस क्षेत्र को बिजली देने कि स्कीम की टेक्निकल जांच की जा रही है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह जांच कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री परसराम मदेरणा : असिस्टेन्ट इन्जीनियर, निवाई बनस्थली लाइन ने सर्वे करके उसकी रिपोर्ट प्रोजेक्ट सर्कल के पास भेज दी है । अभी भेजे सप्ताह भर ही हुआ है । टेक्निकल जांच हो रही है । रेम्युनरेटिव समझी गई तो लोकल डिस्ट्रीब्युशन प्रोगाम में शामिल करेंगे ।

श्री जयनारायण सालोदिया : ५-६ पंचायत समितियों से भी २०-२० प्रार्थना-पत्र आये हैं; वराई, बैर ग्रादि ।

Page No 28

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुल जब्बार ।

नगरपालिकाओं द्वारा गन्ने पर ऑक्ट्राय

५०६. **श्री अब्दुल जब्बार** (निम्बाहेडा): क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान में गन्ने पर ऑक्ट्राय किन किन नगरपालिकाओं द्वारा वसूल किया जाता है?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलत राम सारण): १४२ नगरपालिकाओं में से ३२ नगरपालिकायें गन्ने पर ऑक्ट्राय वसूल करती हैं, परन्तु ३५ नगरपालिकाओं से अभी तक सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है कि वे गन्ने पर ऑक्ट्राय वसूल करती हैं या नहीं ?

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(**कृपया परिशिष्ट ४ देखिये**)

श्री अब्दुल जब्बार : गंगानगर फैक्ट्री में ऑक्ट्राय लेते हैं; क्या दर है इसकी, बता सकते हैं ?.

श्री दौलतराम सारण : गंगानगर में ·०१ नया पैसा पर मन ।

श्री अब्दुल जब्बार : चित्तौड में क्या है ?

श्री दौलतराम सारण : चित्तौड की सूचना प्राप्त नहीं हो सकी ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या सरकार की ओर से ऐसे नियम हैं, ऑक्ट्राय रेट फिक्स कर दी गई है ? ज्यादा या कम ?

श्री दौलतराम सारण : स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार नगरपालिकायें स्वयं तय करती है ।

श्री विजयसिंह झाला : अब ऐसे नियम बने हैं ?

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : आक्ट्राय टैक्स लेते हैं तो मिल के अन्दर गन्ना प्रेस होता है उस पर भी लगाते हैं ?

श्री अध्यक्ष : म्युनिसिपल एरिया में आता है तो लेते हैं ।

श्री दौलतराम सारण: गंगानगर मिल एरिया में आता हैं तो वहां भी लेते हैं ।

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : लेना चाहिये ।

श्री मोतीलाल चौधरी : लेते हैं तो इन्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट कैसे होगा ?

श्री अब्दुल जब्बार : जिन म्युनिसिपेलिटियों की सूचना नहीं आई है तो वे ही म्युनिसिपेलिटियां हैं जो शुगर फेक्ट्री गंगानगर और भोपालसागर से सम्बन्धित होंगी ? उन्हीं की लिस्ट नहीं आयी होगी ?

श्री अध्यक्ष : गंगानगर तो बता दिया ।

श्री दौलतराम सारण : गंगानगर तो बता दिया है । जिनका उत्तर नहीं आया है, आप चाहें तो फाइल पढ़ दूं · · ·

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य क्या पूछना चाहते हैं ? सीधा पूछें ।

श्री अब्दुल जब्बार : गंगानगर और भोपालसागर को गन्ना सप्लाई किया गया ।

Page No 29

(श्री अब्दुल जब्बार)
उनके कांटे लगे हुए हैं। म्युनिसिपेलिटी ने जो ऑक्ट्राय वसूल की है वह इरेगुलर है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जवाब दिया है वह अधूरा है। पूरी जानकारी न दे दें तब तक इसको पेन्डिग माना जाय। प्रश्न एक बार पूछा जा सकता है, ६ महीने निकल जाते हैं।

श्री दौलतराम सारण : कौनसा जवाब चाहिये ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : चित्तौड़ के लिए कहा कि सूचना नहीं आयी। ऑक्ट्राय लिया गया है। चित्तौड़ भी शामिल है। जवाब इस सम्बन्ध में अधूरा होने से आगे क्या सप्लीमेन्ट्री करें।

श्री अध्यक्ष : सप्लीमेन्ट्री पूछिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा : बेकार है जवाब नहीं है तो।

श्री अध्यक्ष : उनकी इन्फॉर्मेशन आ जावेगी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कब आ जावेगी ? सदन को तो मालूम ही नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : महत्व की चीज क्या है वह पूछिये। Why beat about the bush !

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर): महत्व की चीज वह है कि गन्ना जाता है उनकी रेट्स, खास तौर पर गंगानगर और भोपाल सागर शुगर फेक्ट्री, में अन्तर है। उनको एक लाइन पर लाने के लिए प्रश्न पूछा गया है। अन्तर उसी समय मालूम हो सकता है जब कि सूचना आ जाय।

श्री अध्यक्ष : सरकार से पूछ सकते हैं कि एकीकरण करने का है या नहीं उनकी रेट्स को ? They can straightaway ask this question.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : समस्त नगरपालिकाओं के लिए ऑक्ट्राय के रूल्स बनाइये।

श्री अध्यक्ष : That is a different question.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रूल्स होने चाहिए।

श्री मानिकचन्द सुराणा : गन्ने की ऑक्ट्राय ड्यूटी एक करने की नीति है या नहीं ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : माननीय अध्यक्ष, जैसा कि पहले यहां सदन में कहा जा चुका है कि ऑक्ट्राय का जो शिड्यूल एक हो सकता है, लेकिन पैटर्न एक नहीं हो सकता। म्युनिसिपैलिटीज हर एक अपने अपने तरीके से टैक्स लगाती हैं।

श्री अब्दुल जब्बार खां : निम्बाहेडा की जनता और काश्तकारों की ओर से इस बात के लिए रिप्रेजेन्टेशन पेश किया गया कि गन्ने का यहां ऑक्ट्राय नहीं लिया जाय ?

श्री **मानिकचन्द सुराणा** : इस क्वेश्चन को पेन्डिंग माना जाय।

श्री अध्यक्ष : यह पॉलिसी मैटर है। आप इस बारे में डिस्कशन रेज कर लीजिये।

श्री अब्दुल जब्बार : जो रेट गवर्नमेन्ट तय करती, उससे ज्यादा लिया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष : That is hypothetical.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : चित्तौड़ के सम्बन्ध में आपको जानकारी नहीं है कि किस दर से वहां ऑक्ट्रॉय ली जाती है; क्या मंत्री महोदय बता सकेंगे कि निम्बाहेड़ा में दर क्या है ?

श्री दौलतराम सारण : इसकी सूचना नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : प्रतापगढ़ में क्या दर है और भोपाल सागर में क्या दर है ?

श्री दौलतराम सारण : निम्बाहेड़ा का मेरे पास है, .०१ न० पै० पर मन।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : भोपालसागर का इस प्रश्न से सीधा संबन्ध है। वहां क्या ऑक्टॉय ली जाती है, यह बताने की कृपा करेंगे।

श्री दौलतराम सारण : अगर माननीय सदस्य दरों के बारे में अलग-अलग पूछते तो मैं जानकारी करके बता सकता था। अगर आप किसी में विशेष इन्टेरेस्टेड हैं तो उसकी सूची दी जा सकती है।

श्री बरकतुल्ला खां : जहां तक मुझे मालूम है भोपालसागर में म्युनिसिपैलिटी नहीं है।

कृषि कार्य के लिए बिजली व उसकी दरें

५०७. **श्री छोटूराम :** (नीम-का-थाना) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि जो बिजली गांवों में जा रही है उसमें से पच्चीस फीसदी कृषि के काम के लिए दी जायगी ?

(२) क्या यह भी सही है कि किसानों से बिजली की रेट भी कुछ कम ली जायगी ?

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी नहीं, ऐसा कोई पर्सेन्टेज फिक्स नहीं किया गया है।

(२) जी हां। सरकार ने समस्त राजस्थान में एग्रीकल्चर पम्पिंग लोड के लिए १२ न० पै० प्रति यूनिट देने की घोषणा की है।

श्री छोटूराम : क्या सरकार ने ऐसी कोई घोषणा की है कि सब काश्तकारों के लिए कुछ पर्सेन्टेज बिजली का रिजर्व किया जायगा ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : अध्यक्ष महोदय, सरकार की नीति यह है कि १५ प्रतिशत रिजर्व की जाय, लेकिन जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है–गावों में बिजली जाती है उसका पर्सेन्टेज क्या है ? गांवों का पर्सेन्टेज फिक्स नहीं है।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : एग्रीकल्चर लैन्ड के लिए कितना पर्सेन्ट बिजली देंगे, उसके लिए कुछ रिजर्वेशन किया है ?

Page No 31

श्री हरिश्चन्द्र : चीफ मिनिस्टर महोदय ने घोषणा की थी, ऐसा रिजर्वेशन रखेंगे जो १५ पर्सेन्ट तक हो सकता है ।

श्री मोतीलाल चौधरी : अब तक तो राजस्थान में इस तरह से बिजली दी ही नहीं है क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है ।

श्री हरिश्चन्द्र : जहां-जहां से मांग आई है इस बात के लिये कोशिश की गई है कि कृषि के लिए बिजली दी जाय । लेकिन जितना खर्च किया जाना चाहिए उतना हो नहीं रहा है क्योंकि उतनी धन-राशि उपलब्ध नहीं है ।

श्री मोतीलाल चौधरी : जो १५ पर्सेन्टे की घोषणा की है उतना पर्सेन्टेज एग्रीकल्चर को देने के लिए धनराशि नहीं है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने निवेदन किया; ट्रान्समिशन लाइन के लिए काफी नहीं, और नीचे जाने का सवाल नहीं ।

श्री अध्यक्ष: आप फैक्ट्स पूछिये। Please don't argue. Ask facts. This is a very sweeping statement.

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : सरकार ने इस बात की घोषणा की थी कि १५ फीसदी बिजली एग्रीकल्चर पंपस के के लिए दी जायगी । अब सरकार क्या यह कह सकती है कि इस प्रकार पर्सेन्टेज के हिसाब से एग्रीकल्चर के लिए कितनी बिजली दी है ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह पर्सेन्टेज तो मेरे पास नहीं है। १५ पर्सेन्ट तक हम रखेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : किसी को दी है क्या ?

श्री हरिश्चन्द्र : कई जगह दी है । मैं इसके अलावा यह भी निवेदन करूं कि हमने ५० लाख रुपया रोड इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए रखा है । यह पचास लाख रुपया भी कम है । जिस तरह से आप लोग चाहते हैं उसको देखते हुए धनराशी कम है । उसके लिये और भी ज्यादा धन की जरूरत है, तभी कृषि के लिए बिजली पहुंचाई जा सकती है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इन पचास लाख से कितना पर्सेन्टेज हो जायगा ?

श्री अध्यक्ष : १२ न० पै० का रेट अनाउन्स किया है वह क्या एग्जिस्टिंग रेट्स से ज्यादा है ? कन्शेसन देने के बजाय क्या रेट्स बढ़ाई हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र: यह मेरे पास सूचना है कि भाखरा में १२ न० पै० से कम है । अनाउन्समेंट १२ न० पै० का हुआ है, वह इस नजर से रखा गया है कि डीजल-थर्मल से जो सैट चल रहे हैं उनकी दरें ऊंची हैं, उनको भी १२ न० पै० पर ले आया जाय । भाखरा में कम हैं, सरकार इस बारे में जल्दी ही निर्णय लेकर हाउस को सूचित करेगी ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : क्या कृषि के लिए मिनिमम रेट निश्चित कर दी है कि इतनी बिजली का पेमेंट हर महीने देना होगा ? किसान जो है साल में दो तीन महीने बिजली लेता है और उसको १२ महीने तक मिनीमम रेट जो फिक्स की है वह देना

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)
पडेगी। इस तरह से जो कन्सेशन देना चाहते हैं वह सब मिला कर बहुत ज्यादा पडता है।

श्री हरिश्चन्द्र: यह मिनीमम रेट बताई है, लेकिन जिस तरह से आप फरमा रहे हैं; इस बात को भी एग्जामिन किया जा सकता है इसमें मुझे कोई एतराज नहीं।

(दिनांक १२ मार्च, १९६३ का स्थगित प्रश्न)

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग द्वारा की गयी खरीद

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर): क्या मंत्री मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) सन् १९६०-६१ से लेकर अब तक राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग द्वारा किस २ फर्म से १० हजार से अधिक का कितनी कितनी कीमत का सामान खरीदा गया? कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें जिसमें किस किस वर्ष में कितनी कीमत का सामान ऐसी प्रत्येक फर्म में खरीदा गया है अंकित हो।

(ख) इन फर्म्स में से किस किसने माल सप्लाई करने में नियमों का पालन किया और किसने नहीं? कसूरवार फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उप मंत्री, मुद्रण एवं लेखन सामग्री (श्रीमती कमला बेनीवाल): माननीय सदस्य ने विस्तार से जानकारी चाही है उसमें से अधिकतर जानकारी इकट्ठी कर ली गयी है, फिर भी कुछ शेष है। इसमें टाईम लगेगा। अधूरा चाहें तो मैं दे सकती हूं

श्री अध्यक्ष : पूरा ही दे दीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में व्यवस्था चाहूंगा ये प्रश्न आते हैं। और उसके जवाब मिलने में काफी समय रहता है, फिर भी पूरे प्रश्नों के जवाब नही आते हैं। इतना समय मिलने पर भी इसकी जानकारी इकट्ठी नही कर पाये जब कि इतने सारे कर्मचारी हैं। इतना बड़ा स्टाफ है फिर भी समय पर जानकारी नहीं मिलती है। विशेष परिस्थिति, में अगर सूचना एकत्रित नहीं हो पाती है तब तो उसकी सूचना सचिवालय को हो जाय ताकि उनका प्रिन्ट ही न हो। चार दिन बाद वह लिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष: कई दफा सरकार की ओर से जवाब नही आता। वैसी हालत में हम भी चाहते हैं कि कोई मंत्री पोस्टपोनमेंट के लिये दरख्वास्त करें तो सदन में खड़े हो कर करें We want them to face the house.

श्री भैरोंसिह (किशनपोल बाजार, जयपुर): इसका जवाब पूरा आ चुका है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह जवाब हम तो मानते हैं कि यह पूरा नहीं है। जितने सामान के बारे में आपने पूछा है उसकी पूरी जानकारी नही है।

श्री मोतीलाल चोधरी (डीडवाना): जानकारी इसलिये नहीं है कि समूचे विभाग में आज तक खरीद का कोई हिसाब नही रखा जाता?

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह सही नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): ४४८ के सप्लीमेन्टरी।

श्री अध्यक्ष : कौन से प्रश्न के ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : ४८८ के ।

श्री सतीशचन्द अग्रवाल : ४८७ रह गया साहब ।

श्री अध्यक्ष : आपके प्रश्न के सप्लीमेन्ट्री पूछना चाहते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जी हां ।

श्री अध्यक्ष : कौनसा है ?

प्रश्न संख्या ४८८ के अनुपूरक प्रश्नोत्तर

श्री रामानन्द अग्रवाल : ४८८ के । जो ये आंकड़े मुझे दिये गये हैं इनके अनुसार क्या मैं यह मान कर चलूं कि दूसरी योजना के बाद खाद्यान्न आइल सीड और काटन का ईल्ड पर एकड़ कम हुआ है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जी हां । यह आंकड़ों से स्पष्ट है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसका क्या कारण था ?

श्रीमती कमला बेनीवाल: वेदर कन्डीशन्स का खराब होना। इस कारण अकॉर्डिंग टू टारगेट ईल्ड नहीं हो सका ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पर क्या पांचों वर्ष ही ऐसे निकले कि वेदर कन्डीशन्स खराब रही, या विशेष साल ऐसा रहा जिसमें सारा एवरेज गिर गया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह साल के हिसाब से पूरा विवरण नहीं है, पर एवरेज के हिसाब से डिक्रीज दिखाया गया है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह आपने ६०-६१ के ऊपर ६१-६२ में जो प्रोडक्शन के आंकड़े दिखाये हैं उसमें एक साल में ही गेहूं की ईल्ड पर एकड़ में १६ और ऑइल सीड में २४ का अन्तर दिखाया है । एक साल में इन्हीं चीजों में इतना इन्क्रीज रहा है कि पांच साल में इतनी डिक्रीज हो गई वह एक साल की इन्क्रीज से ही सारी ईल्ड में फर्क पड गया ?

श्री अध्यक्ष : एक अच्छी क्रॉप से सारा फर्क पड सकता है । इरिगेटेड तो है नहीं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये आंकड़े सरकार के सब अनरिलायबल हैं । ये जो फिगर्स दिये हैं बजट स्टेडी में, वे भी डिफर करते हैं, टैली नहीं होते दूसरे आंकड़ों से ।

श्री अध्यक्ष: यह तो आपका इन्फरेन्स है । और फैक्ट पूछ लीजिये । आप इन्हीं से यह दिखाना चाहते हैं क्या कि ये सारे आंकड़े अनरिलायेबल हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल: जी हां । ये आंकड़े किस आधार पर दिये हैं?

कृषि मन्त्री श्री नाथूराम मिर्धा : इसका तो एक बड़ा भारी विभाग है । वे आंकड़े इकट्ठे करने का ही काम करते हैं । वे जो बताते हैं वे ही हम आपको यहां देते हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह बजट स्टेडी भी वहीं से आई होगी, तो इसमें आंकड़े डिफर करते हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह तो आपने कह दिया। जो सवाल आपने उठाया था उसमें

(श्री नाथूराम मिर्धा)

सिर्फ दो पॉइन्टस का अन्तर रह गया था एक तो डायरी वाला कोट किया था और दूसरा बजट स्टेटिस्टिक्स वाले में से पोईन्ट आउट किया था उसमें दो पौईन्ट का फर्क है। एग्रीकल्चर विभाग के दो पोइन्टस कम हैं और स्टेटिस्टिक्स वालों के दो पॉइन्ट्स ज्यादा हैं। अब उनको रिकन्सीलियेशन हो कर जाना चाहिये था। मुझे पता नहीं, यह कैसे हुआ ? हमने पूछा है कि तुम्हारे दो आकडे अलग अलग तरीके से कैसे हैं। उनसे जानकारी आने पर हम आपको बता देंगे।

श्री रामानंद अग्रवाल : यही नहीं, ६०' ६१ और ६१-६२ में फूड ग्रेन का पर्सेन्टेज इन्क्रीज्ड बताया है, एक में २० पर्सेन्ट और इसमें २५ परसेन्ट आता है। आपने आइल सीड में पर्सेन्टेज डिक्रीज्ड बताया है ४८ पर्सेन्ट, दूसरे में ४१ पर्सेन्ट है। तो इस तरीके से यह जो फर्क है इसका कारण क्या है ?

श्री अध्यक्ष : इसके लिये मन्त्री महोदय ने बताया है कि वे इसकी जानकारी कर रहे हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : आपने कभी ३ मदें रखी हैं और जो आपने आकडे दिये हैं इसमें पर एकड ईल्ड गिर रहा है। क्या सरकार ने अपने एग्रीकल्चर एडवाइजर से कोई सलाह ली कि इस पर एकड गिरते हुए ईल्ड को रोकने के लिये सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहियें ?

श्री नाथूरामिर्धा : एग्रीकल्चर विभाग में बहुत से लोग सलाह देने वाले हैं।

श्री मानिकचन्द्र सुराणा : बहुत से लोगों की नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो एग्रीकल्चरल एडवाइजर की बात कह रहा हूं जिनको आपने एडवाइजर मुकर्रर किया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : वे भी वन आफ दी पार्ट हैं, इसी के।

श्री मानिकचन्द्र सुराणा : मैं तो उनके बारे म एडवाईजर के बारे में पूछ रहा हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसमें वे क्या सलाह दें, हम तो खुद देखते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरी इस बात का उत्तर नहीं आया कि इतना कम ईल्ड होने का क्या कारण सरकार समझती है, सरकार का एग्रीकलचर विभाग समझता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अब इसके कई कारण हो सकते हैं वेदर कन्डीशन्स है, जो लैण्ड नया कल्टीवेशन में जाता है वह घाटिया किस्म की हो सकती है, मार्जिनल और सब-मार्जिनल लैण्ड हो सकती है, इसका एरिया हर साल बढता रहता है। किसी साल में ज्यादा पैदा हो जाता है, किसी साल कम। किसी साल में अच्छी लैंड ज्यादा काम आती है, किसी में कम काम आती है। लैंड का डिटेरियोरेशन हो जाता है किसी साल फर्टीलाइजर कम यूज होता है, किसी साल ज्यादा होता है। किसी साल बन्ध में पानी कम ज्यादा होता है, तीन पिलाई की जगह दो ही होती है या दो की जगह तीन हो जाती हैं। तो कई ऐसे सर्कमटान्सेज हैं जिनकी वजह से फसलों में अन्तर आता है समय समय पर।

श्री अध्यक्ष : ये कई कारण हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : टोटल फलावट में भाग देने से दो चार पोइन्टस का फर्क हो सकता है। अच्छा साल हो तो बढोतरी

(श्री नाथूराम मिर्धा)
की तरफ हो सकता है और खराब साल हुआ तो घटोत्तरी की तरफ हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

(शोरगुल–एक साथ अनेक माननीय सदस्य बोलने खड़े हुए)

Order please ! Order !!

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है, आइल सीड के बारे में ।

श्री अध्यक्ष : Order please ! Order !!

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक क्वेश्चन रह गया । एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है । ४८७ वैरी इम्पोर्टेन्ट है । क्वेश्चन नम्बर ४८७ को पूछने की इजाजत दे दी जावे ।

श्री अध्यक्ष : कई माननीय सदस्यों के प्रश्न रह गये हैं । एक ही नहीं ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसीन्द) : यह ४७३ तो बहुत ही इम्पोर्टेन्ट है, अध्यक्ष महोदय ।

रोडवेज के फ्री पास

४७३. **श्री ज्ञानचन्द मोदी** (थोई) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सत्य है कि राजस्थान सरकार राजस्थान विधान सभा के सदस्यों को रोडवेज के फ्री पास देने का विचार कर रही ? यदि हां, तो कब से ?

उप मंत्री, स्टेट एन्टर प्राइजेज (श्रीमती कमला बेनीवाल) : वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आप विचार करेंगे इस पर कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष : मैं दुबारा नाम बोलता हूं ।

श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

श्री मथुरेशबिहारी माथुर ।

(अनुपस्थित)

श्री जुझार सिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र ।

स्लॉटर हाउस बाई लॉज, श्री करणपुर म्युनिसिपल बोर्ड

४८७. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

१. क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने श्री करणपुर म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा निर्मित स्लॉटर हाउस बाई लॉज (Slaughter House Bye-Laws) को स्वीकृति प्रदान कर दी है ?

२. क्या यह सही है कि इन बाई लॉज के खण्ड ८ के अनुसार जो गायें दूध देना बन्द कर दें उनको प्राइवेट स्लाटर हाउस में काटा जा सकता है बशर्ते कि इस

Page No 36

(श्री सतीशचन्द्र अगवाल)
प्रकार का सर्टिफिकेट सम्बन्धित स्लॉटर हाउस इन्सपेक्टर से प्राप्त कर लिया गया हो ?

३. क्या यह सही है कि राज्य में किसी भी हालत में गायों का काटा जाना पूर्णतः वर्जित है ? यदि हां, तो फिर यह प्रावधान क्यों कर रखा गया है ?

उपमन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : १. जी हां।

२. जी हां ।

३. जी हां, यह प्रावधान हटाया जा रहा है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि प्राइवेट स्लॉटर हाउस में जो गायें दूध नहीं देती हैं वे काटी जा सकती हैं, इस तरह के कोई बाई लॉज सरकार ने पास कर दिये हैं ?

श्री दौलतराम सारण : गलती से मन्जूर हो गया था । लेकिन कोई गाय कटने का सवाल नहीं है । यह बात ध्यान में आते ही डाइरेक्टर ने आदेश देकर रोक दिया था । अब वह प्रावधान हटाया जा रहा है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये आदेश कब दिये ?

श्री दौलतराम सारण : २६-१०-६२ को ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि ये बाईलाज इसके बाद में पास हुए है; २४ जनवरी, १९६३ को ?

श्री दौलतराम साख बाईलाज सेंक्शन ए २७-७-६२ को ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि बाईलॉज जिस तारीख के गजट में नोटीफाई हुए वह २४ जनवरी, ६३ को है जिसमें है कि

"No female goats, cows, she-buffaloes or any she animals would be slaughtered in any private slaughter houses as long as the female animals are yielding milk; provided a certificate to that effect that female animals have ceased to yield milk would have to be obtained from the Slaughter House Inspector before slaughtering such animals".

यह २४ जनवरी, ६३ का गजट है । डेट ऑफ पब्लिकेशन से यह फोर्स में आया है ।

These rules shall come to force from the date of publication in the Rajasthan Gazette.

इसके बाद आपका कोई आदेश इस सम्बन्ध में नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : यह कहा गया कि गलती से पब्लिश हो गये गजट में । इतनी बड़ी बात ससेप्टिबिलिटीज जिसकी हो । किसने यह गलती की और अभी तक क्यों नहीं आपने उसको पकड़ा और सामने लाये ? पहले भी सवाल उठ चुका है इस तरह का, क्या वह अधिकारी निकाल दिया गया आज तक ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : बड़ी शर्मनाक बात है यह । ऐसी चीजें होती

Page No 37

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
हैं राजस्थान में और सरकार को कोई जानकारी नहीं है इसकी। क्यों नहीं है ?

श्री मोतीलाल चोधरी (डीडवाना) : माननीय अध्यक्ष, जिस प्रकार गलती से ये बाईलाज प्रकाशित हो गये गजट में तो इसमें कई अधिकारियों का हाथ होना चाहिये। निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा मसला है, जिसके पीछे जनता के सेन्टीमेन्ट्स हैं। इस तरह से बाईलाज पास होने से समाज में स्थिति भयंकर हो सकती है। मैं जोर से यह मांग करूंगा कि किस डायरेक्टर ने इन्हें पास किया, उसके खिलाफ सख्त ऐक्शन लिया जाना चाहिये और निश्चित रूप से लिया जाना चाहिये और जो भी कसूरवार हों समें उनको भी सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिये।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात में साफ अर्ज कर दूं कि जो कानून राजस्थान में बना हुआ है उसके मुताबिक कोई इस तरह का स्लॉटर हो नहीं सकता। तो लीगली तो कोई परमिट इस तरह की दी नहीं गई है,न दे सकते थे, जिस पर गाय का स्लॉटर किया जासकता हो। अब बाईलाज गलती से निकल गये तो उसके लिये जरूर कार्यवाही की जायगी पर फिर भी Byelaws are Byelaws and an Act is Act and cow is a protected animal ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह तो हम भी जानते हैं कि Cow is a sacred thing. मगर कानून सन् ५९ में इस बात का मौजूद है, तो फिर डाइरेक्टर ने ऐसे आदेश क्यों जारी किये ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : और किये तो आपने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्री मोतीलाल चौधरी : इससे मालूम पड़ता है कि वह कितना नैग्लीजेंट है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : वह सरकार की नीतियों के खिलाफ है और माननीय मुख्य मन्त्री जी ने आश्वासन भी दिया था कि इस प्रकार की हमारी नीयत नहीं है और न हमने कानून बनाया है। यदि कोई सरकारी अधिकारी इससे संबंधित बाईलॉज निकालता है तो उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी और सख्त कदम उठाया जायेगा।

श्री बरकतुल्ला खां : इसलिये कोशिश की जा रही है कि रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स की जाये।

श्री मानिकचन्द सुराणा : तो यह सरकार सोती क्यों रहती है ? अभी तक रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की है। ये बाई-लॉज गलत निकले हैं और यह कह रहे हैं कि हम रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स कर रहे हैं; आखिर रैड-टेपिज्म का कहीं न कहीं तो अन्त होना चाहिये, कहीं न कहीं तो सरकार की तरफ से ऐसा आचरण होना चाहिये जिससे मालूम हो कि सरकार सो नहीं रही है।

श्री बरकतुल्ला खां : ये जो बाईलॉज निकले हैं इससे तो हमारे वोट कटे हैं। हम तो ज्यादा कांग्रिस हैं और हम चाहते हैं कि रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स की जाये and for that we are trying.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 'वोट कटे' से क्या मतलब है ? ×× ××

×××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल)

या वोट कटे इससे हमारा मतलब नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय कह चुके हैं कि इसमें गलती हुई है। दूसरी बात यह भी कह चुके हैं कि जांच कर रहे हैं। इतने सारे आफिसर्स जिनकी मार्फत ये पेपर्स गये उनमें से कौन कौन जिम्मेदार हैं उससे सम्बन्धी रेस्पोन्सिबलिटी फिक्स की जाय और हम आशा करते हैं कि इसके बारे में जल्दी निर्णय ले लिया जायेगा।

श्री सम्पतिलाल बोहरा ।

(अनुपस्थित)

श्री हरिराम चौहान ।

(अनुपस्थित)

श्री गोविन्द सहाय ।

(अनुपस्थित)

श्री गोपीलाल ।

(अनुपस्थित)

श्री मुक्तिलाल मोदी ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : Point of order Sir मेरे एक प्रश्न का उत्तर गृह मन्त्रीजी को देना बाकी है उन्होंने कहा था कि अगली टर्म पर दे दिया जायेगा। पिछली बार आपने आश्वासन दिया था।

श्री अध्यक्ष : यह छपेगा जब आपका उत्तर आयेगा। मन्त्री महोदय की गलती नहीं है।

(१२.२३ म. प.)

सन् १९५९-६० के आय-व्ययक संबंधी विशेषाधिकार प्रश्न

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने एक विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना दी है, जिसमें यह बतलाया गया है कि श्री हरिभाऊ उपाध्याय, भूतपूर्व वित्त मन्त्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ (१) (ब) में किये गये प्रावधान के अनुसार १९५८-५९ के वित्तीय वर्ष में उस वर्ष के लिए सदन द्वारा दी गई अनुदान की राशि से अधिक धन व्यय होने से सम्बन्धित अधिक मांगों का विवरण न पेश कर एवं १९५९-६० के वार्षिक वित्त विवरण में १२.८६ लाख का सरप्लस दिखलाते हुए गलत विवरण प्रस्तुत कर सदन के विशेषाधिकार का हनन किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने दिनांक ६ मार्च, १९६३ को भी अधिक अनुदानों की मांगों पर विचार करने से पूर्व इसी आशय की एक आपत्ति उठाई थी। मैंने उक्त आपत्ति का निराकरण करते हुए उस दिन यह स्पष्ट किया था कि वित्त मन्त्री द्वारा जो अधिक अनुदानों की मांगों का विवरण सदन को प्रस्तुत किया गया है वह अवैधानिक नहीं है तथा यह भी बतलाया गया था कि किसी वित्तीय वर्ष के लिए सदन द्वारा स्वीकृति

(श्री अध्यक्ष)
अनुदानों की राशि से अधिक खर्च का पता उस वर्ष के पश्चात् ही लगता है। उसके बाद सदन के सामने विनियोग लेखा एवं तत्सम्बन्धी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत होती है और उस रिपोर्ट में अन्य मामलों के साथ साथ बतलाये गये अधिक खर्चों के मामलों की जांच सदन की जन-लेखा समिति द्वारा की जाकर उस समिति द्वारा एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है और तभी इस प्रकार की अधिक मांग सदन के अन्दर आती है।

जहां तक माननीय सदस्य द्वारा दिये गये विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना का सम्बन्ध है मेरी यह मान्यता है कि इस मामले में सदन के किसी विशेषाधिकार का हनन नहीं हुआ है। अतः मैं श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल के विशेषाधिकार के उक्त प्रश्न को सदन में उठाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

इस सम्बन्ध में मैं इतना अवश्य बताना चाहूंगा कि इस तरह की स्वीकृति से अधिक खर्च के मामले जनलेखा समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुत होने के पश्चात् शीघ्रातिशीघ्र सदन के समक्ष पेश किये जाने चाहियें। वर्ष १९५८-५९ में किये गये अधिक व्यय आदि से सम्बन्धित जन लेखा समिति का प्रतिवेदन १० मई, १९६२ को सदन में प्रस्तुत किया गया था और उसके पश्चात् माह अक्टूबर, १९६२ में विधान सभा का जो सत्र हुआ था उसमें उससे सम्बन्धित अधिक मांगें पेश की जा सकती थीं किन्तु ऐसा नहीं किया गया।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आपने रूलिंग दी वह तो सही है, लेकिन ब्रीच ऑफ प्रिविलेज दूसरी प्रकार का हो गया कि १९६० के अन्दर पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट जब पेश हो जाती है तो गवर्नमेन्ट के सामने लाजमी काम है कि वह सदन को कॉन्फीडेन्स में ले। यह सही है कि एक्सेस डिमाण्ड पेश की, उसका ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं हुआ लेकिन जिस इनफार्मेशन को सदन प्राप्त कर सकता था आज से दो वर्ष पहले उसमें डिले हुई—वह अपने आप में, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। ऑडिट सरकार के लिए जरूरी है, पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के इन्तजाम करने का नहीं है। पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी का फंक्शन और हाउस का फंक्शन अलग है। वह हाउस की नॉलेज में आना चाहिये कि ऑडिट में जो एक्सेस डिमान्ड दिखाई गई है उसका रीजन क्या है। क्योंकि सरकार यह बहाना नहीं ले सकती कि सरकार को इसकी जानकारी नहीं मिली कि कितनी एक्सेज डिमाण्ड है, कितनी नहीं है। जिस समय यह डिटेक्ट हुई उस डिटेक्शन के साथ ही वह हाउस में आती है। वह नहीं लायें तो जो हमारा विशेषाधिकार है उसका हनन तो उन्होंने किया है इस पोइन्ट के ऊपर।

श्री अध्यक्ष : जैसा मैंने अभी बताया कि विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता और कम से कम जन लेखा समिति का प्रतिवेदन पेश हुआ उसके बाद तो जल्दी से जल्दी पहले ही अधिवेशन में यह एक्सेस डिमाण्ड पेश करनी चाहिये थी और वह भी नहीं की गयी। इसलिये माननीय सदस्य ने कहा है कि वह बात नहीं भी मानी जाये, लेकिन जन-लेखा समिति के प्रतिवेदन के शीघ्र बाद में पेश की जानी चाहिये। इसलिये विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं रहता। लेकिन भविष्य में इस बारे में ध्यान रखें इसलिये सरकारी पक्ष का इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया है।

पाक सीमा पर अपहृत व्यक्तियों सम्बन्धी स्थगन-प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : एक माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसका संबंध पाक सीमा पर दो व्यक्तियों के अपहरण से है। इसके विषय में व्यवस्था बाद में दी जायेगी।

(१२.१८ म. प.)

लेखन एवं मुद्रण सामग्री विभाग द्वारा की गई खरीद विषयक जांच अधिकारी की नियुक्ति

श्री हरिश्चन्द्र (यातायात मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने यहां प्रेस में जो पर्चेजेज हुई हैं उसके बारे में वक्तन-फवक्तन आपत्तियां उठाई हैं और आपने भी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि कुछ व्यवस्था होनी चाहिये। इसके फलस्वरूप सरकार ने यह निर्णय लिया है कि चेयरमैन, रेवेन्यू बोर्ड को इन्क्वायरी आफिसर नियुक्त किया जाये और वे इस बात की जांच करें कि १९५९ से लेकर १९६३ तक जितनी भी पर्चेजेज हुई हैं उनके बारे में इन्क्वायरी करके सरकार को रिपोर्ट करें। यह भी उनको आदेश दिया गया है कि यह रिपोर्ट सम्भवतः जल्दी से जल्दी की जाये, लेकिन ३ महीने तक के टाइम लिमिट में पेश की जाये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष-महोदय, मन्त्री महोदय ने जो इस बात के लिए घोषणा की है .....

श्री अध्यक्ष: उसके लिये धन्यवाद दीजिये पहले।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : लेकिन इसमें एक बात और है, अध्यक्ष महोदय, कि इस प्रकार की इन्क्वायरी थी १९५९ और ६० के सिलसिले में और उसके बाद में डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी शिवहरे के खिलाफ और एन्टी–करप्शन ने भी इन्क्वायरी की थी ट्रेसिंग पेपर के लिये और ए. जी. की तरफ से स्पेशल ऑडिट हुआ था और वहां भी इन्क्वायरी डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी हुई थी, इन्क्वायरीज तो इसमें कई हो चुकी हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक्शन का सवाल है।

दूसरी बात यह है कि इन्क्वायरी के सिलसिले में पहली बार भी श्री तनखा और श्री मिश्रा साहब जो कि डाइरेक्टर थे वे एवीडेन्स में नहीं आये, जिन क्लर्क्स को पेश किया, एक नवाब अली को पेश किया उसने पहले स्टेटमेन्ट कुछ दिया और एन्टी–करप्शन के सामने जाकर बदल गया। इसका कारण यह होता है कि जब तक वह अधिकारी पद पर रहता है तब तक इम्पार्शियल इन्क्वायरी नहीं हो सकती, न कोई स्टेटमेन्ट देगा, न कोई क्लर्क विटनेस (एविडेन्स) देगा जब तक हैड ऑफ दि डिपार्टमेन्ट को उस पद से नहीं हटाया जायगा। सरकार ने चेयरमैन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को नियुक्त किया है उससे पहले कमिश्नर फॉर डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरीज, एन्टी करप्शन और ए. जी. ने इन्क्वायरी करके शिकायत की कि इसमें गडबड घोटाला है और एस्टीमेट्स कमेटी का प्रतिवेदन जो कल ही प्रसारित हुआ है उस में भी सब्सटेन्शियल नतीजे पर पहुंचे हैं कि खरीद फरोख्त की सभी चीजों में घोटाला है। इसलिये जहां तक फैक्ट्स का सवाल है वे एस्टेब्लिशड हैं इसलिये सरकार को श्री शिवहरे को सस्पेन्ड करना चाहिये।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मैं कहना चाहूंगा कि यह बिल्कुल बोनाफाइड है, मन्त्रीजी, मैं विश्वास करता हूं कि उसको सस्पेन्ड करेंगे तो निश्चित रूप से जांच हो सकेगी। सारा मसला सामने आ सकता है। इस अधिकारी के खिलाफ एस्टेब्लिश्ड तथ्य हैं, इसलिये इसको सस्पेन्ड किया जाय।

श्री अध्यक्ष : मांग संख्या १६ !

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : ऐसे अधिकारी को सस्पेन्ड करना चाहिये।

श्री बरकतुल्ला खां (स्वास्थ्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या १६ मुख्य शीर्षक २९ · · · ·

श्री रामकिशन (वैर) : इसका उत्तर तो मन्त्री महोदय को देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : कोई उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। मन्त्री जी आपकी भावनाओं को अच्छी तरह से जानते हैं।

श्री रामकिशन (वैर) : उसको सस्पेन्ड करने के लिये मन्त्री जी महोदय विचार करेंगे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : मैं नहीं चाहता कि इस तरह की बात सदन में आये कि किसी का ट्रान्सफर कर दिया जाय या किसी को सस्पेन्ड कर दिया जाय। मन्त्री जी मुनासिब समझें तो इस पर कार्यवाही करें। सदन की भावनाओं के वे अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन किसी को ट्रान्सफर कर दिया जाय या किसी को सस्पेन्ड कर दिया जाय, ये बातें व्यक्तिगत रूप से सदन में लाना ठीक नहीं है। कोई बात यहां कही जाती है तो निश्चित रूप से माना जाना चाहिये कि मन्त्री जी नहीं कहें तो भी कि उन पर विचार किया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : इन्क्वायरी की रिपोर्ट तो सदन में प्रस्तुत की जानी चाहिये।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अपने यहां का जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक ऐसे स्टेटमेन्ट के ऊपर क्या सदन में डिस्कशन हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष : बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं सहमत हूं आपसे।

(१२.३२ म. प.)

मांग संख्या १६, १७ व ४० चिकित्सा, जन स्वास्थ्य एवं जन–स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत

श्री बरकतुल्ला खां (स्वास्थ्य मंत्री) : मैं पहले पढ चुका हूं। वापिस पढ़ूं क्या ?

श्री अध्यक्ष : वापिस पढ दीजिये।

श्री बरकतुल्ला खां (स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९ चिकित्सा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४,१७,३९,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३० जन स्वास्थ्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित

Page No 42

(श्री बरकतुल्ला खां)
राज्यपाल महोदय को २,६४,१८,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

श्री **हरिश्चन्द्र** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ९४, जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के संबंध में ३१ मार्च १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४६,७०,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

श्री **अध्यक्ष** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

कटौती प्रस्ताव इस प्रकार प्रस्तुत हुए ।

महारावल श्री **लक्ष्मणसिंह** (आसपुर) :

37. Demand No. XVI, Major Head 29-Medical be reduced by rupee one (to discuss the failure of Government to maintain the due dignity of the madical Institution and proper management in Hospitals and dispensaries).

श्री **विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) :

मांग संख्या १६

(२) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में १००) रु० की कटौती की जाय (चिकित्सा को ग्रामीण क्षेत्र से वंचित रखा उस पर बहस करने हेतु) ।

(३) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में १००) रु० की कटौती की जाय (ग्रामीण क्षेत्र में डाक्टरों की कमी पर बहस करने हेतु) ।

(४) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में १००) रु० की कटौती की जाय (आयुर्वेदिक विभाग को कम सहायता मिलती है उस पर बहस करने हेतु) ।

(५) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में १००) रु० की कटौती की जाय (पी० एम० ओ० तथा डी० एम० ओ० पोस्टों के आपसी सम्बन्ध पर बहस करने हेतु) ।

(६) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में १००) रु० की कटौती की जाय (क्षय निरोधक की नीति पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या १७

(७) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन स्वास्थ्य में १००) रु० की कटौती की जाय (पंचायतों को जो सहायता का अनुदान जनस्वास्थ्य के लिये दिया जाता है उस पर बहस करने हेतु) ।

(८) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में १००) रु० की कटौती की जाय (परिवार नियोजन केन्द्र की नीति पर बहस करने हेतु) ।

श्री **ज्वालाप्रसाद शर्मा** (नसीराबाद) :

मांग संख्या १६

(९) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (नसीराबाद में चिकित्सा विभाग की अव्यवस्था पर बहस करने हेतु) ।

(१०) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (राज्य में चिकित्सा विभाग के प्रति व्याप्त असंतोष पर बहस करने हेतु) ।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

(११) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (अजमेर में मेडिकल कालेज न खोलने पर बहस करने हेतु)।

(१२) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (अजमेर विक्टोरिया अस्पताल में और बढोतरी करने संबंधी पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १७

(१३) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन स्वास्थ्य में एक रुपये की कटौती की जाय (जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा नसीराबाद, में पूरा ध्यान न देने पर बहस करने हेतु)।

(१४) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन स्वास्थ्य में एक रुपये की कटौती की जाय (मलेरिया उन्मूलन में सरकार की असफलता पर बहस करने हेतु)।

श्री **केसरी सिंह** (पाली):

(१५) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३० जन-स्वास्थ्य में १) रु० की कटौती की जाय (तहसील पाली के कुछ गांवों में पीने के पानी का यथोचित प्रबन्ध करने की आवश्यकता पर बहस करने हेतु)।

कुमारी उमा माथुर (रामगढ):

(१६) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९ चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (चलिष्णु शल्य-चिकित्सा पर बहस करने हेतु)।

(१७) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (अस्पतालों में डाक्टरों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर बहस करने हेतु)।

श्री **विठ्ठल** (बांसवाड़ा-सु०):

(१८) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (दानपुर में मेडिकल डिस्पेन्सरी खोले जाने पर बहस करने हेतु)।

(१९) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (बांसवाडा जिले में आयुर्वेदिक औषधालयों में समय पर दवाई नहीं मिलती है पर बहस करने हेतु)।

(२०) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (बांसवाडा मेडिकल अस्पताल में मरीजों के ठहरने की अव्यवस्था पर बहस करने हेतु)।

श्री **मोहनराज** (बाली):

मांग संख्या १६

(21) Demand No. XVI, Major Head 29-Medical, be reduced by rupee one (to discuss the inadequate staff and improper maintenance of the hospitals and ayurvedic aushdhalayas specially in rural areas).

मांग संख्या १७

(22) Demand No. 17 Major Head 30-Public Health be reduced by rupee one (to discuss the failure of the Government to provide necessary funds for the measures very necessary in the rural areas).

श्री हरदत्त सिंह (नोहर) :

(२३) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में १००) रु० की कटौती की जाय (नोहर सब-डिविजन में चिकित्सा के संबंध में सरकार द्वारा दिखलाई गई उदासीनता पर बहस करने हेतु) ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन):

(२४) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में १००) रु० की कटौती की जाय (पाटन तहसील में चिकित्सा के अभाव से होने वाली हानियों पर बहस करने हेतु) ।

(२५) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९–चिकित्सा में १००) रु० की कटौती की जाय (पशु चिकित्सालय की आवश्यकताओं पर बहस करने हेतु) ।

(२६) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९––चिकित्सा में १००) रु० की कटौती की जाय (बूंदी अस्पताल में बीमारों की दयनीय स्थिति दवाओं का अभाव व भवन की कमी के कारण पर बहस करने हेतु) ।

श्रीमती गौरी पूनिया (डेगाना):

(२७) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९––चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (गांवों में चलती फिरती सर्जिकल यूनिट की आवश्यकता पर बहस करने हेतु) ।

श्री विजयपाल (डूंगरपुर सु०):

(२८) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९––चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (डूंगरपुर अस्पताल में चल रही अव्यवस्था पर बहस करने हेतु) ।

श्री लक्ष्मीचन्द (पीपलदा):

(२९) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९–चिकित्सा में १००) रु० की कटौती की जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक चिकित्सा व्यवस्था पहुंचाने में सरकार की असफलता पर बहस करने हेतु) ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंह नगर):

(३०) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान के विभिन्न Hospitals में रोगियों के अनुपात में दवाईयां न दिये जाने की सरकार की गलत नीति पर बहस करने हेतु) ।

(३१) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९––चिकित्सा में १०) रु० की कटौती की जाय (गंगानगर District Hospital में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा बद-इन्तजामी पर बहस करने हेतु) ।

(32) Demand No. XVI, Major Head 29-Medical be reduced by rupees 100/- (to discuss the need of increasing medical facilities in Ganganagar Hospital).

(33) Demand No. XVI, Major Head 29-Medical be reduced by rupees 100/- to discuss the need of an-X-Ray plant at Raisinghnagar Hospital).

(34) Demand No. 16, Major Head 29-Medical be reduced by Rs. 100/- (to discuss the mal-administration and bad conditions of Government Hospital Sikar).

श्री पोहूमल ईशरदास (अजमेर-पश्चिम):

(35) Demand No. XVI, Major Head 29-Medical be reduced by rupee one (to discuss the grant-in-aid to Homeopathic Dispensaries and insufficient Homeopathic Government dispensaries for treatment of patients).

(श्री पोहूमल ईसरदास)

(36) Demand No. XVI, Major Head 29-Medical be reduced by rupee one (to discuss the insufficient stock of medicines provided to Government hospitals).

(37) Demand No. XVI Major Head 29-Medical be reduced by rupee one (to discuss the failure of Government in providing Medical College at Ajmer).

श्री वेकीलाल मीणा (सराडा–सु०) :

मांग संख्या १६

(३८) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९ चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (तहसील सराडा में आदिवासी क्षेत्र में औषधालय खोलने पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या १७

(३९) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक रु३०—जन स्वास्थ्य में १) रु० की कटौती की जाय (तहसील सराडा ग्राम चावन्ड में सेकेन्ड्री हेल्थ सेन्टर खोलने पर बहस करने हेतु) ।

(४०) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०—जन स्वास्थ्य में १) रु० की कटौती की जाय (तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर ऋषभदेव प्राइमरी हेल्थ सेन्टर में डाक्टरों की कमी पर बहस करने हेतु) ।

श्री चन्दनसिंह बर्फा (बिलाडा):

(41) Demand No. XVI, Major Head 29-Medical be reduce by rupee one (to discuss on purchasing scheme of medicines and surgical Equipments & Instruments).

(42) Demand No. XVI, Major Head 29-Medical be reduced by rupee one (to discuss on Accommodation and diets for patients in Hospitals).

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय) :

मांग संख्या १६ .

(४३) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९ चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (देहात में चिकित्सा पर कोई सरकार तवज्जह नहीं देती है और बाजार में मुनाफाखोरी बढ़ गई है—देहात में चिकित्सालय खोलने पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या १७

(४४) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन स्वास्थ्य में एक रुपये की कटौती की जाय (जो फिजूल खर्चा कर रहे हैं और बसें जो मलेरिया दवाईयां छोडना, बुखार की गोली देना व खून टेस्ट करना व माता के टीके लगाने पर बहस करने हेतु) ।

श्री राम किशन (वैर) :

मांग संख्या १६

(४५) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (भरतपुर जिले के औषधालयों को दी जाने वाली दवाइयों की कमी पर बहस करने हेतु) ।

(श्री रामकिशन वैर)

(४६) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (भरतपुर जिले के औषधालयों तथा चिकित्सालयों में रोगियों को दी जाने वाली सुविधाओं की कमी पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १७

(४७) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में एक रुपये की कटौती की जाय (दवाई वितरण तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी सरकार की नीति पर बहस करने हेतु)।

(४८) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में एक रुपये की कटौती की जाय (व्यापक रोगों को मिटाने में सरकार असमर्थ रही है कार्य प्रणाली पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या ४०

(४९) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ९४-जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत में एक रुपये की कटौती की जाय (भरतपुर जिले के नगरों में नल लगाये जाने के सम्बन्ध में बहस करने हेतु)।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :

मांग संख्या १६

(50) Demand No. XVI Major Head 29-Medical be reduced by rupees 100/- to discuss insufficient emolument of compounders during P. N. R. C. Training).

(५१) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (अस्पतालों में मरीजों को दवाइयां मिलने में अव्यवस्था पर बहस करने हेतु)।

(५२) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा प्रबन्ध के प्रति उपेक्षा पूर्ण नीति पर बहस करने हेतु)।

(५३) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में १००) रु० की कटौती की जाय (अलवर के अलैक्जैन्ड्रा हस्पताल में कोई भी वैज्ञानिक सर्जन नियुक्त न करने की सरकारी नीति पर बहस करने हेतु)।

(५४) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (अस्पतालों में Indoor patients के रूप में भर्ती होने में धांधली पर बहस करने हेतु)।

(५५) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (डाक्टरों के वेतन श्रृंखलाएं इन्जीनियरों के समान स्तर पर लाने की आवश्यकता पर बहस करने हेतु)।

(५६) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (डाक्टरों को सर्विसेज के integration में अनावश्यक देरी पर बहस करने हेतु)।

(५७) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (प्रान्त में अधिक T. B. Sanitorium की आवश्यकता की ओर सरकार का ध्यान खींचने पर बहस करने हेतु)।

(५८) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
(सरकारी अस्पतालों में भर्ती हुए मरीजों के लिए भोजन की दुर्व्यवस्था पर बहस करने हेतु) ।

(५९) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में १००) रु० की कटौती की जाय (सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दवाइयों की उचित व्यवस्था न होने की स्थिति पर बहस करने हेतु) ।

(60) Demand No. XVI, Major Head 29-Medical be reduced by rupee one (to discuss the inability of the Govt. to provide proper medical facilities to the rural people.

(61) Demand No. XVI, Major Head 29-Medical be reduced by rupee one (to discuss in-ability of the Government to check deterioration in the medical service to the people).

मांग संख्या १७

(६२) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन स्वास्थ्य में १००) रु० की कटौती की जाय (अलवर मलेरिया उन्मूलन विभाग में घनश्याम नामक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को मंत्री द्वारा पुनः काम पर लगाने का आश्वासन के बावजूद काम पर न लगाने पर बहस करने हेतु) ।

(63) Demand No. XVII, Major Head 30-Public Health be reduced by rupee one (to discuss inability of the Government to check gro-wth of diseases in Rajasthan).

(६४) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन स्वास्थ्य में एक रुपये की कटौती की जाय (वाटर वर्क्स विभाग द्वारा बिलों की अदायगी में विलम्ब होने पर २५ प्रतिशत का भारी व un Consessionables ब्याज लेने के प्रश्न पर बहस करने हेतु) ।

(65) Demand No. XVII, Major Head 30-Public Health be reduced by rupee one (to duiscuss the desirability of creating a separate water works Board for the Urban Water Supply Schemes from the rural water supply schmes and running it on commercial basis).

(६६) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में १००) रु० की कटौती की जाय (अलवर में जिला जन-स्वास्थ्य विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से दुर्व्यवहार पर बहस करने हेतु) ।

(६७) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में १००) रु० की कटौती की जाय (अलवर नगर नल योजना की अव्यवस्था पर बहस करने हेतु) ।

(६८) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन स्वास्थ्य में १) रु० की कटौती की जाय. (जल प्रदाय योजनाओं के अन्तर्गत पानी के रेट निर्धारित करने की गलत नीति पर बहस करने हेतु) ।

(69) Demand No. XVII, Major Head 30-Public Health be reduced by rupee one (to discuss inability of the Government to check gro-wth of diseases in Rajasthan).

श्री रविशंकर याज्ञिक (पिंडवारा) : (७०) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (ग्रामीण व

(श्री रविशंकर याज्ञनिक)
आम जनता पर डाक्टरों का ध्यान न दिए जाने पर बहस करने हेतु) ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (ग्रासपुर) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या १६ मुख्य शीर्षक २९ के संबंध में मैं अपना कटौती प्रस्ताव मूव करता हूं । चिकित्सा विभाग मूलतया दो हिस्सों में विभक्त है । एक एलोपैथिक और दूसरा आयुर्वेदिक । समय के अभाव के कारण आयुर्वेद विभाग के संबंध में मैं कुछ विशेष नहीं कहूंगा; एलोपैथिक के संबंध में मैं अवश्य कुछ कहना चाहता हूं ।

मैं समझता हूं कि प्रशासन टोप हैवी, ऊपर के स्तर के ऊपर कुछ महंगा है, खर्चा विशेष है । इसके अन्दर संभवतः कमी करने के संबंध में माननीय मंत्री महोदय विचार करें । डाइरेक्टर आफ मेडिकल और हैल्थ सर्विसेज के अन्तर्गत ११ डिप्टी डाइरेक्टर्स और असिस्टेंट डाइरेक्टर्स हैं । उनमें तीन असिस्टेंट जोनल डाइरेक्टर्स हैं अन्यथा एडमिनिस्ट्रेटिव, मलेरिया, प्लानिंग, स्माल-पाक्स इत्यादि इत्यादि के विभिन्न विभाग हैं । इस संबंध में मैं समझता हूं ११ की जगह ८ डिप्टी डाइरेक्टर्स या असिस्टेंट डाइरेक्टर्स रखे जायं तो पर्याप्त हो सकते हैं । संभवतः एडमिनिस्ट्रेटिव, प्लानिंग, फेमिलि प्लानिंग के अलग अलग हैं उनके बजाय आप एक ग्रुप बना दीजिये । हैल्थ और मेडिकल का एक ग्रुप बना दीजिये । ग्रूपिंग करने से मितव्ययता संभवतः आ सकती है । इस संबंध में मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय उचित समझें तो विचार कर सकते हैं ।

मेरे सुझाव का मूल कारण है कि डी. एम. एन्ड एच.ओ. पी. एम. ओ. और सी. एम. ओ. क्रमशः १२, ७ और ४ हैं । सब मिला कर २३ हैं । २३ राजस्थान के लिये पर्याप्त नहीं हैं । मेरे ख्याल से इस ग्रेड के ओफिसर कम से कम ३० होना परमावश्यक है । राजस्थान के क्षेत्रफल को देखते हुए, भौगोलिक स्थिति को देखते हुए मेरे ख्याल से चिकित्सा के प्रशासन को सुचारु रूप से चलाने के हेतु मैं समझता हूं यह परमावश्यक है ।

जहां तक मुझे मालूम है ४ सी. एम. ओज. राजस्थान में थे वह अभी डी. एम. एच. ओ. करार दिये जा चुके हैं । लेकिन डूंगरपुर में अब तक सी. एम. ओ. ही मौजूद है । इसका क्या कारण है कि वहां के सी. एम. ओ. को डी. एम. एच. ओ. के स्तर पर उसका डेजिगनेशन अब तक क्यों नहीं किया गया, कुछ मुझे मालूम नहीं इस संबंध में भी जानकारी प्राप्त करने के लिए मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा ।

सब खर्चा इस विभाग का ४ करोड़ १९ लाख का है उस संबंध में ५२ लाख ५६ हजार की दवाइयों आयुर्वेदिक और एलोपेथिक का प्रावधान है । २० लाख २४ हजार का खाना अर्थात् डाइट का प्रावधान है । १८ लाख ३८ हजार का इक्विपमेंट का प्रावधान है अर्थात् कुल मिला कर ९१ लाख १ हजार का प्रावधान है अन्यथा ३ करोड़ १९ लाख का एडमिनिस्ट्रेशन, एस्टाब्लिशमेंट के संबंध में प्रावधान है अर्थात् चिकित्सा के संबंध में २५ परसेण्ट से भी कम खर्चा राजस्थान सरकार कर रही है अन्यथा खर्चा एडमिनिस्ट्रेशन और एस्टाब्लिशमेंट के संबंध में है । एस्टाब्लिशमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में जो खर्चा हो

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

रहा है वह उचित है उसमें आवश्यकता है कि बढ़ाया जाय लेकिन अभी की इमर्जेंसी की स्थिति को देखते हुए यदि इसमें बढ़ोतरी की संभावना नहीं भी हो तो मैं, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि चिकित्सा के संबंध में, मरीजों की खुराक के संबंध में आज जो प्रावधान २० लाख का है वह कम से कम ४० लाख का होना चाहिए। ४ करोड़ १६ लाख का कुल खर्चा है उसका कम से कम १० प्रतिशत प्रावधान इसके लिये अवश्य होना चाहिए। चिकित्सा और खुराक मुफ्त में गरीब मरीजों को वितरित हो यह भी परम आवश्यक है। विलीनीकरण से पहले सभी विभिन्न राज्यों में यह व्यवस्था थी कि गरीबों को मुफ्त दवाइयां मिलें, मुफ्त खाना मिले, दलिया, खिचड़ी, समय पर दूध आदि। वह आज धीरे धीरे लुप्त सी हो गई है और चिकित्सा की व्यवस्था दिन ब दिन मंहगी होती जा रही है।

मैं समझता हूं कि सोशिलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी को यदि ध्यान में रखा जाय तो चिकित्सा का मंहगा होना, न्याय का मंहगा होना, शिक्षा का मंहगा होना—ये बातें ऐसी हैं जो सोशियलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी के विपरीत हैं, उसके प्रतिकूल हैं, उसके अनुकूल नहीं है—यह मेरी दृढ़ मान्यता है।

अध्यक्ष महोदय, चेचक के संबंध में केन्द्र से प्रावधान हुआ है कि नॉन-रेकरिंग एक्सपेण्डीचर शत प्रतिशत हद तक राजस्थान को अनुदान के रूप में केन्द्र के द्वारा प्राप्त हो, नॉन रेकरिंग एक्सपेण्डीचर के संबंध में ७५ प्रतिशत केन्द्र राजस्थान सरकार को मदद देने का वायदा कर चुका है। इस तरह से अगर इस योजना को समस्त राजस्थान में बढ़ाया जाय, फैलाया जाय तो मेरे ख्याल से उचित होगा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में अभी चेचक माता की बीमारी में बहुत से बच्चे मरे, यह भी प्रश्न के संबंध में मुझे जानकारी यहां प्राप्त हुई है कि राजस्थान के दूसरे क्षेत्रों में भी चेचक की बीमारी है। सरकार यथाशक्ति इस संबंध में प्रयास करती है, ये प्रयास पर्याप्त नहीं हैं तो भी एक हद तक मैं मानता हूं, प्रशंसनीय है। मैं आशा करता हूं, इस योजना को समस्त राजस्थान में लागू किया जायगा और डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले, जहां अभी भी चेचक से बच्चे मर रहे हैं, बालक उत्पीड़ित हैं, वृद्ध लोगों को भी यह बीमारी हुई है—उस संबंध में भी प्रबंध राजस्थान सरकार करेगी। डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा उदयपुर जिले के दक्षिण के हिस्से में जंगल अधिक होने के कारण, पानी अधिक गिरने के कारण वहां मलेरिया विशेषतः होता है। मलेरिया जब क्रोनिक हो जाता है तो उससे टी. बी. होती है। और टी. बी. के द्वारा लोगों की वाइटेलिटी घटती है और जनता का स्वास्थ्य, और उत्पादन भी पर्याप्त रूप से, स्वस्थ रूप से नहीं रह सकता। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन क्षेत्रों के अन्दर मलेरिया को रोकने की व्यवस्था लागू की जाय, आठ महीने, साल भर तक यदि सुचारु रूप से यह लागू की जायगी तो मुझे विश्वास है कि इसका जनता के ऊपर लाभदायक प्रभाव पड़ेगा। यदि सरकार चाहे तो फरवरी, मार्च, अप्रेल, मई—यह व्यवस्था यहां पर लागू न करे, अन्यथा शेष महीने, साल भर यह व्यवस्था

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

वहां पर लागू की जायगी तो विशेष हितकारी होगी ।

ट्रेकोमा के संबंध में जहां तक मुझे जानकारी हुई है, राजस्थान सरकार ने निश्चित रूप से निर्णय नहीं किया है, परन्तु यह केन्द्र के द्वारा आश्वासन राजस्थान सरकार को प्राप्त है कि शत प्रतिशत केन्द्र के द्वारा मदद आर्थिक रूप से सरकार को दी जायगी । इस संबंध में भी मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी, जो कुछ भी भारत सरकार का निर्णय है, वह योजनावद्ध रूप से राजस्थान के अन्दर लागू हो जाना चाहिए । पी. एम. एच. ओ.; डी. एम. एच. ओ.; जो ऑफिसरान हैं, अधिकांश रूप से उनके फंक्शन्स, उनकी जिम्मेदारियां हैं वे प्रशासनिक ढंग की हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ढंग की हैं, वे अपने अनुभव से पर्याप्त रूप से जनता को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से समय नहीं दे सकते । संभवतः यह बहुत कठिन समस्या है कि उनका कुछ समय जनता के हित के लिये देने की व्यवस्था की जाय परन्तु मैं समझता हूं कि सीनियर कैडर के आफिसर यदि सप्ताह में अमुक दिन में अमुक समय जनता को लाभान्वित करने के लिए दे सकें तो सोने में सुगन्ध रहेगी । मैं यह नहीं चाहता कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन्स उनसे ले लिये जायं लेकिन कोई न कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन का बर्डन कम करके, उस मात्रा में कम करके, उनके अनुभव का लाभ जनता को मिल सके तो मेरे ख्याल से यह और भी विशेष लाभकारी होगा ।

लेडी डॉक्टर्स राजस्थान के अन्दर ६५ हैं, लेडी डॉक्टरों का बिल्कुल दुष्काल है, अभाव है; लेकिन इसके उपरान्त में डूंगरपुर के लिए निवेदन करूंगा कि डूंगरपुर का अस्पताल पहले भी एक अच्छा अस्पतालों में माना जाता था । वहां पर लेडी डाक्टर नहीं है । चार पांच लेडी डाक्टर नहीं, एक भी लेडी डाक्टर नहीं है । मेरे ख्याल से यह सरकार के लिए शोभनीय वस्तु नहीं है । मैं आशा करता हूं, डूंगरपुर में कम से कम एक लेडी डाक्टर देने की सरकार की ओर से व्यवस्था की जायगी ।

अध्यक्ष महोदय, कुछ अस्पतालों में मैंने देखा है कि दिनों दिन उनकी उन्नति के बजाय अवनति हो रही है, जैसा कि मैंने एक मिनट पहले कहा, शिक्षा मंहगी होती जा रही है, पाठ्य-पुस्तकों की व्यवस्था दूषित है, शिक्षा का स्तर बिल्कुल घट चुका है । बीस वर्ष पहले का मेट्रिक्यूलेट वही योग्यता रखता है जो आज बी. ए. योग्यता रखता है । उसी तरह से चिकित्सा मंहगी होती जा रही है । चिकित्सा भी गरीबों से दूर और दूर हटती जा रही है, और न्याय व्यवस्था का भी यही हाल है । न्याय व्यवस्था के लिए भी एक मिनट का समय लेकर सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं लेकिन मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि स्वतंत्रता के समय गांधीजी तक ने कहा था–चिकित्सा, शिक्षा और न्याय हम हरएक घर पर पहुंचायेंगे, सस्ते रूप से पहुंचायेंगे, उचित रूप से पहुंचायेंगे—उचित रूप से पहुचायेंगे–उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से करेंगे । उसका परिणाम आज हम देखते हैं कि अस्पतालों में मरीजों की खुराक के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं है, अस्पतालों में दवाइयां नहीं हैं, अस्पताल में अगर कोई मरीज जाता है, सामान्य हैसियत का, मरीज

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

हैसियत का आदमी तो उसको कहा जाता है, पंसारी के पास जाओ, केमिस्ट के पास जाओ और वहां से मुझको दवाई की व्यवस्था की जा सकेगी। जब विलीनीकरण हुआ, उस समय भी मैंने स्वयं सरदार पटेल के समक्ष यह प्रश्न उठाया था, कम से कम भूतपूर्व राज्यों की जहां राजधानियां हैं, वहां चिकित्सा, शिक्षा और न्याय व्यवस्था जो आज है, उसमें कम से कम कभी नहीं होगी और कोवनेन्ट में यह प्रावधान है कि बहुत से दूसरे कारणों के अलावा भी जो एक कारण रखा गया था विलीनीकरण के सम्बन्ध में, वह बैटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रखा गया था।

अध्यक्ष महोदय, अगर यहां पर यह कहा जाय कि जयपुर में हाई कोर्ट तक नहीं है और उसका कारण यह कि सदन कोई भी एक राय से इस सम्बन्ध में व्यवस्था नहीं कर सका, तो मैं समझता हूं कि यह सरकार के लिए महान् अशोभनीय चीज है। मैं जोधपुर के लिए नहीं कहता कि वहां से हाई कोर्ट हटाई जाय, लेकिन यहां सर्किट कोर्ट भी नहीं है, यह कहां का न्याय है? यह अन्याय है और उसके ऊपर सरकार कहे, सदन एकमत होकर इस चीज का निर्णय नहीं कर सके तब तक सरकार निर्णय नहीं करेगी, यह मेरी समझ के बिल्कुल परे है, वास्तविकता से बिल्कुल परे है, जनहित के लिये कुठाराघात है।

इसी तरह से मैंने देखा, प्रतापगढ़ के अन्दर वहां का अस्पताल है, उसकी भी व्यवस्था चित्तौड में ले जाई जा रही है। डूंगरपुर के अन्दर भी निर्णय हो चुका है कि पी. एम. एच. ओ. का वहां पर स्थानान्तरण होगा। उस सम्बन्ध में भी कोई व्यवस्था नहीं हुई है। मैं यह समझता हूं कि कम से कम जो अस्पताल, जो चिकित्सा विभाग के सम्बन्ध में व्यवस्था थी भूतपूर्व राज्यों की राजधानियों के अन्दर वह ज्यों की त्यों रखी जाय, उसमें कमी नहीं की जाय। अगर उसमें कमी की जाती है, तो यह बैटर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, यह प्रगतिशील कदम नहीं है, यह तो एक मात्र अनप्रोग्रेसिव और रेट्रांगेट स्टेप है इस सम्बन्ध में मैं कहे बिना नहीं रह सकता कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, आसपुर से जहां से मैं आता हूं वहां आसपुर तहसील हेड-क्वार्टर है वहां न बिजली है, न सड़क है, न स्कूल है और न कोई अस्पताल ही है। दूसरे पास पडौस की तहसील सागवाडा है जहां से माननीय मंत्री आते हैं वहां पर उन्होंने सारी बातों की व्यवस्था की है, सडकों की, बिजली की, स्कूलों और अस्पतालों की, सब की व्यवस्था है। सलूंबर पडौस में है वहां पर भी सडकें, स्कूलें आदि का प्रबन्ध है। खेरवाडा और सानड में अस्पताल है और गिरवा में अस्पताल है। यह सुविधा आसपुर को छोड कर सभी पडौसी जगहों में है और आसपुर में यह व्यवस्था नहीं होना मेरे

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

ख्याल से सरकार के लिए एक मुझे ताज्जुब सी बात लगती है । इसके लिये यदि यह कहूं, अध्यक्ष महोदय, कि यह स्टेप-मदरली ट्रीटमेंट है तो यह कोई अतियुक्ति नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना तो नहीं चाहता परन्तु इस सदन में बार बार तरह तरह की बातें कही जाती हैं, मैं उस संबंध में भी दो शब्द कहूंगा। दो तीन दिन पहले यहां कुछ बातें कही गईं, यह कटुता की भावना प्रदर्शित करते हुए कि भारतवर्ष में एक XXXX सबका एक वोट है । हम इस बात का स्वागत करते हैं कि सबका एक वोट है। यह विधान बना हुआ है और उसको बनाने में हम लोगों का हाथ है । उस विधान को आपने और हमने मिल कर बनाया है । अगर हम नहीं होते और हमारा सहयोग नहीं होता तो देश में क्या होता । खैर, कुछ भी हुआ, हुआ। तो हमने सहयोग भी दिया और त्याग भी किया । तो वह हमने अपना देश के प्रति पुनीत कर्त्तव्य समझ कर किया । हम मानते हैं और स्वागत के साथ मानते हैं कि हर एक व्यक्ति को एक ही वोट का अधिकार है चाहे वह राष्ट्रपति हो चाहे अन्य व्यक्ति क्यों न हो । इसलिए मैं यह कहूंगा कि जब हमारे यहां विधान में एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है तो मेरे ख्याल से यह भी अधिकार है कि वह चुनावों मे खड़ा हो और अगर उनको हजारों और लाखों भी वोट मिल सकते हैं तो आज उन माननीय सदस्यों के संबंध में तोड मरोड कर जो नाम दिया गया है, उनका नाम श्रीमती महारानी गायत्री देवी था । अगर उन्होंने महज जवाहरलाल नेहरू से अधिक वोट लिये तो उनको वह अधिकार है । अगर इसी प्रकार कांग्रेस के काले कारनामे होंगे तो उनको वोट मिलने की संभावना कम है और वे लोग ही आवेंगे ।

एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि मुझे दरबार कहलाने का शौक है । मैं यह भी कहूंगा कि हम पहले दरबार कहलाते थे । मैं आज से ३० वर्ष पहले दरबार था मगर मैंने किसी को यह नहीं कहा कि वह व्यक्ति दरबार कहे । कोई व्यक्ति श्रद्धा की भावना से यदि मुझे दरबार कहे तो मैं उसको ना नहीं देता । मगर आज तक जितने भाषण हुए हैं उनमें मैंने आम सभाओं में अपने आपको एक तुच्छ सेवक के नाम से संबोधित किया है । इसके उपरान्त अगर कोई कुछ भी कहे और बदले की भावना ही उनके यह कहने का आधार है. . . .

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : किसी को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप मुझे माफ कीजिये । माननीय सदस्य नसीराबाद से आते हैं। मैं आपको करबद्ध निवेदन करूंगा कि अगर ये ६३-६४ के बजट के बारे में जिक्र करते समय ऐसी बातें कहते हैं जो १५-१५ और २०-२० वर्ष पुरानी हैं, अगर आप वह भी समझते हैं कि· · · · ·

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : अप-शब्दों का प्रयोग किसी के लिये भी नहीं किया जा सकता है। उन्होंने यह कहा है।

XXXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं माननीय सदस्य से माफी चाहता हूं। अब मैं बुड्ढा हो गया हूं और कानों से भी कम सुनाई देता है। मैं उनसे क्षमा-याचना करता हूं।

श्री रामकिशन (वैर) : वे कभी कभी जो ठीक कहते हैं और वह भी आपने सुना नहीं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं विरोध में मान्यता रखने वाला हूं। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं, मैंने १५ वर्षों से सैद्धान्तिक विरोध किया है। मैंने नियमित रूप से विरोध किया है। चाहे विरोध में मंहगा सौदा लेना पडा तो भी मैंने विरोध किया, वहां पर वर्माजी, हमारे मुख्य मंत्री श्री सुखाडियाजी, श्री जोशीजी जो राजस्थान प्रादेशिक कांग्रेस के अध्यक्ष है, पांड्याजी जो भूतपूर्व मंत्री रह चुके हैं—उनसे, अगर उनका बोल-बाला हो तो आज उदयपुर में कोई विरोध जैसी बात नहीं। आखिर विरोध के सिद्धान्तों को मान कर मैंने जनतंत्र के सिद्धान्तों की प्रणाली को कायम रखने के लिये विरोध किया।

शायद डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य के सौभाग्य के कारण और मेरे जैसे के अभाग्य और दुर्भाग्य के कारण स्वर्गीय महाराज हनुवन्तसिंहजी नहीं है, अगर होते तो आज हम उनको विरोध का महत्व, डीडवाने से आने वाले माननीय सदस्य को, बताते। यह भी कहा जाता है कि हम सांप हैं। अगर आप यह समझते हैं कि मैं सांप हूं, अगर आप मुझे सर्वथा अनुच्य व्यक्ति समझते हैं तो मुझे जहाज में बन्द करके इन्डियन ओसन में फेंक दिया जावे।

अध्यक्ष महोदय, आश्चर्य की बात है कि राजाजी जैसे तपे हुए नेता के लिये, जो भारतीय संस्कृति और सिद्धान्तों की कसोटी है, यह कहा जाए कि राजाजी भी भूतपूर्व राजाओं के टुकडों से मोल ले लिये गये तो मेरे खयाल से ऐसे व्यक्ति के लिये जो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं उनकी अक्ल का दिवाला निकल गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन हाउस का स्वास्थ्य ठीक कर रहे हैं ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : संबन्धित रूप से और असंबन्धित बातों को संबन्धित रूप से मैं उचित समझता हूं, कहता हूं। अगर वास्तविक रूप से कोई अप्रासंगिक बात हुई हो तो मैं मानता हूं और अगर पहले हुई हो तो मेरी यह बात उदाहरणार्थ, उदाहरण के रूप में मानेंगे। ऐसी मुझे आशा है।

तो मेरा यही निवेदन करना था कि गरीबों के लिये चिकित्सा और मरीजों के लिये खुराक की व्यवस्था होनी चाहिये। आज अधिकांश चिकित्सालयों में देखा जावे तो वेन्डेज, कोटन आदि की भी व्यवस्था नहीं है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि इस ओर विचार करें और एक लकीर के फकीर होकर कि सारे भारत वर्ष में एक ही युनिफॉर्मिटी हो तो उसकी युनिफॉर्मिटी को मान लीजिये। मेरे ख्याल से यह एक विशाल देश है और हम डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं। अगर हम भूतपूर्व राजाओं के शासन के समय की अच्छी बातों को लेकर चलें तो मेरे ख्याल से कोई बुरी बात नहीं होगी और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे। यह हम मानते हैं कि डाक्टरी शिक्षा मंहगी है और लंबे अर्से तक रहती है। आज राजस्थान में मैंने सुना है कि बहुत से डाक्टर हैं उनको पहले गैर मुस्तकिल तौर पर रखा जाता है और फिर प्रोवेशन पर मुस्तकिल किया जावे। यह मेरे

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

ख्याल से सर्वथा अनुचित है और अनावश्यक है। इससे यह होगा कि उनको जो उत्साह उत्पन्न होता है वह भी नहीं रहेगा और सरकार का जो सिद्धान्त है और उद्देश्य है वह भी पूरा हो जायगा, अगर उनको जहां पर डाक्टर नहीं है वहां पर भेज दिये जावें। ताकि डाक्टरों की कमी की जो शिकायत हैं वह दूर हो जाय।

अध्यक्ष महोदय, हमारे जिले में इन्स-पेक्टर ऑफ आयुर्वेद औषधालय की पोस्ट है। वह लगातार १५ वर्ष से वहीं हैं, चन्द महीनों के लिये शायद उनका स्थानान्तरण हुआ। सागवाड़ा से मंत्री महोदय आये हैं वे मेरे सामने बैठे हैं उन्हीं के वहां डाक्टर साहब ९ वर्ष से हैं। चाहे पंचायत समिति के चुनाव हों, चाहे म्युनिसिपल कमेटी के चुनाव हों, चाहे आम चुनाव हों निरन्तर कांग्रेस की कोशिश और प्रचार करने के सिवाय कुछ काम नहीं करते, कुछ करते होंगे तो थोड़ा करते होंगे। अधिकांश प्रवृत्तियां उनकी यही है कि मंत्री महोदय जो सागवाड़ा से आये हैं, उनके गुणगान करें उनकी तारीफ करें, प्रचार करें।

मेरे ख्याल से वर्षों तक स्थानान्तरण ही नहीं होता तो जागीरदारियां तो खत्म हो गईं, पर उनकी जगह परमानेन्ट वेस्टेड इन्ट्रेस्ट फिर भी स्थापित कर दिये। अगर ऐसे मामले भूतपूर्व शासन में भूतपूर्व नरेशों के पास आते तो एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करूंगा कि वे ऐसा कायदा बनायें कि दो साल, तीन साल हद से हद ५ साल से अधिक कोई व्यक्ति एक स्थान पर नहीं रहे तभी तो जनतन्त्र की विशुद्ध प्रणाली को स्थापित कर सकेंगे। नहीं तो यह सोशियलिस्टिक पैटर्न नहीं, प्रतिक्रियावाद है, भ्रष्टाचार है। औषधि जैसे पवित्र काम में ब्लैक मार्केट, इन्जेक्शन्स में ब्लैक मार्केट, मेडिशन्स में ब्लैक मार्केट, तो यह सोयशिलिस्टि पैटर्न नहीं यह ब्लैक मार्केटिंग पैटर्न हम रोज रोज देख रहे हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ जो कुछ मैंने उचित समझा निवेदन किया है, मंत्री महोदय उन्हें, जो उचित जंचे उस पर विचार कर सकें, करें।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला।

(१.०० म. प.)

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, इस विषय में मेरे ७ कटौती प्रस्ताव हैं उनमें से एक कटौती प्रस्ताव ग्रामीण क्षेत्रों में जो चिकित्सा का अभाव है उसके बारे में है। माननीय अध्यक्ष, जो मेमोरेन्डम में इस वर्ष आयोजन–व्यय रखा है उसमें ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित व्यय को देखें तो मालूम होगा कि सारी ग्रामीण जन-संख्या के हिसाब से पर–केपिटा ५ नये पैसे खर्चा है। तो इस तरह ग्रामीण क्षेत्र के लिये यह जो रखा गया है मैं इसको उपयुक्त नहीं समझता। इसी आयोजन व्यय में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऐसे हैं जहां ४३५ हजार रुपया खर्च होता है ऐसे हैं जहां से ग्रामीण जनता को दवाइयां मिल सकती हैं, इसके बाद आयुर्वेदिक औषधालय ग्रामीण क्षेत्रों में खुले हैं, उनमें ग्रामीण औषधियां प्राप्त कर सकते

(श्री विजयसिंह झाला)
हैं, तो मैं समझता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में दवाइयों का इतना कम प्रावधान रखा है, कोई भी इसे उपयुक्त नहीं कह सकता।

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत, सभानेत्री, पदासीन)

चल चिकित्सालयों की भी ग्रामीण क्षेत्रों में ठीक तरह से योजना नहीं है। कभी कभी डाक्टर ग्रामीण क्षेत्र में चक्कर लगाने आता है और दरवाजे पर आवाज देकर जैसे भिक्षा की फेरी देने आया हो फौरन चल देता है, कोई आदमी घर से बाहर निकलता है तब तक तो वह १० घर आगे जाता हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रकार की योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों को कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिये चल-औषधालयों की ऐसी योजना बनाई जाय कि गांव २ में घूमें सात दिन में कम से कम एक बार तो ये अवश्य एक गांव में जायें।

इसी तरह चेचक के टीकों के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि अभी चेचक का ग्रामीण क्षेत्रों में बडा प्रकोप है और चेचक के टीके लगाने पर भी ५० प्रतिशत बालकों के बीमारी हुई है। तो मैं निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार के टीके लगाये जाते हैं, इसकी जांच होनी चाहिये और इसका सही प्रबन्ध होना चाहिये।

सभानेत्री महोदया, एक बडी रकम जला योजना के लिये रखी गई है। जलयोजना के लिये इतनी बडी रकम रखी है वह ग्रामीण क्षेत्रों में निरर्थक साबित हुई है। माननीय सदस्य, जो राजनगर से आये हैं, क्षेत्र के एक गांव में, केलवा गांव में नल-योजना लगी हुई है, वहां लोग नल को काम में नहीं लेते हैं, इसका कारण यह है कि पंचायत को मेन्टीनेन्स का खर्चा देना पडता है और वह पंचायतें दे नहीं सकतीं, जिससे लाखों रुपयों की सम्पत्ति इस योजना के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में लगी हुई है वह कुछ भी काम में नहीं आती है। यही कारण है कि ६२-६३ में जो रकम रखी थी वह खर्च नहीं हुई और परिवार नियोजन क्षेत्र में लगाई गई।

तो इस योजना की तरफ ध्यान दें और इस पैसे को चल चिकित्सालय और औषधियों के लिये रखें तो अच्छा रहेगा।

मलेरिया के उन्मूलन का प्रावधान रखा गया है, मच्छरों को मारने के लिये दवाइयां छिडकते हैं, यह भी सब निरर्थक साबित हो रहा है। यातो पहले आती थीं वैसी दवाइयां नहीं आती हैं, या बीच में लोग रख लेते हैं, जिस वजह से मच्छर मारने में ये दवाइयां पहले जैसा काम नहीं करती हैं।

सभानेत्री महोदया, गवर्नमेंट डाक्टर्स की प्राइवेट प्रेक्टिस है इस सम्बन्ध में मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर में ऐसे गवर्नमेंट डाक्टर्स हैं जिनकी ५०० रुपया दैनिक आय हैं, इसी कारण वे सरकारी सफाखानों में रोगियों की अच्छी तरह देखभाल नहीं कर सकते और सबको अपने घर की तरफ आकर्षित करते हैं। तो इन पर रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहिये कि अपने बंगलों पर गवर्नमेंट डाक्टर रोगियों को नहीं देखें। यह बहुत बुरी प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति के कारण जिस तरह से इन्ट्रेस्ट इन्हें अस्पतालों में लेना चाहिये उस तरह का इन्ट्रेस्ट नहीं लेते हैं और धनवान रोगियों को घर पर आने के लिये मजबूर करते हैं। दवाइयों की दूकानों से कमीशन

(श्री विजयसिंह झाला)

लेते हैं। कोई दवाई खरीदता है तो कमीशन उसमें जोड दिया जाता है।

समानेत्री महोदया, प्रसूति गृह के लिये इस वर्ष आयोजन ११० हजार का रखा गया है। मेरे ख्याल से इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है, इसमें रुपया और बढाना चाहिये। नाथद्वारा के प्रसूति-गृह की ओर नजर दें तो वहां २ बेड्स हैं। १० केसेज प्रसूति के आ जाते हैं तो उनको बरामदे में सोना पडता है। प्रसूति-गृहों का समुचित प्रबन्ध न होने के कारण प्रसूतियों की मृत्यु संख्या बढ रही है। तो मैं यह निवेदन करूगा कि इस मद में ज्यादा पैसा दें और बैड बढायें।

उसके बाद में मैं आयुर्वेदिक औषधालयों के बारे में आता हूं। जहां जहां पर आयुर्वेदिक औषधालय खोले गये हैं मैं महसूस करता हूं कि रकम बहुत कम है। नाथद्वारा का ही उदाहरण दूं। रोगियों की जितनी संख्या है, आपने इस साल जितनी दवाइयां दी है, वैसे बजट में तो ९००) रु० ही हैं किन्तु आपने और भी सहायता दी है उनको जोड कर भी, रोगियों की संख्या में उस रकम का भाग दिया जाय तो तीन पैसे एक रोगी पर खर्च होंगे। तीन पैसे में वह रोगी कैसे अच्छा हो सकता है और किस प्रकार से उसको वैद्य दवाई देगा, यह आप भी जरा अनुमान तो लगाइये? आयुर्वेदिक औषधालयों में ज्यादा से ज्यादा पैसा लें। मैं महसूस करता हूं कि आयुर्वेदिक मंत्री जी को या तो कहने का इतना साहस नहीं है या चिकित्सा मंत्री आयुर्वेदिक मंत्री पर सवार हो गये हैं और उनको साहस नहीं हो रहा है इसलिए अयुर्वेद मंत्री का बजट घाटे में रहता है। आयुर्वेदिक मंत्री को मैं विश्वास दिलाता हूं कि सदन आपके साथ है, आपको दबना नहीं चाहिये, यदि आप दबते गये तो आपका बजट जीरो हो जायगा और आपका महत्व कम हो जायगा।

आयुर्वेद औषधालयों की ओर से पंचायतों में बोक्स दिये गये हैं। किसी भी पंचायत में जाकर देख लीजिये कि उन बॉक्सों में कितनी दवाइयां हैं। खाली आवाज के रूप में बॉक्स आपके गीत गाते हैं।

(समय—समाप्ति—सूचक घंटी)

उसके बाद में यह कहूंगा कि उदयपुर में मेडिकल कॉलेज खोलने के बाद अव्यवस्था हो गई है। डी.एम.एच. ओ. और पी.एम.एच. ओ. दो अलग अलग पोस्टें वहां कायम की हैं जब कि एक ही व्यक्ति पहले दो का काम करता था। अब पी.एम.एच.ओ. प्राइमरी हेल्थ सेन्टर का काम देखते हैं जिनका गांवों से सम्बन्ध होता है और डी.एम.एच.ओ. का आपसे सीधा सम्बन्ध रहता है। हॉस्पिटल से पी.एम.ओ.एच. का कनेक्शन अब टूटसा गया है। इसलिए उनका उदयपुर अस्पताल से सम्बन्ध हो जिससे जब प्राइमरी हेल्थ सेन्टर की कोई बात हो तो वे आसानी से कर सकें।

(समय—समाप्ति—सूचक घंटी)

एक बात और है। डोग बाइटिंग के लिए कहना चाहता हूं। गांवों में ये डोग बाइटिंग के केसेज बहुत होते हैं। हरएक गांव में हर साल एक आदमी की मृत्यु होती है। प्राइमरी हेल्थ सेन्टर में डोग बाइटिंग का इन्जेक्शन जरूर होना चाहिये। इन सुझावों के साथ समाप्त करता हूं।

श्रीमती सभापति: श्री ज्वाला प्रसाद।

श्री ज्वाला प्रशाद शर्मा (नसीराबाद) : सभापति महोदया, मेरे इन मांगों के ऊपर कुछ कटौती के प्रस्ताव हैं। मेरे चार कटौती प्रस्ताव हैं उनके विषय में पहले कह कर फिर आपके सामने और कुछ निवेदन करूंगा। पहली बात तो मैं सरकार के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि नसीराबाद में २७ हजार की बस्ती है उसमें अब तक कोई ऐसी डिस्पेन्सरी नहीं थी, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने उसकी शुरूआत की। लेकिन आपको ध्यान में रखना चाहिये कि इतनी जन-संख्या के लिए कोई ऐसी बात नहीं हो सकती है कि २७ हजार लोगों की जन-संख्या जहां हो वहां सरकार की डिस्पेन्सरी न हो उसके लिए कुछ सरकार को करना चाहिये।

अब मुझे यह कहना है कि हर बजट के अन्दर उस बजट को हम रूप देते हैं इस बात का कि हमारी डवलपमेन्ट की जो योजनाएं हैं उनको बढ़ाने की सोच रहे हैं और सब जगह यह प्रचार होता है लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं इस बारे में, इस बजट में आपने जो रुपया रख दिया है, रुपया आना पाई की सरकार में ज्यादा कीमत है बनिस्बत आदमी के। आदमी के लिए सब कुछ होता है। दो करोड राजस्थान के आदमियों के प्रति आप, आपका यह डिपार्टमेन्ट जन–स्वास्थ्य का क्या करते है? आपके कार्य-कलाय से यह पता लगता है कि कोई सरकार राजस्थान के आदमियों की कितनी कद्र करती है। इसलिए जोर देना चाहता हूं कि ये डवलपमेन्ट, ये पंचवर्षीय योजनाएं, मैंने एक दफा कहा था, बंदर की तलवार की तरह नहीं काट सकते मको।

कोर प्लान बनता है, मुंह से कह दिया कि पांच सौ डाक्टरों की कमी है। यह मांग आगे बढती जाती है। पांच सौ डिस्पेन्सरियां हैं, डाक्टरों की सब में कमी है। आपका काम पूरा होना मुश्किल है। आदमी की यहां सरकार कितनी कद्र करती है उससे पता चलता है। पहला हथौडा प्लान्स पर पडा। एक मेडिकल कॉलेज बनाने वाले थे उसको काट दिया। आपकी रिपोर्ट और आपकी व्यक्तिगत सोचने के बजाय सारे राजस्थान और सारे लोगों के लिए सोचने की प्रक्रिया होनी चाहिये। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज डवलपमेन्ट आदि के बढा चढा कर दर्शन कराये जाते हैं। जो स्वीकृतियां हम देते हैं उस वक्त हम यह सोचते हैं हमने बडा काम किया, बडी सेवा की, सोशियलिज्म बढ कर आ गया वित्त मंत्रीजी के मुंह से। स्वास्थ्य डिपार्टमेन्ट सेवा का डिपार्टमेन्ट है। उसकी सेवा की क्या हालत कर रखी है। वे नदियां, पहाड और बिजली किसके काम आवेंगे? मैं समझता हूं कि डिपार्टमेन्ट यह है। मैं जोर देना चाहता हूं कि जो उपेक्षा–वृत्ति काम में लायी जा रही है, मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि इस विभाग की ओर से सबसे बडी इम्पोर्टेन्स देनी चाहिये। सम्माननीय सदस्यों से अपील करूंगा। दूसरी जगहों के बजट उठा कर देख लीजिये। यू.पी का ले लें। पांच मेडिकल कॉलेज नये खोलने की व्यवस्था की है। वे आदमी की कीमत जानते हैं और उस पर जोर देते हैं। हमारे जो सिटीजन हैं, किसी ने कुछ कहा हो, मैं कहता हूं, हमारी गरीबी समझ में आ सकती है। लेकिन वह समझ में नहीं आती कि हमारी कोशिश के बिना आज बच्चों की आखें हमेशा के लिए मुंद रही हैं, मां की गोद में सुबक सुबक कर जो मर रहे

(श्री ज्वाला प्रशाद शर्मा)

हैं, आज राजस्थान में उसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब आप प्रश्नों का जवाब देते हैं तो कहते हैं कि ५०० डाक्टरों की कमी हैं। जिस सरकार में कोई बात न हो, कोई डॉक्टर और डॉक्टरनी की व्यवस्था न हो—१५ वर्ष में भी वही हालत हो, कोर का नाम लेते हैं यह हमारे ऊपर पहला कुठाराघात है शराबी आदमी, अपनी आदत से जब उसकी फिजूल खर्ची की आदत पड जाती है और जब उसके पास आमदनी न हो तो पहला हाथ वह अपने बच्चों के दूध पर डालता है। इस तरह से सरकार को नहीं करने देना चाहते। दूसरी जगहों के बजट उठा कर देखें वहां पांच-पांच मेडिकल कॉलेजज खुल सकते हैं। स्टूडेन्टस को बढाओ, यह इमर्जेन्सी के लिए जरूरी है। इमर्जेन्सी के नाम पर आप हम से कराये जाओ। नर्सेज वगैरह की जरूरत हो, केन्द्रीय सरकार आपको लिख कर भेज देती है, आप बढाओ, इस सेवा के लिए वहां पर जरूरत हैं और आप काटते हैं। मेडिकल कॉलेज नहीं बनेगा। यह आपकी बन्दर की तलवार है, उसका विरोध करते हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि ५०० डिस्पेन्सरियों में कब तक डाक्टर भेजे जावेंगे? जवान और निरीह लोगहैं उनकी तरफ से पूछते हैं पांच साला हमारे प्लान हैं, हम वहां पर बैठने वाले एक लाख की रिप्रजेन्ट करते हैं, हम समाज के दो करोड आदमी हैं, वे बिना मेडिकल हेल्प और दवा के नहीं मरें, केवल हम शान्ति चाहते हैं। हमारी आत्मा को शान्ति नहीं है। हमें शान्ति की पहले जरूरत है। आज मैं देखता हूं कि इसके लिये वित्त मंत्रालय का कोआर्डिनेशन नहीं है। वे चाहे भीतरी बात कहना न चाहें लेकिन यह सब को साफ तौर से दिखाई देता है, भीतरी बात छिपी नहीं रहती है। आप पावर से महरूम रख सकते हैं लेकिन जहां स्वास्थ्य का प्रश्न आता है आपने जिस तरह का प्रोपोज किया उस तरह का आपने आगे मूव नहीं किया। यह ऐसा सवाल है इसमें पॉलिटिकल बातों को एक तरफ रख दीजिये—यह तो इन्सान की जिन्दगी का सवाल है, हमें इन्सान की ज्यादा कीमत करनी है।

मेरा एक और कट मोशन है। इस पर अधिक न कहता हुआ यह निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपके पास पैसे की कमी है यह सदन आपको तिगुना, चार गुना पैसा देने के लिये तैयार है लेकिन आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के क्या इरादे हैं उसका तो जवाब दें। ८० लाख के बजाय आप आठ करोड लीजिये आपके पास स्टाफ नहीं। आप किस प्रकार यह कार्य सेवा का हाथ में ले सकते हैं इमरजेन्सी के नाम पर भारत सरकार की मांग है कि डाक्टरों की भरती ज्यादा की जाय, मेडिकल कॉलेजों में ज्यादा एडमिशन दिया जाय। कालेज खोलने के लिये आप रुपया नहीं निकाल सकते। एन्टरटेनमेन्ट के नाम पर बडी रकमें खर्च कर सकते हैं और और चीजों के लिये कर सकते हैं आपकी सुरक्षा के लिये नहीं हो सकता। वित्त मंत्री को मैं इस के लिये जिम्मेदार मानता हूं। आपको, ओथोरिटी दी हुई है। आपको उसके लिये अडना चाहिये उसमें हर सदस्य इस ओर और उस ओर के आपके साथ में है।

मैं इसके साथ साथ यह भी कहना चाहता हूं, इस पर अधिक जोर न देते हुए एक

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

चित्र खींचना चाहता हूं जिस चित्र का नजारा आपको भी नजर आता होगा। गांवों के अन्दर जहां से हम बीघोडी लेते हैं, जिस जमीन पर टैक्स की बात करते हैं, उस टैक्स देने वाले के लिये हम कितना खर्च करते हैं ? उससे टैक्स लिया जाता है उसका फायदा दूसरे वर्ग को मिलता है। टैक्स किसी से लिया जाता है और आनन्द इस हुकूमत का और कोई उठाते हैं। जिनको पूरा कर देना पड़ता है उन लोगों के स्वास्थ्य के लिये हम क्या मदद करते हैं, कभी इस ओर भी ध्यान दिया है। आप उनको तसल्ली दें लेकिन उनको तसल्ली देने वाली कोई बात नहीं है। यह भी सही है, पता नहीं चलता कि ५०० डाक्टर्स की जो कमी है और इमर्जेन्सी के नाम पर सारे मुल्क में डाक्टरों की मांग है। जिस इमर्जेन्सी के लिये इस राजस्थान ने हर तरह की कुर्बानी दी, जो जोश राजस्थान की जनता ने और यहां की तमाम पार्टीज ने इस इमर्जेंसी के समय बताया है उसी जोश के साथ। हम मांग करते हैं कि जितने भी लोगों को तकलीफ है उनकी तकलीफों को दूर किया जाय, उनके दुखों को दूर किया जाय। सब से बड़ी जरूरत है हमारे यहां जो ५०० डाक्टरों की कमी है उसकी पूर्ति करने को दो मेडिकल कॉलेज और खोले जाने चाहिये, तीन के बगैर यह कमी पूर्ति नहीं हो सकती। इसी प्लान में तीसरी प्लान में जो मेडिकल कॉलेज की योजना थी वह सब काट दी गई। राजस्थान नहर भले ही रुक जाय, पोंग डेम कुछ अर्से के लिये न बने लेकिन जो इन्सान को तकलीफ है, जहां हम राज्य कोवेलफेअर राज्य कहते हैं वहां हम मेडिकल कॉलेजों के काटने की बातें करते हैं मैं राज्य की दो में करोड जनता के नाम से अपील करता हूं आप इस बारे में आवाज उठाइये, आप उसके लिये चाहे जितना पैसा मांगिये जनता उसकी पूर्ति करेगी।

आज इस मेडिकल विभाग के द्वारा मिल रही फेसीलिटीज का फायदा कौन उठा रहा है, जिसकी तरफ अजगर की तरह मुंह करती है सरकार। आज आप देख लीजिये, हर विभाग के मैडिकल रिएम्बर्समेन्ट के बिलों को देखिये। मैंने इन बजट की किताबों में यह जानने की कोशिश की कि कितना रुपया क्लास फोर्थ को मिला है और कितना अन्य अधिकारियों को मिला। मैं ये फीगर्स नहीं निकाल सका। मैं इसमें फेल हो गया। इतनी सारी बुक्स हैं लेकिन सब इसके लिये बेकार की हैं। सरकार का तंत्र ही ऐसा है जो इसको इस प्रकार रखता है कि किसी भी सदस्य को पता न चल सके। एक एक बिल को देखे, तनख्वाह के बराबर बिल बनाये गये हैं। फी मेडिकल चिकित्सा के नाम पर ८००) रु०, ९००) रु० तक के बिल बनाये गये हैं। बीमार नहीं पड़े, बीमारी के नाम पर दवाइयां नहीं लीं; झूठे बिल बनाकर रुपये उठाये जाते हैं। आज इस शर्मनाक स्थिति को बर्दाश्त किया जाता है। आज दीए तले अन्धेरा हो रहा है। दूसरे लोग इसका फायदा उठा नहीं सकते। जब जब वे लोग अस्पताल में घुसते हैं उनको दवाइयों के लिये इन्कार किया जाता है। वे जाकर आज वहां इलाज नहीं करा सकते और जो लोग झूठे बिल बनाकर सरकार से पैसा लेते रहते हैं बीमार बने रहते हैं लेकिन कार्यालय से से अवकाश नहीं पर मेडिकल बिल अवश्य बनते रहे हैं। आप ढक्कन लगाये बैठे हैं और इस प्रकार की हरकतों को

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

बर्दाश्त करते हैं। आज कोई भी हिम्मत करके कहे कि मेरे अधिकारी ऐसे हैं जो इस प्रकार के बिल नहीं बनाते। कोई कहे तो सही। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं। कागजी गवर्नमेन्ट है, कागज पर केवल दस्तखत होते हैं। झूठे बिल बनाकर लाखों रुपये उठाने का एक प्रकार से तरीका बना रखा है। इस तरीके को बिल्कुल बन्द करिये, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इससे जो बचत हो वह मेडिकल कॉलेज खोलने में लगाइये।

एक मेरा कट मोशन है जो बीमारियों के बारे में है। बीमारी से कोई मरे तो चिन्ता नहीं लेकिन जितनी बीमारी फैलती है उसके अन्दर सवाल उठता है। मैं यह भी महसूस करता हूं कि वित्त मंत्री द्वारा जो रकम दी गई है वह बहुत कम है। मेरा आपसे यह कहना है कि आप साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि हमारे पास न तो पैसा है और न डाक्टर ही। क्यों सच बात बताने से डरते हैं। किसी को माता निकलती है, कहीं पर माता का प्रकोप है यदि आपको पैसा नहीं मिलता तो हम क्या करें। इन्तजाम नहीं हो पाता, यह कहने में आपको क्या दिक्कत है। जब इस प्रकार के रोग से मासूम बच्चे मरते हैं हमारे देखते देखते तो हमारे सिर नीचे हो जाते हैं। इसके लिये गवर्नमेन्ट को दिक्कत हो सकती है सब को सहूलियत पहुंचाने में लेकिन इसके साथ साथ मैं यह भी मानता हूं जहां आप लाखों रुपयों का ऋण कर लेते हैं, उधार हो जाता है; क्या इन निरीह बच्चों को, जो बाल बच्चेदार है, अपने बच्चों का जीवन आपकी इस बचत के लिये दे सकता है?

यह सरकार जो दावा करती है कि देहाती जनता की वह हित-चिन्तक है, उसका भला चाहती है, उसकी मदद करना चाहती है, पर एडमिनिस्ट्रेशन उसका इस प्रकार का है कि अस्पतालों में आज गरीबों के लिये न कोई दवा है, न इन्जेक्शन। पर सरकारी अधिकारियों और ऊंचे अमीरों के लिये वहां इन्जेक्शन भी होंगे और दवाइयां भी सब आ जावेंगी। ऐसी सरकार के शासन में क्या एक गरीब इस इत्मिनान के साथ अपनी झोंपडी में, अपने घर में रह सकता है कि यह हमारी सरकार पुलिस में भले ही हमसे घूस खाती हो, इसके न्यायालय में भले ही रिश्वत के बिना काम न चलता हो, इसके दुनिया भर के विभाग कितने भी भ्रष्टाचार और घूसखोरी के घर हों, पर इस सब के बावजूद एक दिन अगर ऐसा आया कि जब मैं बीमार हो जाऊं, या ऐसी कोई कैलेमिटी आवे तो उस वक्त यह सरकार मुझे सहलावेगी, हमारी तरफ देखेगी, हमारी चिकित्सा की व्यवस्था तो कम से कम कर देगी, दवाइयां उसकी तरफ से मिल जावेंगी, इन्जेक्शन मिल जावेंगे और बीमारी की पूरी देख-भाल हो जावेगी। इसलिये मैं कहता हूं वित्त मंत्रीजी से आप मांग करें ८० लाख नहीं ८ करोड की मांग आप करें, यह सदन उसे पास करेगा।

इन शब्दों के साथ मैं फिर अपील करता हूं कि आप इस विभाग को जनता की सही मायने में सेवा करने वाला बनावें।

श्री केसरीसिंह (पाली): मेरा एक कट मोशन है मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३० के बाबत, जनस्वास्थ्य में तहसील पाली के कुछ गांवों में पीने के पानी का यथोचित

(श्री केशरीसिंह)
प्रबन्ध करने की आवश्यकता पर बहस करने हेतु ।

गवर्नमेन्ट का यह आश्वासन है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक चार सौ की आबादी का जो भी गांव होगा वहां पर पीने का अच्छा पानी उपलब्ध करा दिया जावेगा । इस साल जो अनुदान रखा गया है इस काम के लिये उस में हर साल के बजाय कम रकम है ।

अब प्रायोरिटी का जहां सवाल है वहां यह बताया गया है कि जिन गांवों में मीठे पानी का प्रबन्ध है ही नहीं, जहां कुछ दूरी से लाना पडता है, वहां पर कोई ऐसी जगह से, जहां पर कि पानी अच्छा उपलब्ध हो, उन गांवों में पानी पहुंचाने के लिये प्रयत्न करने को प्रायोरिटी दी जावे ।

मेरा निवेदन है कि तहसील पाली में कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर पीने के पानी की बडी कमी रहती है । खास कर के गर्मियों के मौसम में और जब अकाल पड जाता है तब तो यह कमी और भी ज्यादा महसूस होती है । खुशकिस्मती से इस तहसील में से जवाई और हेमाबास की नहर जोधपुर की तरफ जाती हुई बहती है जिससे जवाई बान्ध से और हेमावास बान्ध से जोधपुर को पीने का पानी सप्लाई किया जाता है । तो पिछले सालों में जब जब पानी की कमी विशेष रूप से महसूस की जाती थी तो इस नहर के जरिये इन गांवों में पानी दिया गया । कठिनाई तो बडी पडी थी, पर आठ आठ और दस दस मील तक नहरें लोगों ने अपने आप ही यानि श्रम-दान से खोदी और वहां के अधिकारियों ने कृपा करके पानी की व्यवस्था कर दी जिससे कई बार उनको लाभ हुआ राहत मिली, खास कर के ६०-६१ में जब कि अकाल पडा था । और इस साल भी पानी की कमी महसूस हो रही है । तो मेरा निवेदन यह है कि यह जो कठिनाई आये साल होती है इसको एक परमानेन्ट बेसिस पर हल कर दिया जावे—ऐसी कोई योजना बनाई जानी चाहिये । यह कोई मुश्किल नहीं है ।

इसके लिये सिर्फ दो बातों की आवश्यकता है ? एक तो यह कि कुछ स्पेशल फण्ड प्रोवाइड किया जावे । यों तो कुछ पंचायत समितियों को मिलता ही है, पर यह काम विशेष है । ऐसे गांव हैं जो आठ-दस मील दूर हैं नहर से, कोई पांच मील दूर हैं तो वहां पानी पहुंचाया जाना है । चैनल्स खोदी गई हैं उनको ठीक करा दिया जावे । जहां पर से पानी लिया जाता है वहां पर आउट लैट प्रोवाइड कर दिये जावें और दूसरी बात जो जरूरी है वह यह है कि जवाई और हेमाबास बान्ध में इस कार्य के लिये कुछ और पानी रिजर्व रख लिया जाना चाहिये । उस वक्त यह भी ख्याल रखना चाहिये कि उससे जो इरिगेशन करते हैं, उसे विशेष नुकसान नहीं हो यानि ऐसा न हो कि पानी रिजर्व कर लें और इरिगेशन के लिये पानी मिले ही नहीं । इसके लिये जरूरी हो यदि, तो जवाई बान्ध और हेमाबास बान्ध के कैचमेन्ट एरियाज को कुछ आगमेन्ट किया जावे । मुश्किल नहीं है यह । जवाई बान्ध के पास, सेवाडी के पास से मीठडी नदी जाती है । उसको उस बान्ध में डाइवर्ट किया जा सकता है । मैंने सुना है कि इसके लिये अलग बान्ध बनाया जावेगा सिंचाई के लिये । उस विषय में तो इस समय नहीं जाना चाहूंगा, जब इरिगेशन की डिमान्ड आवेगी तब कहूंगा ।

(श्री केशरीसिंह)

पर ज्यादा उपयुक्त यह होगा कि उस पर कोई बान्ध नहीं बान्धा जावे क्योंकि इससे नीचे के खेतों को नुकसान होगा। सिर्फ आधी नदी को फांट कर पानी उसका जवाई बान्ध में डाल दिया जावे। जिसमें दो चार लाख से ज्यादा रुपया नहीं लगेगा। तो यह समस्या हमेशा के लिये हल हो सकती है।

जब जोधपुर की नहर के लिये चालीस-पचास लाख खर्च किया गया है तो इसके लिये अगर दो-चार लाख और खर्च हो जावे और हमेशा के लिये इस एरिया के पीने के पानी का पुख्ता बन्दोबस्त हो जावे तो यह बहुत अच्छा होगा। इससे इस एरिया की पानी की जरूरत पूरी हो जावेगी, इरिगेशन के लिये भी पानी की जरूरत है, उसमें भी किसी तरह से कमी नहीं पडेगी। यह तो अर्ज की मैंने उस एरिया के लिये पीने के पानी के परमानेन्ट वन्दोबस्त के लिए।

इस साल जो है, टेम्प्रेरी इमीजिएट अरेन्जमेन्ट की जरूरत है। इसके बारे में भी अर्ज कर दूं। अब के भी वहां पर स्केयर-सिटी घोषित की गई है और कई गांवों में पानी बहुत कम है। गर्मी में अत्यधिक कठिनाइयां हो जावेंगी जैसी पार के साल हुई थी। अब के जो पानी मांगा गया है जवाई बान्ध से तो वहां के अधिकारियों ने बताया है कि पानी उतना ही है जितना जोधपुर की जरूरत के लिये जस्ट सफीसियेंट है। इसके लिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अधिकारियों का यह रवैया रहा है, मैं कोई यह कह कर उनको क्रिटिसाइज नहीं करता, कि जितना वे दे सकते हैं, उससे कुछ कम बताते हैं, और यह वाजिब भी है। इसी प्रकार पानी रिजर्व किया जाता है तो भी अपनी जरूरत से ज्यादा रिजर्व कराया जाता है। तो जस्ट सफीसियेंट है जोधपुर की रिक्वायरमेन्ट को मीट करने के लिये तो अर्ज करूंगा कि वह कुछ ज्यादा ही है। इस प्रकार जोधपुर के लिये रिजर्व किया है जिसे जस्ट सफीसियेन्ट कहा जाता है तो इसका मतलब हुआ इट इज स्लाइटली मोर देन सफीसियेन्ट।

निवेदन करने का मतलब यह है कि निश्चित रूप से पीने के लिये पानी इस साल अब भी दिया जा सकता है। जोधपुर के लिये रेन्स तक के लिये सफीसियेन्ट है। इसी तरह का प्रावि.जन है, तो मुझे पूरा यकीन है कि उसमें से कुछ पानी निश्चित रूप से गांवों को दिया जा सकता है और विशेष कठिनाई जोधपुर में उपस्थित नहीं होगी। तो यह जो अब के टैम्प्रेरी अरेन्जमेन्ट है वह इमीजिएट हो इसके बारे में निवेदन है।

और आइन्दा के लिये, इसका परमानेन्ट बन्दोबस्त करने के लिये भी सुझाव रक्खे हैं। मुझे उम्मीद है कि जब सम्बन्धित मंत्री महोदय अपना उत्तर देंगे तो इन बातों की ओर अवश्य ध्यान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में अपना कट मोशन प्रस्तुत करता हूं।

कुमारी उमा माथुर (रामगढ, अलवर): चेयरमैन महोदया, मांग संख्या १६, चिकित्सा में मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं; एक डाक्टरों की कमी के विषय में है और दूसरा मोबाइल सर्जिकल चिकित्सा के विषय में है। आज आजादी के १५ साल बाद भी ग्रामीण जनता को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें प्राप्त नहीं

(कुमारी उमा माथुर)

हैं। दस-दस और पन्द्रह-पन्द्रह मील तक भी कोई चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं उनको उपलब्ध नहीं है। गरीब किसान, मजदूर जब बुखार से कांपता हुआ अपने मोटे पेट और पतली टांगों वाले बच्चे का हाथ पकड कर हॉस्पिटल में पहुंचता है तो दो-दो और तीन-तीन घन्टे खडे होने के बाद भी उसको निराश होकर लौटना पडता है। जिस अस्पताल में आठ आठ, दस दस और बारह बारह डाक्टर होने चाहिये यहां एक, दो या तीन डाक्टरों से काम चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भी जो डाक्टर मौजूद हैं उनमें से कोई तो छुट्टी पर चला जाता है और कोई नाइट ड्यूटी पर रहता है। इस प्रबन्ध में जैसा कि नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह बहुत बडी कमी है। हम जानते हैं कि डाक्टरों की कमी है और डाक्टरों के बनने में भी काफी समय लगता है, इसको हम मन्जूर करते हैं लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से यह कमी अधिक महसूस होती है।

आज राजस्थान में बडे बडे हॉस्पिटल्स हैं जहां मेडिकल कालेज हैं और अधिकतर डॉक्टर पढ़ लिख कर वहीं रहना चाहते हैं, कुछ लोग आगे पढना चाहते हैं, कुछ लोग बडे शहरों का आकर्षण नहीं छोडना चाहते हैं। हमारे स्वास्थ्य मन्त्री जी कुछ रहम दिल व्यक्ति हैं, जब कभी कोई डाक्टर रोये या गिडगिडाये और अपने ट्रान्सफर के विषय में कहे तो उनको फौरन कैन्सिल करना पडता है। यह मेरा अनुभव है कि कई डाक्टरों का अलवर हॉस्पिटल में पोस्टिंग हुआ और इसके पहले कि वह ड्यूटी जोइन करे उसका दुबारा ट्रान्सफर कर दिया गया। मेरा कहना यह है कि बडे बडे हॉस्पिटल्स में डाक्टरों का कन्सेन्ट्रेशन हो जाना और छोटी डिस्पेन्सरीज में सिर्फ कम्पाउन्डर्स के भरोसे पर छोड देना, बहुत अफसोस की बात है। अगर मन्त्री महोदय इन कुछ बातों का ध्यान दें और जब तक मेडिकल कॉलेज और खुलें या और डाक्टर इस राजस्थान में बना सकें तब तक इन बातों की तरफ ध्यान देकर जनता को कुछ सुविधायें दे सकें, तो यह बहुत प्रशंसा की बात होगी।

मेरा दूसरा प्रस्ताव है, मोबाइल सर्जिकल चिकित्सा के विषय में। एक ओर तो मैंने यह स्थिति आपके सामने रखी, दूसरी ओर हमारी स्थिति यह है कि २ लाख रुपया हम मोबाइल सर्जरी के नाम पर हर साल खर्च कर रहे हैं। मैं यह बता देना चाहती हूं और मैंने पता लगाने की कोशिश भी की है कि भारत में किस और स्टेट में इस तरह Mobile सर्जिकल जैसी चीज है, पर ऐसा कहीं नहीं है। मैं जानती हूं कि यह २ लाख रु० वास्तव में इस चिकित्सा के लिए प्रोत्साहन देने के लिए नहीं हैं बल्कि जो सरकार के चहेते व्यक्ति हैं उनके फायदे के लिये यह २ लाख रुपये खर्च किये जाते हैं और उनके लिए विशेष रूप से यह पैसा रखा गया है। आश्चर्य की बात यह है कि यह सज्जन ४ पोस्टों पर एक साथ काम कर रहे हैं—प्रिन्सिपल, उदयपुर मैडिकल कांलेज, कन्ट्रोलर आफ हॉस्पिटल्स इन उदयपुर, प्रोफेसर इन सर्जरी जयपुर में भी हैं और डाइरेक्टर ऑफ मोबाइल सर्जिकल यूनिट भी हैं। मैं हिसाब नहीं लगा सकी कि इन महाशय के लिये यह सरकार इतने रुपये खर्च क्यों कर रही है। यह आश्चर्य की बात अवश्य है। मैं नहीं कह सकती कि उसके पास क्या जादुई करामात

(कुमारी उमा माथुर)

हैं कि यह व्यक्ति एक साथ ४ काम कर रहा है । क्या इस सरकार को उससे मोह है कि वह किसी तरह इस बात पर ध्यान नहीं दे रही है। इसके अलावा मैं मोबाइल सर्जरी के लिए एक बात और कहना चाहती हूं कि यह लोग १०-१२ दिन के कैम्प स्थान स्थान पर लगाते हैं और वहां पर बिना पूरा इनवेस्टीगेशन किये और बगैर किसी तरह का पता लगाये कि क्या डिसीज है—क्योंकि ऐसे साधन उनके पास कैम्प्स में नहीं होते हैं, भोली भाली जनता जो कुछ नहीं जानती, उनको चीर फाड कर वहां पटक देते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कितने आपरेशन किये गये और उन मेंसे कितने आदमी मर गये, आपरेशन के नम्बर बढाने के लिए जरूर हैं, लेकिन कितने लोगों ने इससे फायदा उठाया इसका हिसाब आपके पास मिलने वाला नहीं है। इस बारे में मेरा निवेदन है कि इसकी ओर सरकार ध्यान दे। मन्त्री महोदय उत्तर में अवश्य कहेंगे कि डाक्टर महोदय जर्मनी की डिग्री रखते हैं। तो मेरा निवेदन है कि आज भी आपके यहां एफ. आर. सी. एस. और बडी बडी क्वालीफिकेशन्स के डाक्टर हैं जिनको ठीक समय पर प्रमोशन्स वगैरह नहीं मिलते और इन एक महाशय पर इस तरह से रुपया बरबाद किया जाता है। एक बात और है कि कोटा में एक कैम्प हुआ उसका प्रदर्शन नेहरूजी आये तब किया गया। मन्त्री महोदय अवश्य कहेंगे कि नेहरूजी ने भी उसकी प्रशंसा की। मैं मानती हूं, बहुत बडा सर्टीफिकेट मिला लेकिन मैं इस बात पर एक स्थिति आपके सामने रखना चाहती हूं कि कुछ दिनों पहले ही जब प्रेसीडेन्ट नासिर भारत आये थे तो उनको एक ब्लाक दिखाने के लिए अलवर लाया गया। अलवर में किशनगढ ब्लाक बहुत पुराना ब्लाक है और वहां एक छोटा सा गांव है चिकानी। मुझे भी सौभाग्य हुआ वहां जाने का तो मैंने देखा कि बडा सुन्दर पोल्ट्री फार्म है। एक से एक खूबसूरत नागौरी बैल और लिपे पुते छपरे मैं देखकर चकित रह गई कि इस राजस्थान में इतना सुन्दर गांव। जब दो साल बाद इलैक्शन के सिल-सिले में मुझे वहां जाना पडा तो मैंने देखा कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर नागौरी बैल ले गये और सब ने अपने अपने सामान की दुकानें उठा लीं और अब वही छोटी छोटी झोंपडियां, वही कीचड में डोलने वाले बच्चे उधर पल रहे हैं। तो यह जो दिखावटी नीति है, हिपोक्रेसी की नीति है इसको छोडना पडेगा । मन्त्री महोदय पूरी तरह से जानते हैं, कहीं उद्घाटन करने, भाषण करने जाते हैं तो उनको सुन्दर सुन्दर चीजें दिखाई जाती हैं; लेकिन उसका वास्तविक रूप भी आप जानते होंगे। मेरा निवेदन है कि गरीबों की गाढी कमाई का पैसा—२ लाख रुपया—जिससे कितनी ही छोटी मोटी डिस्पेन्स-रीज खुल सकती हैं, मैटरनिटी सेन्टर्स खुल सकते हैं और दूसरी कमियों को पूरा किया जा सकता है उसको इस तरह एक व्यक्ति के बडा बनाने के लिए, उसको रखने के लिए क्रिमिनल वेस्ट नहीं किया जाये; नहीं तो यह बहुत गम्भीर बात होगी।

श्री सभापति : श्री विट्ठल।

श्री विट्ठल (बांसवाडा-सु०) : सभापति महोदया, मांग संख्या १६ मुख्य शीर्षक २७ चिकित्सा के संबंध में मेरे तीन कटौती के प्रस्ताव हैं । पहला है कि चिकित्सा की मांग में १ रु० की कटौती की जाय (दानपुर में मेडीकल डिस्पेन्सरी खोले जाने पर बहस

(श्री बिट्ठल)

करने के लिये), दूसरा है बांसवाडा जिले में आयुर्वेदिक औषधालयों में समय पर दवाइयां नहीं मिलती है इस पर वहस करने हेतु और तीसरा कटौती का प्रस्ताव बांसवाडा मेडिकल अस्पताल में मरीजों को ठहरने की अव्यवस्था के संबंध में।

चेयरमैन महोदया, बांसवाडा जिला एक ऐसा जिला है जो कि बरसात के टाइम में चारों तरफ से नदियों से घिर जाता है और लोगों को आने जाने में और कहीं बाहर मरीजों को ले जाने में बहुत दिक्कतें होती हैं। मैं कहूंगा कि बांसवाडा के मेडीकल अस्पताल के लिए कुछ हमारी सरकार की तरफ से ऐसा वातावरण चल रहा है कि वहां से डी. एम. ओ. की पोस्ट हटाई जाये। पहले यह बातचीत चल रही थी इसके लिये कुछ रुकावट हुई है लेकिन इसके लिये काफी जनता में असन्तोष फैला हुआ है। मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसा जिला जो कि आदिवासी इलाका है, आदिवासी इलाके में वहां के लोगों और वहां की जनता को दवाइयों के लिए परेशानी होती है और कहीं आने जाने में दिक्कत होती है और वहां के डी. एम. ओ. की पोस्ट तोडना बहुत बुरी चीज है। अब वही एक जिला सरकार की नजर में आया कि वहां की डी. एम. ओ. की पोस्ट हटाई जाये। मैं कहूंगा कि वहां से डी. एम. ओ. की पोस्ट नहीं हटानी चाहिए क्योंकि उस जिले में ४ लाख जनता के पीछे एक ही अस्पताल है—इसलिये उसको नहीं हटाना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि अस्पताल में बाहर से जो मरीज लोग आते हैं उनके लिये क्वार्टर्स नहीं होने से मरीजों को ठहरने के लिये जगह नहीं मिलती। २०-२० मील से मरीजों को लाते हैं, खटियों पर लाते हैं क्योंकि सडकों की व्यवस्था वहां पर नहीं है और वहां पहुंचने पर डाक्टर को कहते हैं कि हमारे बीमारों को ठीक करो, लेकिन वहां पर कोई ऐसी जगह नहीं है कि मरीज ठहर सकें। ठहरने की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है और कई लोग तो ऐसे हैं जिनको दवाइयां दे देते हैं और कह देते हैं कि घर पर जाकर इलाज करो, हमारे पास रहने की व्यवस्था नहीं है; इसलिये लोग अपने मरीजों को वापिस ले जाते हैं और उनमें से कोई तो रास्ते में मर जाता है और कोई घर में मर जाता है।

इसी तरह से हमारे यहां टी. बी. का बहुत चलन चल गया है। हर साल इतने टी. बी. वाले आते हैं कि वहां पर भर्ती करने को जगह नहीं मिलती है। कई लोग टी. बी. वार्ड के आस पास आम के वृक्षों के नीचे पडे रहते हैं और कई वापिस चले जाते हैं। तो कम से कम टी. बी. वार्ड में उनको भर्ती करने के लिये व्यवस्था करनी चाहिए और वहां पर पूरी की पूरी व्यवस्था करके क्वार्टर्स के लिये भी व्यवस्था करें। यदि इस तरह से व्यवस्था नहीं की जाती है तो फिर सरकार को यह नहीं कहना चाहिए कि हम लोगों के लिये दवाइयां दे रहे हैं, चिकित्सा की व्यवस्था कर रहे हैं, लोगों का स्वास्थ्य ठीक रख रहे हैं। वहां पर न तो कोई इलाज हो रहा है और न अच्छी दवाइयां मिल रही हैं। आप चाहे कितना ही कहें कि अच्छी व्यवस्था है लेकिन मैं कहूंगा कि अच्छी व्यवस्था नहीं है। वृक्षों के नीचे पडे पडे टी. बी. के मरीज मर गये हैं। गई साल भी दो आदमी मर गये थे। गांव वाले उनको उठा कर ले गये लेकिन अस्पताल वालों ने उनको भर्ती नहीं किया।

(श्री बिट्ठल)

कई जगह ऐसे इलाके हैं, जैसे पीपल कोट पंचायत समिति, जहां एक भी मेडिकल डिस्पेन्सरी नहीं है। आयुर्वेदिक औषधालय खोल रखे हैं दो चार 'सी' क्लास के लेकिन वहां पर भी दवाइयों की व्यवस्था नहीं है। कहीं पर सौ पचास रुपयों की दवाइयां साल भर में दे देते हैं। कई बार मैंने वैद्यों से बातचीत की तो वे कहने लगे कि क्या करें; बडी तकलीफ है; वक्त पर दवाइयां देते नहीं हैं, सौ–दो सौ की दे देते हैं, वह भी साल खत्म होने के समय खराब हो जाती हैं और काम में आती नहीं हैं। कोई व्यक्ति उनसे अच्छा नहीं होता। औषधालयों में हमारे उधर तो एक मरीज भी अच्छा नहीं हुआ। प्राइवेट इलाज करायेंगे तभी अच्छा होगा।

एक गांव है दानपुर वहां पर तीन प्राइवेट आदमी काम कर रहे हैं लेकिन सरकारी औषधालयों से कोई बीमार अच्छा नहीं होता। रजिस्टर खोल रखे हैं उनमें झूठे नाम भर लेते हैं। दवाइयां सडी-गली देते हैं इसलिये कोई मरीज अच्छा नहीं होता। दानपुर के लोगों ने मांग की थी कि हमारा बहुत बडा इलाका है डिस्पेन्सरी खोली जाय लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मंत्रीजी से लिखा–पढी ग्राम पंचायत ने की, गांव वालों ने भी लिख कर दिया लेकिन मंत्री महोदय का आज तक कोई जवाब नहीं आया और न उन्होंने इस पर कोई ध्यान दिया। हो सकता है कि वहां का इलाका समाजवादी होने के नाते आपको कोई दिलचस्पी न हो, और तो क्या हो सकता है क्योंकि वहां के नेता लोग, मैं कहना तो अच्छा नहीं समझता था, लेकिन कांग्रेस के लोग वहां पर जनता को जाकर कहते हैं कि हमारे साथ रहोगे तो डिस्पेन्सरी और मिडिल स्कूल खुलवा देंगे। हमारे साथ नहीं रहोगे तो जिन्दगी भर फायदा नहीं होगा। इस तरह की कई बातें यहां पर उन्होंने कहीं, मिडिल स्कूल के लिये भी यह कहा। मिडिल स्कूल के लिये गांववालों ने मुख्य मंत्रीजी जब वहां गये चुनाव से पहले, से तब कहा। लेकिन जोशीजी ने कहा कि सफेद टोपी रखोगे और हमारा साथ दोगे तो खोलेंगे, नहीं तो नहीं खोलेंगे। (शेम शम) जहां पर लोग मरे जा रहे हैं वहां पर इस तरह से पार्टी बाजी होती है और हमारे लोग परेशान हैं पर आज तक वहां पर कोई काम नही होता है। हमारे इलाके में ५० हजार जनता रहती है उसके लिये दवाई का कोई प्रबन्ध नहीं है। कांग्रेस के राज्य में हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है। हम से लोग कहते हैं कि आप वहां जाकर क्या करते हैं? हम कहते हैं कि हम आपकी आवाज तो यहां पर उठायेंगे लेकिन हमारी कौन सुनता है। हम आवाज पहुंचाते हैं लेकिन हमारी कौन सुनता है, जोशीजी की बात सुनेंगे, लेकिन आज हम भी एक लाख जनता के वोट पाकर आये हैं, हमारी आवाज सुननी चाहिये। जब भी मंत्रीजी, चाहे रेवेन्यू मंत्रीजी हों, चाहे स्वास्थ्य मंत्रीजी, वहां आते होंगे हमसे कभी उनकी बात नहीं होती है। वे नहीं सोचते कि एम. एल. ए. से बात करें और पूछें कि वहां की क्या समस्या है। ये लोग हमारे साथ में सौतेला व्यवहार करते हैं। आप चाहे कितना ही कर लें लेकिन हम तो जीतने वाले हैं और जीतेंगे। १०-१५ साल हो गये हैं, हमारी जनता आपसे परेशान हो गई है। अभी जो दो सीट्स आपकी आ गई हैं आयन्दा के लिये वह भी नहीं आयेंगी यह मैं साफ कहता हूं। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति (श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूडावत) : श्री मोहनराजजी।

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस को दुबारा टाइम दिया जा रहा है।

श्री सभापति : टाइम सबको दिया जायगा।

श्री मोहनराज जैन (बाली) : सभापति महोदया मांग संख्या १६ पर डाक्टरों की कमी और अस्पतालों की व्यवस्था के बारे में मेरा कटौती प्रस्ताव है। इस समय राजस्थान में डाक्टरों की कमी है और जितने धन और जितने साधन की हमारे यहां के सभी अस्पतालों और दवाखानों में आवश्यकता है उन सब को मुहैय्या करने के लिये आवश्यक धनराशि भी नहीं हैं। लेकिन फिर भी किसी भी राज्य के लिये वहां के जन स्वास्थ्य को उन्नत बनाने के लिये जो योजना है उसको पूरा करने में कन्जूसी करना और उसके लिये आवश्यक धन नहीं जुटाना—यह बहुत बुनियादी गलती रह जाती है। हम हमारे राज्य को हर हालत में संपन्न बनाना चाहते हैं तो यह मानकर चलना पडेगा कि यदि जनता का स्वास्थ्य ठीक है तो दूसरी हालत भी ठीक हो सकती है क्योंकि स्वास्थ्य का असर सब और तमाम क्षेत्रों में पडता है। इसलिये मैं थोडे से समय में सिर्फ राज्य द्वारा जो निश्चित बातें लोगों से कही गई थीं किसी क्षेत्र में, सरकार ने कमिटमेन्ट्स किये थे, आज नहीं, २ साल पहले नहीं, ५ साल पहले नहीं बल्कि १० साल पहले सरकार के जो कमिटमेन्ट्स थे और जो आज तक पूरे नहीं किये गये हैं उनकी ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

सबसे पहले पाली जिले में रानी कलां नाम का गांव है जो रानी स्टेशन के पास एक व्यापार की मंडी है और पंचायत समिति का हैड-क्वार्टर है – आज से करीब १५ वर्ष पूर्व वहां के एक धनदाता ने चाइल्ड वेलफेयर एंव मेटरनिटी हैल्थ सेन्टर के लिये एक भवन बना कर जोधपुर सरकार (भूतपूर्व) को दिया था। जोधपुर सरकार ने उस वक्त उस दान-दाता के साथ एक एग्रीमेन्ट किया था कि हम वहां पर लेडी डाक्टर रखेंगे और मेटरनिटी सेन्टर चालू रहेगा। मुझे अफसोस है कि आज १५ वर्ष बीतने आये हैं लेकिन वहां पर चाहे फर्रास कहिये, चाहे दाई कहिये, एक महिला रखी हुई है जो खुद अपना काम कतई नहीं जानती। इतना बडा मकान और साधन उपलब्ध हैं लेकिन वहां के सारे क्षेत्र को कोई फायदा नहीं पहुंचता है। मैं इतना भी मानता हूं कि वह क्षेत्र ऐसा है कि जिसके आस-पास १५ मील तक कोई सरकारी दवाखाना किसी भी तरह का नहीं है। इसलिये इस बडे मकान का पूरा पूरा उपयोग हो और जो सरकार ने वायदा किया है वह पूरा किया जाय, यह न्याय की बात है।

साथ ही उस भवन का निर्माण पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा किया गया, मकान पूरा होने के बाद ४,०००) बच गये थे।

(२.०० म.प.)

वह भी सेठ ने इसलिये डिपार्टमेंट को सौंप दिये कि इस भवन के अहाते के अन्दर एक बेरा खुदवा कर अस्पताल के काम में लाया जाय। वह रुपया आपके डिपार्टमेंट के द्वारा पी. डब्ल्यू. डी. को दिया और उनके पास में जमा है। आज इतने साल हो गये हैं लेकिन वह बेरा नहीं खुदवाया है। जो पैसा वहां रखा गया है, उसका उपयोग होना चाहिए और बेरा खुदवाया जाना चाहिए।

(श्री मोहनराज जैन)

दूसरी बात मैं अर्ज करूंगा कि पाली जिले के अन्दर जो देसूरी की पंचायत समिति है, उसके नाडोल गांव में एक प्राइमरी हैल्थ सेन्टर है। वह बडा कस्बा है, वहां पर हायर सेकन्ड्री स्कूल है। वहां पर प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोला गया, उसके लिए बडा आलीशान मकान बना और कम्पाउन्डर्स और डाक्टर्स के लिए रहने के क्वार्टर बने हुए हैं। लेकिन इस प्राइमरी हैल्थ सेन्टर को देखने के लिये कोई डाक्टर नहीं है। वहां शुरुआत में एक डाक्टर भेजा भी गया था लेकिन उन्हें शहरी जीवन पसन्द था। जो डाक्टर होते हैं वे छोटे गांव में रहना नापसन्द करते हैं। इसलिये कोई न कोई रास्ता निकाल कर वहां से निकल जाना चाहते हैं। चार महीने से वहां पर डाक्टर नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि वहां डाक्टर भेजा जायगा। यह नाडोल गांव ऐसा है, जिसके इर्द–गिर्द बीस मील के क्षेत्र में कोई अस्पताल नहीं है। वैसे एक प्राइमरी हैल्थ सेन्टर में दो डाक्टर रहते हैं और हजारों रुपये की दवा देने का बजट है और सुविधायें दी जाती हैं। लेकिन वह प्राइमरी हैल्थ सेन्टर बिना डाक्टर के रखा जाय तो मेरे ख्याल से जो बजट का प्रॉपर यूटीलाइजेशन होना चाहिये, वह नहीं होगा। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि वह सारा ऐसा इलाका है, जहां बीस मील के एरिया में कोई अस्पताल नहीं है और किसी प्रकार दवा देने का इन्तजाम नहीं है, इसलिए वहां डाक्टर भेजना निहायत जरूरी है।

तीसरी चीज मैं अर्ज करना चाहता हूं कि एक होड गांव है, जिस गांव की पांच हजार की आबादी है। वहां ३ साल से एक अस्पताल का भवन बना हुआ है। उसका उद्घाटन हमारे मुख्य मंत्री जी ने किया था। पाली जिले के अन्दर इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में एक डिस्पेन्सरी खोलने का प्रावधान है, और उस वक्त हमारे जिले के मैडीकल आफिसर साहब ने यह लिख कर डिपार्टमेंट को भेजा था कि जिस डिस्पेंसरी का प्रावधान है, वह होड गांव में खोल देते हैं तो हमें एतराज नहीं है और होड गांव में डिस्पेंसरी खोलना निहायत जरूरी है। इस लिखावट के आधार पर, इस आश्वासन के आधार पर हमारे मुख्य मंत्री से हमने निवेदन किया था कि इसकी सब जगह से सिफारिश हो चुकी है और यहां औषधालय खुलने वाला है। उन्होंने इस की जांच की थी और जांच पडताल से उन्हें विश्वास हो गया कि यहां डिस्पेंसरी खोल दी जायगी, तब ही उन्होंने उस भवन का उद्घाटन किया था। उसके बाद में व्यक्तिगत रूप से निवेदन किया था कि अगर डाक्टरों की कमी की वजह से होड कस्बे के अन्दर डाक्टर नहीं भेजा जाता है तो वहां किसी कम्पाउन्डर को भेज दें क्योंकि होड गांव के इर्द-गिर्द दस पन्द्रह मील का ऐसा इलाका है जहां कोई डिस्पेन्सरी या अस्पताल नहीं है, इसलिये वहां डिस्पेंसरी चालू करना निहायत जरूरी है। अगर आप वहां कम्पाउन्डर भी भेज देंगे तो इस संकटकालीन स्थिति के अन्दर डाक्टरों की कमी के कारण डाक्टर के न होने से भी वहां की जनता को संतोष होगा और उन्हें राहत मिलेगी।

दूसरी चीज मैं अर्ज करना चाहता हूं, कि आयुर्वेदिक विभाग की ओर से जो औषधालय चल रहे हैं, उनके विषय में सिर्फ एक बात मेरे ध्यान में आई है वह अर्ज करना चाहता हूं। अभी चन्द दिन पहले मैं पाली जिले के दादाई गांव गया था। वहां पर औषधालय बना हुआ है, उसके लिए एक नया भवन बना हुआ है। जब मैं वहां गया तो

(श्री मोहनराज जैन)

मैंने देखा कि उस भवन के बाहर इस तरह के पैकट पडे हुए हैं, कागजों के पैंकिंग पडे हुए हैं, उनमें जिस कीडे को उदयी कहते हैं वह लगी हुई थी। वे पैंकिंग फटे हुए थे, उदयी के द्वारा नष्ट किये हुए थे। मुझे ख्याल हुआ कि सारी की सारी औषधियों की हालत ऐसी इसलिये हो गई है, इसलिये नष्ट हो गई है क्योंकि इस मकान में उनको रखने की ठीक व्यवस्था नहीं होगी। जो उस भवन को बनाने वाले सेठ थे, जो दानदाता थे वे भी मेरे साथ थे। तो मैंने वहां वैद्यराज से पूछा कि इन पैंकिंग में इस तरीके से सारी की सारी उदयी कैसे लग गई है, इन औषधियों का नाश कैसे हो गया है। तो उन्होंने मुझे बताया, हालांकि बडे हिचकिचाते हुए क्योंकि यह उनके विभाग की बात थी, वे खुल कर नहीं कहना चाहते थे, इसलिये छान-बीन करने पर ज्ञात हुआ कि वे औषधियां दो तीन रोज पहले पैंकिंग करके उदयपुर से भेजी गई थीं उस गांव के अन्दर। जब वे वहां पहुंची और खोला तो देखा कि सारी की सारी औषधियां उस हालत में थीं कि किन्हीं मरीजों को दी नहीं जा सकती थीं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरह का जो पुराना स्टाक औषधियों का पडा हुआ है, जिसे काम में लेना नहीं है, उसको अलग अलग औषधालयों में भेज कर वितरण नहीं करना चाहिए, उसे नष्ट कर देना चाहिये। वह मरीजों को देने के काबिल नहीं है, उस पर पैसा खर्च होता है, उसे कागजों में लिख दिया जाता है कि औषधालयों में भेज दी है। मैं समझता हूं कि इस ओर भी ध्यान देना चाहिए।

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि दो-तीन गांव पाली में एसे हैं जहां पीने के पानी की दुविधा है, उसकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना आवश्यक समझता हूं। इसके संबंध में मैं दो मिनट अर्ज कर दूं। बीजापुर गांव है, जहां के निवासियों ने आज से पन्द्रह वर्ष पूर्व

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

२० हजार रुपया एकत्रित करके बैंक में जमा करके सरकार को लिखा था कि यह हमारी ओर से मदद ह, आप पीने के पानी की व्यवस्था कीजिये, लेकिन अभी तक उसकी व्यवस्था नहीं हो पाई है और न सरकार ने इसकी स्वीकृति दी है। यह स्कीम सर्वेड और सैंक्शन्ड है, लेकिन यह पांच साल से विचाराधीन है और पैसे के अभाव में काम की पूर्ति नहीं हो रही है। मैं निवेदन करता हूं कि जो इस तरह की समस्यायें, कठिनाइयां और मुश्किलात लोगों के सामने हैं, उनको शीघ्रातिशीघ्र हाथ में लेकर दूर करें। यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री हरदत्तसिंह।

एक माननीय सदस्य : आप, दूसरों का नाम नहीं,

श्री सभापति : नाम तो जानता हूं, लिस्ट में लिखा है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : सभापति महोदया, कटौती प्रस्तावों की लिस्ट में मेरा नम्बर चौथा-पांचवा है। इस दृष्टि से मेरा नाम प्रथम है। मैं समझता हूं . . .

श्री सभापति : अभी हरदतजी बोल लें, फिर आपका नम्बर आ जायेगा।

श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : अभी आपका भी नम्बर आ जायगा।

(श्री हरदत्तसिंह)

सभापति महोदया मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९–चिकित्सा के बारे में मेरा जो कटौती प्रस्ताव है, उसके बारे में जो १९६२-६३ के एस्टीमेट्स हैं उनकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । १९६२-६३ के एस्टीमेट्स में ३,८०,९९ रुपये का प्रावधान रखा गया था, रिवाइज्ड एस्टीमेट ३,८४,३८ रुपये के करीब है और अब जो १९६३-६४ का एस्टीमेट है वह करीब चार करोड के कुछ ऊपर है । २१ लाख ७९ हजार की इसमें बढोतरी की गई है । मेमोरेन्डम आफ स्पष्टीकरण दिया गया है, उसमें यह दर्ज है कि मकान किराया, वैद्य, दवायें और उपकरणों के सम्बन्ध में यह बढोतरी हुई है और ३६ विकास खंडों का भार भी इसमें जोड दिया गया है । औषधियों और उपकरणों के बारे में मैं खास तौर पर अर्ज करना चाहता हूं, इसके पहले मैं दो जरूरी बातें, सभापति महोदया आपकी मार्फत सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं । अमूमन यह देखने में आया है कि जब किसी डाक्टर का ट्रान्सफर हो जाता है, अगर वह जगह उस डाक्टर के नुकते निगाह से अच्छी है तो वह इस प्रयत्न में लग जाते हैं कि किसी तरह अपना ट्रान्सफर केन्सल करा लें । और इस बात के लिये सप्ताह सप्ताह भर तक डाक्टर लोग राजधानी के चक्कर लगाते रहते हैं । यह होता है, सभापति महोदया कि जिस डाक्टर का एक घंटा भी अपने अस्पताल से गैर-हाजिर रहना जनता के स्वास्थ्य की दृष्टि से और जन-जीवन की दृष्टि से बहुत हानिकर है, क्योंकि वहां उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है । इसलिये माननीय स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान, मैं आपकी मार्फत इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वह भविष्य में इस बात का ध्यान रखें कि किसी डाक्टर का ट्रान्सफर होने के बाद राजधानी में चक्कर लगाता हुआ उनको नजर में आये तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें ताकि जनता के जीवन के साथ खिलवाड होने से रोका जा सके ।

इस संबंध में दूसरी बात पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है सभापति महोदया कि कई जगह मेरे देखने में यह आया है कि वहां बहुत बुड्ढे डाक्टर होते हैं । बडी उम्र के डाक्टर हैं । उसका नतीजा बहुत खराब होता है । मेरे कस्बे की बात है । बात तो पुरानी है । एक बुड्ढा डाक्टर था । एक मरीज उसके पास दांत के दर्द का आया था । उसने उसको कहा कि तुमको दांत निकलवाना पडेगा । मरीज ने हां कर ली । डाक्टर दांत निकालने के लिये जंबूरा लेने के लिये गया तो उसको मिला नहीं । नजर कमजोर थी । उसको ढूंढने में देर लगी । जब डाक्टर बहुत देर बाद जम्बूरा तलाश करके लौटा तो उस रोगी की जगह कोई दूसरा रोगी बैठा था । दांत के दर्द का रोगी जा चुका था । उसको जुकाम की शिकायत थी । डाक्टर ने कहा-मुंह खोलो । रोगी ने समझा कि डा० कोई गले में दवाई लगाना चाहता है । डा० ने तुरन्त उसका दांत जम्बूरे से निकाल दिया । अगर डाक्टर तन्दुरुस्त नहीं है तो वह ठीक काम नहीं कर सकता । उस रोगी को; जिसका दांत उखाडा था, आखिर में सभी दांत निकलवाने पडे ।

श्री बरकतुल्ला खां (स्वास्थ्य मंत्री) : उस डाक्टर का आप नाम बतावें ।

श्री हरदत्तसिंह : मैंने पहले ही निवेदन किया कि यह बहुत पुरानी बात है । सरकारी

(श्री हरदत्तसिंह)
पक्ष की ओर से अगर कोई आलोचना भ्रष्टाचार की की जाती है या कोई सरकार की कमजोरी की बात कही जाती है तो आम तौर पर यह बात कही जाती है कि माननीय सदस्यों को कोई व्यक्तिगत नाराजगी होगी या पार्टी बाजी की नाराजगी होगी।

श्री बरकतुल्ला खां : यह मेरी भावना नहीं है।

श्री हरदत्तसिंह : सभापति महोदया, मैं डाक्टरों के पेशे को बहुत अच्छा समझता हूं और उनको ब्राह्मण और साधुओं के समान मानता हूं। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण ब्रह्म-राक्षस हो जावे तो उसका इलाज किया जाना चाहिए।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि कई जगह बीमार डाक्टर हैं। जो हर वक्त बीमार रहते हैं। जब कोई मरीज उसके पास जाता है तो डा० बीमार तो वैसे ही होता है और उसकी वजह से उसका स्वाभाव चिड चिडा हो जाता है और वह मरीज के साथ अच्छी तरह से पेश नहीं आता है। इसलिये जो डाक्टर लम्बी बीमारी में रहते हैं उनको या तो इलाज के लिये छुट्टी दी जावे और अगर ठीक नहीं हो सकते हैं तो उनको छुट्टी दे दी जावे। इसके लिये मैं, अगर चाहें तो, इन्सटेन्सेज भी दे सकता हूं।

माननीय सभापति महोदया, आम तौर पर आज कल के हॉस्पिटलों में पेंसलीन का बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा है और कस्बों में रहने वाले डाक्टर इस बात से अनभिज्ञ हैं कि कितने लोगों को एलर्जी होती है और उसके भयंकर परिणाम देखने को आते हैं। इसलिए मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जहां पर पेन्सलीन के इंजेक्शन भजे तो उसके साथ साथ स्पेशल इन्सट्रक्शन्स यह भी होने चाहिये कि इसका एन्टी-डोट भी अवश्य भेजें ताकि एन्टी-एलर्जिक दवाइयों से भयंकर परिणाम से बच सकें।

मुझे बड़ा अफसोस है कि जहां छोटे छोटे हॉस्पिटल हैं सरकारी तौर पर वहां सिवाय टिन्चर आयोडिन के कोई भी दवाई उपलब्ध नहीं होती है। इसका नतीजा यह हो गया है कि आम तौर पर टिन्चर आयोडिन के अलावा जितनी दवाइयां वहां पर जाती हैं बाजार में केमिस्टों के यहां बिकती हैं। हमारे यहां ४ करोड रुपयों का खर्च सालाना होता है, उससे आम लोगों को राहत नहीं मिलती। मैं यह चैलेंज के तौर पर कह सकता हूं और खास तौर से नौहर की बात कह सकता हूं कि वहां टिन्चर आयोडिन के अलावा जितनी दवाइयां जाती हैं वे वहां के दवा-फरोशों को बेची जाती है और जो लोग दवा लेने के लिये आते हैं उनको दवाइयां बाजार से लाने के लिये लिख दी जाती हैं। जिस प्रकार आम लोग झाड़ा फूंका करते हैं और उसके लिये माला व जाप आदि बता देते हैं कि इससे जाओ ठीक हो जावेगा। इसी तरह से डा० नुश्खा लिख देते हैं और लोगों को दवा-फरोशों से जाकर दवाइयें लानी पडती है। इसलिये हैल्थ मिनिस्टर से निवेदन है कि इसकी रोक थाम की जावे।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। इसी तरह से लेडी डॉक्टर और नर्सों का भी बहुत अभाव है। मैं यह कहूंगा कि हमारे लिये यह एक

(श्री हरदत्तसिह)
बहुत लज्जाजनक बात है कि एक अच्छे घराने की महिला चाहे किसी तरह का रोग हो उसके इलाज के लिये लेडी डा० नहीं मिलता है और उसको पुरुष से इलाज कराना पडता है । मैं आपको मिसाल के तौर पर बताना चाहता हूं कि चुरू में वहां पिछले १२ महीनों से कोई नर्स नहीं है ।

अब मैं अपने कस्बे के दो इन्सटेन्स देकर अपना भाषण खत्म करता हूं । भादरा में एक दानी व्यक्ति ने ४० हजार रुपये मातृ सदन के लिये दिये थे मगर चार वर्ष हो चुके हैं सरकार उसको इस्तेमाल नहीं कर रही है। एक एक्स-रे प्लान है। आज से तीन साल पहले उसको खराब कर दिया था । वहां पर एक ही तो एक्स-रे की मशीन है और वह भी डा० ने खराब कर दी और उस पर अफसोस की बात है कि ६ हजार का एस्टीमेट उसके लिये है । मगर फिर भी वह मशीन ठीक नहीं हो पाई है । ये रुपये डा० से या टेक्निशियन से वसूल नहीं किये हैं । जनता को परेशानी बगैर एक्स-रे मशीन के हो रही है ।

इसके अलावा, सभापति महोदया अगर कोई मालदार मरीज मिल जावे तो उसकी बीमारी को लम्बी करने में डाक्टरों को लाभ हो सकता है । इसके अलावा दानी ने कहा कि मैं दुरुस्त करा कर देता हूं उसको भी नहीं कराने देते, न सरकार उस एक्स-रे की मशीन को दुरुस्त कराती है ।

इसलिये मैं पुरजोर निवेदन करूंगा कि इसके लिये सरकार विचार करे और जो जनता को कठिनाइयां हैं उनको दूर करे ।

श्री हरि प्रसाद शर्मा (पाटन): सभापति महोदय, मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९ चिकित्सा में १००) रु० की कटौती की जाय (पाटन तहसील में चिकित्सा के अभाव से होने वाली हानियों पर बहस करने हेतु) व बूंदी अस्पताल में बीमारों की दयनीय स्थिति, दवाइयों का अभाव व भवन की कमी के कारणों पर बहस करने के लिये मैंने अपने कटौती प्रस्ताव भेजे हैं। राज्य सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी यह है कि जनता के स्वास्थ्य को ठीक तरह से रखे । जिस जनता का स्वास्थ्य ठीक होगा वही जनता इतनी सबल और ताकतवर होगी और दुश्मनों का डट कर मुकाबला करने में सफल होगी ।

इसके अलावा जिन माननीय सदस्यों ने कटौती के प्रस्तावों द्वारा आपका ध्यान आकर्षित किया है उससे पता चल गया होगा कि राजस्थान की सरकार ठीक तरह से चिकित्सा का प्रबन्ध करने में असमर्थ रही है ।

आर्थिक समस्या के सम्बन्ध में जैसा नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया उस सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उससे अच्छा यह हो कि आप आयुर्वेद को बढावा दें । इससे आयुर्वेद को प्रोत्साहन मिलेगा । पुराने जमाने में आयुर्वेद ही प्रचलित था और लोग दो पैसों की दवा से बीमारी मिटाते थे और लोगों को कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा लाभ होता था । मैं यह निवेदन करूंगा कि हर पंचायत में कम से कम एक वैद्य की नियुक्ति करावें जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और आपका आर्थिक अभाव भी मिट सके ।

आपने चलते-फिरते औषधालयों का निर्माण किया है । मैं यह कहूंगा कि इनको

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जावे । ज्यादा से ज्यादा इससे पब्लिक की सेवा हो सकेगी । इसलिये ज्यादा से ज्यादा चलते-फिरते औषधालय रखें तो काफी सेवा हो सकेगी । आपके यहां २ करोड़ ३२ लाख का आयुर्वेद और ४ करोड़ का चिकित्सालयों का बजट है । माननीय सभापति महोदया हमारी सरकार में इतना भ्रष्टाचार है कि दवाइयों का सदुपयोग नहीं हो पाता । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जयपुर मेडिकल स्टोर्स से पर्चेजेज में काफी गड़बड़ी है । यह हमारे विरोधी दल के नेता श्री भैरोंसिहजी ने सरकार को लिखित में दिया है । उसकी कोई जांच नहीं की गई और अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है ।

एक बात मैं और कहना चाहूंगा, भरतपुर के बारे में नहीं है, अलवर के बारे में है । अलवर में अलेग्जेन्डर, जनाना अस्पताल और टी. बी. सेंटर—ये ३ अस्पताल हैं । इनमें दूध देने का ठेका, एक दुर्गाप्रसादजी, कांग्रेस के नेता हैं, को दिया हुआ है । २५००) का पेमेन्ट होना चाहिये वहां ७००) रुपये का पेमेन्ट होता है । कम पेमेन्ट इसलिये होता है कि उनके द्वारा सप्लाई किया हुआ दूध यहां जयपुर की लेबोरेट्री में टैस्ट करने के लिये आता है । टैस्ट करने के बाद उसमें मिलावट पाई जाती है और २५०० में से ७०० रुपयों का पेमेन्ट होता है, १८०० रुपयों का पेमेन्ट नहीं होता । मैं राजस्थान सरकार से जानना चाहूंगा कि जब ऐसी रिपोर्ट है, फूड इन्सपेक्टर जगह जगह मुकर्रर हैं, थोड़ी सी मिलावट चाय के प्याले में होती है तो बड़े बड़े जुर्माने किये जाते हैं तो यह आंखों के नीचे अन्धेरा क्यों ? जिसकी प्रत्यक्ष रिपोर्ट है, वहां उसे कोई कड़ा दण्ड नहीं दिया गया । इस भ्रष्टाचार को कैसे मिटायें ? जहां हमारी सरकार इतनी अकर्मण्य हो, जनता के प्रतिनिधि इस प्रकार उदासीन हों तो वहां कैसे भ्रष्टाचार दूर होगा !

सदन में मैंने एक प्रस्ताव दिया था कि लाखेरी सीमेन्ट फैक्ट्री के गन्दे पानी, पेशाब और टट्टी मिले हुए सीमेन्ट के गन्दे पानी का गन्दा नाला लाखेरी के समीप एक बरसाती नदी में मिलाया जाता है । गन्दे नाले को नदी में मिला दिया जाता है ।

सभापति महोदया, समय की चिन्ता न करें मेरी पार्टी का २३ मिनिट समय बाकी है ।

इस मल मूत्र के नाले के पानी को, जो राहगीर आते हैं, नदी का समझ कर पीते हैं । मलेरिया को रोकने के लिये मच्छर मारते हैं, मलेरिया के लिये बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं और दूसरी तरफ मच्छर पैदा करने वाली चीजें हैं उनको आप पैदा करते हैं । वहां की जनता चिल्ला चिल्ला कर आपके कान के पर्दों को खोलने की कोशिश करती है, मिनिस्टर खुद देख कर आते हैं । मन्त्री महोदय को सारी जानकारी के बाद भी क्या असमर्थता है यह मैं नहीं समझ पाया । मन्त्री महोदय यहां से शान से बिदा होकर चले गये । यहां आश्वासन दिया, लाखेरी गये । उन्होंने मुझे कोई चिट्ठी या ईत्तला नहीं दी । वह मेरा क्षेत्र है, मैं वहां का रहने वाला हूं, वहां की म्युनिसिपैलिटी को सूचना नहीं दी । तोरण दर्वाजे बनने लगे तो लोगों ने पूछा कि क्या बात है तो पता लगा कि बरकतुल्लाजी पधार रहे हैं....

श्री उमरावसिंह डाबरिया (बनेड़ा) : तोरण क्या शादी के लिये बने ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : बड़ी खुशी की बात है, उनको जाना चाहिये था। मैं एक दूसरे कार्य में व्यस्त था, वहां नहीं था। जनता ने मिनिस्टर साहब से कहा कि वहां जाकर देख आवें। मेनेजमेन्ट के साथ वहां गये, मेनेजमेन्ट वाले साथ थे जल्दी ही वापिस ले आये फिर दिन भर मन्त्री महोदय को अपने यहां रखा। उनके बंगलों को देख कर मन्त्री महोदय बहुत प्रभावित हुए, उनको धन्यवाद दिया। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उस गन्दे नाले के बारे में जिसमें टट्टी और पेशाब बहता है और लोग उसे नदी का पानी समझ कर पीते हैं, उसके बारे में आपने क्या किया जिसके लिये आप वहां गये, टी. ए. डी. ए. और भत्ता कमाया, उस गन्दे नाले के लिये आपने क्या किया ? उल्टा आपके जाने के बाद कम्पनी को प्रोत्साहन मिला है। उनको कहते हैं तो कहते हैं कि मन्त्री महोदय को कहिये, आपने सरकार तक पुकार की है, सरकार को कहिये। अपनी रिपोर्ट म्यूनिसिपल चेयरमैन से मांगी है पर वह चेयरमैन भी आप जैसा ही है, आप, वहां गये और चले आये। यदि आपको जनता के स्वास्थ्य के बारे में चिन्ता है तो इस ओर शीघ्र ध्यान देकर कदम उठाना चाहिये।

बूंदी जिले की जनता के साथ बड़ा पक्षपात पूर्ण बर्ताव किया जा रहा है। वहां की जनता के लिये औषधियों की, हास्पिटल की कोई व्यवस्था नहीं है। बूंदी में बेड्स नहीं है, रास्ते में पड़ता है; पर कोई उस ओर ध्यान नहीं देता, वहां मरीज बरामदे में रखे जाते हैं। बरसात, सर्दी, गर्मी में उन्हें वहीं रहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पास पैसा नहीं है, आप दवाई नहीं दे सकते, मकान नहीं दे सकते तो मरीजों को यह सुविधा तो दीजिये। जो अनुदान देते हैं उसको देखना होगा कि उसकी उपयोगिता भी है कि नहीं हेल्थ के लिये। खास तौर से मैं पाटन, बूंदी क्षेत्र के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि वहां जाइये वहां नावड़ियों में, कुओं में कीड़े पड़ जाते हैं, उन कीड़ों को मारने की कोई व्यवस्था नहीं है कोई दवाई की व्यवस्था नहीं की जाती। उन कीड़ों से बाले जैसा भयंकर रोग पैदा हो जाता है, जिससे हाथ पैर हमेशा के लिये बेकार हो जाते हैं। आप अपनी ही इनर्जी बढ़ाने की फिक्र में हैं, इस ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिये।

सभापति महोदया, मैं जल प्रदाय योजना के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। लाखेरी की म्युनिसिपेलिटी ने अपनी स्वयं की योजना बना कर ८० लाख की योजना कार्यरूप में परिणित की है। मुख्य मन्त्री ने उद्घाटन किया, एक पैसा भी सरकार ने नहीं दिया। गन्दे पानी को नालियों के जरिये बाहर निकाल कर निश्चित जगह पहुंचाने की व्यवस्था वहां की नगरपालिका करना चाहती है। फिल्टर की भी व्यवस्था करना चाहती है। इसके लिये वहां की म्युनिसिपेलिटी ने सरकार को बार बार लिखा है। पर वहां कांग्रेस की म्युनिसिपेलिटी होते हुए भी उसकी उपेक्षा की जाती है। राजस्थान के मन्त्री बनते हैं तो उनको सारे राजस्थान के बारे में सोचना चाहिये। चाहे अपने वोटों की भी फिक्र करें पर सारे राजस्थान के बारे में समान रूप से सोचना चाहिये। इसका सीधा असर चीफ मिनिस्टर पर जाता है।

अब मैं कुछ आयुर्वेदिक औषधालयों के बारे में बतलाऊंगा। लाखेरी में २० हजार की

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

आबादी है, आस पास में ५० हजार की आबादी में राजस्थान सरकार की एक भी डिस्पेन्सरी नहीं है। जहां मजदूरों का क्षेत्र है वहां एक भी डिस्पेन्सरी नहीं है। चिट्ठियां लिख कर दीं उन पर आश्वासन दिया है कि सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान में करेंगे, फिर कहां तीसरी पंच वर्षीय योजना में रखा है पर अभी तक कुछ नहीं किया गया है।

इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि मजदूर बस्तियों का सेनिटेशन बिलकुल खराब हो रहा है, इसको सुधारने के लिये वहां की पंचायत कुछ व्यवस्था करना चाहती है पर उस पंचायत को ही तोडने का पूंजीपति षडयन्त्र कर रहे हैं।

तो लाखेरी में औषधियों का अभाव है, सेनिटेशन की दशा खराब है उसे सुधारने के लिये कोई कदम नहीं उठाया जाता। म्युनिसिपैलिटी ने २५ हजार की लागत की बिल्डिंग बना कर दी है पर सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

इन्हीं शब्दों के साथ में कटौती प्रस्ताव पेश करता हूं। स्वास्थ्य और चिकित्सा जनता के लिये बहुत आवश्यक है। यदि सरकार के पास पैसा नहीं है, वह डाक्टरों के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकती, एलोपेथी दवाइयां नहीं दे सकती तो आयुर्वेदिक औषधालय खोलिये। यह सरकार का कर्तव्य है और वह इसका पालन करे।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री सभापति : श्रीमती गौरी पूनिया।

श्रीमती गौरी पूनिया (डेगाना) : सभापति महोदया, मेरे ३ कटौती प्रस्ताव हैं। मांग संख्या १६ पर दो और मांग संख्या १७ पर १। मेरा पहला कटौती प्रस्ताव प्राईमरी हैल्थ सेन्टर डेगाना के बाबत है। प्राईमरी हैल्थ सेन्टर केवल नाम है। सभापति महोदया, पहले राजकीय औषधालय था, उसमें जो स्टाफ था; डाक्टर, कम्पाउन्डर, चपरासी वही अब भी है, केवल नाम बदला है। रूप नहीं बदला है। यह नामकरण हुए एक साल बीत गया है, इस बीच में कई पत्र दिये गये हैं और उनके उत्तर में हिदायत मिली है कि पैसे की कमी के कारण अभी हैल्थ सेन्टर चालू नहीं कर सकते। गांवों में जाकर मकानों की व्यवस्था करिए, फिर हम प्रबन्ध करेंगे। मैं स्वयं गांवों में गई, तीन गांवों में गई वहां सेन्टर्स के लिये डिपार्टमेन्ट ने जो चाहा वह उपलब्ध करा दिया। यह किये आज ३ महीने हो गये पर डिपार्टमेन्ट के कान पर जूं तक नहीं रेंगी है। नर्स तो दूर रही वहां दाई भी नहीं गई है।

तो प्राईमरी हैल्थ सेन्टर डेगाना की यह हालत है, नाम बदल गया है पर रूप वही है। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि इसका जल्दी से जल्दी प्रबन्ध किया जाय।

अब हम जनता को केवल नाम बदल कर सन्तुष्ट नहीं कर सकते। जब तक रूप नहीं बदला जाता जनता सन्तुष्ट नहीं हो सकती। एक तरफ आप कह रहे थे कि मकान की व्यवस्था करदो, स्टाफ के रहने के लिये व्यवस्था कर दो, सेन्टर के मकान की व्यवस्था करदो, हमने वह सब व्यवस्था करदी फिर भी आपकी ओर से वहां मेडिसन व स्टाफ की सुविधा की व्यवस्था न हो पायी है।

(श्रीमती गौरी पूनिया)

प्राईमरी हैल्थ सेन्टर डेगाना में दवाई के लिए कोटा अधिक नहीं मिलता है। जीप का प्रोविजन है लेकिन जीप के कब दर्शन होंगे, पता नहीं। इस ओर मन्त्री महोदय से यही आशा करूंगी कि वे जल्दी से जल्दी ज्यादा देंगे।

दूसरा जो मेरा कटौती प्रस्ताव है वह है चलती फिरती सर्जिकल यूनिट के लिये। अभी एक माननीय सदस्या ने इसका सुन्दर रूप बताया है और मैं इस के लिये रिपीटिशन नहीं करूंगी। इसमें मेरा केवल मात्र इतना ही सुझाव है कि सर्जिकल युनिट की जगह मेडिकल यूनिट कर नाम दिया जाय। छोटी छोटी यूनिट हो जिससे गांवों को अधिक लाभ मिल सके। १५ वर्ष हो गये किन्तु चिकित्सा की यह स्थिति है। मेरी पूरी तहसील में मैडिकल की कोई पूरी व्यवस्था नहीं है। जब दो चार महीनों में उधर जाने का अवसर मिलता है तो पचास साठ गांवों का दौरा करने पर भी, दो सौ मरीज ऐसे मिलते हैं जिनको देख कर बड़ी दया आती है, करुणा आती है पर उनको अस्पताल में कैसे भेजें? और उनके लिए दवाई का प्रबन्ध कैसे किया जाय? सभापति महोदया, यदि इस ओर अब तक कुछ न कर सके तो कम से कम अब तो मेडिकल डिपार्टमेन्ट इस ओर ध्यान दे। हर जिले में मेडिकल यूनिट का प्रबन्ध हो जाय जिससे १५ दिन के अन्दर प्रत्येक गांव में वह यूनिट दौरा करे और वहां इस प्रकार के बीमारों को हास्पिटल पहुंचावें।

तीसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव मांग संख्या १७ पर है ग्राम जलप्रदाय योजना की जो शिथिल गति है उसके लिए है यह कहा जाता है कि इस पर काफी रुपया खर्च होता है। पता नहीं कहां खर्च होता है। मेरी तहसील में ऐसे कुए हैं जहां पर खारा पानी होता है। पंचायत समितियां रुपया देती हैं कुआ खोदने के लिए, कुआ खुदवाने पर भी वहां खारा पानी निकलता है। राज्य सरकार की नीति यह है कि तालाब के लिए रुपया नहीं दिया जाय क्योंकि उनका पानी पीने से बाले निकलते हैं। माननीय सभापति महोदया, मैं जानना चाहती हूं कि पानी जैसी चीज जिसके बिना लोग जिन्दा नहीं रह सकते क्यों नहीं लोगों को उपलब्ध की जाय। चाहे तालाब का ही पानी हो लोग उसको छान कर या और कुछ कर पी लेंगे लेकिन उसके बिना तो जिन्दा नहीं रह सकते। राज्य सरकार की इस ओर ऐसी क्या कठोर नीति है? क्यों नहीं उसको थोड़ा लचकदार बनाया जाता है। सरकार को अपनी नीति को बदलना चाहिये जिससे लोगों को पानी पीने के लिए मिल सके।

माननीय सभापति महोदया, ८–१० कुए ऐसे हैं जहां नीचे पत्थर हैं, चट्टानें निकल आयी हैं। गांव वाले प्रयत्न कर चुके हैं और वे प्रयत्न करते करते हार चुके हैं। इस ओर कई प्रार्थना-पत्र भी भेज दिये। मंत्री महोदय से इस सम्बन्ध में बात करते हैं तो कहते हैं कि बौरिंग मशीन है उसको काम में लेना चाहिये। उनसे चट्टानें तोडी जा सकती हैं लेकिन उनको काम में लाना कठिन है। गरीब लोग इतना खर्चा नहीं कर सकते हैं। गांव गांव में धनवान लोगों ने अपने पीने के पानी के लिए व्यक्तिगत रूप से टांके बना लिये हैं जिनमें पानी इकट्ठा कर लेते हैं लेकिन गरीब लोगों को दस दस मील दूर जाकर पानी लाना पड़ता है, चट्टानें उनसे टूटती नहीं हैं और वे साल भर तक दुखी रहते हैं। मैं माननीय मंत्रीजी का

(श्रीमती गौरी पूनिया)
इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि गांव गांव का सर्वे करवा कर पीने के पानी की समस्या हल करें। चाहे आप गांव में स्कूल और कोऔपरेटिव की व्यवस्था न करें, उनको चाह भी नहीं है, दूर भी बच्चे जाकर पढ सकते हैं, लेकिन पानी जैसी चीज जिसके बगैर आदमी जिन्दा नहीं रह सकता, उसकी व्यवस्था १५ साल में राज्य सरकार नहीं कर सकी है तो क्या कर सकी है? हर गांव का सर्वे करवा कर हर गांव में पीने के पानी की व्यवस्था होनी ही चाहिये।

मैं आशा करती हूं कि मेरे तीनों कटौती के प्रस्तावों का जवाब जरूर मिलेगा। नहीं मिलेगा तो इतना समझूंगी कि दिये तले सदा अन्धेरा ही रहता है। सम्बन्धित मन्त्री हमारे उधर के हैं और अन्धेरा ही रखना चाहते हैं तो अच्छी बात है।

श्री सभापती : श्री विजयपाल।

एक माननीय सदस्य : मेरे कट मोशन्स हैं, मुझे समय नहीं दिया जा रहा है। मुझे टाइम दिया जाय।

श्री सभापती : आपके दल की ओर से जो नाम दिये हैं। उसमें नहीं है।

श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर सु.) : सभापति महोदया, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण भी देखा और पढा। बजट भाषण भी मैंने पढा व देखा। हर आदमी यह बोल रहा था कि गरीबों को आगे बढाया जाय। आज गरीबों की क्या स्थिति है थोडा सा आपके सामने वक्तव्य दे देना चाहूंगा।

गरीब पहले से दिक्कतों से निकल कर महसूस करता था कि गांधीजी के सिद्धान्तों के अनुसार उनकी मान्यताओं के अनुसार हमको ऊंचा लाया जावेगा। आज इन आदिवासियों को सरकार बिल्कुल भूलती जा रही है। जब मौका आता है उस समय आदिवासियों को गरीब लोगों को आगे नाम लगा कर पुकारा जाता है लेकिन जब काम निकल जाता है तब असली रूप धारण किया जाता है और उनको पछाड दिया जाता है। सबसे ज्यादा खराब रवैया डूंगरपुर के लोगों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। लोग यह महसूस कर रहे हैं कि राजा महाराजाओं के राज्य थे, उनके समय में अच्छी सुविधा थी सिर्फ कुछ वैठ बेगार करनी पडती थी। आज श्रमदान करना पडता है, कानून के द्वारा श्रमदान लिया जा रहा है। क्या यह प्रजातन्त्र है? क्या यह गांधीजी की नीति है? यह गांधीजी की नीति नहीं है। यह तो कोसों दूर चली गई। माननीया सभापति, सरकार का ध्यान आपके द्वारा आकर्षित करना चाहूंगा। संविधान के अनुसार आदिवासियों को सुविधा दी है सरकार ने पिछडे हुए वर्गों को आगे बढाने के लिए संविधान के अन्दर जो प्रावधान दिये हुये हैं उसका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन इस प्रावधान के अनुसार आज कोई भी चलने के लिए तैयार नहीं है।

मेरा कट मोशन डूंगरपुर अस्पताल में जो अव्यवस्था फैली हुई है उस पर है। मैं डूंगरपुर अस्पताल में १५ रोज तक बीमार रहा हूं। वहां स्थिति है कि खाने की, रहने की और पीने की कोई अच्छी सुविधा नहीं है। गरीबों को दवाई के लिए बाजार में भेजा जाता है। गरीबों को आने से रोका जाता है। भर्ती नहीं किया जाता है। फीस ली जाती है। क्या यह गांधीजी का स्वराज्य है? यह गांधीजी का शासन है?

(श्री विजयपाल कटारा)

क्या यह प्रजातन्त्र का शासन है ? प्रजातन्त्र नहीं है। मखौल के तरीके से आदिवासियों पर कुठाराघात किया जा रहा है। इसलिए अधिक से अधिक अस्पतालों की ओर ध्यान रखा जाय। कहा जाता है कि दवाखाने खुलने के लिए मकान दीजिये ताकि अस्पताल खुलेंगे। कुछ नहीं। श्रमदान से ही खुलेंगे। यह प्रवृत्ति पहले नहीं थी। सरकार यह कहती है कि अस्पताल और शिक्षा के लिए स्कूल के लिए श्रमदान देना होगा। आज गांव गांव में घर घर के अन्दर लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। आज पंचायती राज्य होने से गांव में कई प्रकार के ग्रुप हो गये हैं। भवन अधूरे रह जाते हैं। एक सरपंच हिम्मत करके आगे जाता है तो दूसरी पार्टी सहयोग नहीं देती है। सरकार से निवेदन है कि स्कूल और अस्पताल के भवन तो बिना श्रमदान से ही बनाने चाहियें।

शहरों के अन्दर श्रमदान नहीं लिया जाता है अब वहां ज्यादा से ज्यादा फेसीलिटीज दी जाती हैं। ज्यादा से ज्यादा सरकार ने शहरों की ओर ध्यान दिया है आदिवासियों के लिये कुछ नहीं किया है। उनको ज़िन्दा रहने के लिये भी दवाई उपलब्ध नहीं है। दवाइयां भी उन लोगों को मिलती है जो पैसे वाले हैं। हर अधिकारी गांव की ओर पहुंचता है आपका बी. डी. ओ. कलक्टर सब जाकर कहते हैं आप वालन्टियर कोर्स के अन्दर भरती हो जाइये। इसके लिये पंचायत समिति लेवल पर और ज़िला लेवल पर कमेटियां बना रखी हैं राजस्थान लेवल पर न मालूम क्या बातें होती हैं इन सब कार्यवाहियों में डूंगरपुर सब से आगे है लेकिन जो कुछ कठिनाइयां वहां की जनता में, वहां के आदिवासी लोगों को हैं इन कठिनाइयों को कोई सुनने के लिये तैयार नहीं।

जहां तक तकावी देने का सवाल है वहां पर आदिवासी लोगों को कम मिलती रही है। आज जब फौज में भरती होने का सवाल आता है तो उन लोगों को भर्ती के लिये कहा जाता है लेकिन और सुविधायें सरकार की ओर से नहीं मिलती है। अस्पताल के अन्दर पूरी सुविधा नहीं। लोग सर्विस करने वाले लोगों का अपॉइन्टमेन्ट हो जाता है लेकिन चार पांच रोज तक फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए अस्पताल के चारों ओर चक्कर काटने पडते हैं फिर भी नहीं दिया जाता। मैं डूंगरपुर अस्पताल के अन्दर पन्द्रह दिन तक रहा मैंने वहां की हालत देखी वहां जो भोजन खाने के लिये दिया जाता है व खुराक दी जाती है भोजन के अन्दर कंकर, रोटी के अन्दर कंकर, दूध पानी मिला हुआ दिया जाता है। जब मैंने कहा यह दूध और भोजन इस प्रकार का क्यों मिलता है उनका कहना है कि हम क्या करें हमें तो आदेश ही इस प्रकार के दे रक्खे हैं। सभापति महोदया, मैं मंत्री महोदय को पूछना चाहूंगा कि यह जो इस प्रकार की बातें होती हैं उसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

(२.४० म.प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अब महोदया नहीं महोदय आ गये हैं उपाध्यक्ष महोदय कहिये।

श्री नरेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : इन्हें कोई फर्क नजर नहीं आया।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह आपकी अक्ल का नमूना है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी और मेरी अक्ल एक सी ही है।

श्री विजयपाल : सीमलवाडा और बीछीवाडा एक व्यापारियों का कस्बा है, वहां पर कोई अस्पताल की व्यवस्था नहीं है। डाक्टर साहब तो सीमलवाडा पंचायत समिति की जीप में बैठकर गर्मियों में घूमते रहते हैं। गरीजों को कोई संभालता नहीं। मरीज आते हैं, बेचारे पडे रहते हैं। सरकार की तरफ से इनके लिये कोई ध्यान नहीं है।

बीछीवाडा के अन्दर दवाई का प्रबन्ध नहीं वहां के लोग दवाई लेने के लिये डूंगरपुर आते हैं। तो मैं उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का ध्यान इन अस्पतालों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासियों को मुफ्त में अच्छी दवाईयें देकर के उनको अधिक से अधिक सुविधा दी जाय ताकि वे भविष्य में आगे बढ सकें। जिसका स्वास्थ्य अच्छा होगा या वह देश के लिये अच्छी तरह से लड भी सकेगा, हिम्मत रख सकेगा यही मेरा निवेदन है।

श्री लक्ष्मीचन्द (पीपलदा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी इस चिकित्सा के संबन्ध में कट मोशन है। इसके बारे में मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य बहुत कुछ कह चुके हैं इस विषय में मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। चिकित्सा के बारे में मैं कहूंगा कि हमारे यहां डाक्टरों की बहुत कमी है मैं इस बारे में एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा।

कोटा में सरकारी अस्पताल है डाक्टरों की कमी के कारण वहां पर मरीज अपना इलाज नहीं करा सकते अतः उनको प्राईवेट अस्पतालों में इलाज कराने जाना पडता है। मैं आपसे निवेदन करूं मन्नालाल नाम का एक काश्तकार था वह बेचारा अस्पताल में भर्ती होने आया उस मन्नालाल को वहां भर्ती नहीं किया गया उससे कहा गया कि कल आओ। जब वह दूसरे दिन गया तो उससे कहा गया कि मेरे घर आओ इस तरह से उसकी दुर्दशा होती रही। फिर उसने दूसरे दिन डाक्टर साहब के घर जाना उचित समझा और वहां गया। मैं अपने घर पर तुम्हारा इलाज शुरू करूंगा पचास रुपये फीस के लाओ। उस बेचारे ने पचास रुपये दे दिये वह इसलिये कि उसने सोचा कि इससे जल्दी इलाज हो जायगा। उसके पचास रुपये फीस देने पर भी आज दिन तक वह ठीक नहीं हुआ अस्पताल में पडा हुआ है। इस तरह के बहुत से उदाहरण हैं जिनसे डाक्टर लोग फीस लेते हैं और उनका इलाज नहीं करते। अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं लेकिन वहां पर खाने को ठीक भोजन नहीं मिलता। दूध में पानी मिला कर दिया जाता है अस्पताल से मिलने वाली दवाइयां भी ठीक समय पर नहीं दी जातीं। उनसे फीस लेकर भी दवाइयां बाहर से मंगवाई जाती हैं।

इसी तरह से जो औरतें डिलीवरी के लिये अस्पताल में जाती हैं उनको भी ठीक तरह से देखा नहीं जाता। डिलीवरी के लिये रुई आदि भी उन्हीं से मंगाई जाती हैं। जो सरकार समाजवाद का नारा लगाती है उसके राज्य में अस्पतालों की यह हालत है। दो दो हजार की आबादी पर आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का था लेकिन आयुर्वेदिक औषधालय भी नहीं और इस तरह से मरीजों को कोई सुविधा नहीं। कोई बीमार पडता है तो उसको दवाई के लिये दस दस मील दूर जाना पडता है। गरीब जनता इतना पैसा खर्च नहीं कर सकती, ८० प्रतिशत काश्तकार जो गांवों में रहते हैं उनके लिये कोई सुविधा नहीं। मेरा निवेदन है कि गांव की

(श्री लक्ष्मी चन्द)
जनता के लिये आयुर्वेदिक औषधालय खोले जायं।

आथाना ग्राम में आयुर्वेदिक औषधालय के लिये भवन है लेकिन वहां अस्पताल के लिए सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। उसके लिये कोई धन राशि सरकार द्वारा मन्जूर नहीं की गई। इसका क्या कारण है ८० प्रतिशत जनता जो आपको सब से ज्यादा टैक्स देती है उसकी सुविधा के लिये आप अस्पताल नहीं खोल सकते। आप टैक्स बढ़ाते समय उनसे पैसा मांगते हैं लेकिन शहर की जनता के लिये अस्पताल, स्कूल आदि किसी के लिये पैसा नहीं मांगते। और गांवों में यदि स्कूल, अस्पताल खोलने होते हैं तो कहा जाता है कि उसके लिये भवन बनाकर दो। इसलिये मेरा निवेदन है कि गांव की जनता को जो तकलीफ है उसको दूर करने के लिये सरकार की तरफ से योजना बनाई जाय।

मैं इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी पंचसाला योजना में ३८१ बैड्स अधिक लगाकर हैल्थ डिपार्टमेन्ट ने बहुत बडा गौरव लिया है और वह गौरव यह कि सारे भारतवर्ष के जितने ६०।६१ के टारगेट थे उनको उन्होंने ५९ में ही पूरा कर लिया।

सारे भारत के टारगेट्स में जहां २९ अस्पताल की बात थी ५९ में ३४ अस्पताल पर मिलियन लाकर बडा भारी गौरव राजस्थान ने लिया लेकिन इस गौरव के अन्दर जो पोल है उसे मैं प्रकट करना चाहूंगा। अगर राजस्थान के क्षेत्रफल को देखें और राजस्थान की पापूलेशन को देखें तो भारतवर्ष के अन्दर सबसे बडा दूसरा नम्बर का क्षेत्रफल का राज्य राजस्थान आता है। जहां जैसलमेर के अन्दर ९ आदमी प्रति मील बसते हैं वहां अलवर और अजमेर में ३२९ व्यक्ति प्रति मील की डेन्सिटी भी है।

इसके अतिरिक्त १,३१,९४३ मील राजस्थान का क्षेत्रफल है और दो करोड से अधिक की पापूलेशन है। इसमें डिस्पेन्सरीज और अस्पतालों को बांटा जावे तो सैंकडों मील में एक अस्पताल आता है और हजार आदमी के पीछे एक अस्पताल आता है और फिर शहरों और देहातों में बढती हुई पापूलेशन भी एक समस्या बनती जा रही है। डेन्सिटी आफ पापूलेशन भी अब बढती जा रही है। मिसाल के तौर पर मैं निवेदन करूं कि गंगानगर में यह १० लाख है। पिछली सेंसस में यह ६ लाख थी। सबसे अधिक पापूलेशन गंगानगर जिले में बढी है। ६४ प्रतिशत बढी है। जिस अनुपात में आबादी बढी है उस अनुपात में नये अस्पताल और डिस्पेन्सरियां नहीं खोली गई।

उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य का मामला एक बहुत जरूरी मामला है। दो बहुत बडे विषय हैं जिनका उल्लेख संविधान में भी आया है; एक है चिकित्सा का और दूसरा है शिक्षा का। इन दो की अवहेलना करना संविधान की अवहेलना करना है।

यह ठीक है कि आज हमारे अस्पताल हैं, पर आज उनकी जो हालत है उसको देखते हुए अगर उनको बूचडखाना कहा जाय तो बुरा नहीं होगा। इनको आज बूचडखाना कहा जा सकता है। मैं अपनी तकरीर के दौरान यह स्पष्ट करूंगा और कुछ बूचडखानों का चित्र प्रस्तुत करूंगा।

इसके साथ साथ मैं यह अर्ज कर दूं कि आज बीमारियों से लडने के लिये हमें जगह जगह

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

हर विषय की लेबोरेटरियां खोलना जरूरी है जिससे कि एकेडेमिक बीमारियां, मलेरिया, Small Pox टी. बी. आदि की बेक्टेरियोलोजी और जर्म्स की रिसर्च की जा सके, उनको कन्ट्रोल करने का आसान और सरल तरीका निकाला जा सके पर इस सम्बन्ध में इस सारे बजट में दुर्लक्ष्यपूर्ण नीति रही है। जितना पैसा दूसरी प्लान में इन लेबोरेटरियों के लिये दिया गया वह यूटीलाइज नहीं कर सके, दूसरी प्लान में १०.७४ लाख रखा गया था। जिसमें से ४.४३ लाख यूटीलाइज कर सके और कुल लेबोरेटरीज दस थीं। इसके अतिरिक्त दूसरी योजना में भी ८.५ लाख प्रोवाइड किया है। इसके साथ साथ टी. बी. के नये नये बेड्स खोलने के नाम पर जो रवैया है वह भी देखा जा सकता है।

प्रश्न यह है कि सरकार हरेक व्यक्ति के लिये चिकित्सा सुलभ बनावे, कारगर बनावे। बडे बडे शहरों में रहने वाले कई अपने को डाक्टर कहने वाले आंखों के आपरेशन करने के लिये अपने हथियार लेकर गांवों में आ जाते हैं और हजारों की आंखें अन्धी करके चले जाते हैं। पर आई स्पेशिलिस्ट अस्पतालों म बैठे रहते हैं सरकार के। उन्होंने कोई इन्टेन्सिव केम्प राजस्थान में नहीं किया।

मलेरिया के इरेडिकेशन के लिये सात यूनिट कायम किये गये हैं। कहा गया कि एक लाख रुपयों की गोमेक्षिन मेगाफीन पानी में बह गई ५९-६० में। ६१-६२ में भी बह गई जिसके सम्बन्ध में कहा गया कि वारिश में बह गई। कोई वहां गोदाम था कि वह बाढ़ आई और बह गया। मैं इस बात में निश्चित रूप से कहता हूं कि वह बह नहीं गई, पर जो दवाई मच्छरों को मारने के लिये काम आनी चाहिये थी, वह बाजारों में बेच दी गई।

उपाध्यक्ष महोदय, रूरल और अर्बन में गन्दगी दूर करने का सवाल आता है। इनसे पैदा होने वाली डिजीजेज के इरेडिकेशन का सवाल है। इस बारे में मैं निवेदन करूंगा कि इस बारे में सरकार ने क्या किया? मैं गंगानगर का ही उदाहरण दूं। वहां एक गड्ढा बना हुआ है। गन्दा पानी उस गड्ढे में एकत्रित हो जाता है। शुगर मिल्स के मौलेसेज भी इसी स्लम्प में जाते हैं, शहर की गन्दगी भी इसी में जाती है वाटर वर्क्स का पानी भी इसी गढे में जाता है और शहर का सारा गन्दा पानी भी इसी में जाता है। वार्ड १८ और १० में पांच हजार आदमी इस गन्दे पानी के टैंक के चारों तरफ रहते हैं जिसमें से ६० प्रतिशत से अधिक बीमार रहते हैं। मच्छरों से और गन्दगी से और इनसे पैदा होने वाली बीमारियों से वे लोग हैरान हैं। यह पानी जो आज हजारों लोगों को नरक में भेज रहा है वही पानी कृषकों के लिये बहिश्त हो सकता है। यहां से थोडी दूर अबोहर में मंडी है जिसमें बाकायदा ड्रेनेज है और लाखों रुपयों में वहां का वह पानी बिकता है और लाभ होता है और कृषक पैदावार करते हैं। गंगानगर में यह ड्रेनेज लोगों को बीमार करने के काम आता है।

उपाध्यक्ष महोदय, यही हाल बीकानेर का है। चालीस साल से बीकानेर के अन्दर खाद इकट्ठा हो रहा है और लाखों टन की तादाद में हो गया है। बीकानेर से नजदीक सूरतगढ़ में एशिया का सबसे बडा कृषि फार्म है, अगर इस मैले को वहां तक पहुंचा दिया जावे ड्रेनेज सिस्टम से, तो लाखों मन अनाज अधिक पैदा हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब आपका ध्यान चन्द बूचडखानों की तरफ दिलाना चाहता हूं जिनके अन्दर जल्लाद काम कर रहे हैं।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

गंगानगर का ही एक बूचडखाना मैं ले लेता हूं। वैसे तो सारे राजस्थान में यह परम्परा है कि डॉक्टर प्राइवेट प्रेटिक्स करते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि उनके घर पर लोग जावें और इलाज करावें। मैं और इस सदन के एक माननीय सदस्य एक डाक्टर के पास जयपुर के अस्पताल में गये। वे सदस्य भादरा से आने वाले थे। उन डाक्टर ने एक चिट लिखी जिसमें कि एक्सरे और ब्लड अनेलिसिस के लिए एक प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन को लिखा। तीस-चालीस रुपया देने के बाद यह ब्लड एग्जामिन हुआ और एक्सरे हुआ। जब कि अस्पताल में ही इसका सेन्टर है, इसकी व्यवस्था है और बहुत थोडे खर्चे में वहां हो सकता है। पर डाक्टर साहब प्राइवेट फर्म से कराना चाहते हैं। यही गंगानगर में हाल है। मेडिकल जूरिस्ट के एक केस में एक्सरे की प्लेट पकडी जाती है और विजयनगर के डाक्टर बंसल थ जिसके खिलाफ सैशन्स कोर्ट तक ने स्टिक्चर पास किये हैं जिसमें साफ कहा गया है कि इसमें प्लेट ही बदल दी गई है। वहां के डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर को यह लिखा गया कि आप इसकी इन्क्वायरी करें और सम्बन्धित कुसूरवार को सामने लावें। पर इसको छः महीने गुजर गये। कोई इन्क्वायरी नहीं की गई। गंगानगर के इसी अस्पताल के अन्दर कैरी गांव का एक गरीब इन्सान आया, जिसको तीरवीं गांव वालों ने मार मार कर चियडा कर दिया। वह बीमार शैया पर था। पर उसका इलाज करने से पूर्व डाक्टर साहब ने उसकी जिन्दगी का सौदा ५०० रु० में किया। यह है डाक्टर कल्ला। उसने कहा कि अगर पांच सौ रुपया दे दोगे तो मैं इसको बचा दूंगा। इन अस्पतालों में, इन समाजवाद का नारा लगाने वालों के स्वराज्य में इन्सान का मृत्यु शय्या पर चांदी के चन्द टुकडों में उसकी जिन्दगी का सौदा होता है। राजस्थान के अधिकतर अस्पतालों में ऐसा ही होता है। वह इन्सान मर गया और जो पंचायत चल रही है उसने वे ५०० रुपये वापिस मांगे मगर वह वापिस नहीं देता है। यह तो क्या दोपहर और सुबह अस्पताल के आगे एक लम्बी क्यू लगी होती है और उस क्यू में सौ सौ आदमी खडे होते हैं। मरीज मलेरिया से पिटे हुए, जिन्दगी से मायूस और वहां के डाक्टर कल्ला अपने पास के बंगले में चले जाते हैं और अपनी प्राईवेट फीस लेकर प्राईवेट पेशेन्ट्स को देखते हैं। एक आर०ए०सी० की थर्ड बटालियन के डाक्टर कल्ला हैं। हमारे माननीय गृह मंत्री जी वहां हो आये हैं और वे एक एक जवान से मिले हैं। वहां जवानों से पूछा गया कि तुमको डाक्टर ने कितनी दफा देखा तो आर० ए० सी० के जवानों ने कहा कि ३ माह हो गये कोई डाक्टर हमें देखने नहीं आया और वह डाक्टर नागपाल है उन्होंने रायसिंहनगर में एक प्राईवेट डिस्पेन्सरी खोल रखी है। हमारी उस आर० ए० सी० के थर्ड बटालीयन में ८०० जवान हैं। वह डाक्टर साहब मुश्किल से महीने में ५० जवानों का भी इलाज नहीं करते। वे लोग जो सीमा के प्रहरी हैं, वे लोग जो बर्फीले हिमालय की पहाडियों पर रक्त बहा रहे हैं उनके ऊपर भी तरस नहीं आता, इस मेडीकल डिपार्टमेन्ट को। प्राईवेट प्रेक्टिस करते हैं। आप आर० ए० सी० का रेकार्ड उठाकर देख लीजिए कि आज आर० ए० सी० का हर जवान सिविलियन डिस्पेन्सरी में जाकर वहां इलाज कराता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी का टाइम है उसमें काट लिया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, एक फैक्ट्री एरिया के अन्दर एक कैमिस्ट को

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

लाइसेन्स दिलवा दिया। उसके पास कोई दवाइयां नहीं हैं, उस कैमिस्ट की दुकान में। लेकिन उसको बाकायदा लाइसेन्स दिलवा रखा है। कोई भी शख्स दवा की चिट्ठी लेकर आये तो पर्टीकुलर कैमिस्ट का नाम बताया जाता है। अगर वहां से दवाई न लें तो उसके बाद उसका इलाज नहीं किया जाता और उसको भगा दिया जाता है। कोई भी शख्स प्राईवेट इलाज डाक्टर से नहीं कराये तो उसका इलाज नहीं किया जाता।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर मेडिकल डिपार्टमेन्ट और उससे संबंधित मंत्री महोदय इस संबंध में जांच करना चाहें, जैसी कि मैं आशा करता हूं कि वह अवश्य ऐसे गम्भीर मामले की जांच कराना चाहेंगे, तो मैं अधिक तथ्य इस संबंध में पेश कर सकता हूं जो कि मेरे पास हैं। मैंने कुछ मोटी मोटी बातें और तथ्य आपके सामने उपस्थित किये हैं।

अब मैं एक चीज अर्ज करूं कि जो सबसे बड़ी आवश्यकता हमारी है और राष्ट्रीय संकट के समय है कि हमें इन्जीनियर्स और डाक्टर्स चाहिएं। इन दोनों के प्रति राजस्थान सरकार का बड़ा दुर्लक्षपूर्ण व्यवहार है। जहां २·२ करोड़ रुपया टैक्नीकल एज्यूकेशन के लिए था वहां उसको १.५ करोड़ कर दिया और एकेडेमिक जिसमें भारत नाट्यम होता है उसमें १८ लाख रुपये को बिलकुल नहीं छेड़ा है। लेकिन टैक्नीकल कोर्स को स्ट्रेन्थन करने के लिए उसको बड़ी बेरहमी से काट दिया गया। इसी प्रकार डॉक्टरों के विषय में जरा देखिये कि राजस्थान में कितने डाक्टरों की जरूरत है और कितने डाक्टर आप प्रोवाइड कर सके हैं। हमारी रिक्वायरमेन्ट १३५४ डाक्टरों की है वहां हम ५४५ डॉक्टरों को प्रोड्यूस कर सके हैं और इसी प्रोफेशन के लिए जिनकी जरूरत है हैल्थ विजीटर्स जहां ३५० की जरूरत है वहां हम २०० ही प्रोवाइड कर सके हैं, नर्सेज एण्ड सिस्टर्स की जहां ४२२ की जरूरत है वहां हम ४९९ प्रोवाइड कर पाये हैं इसमें तो जरा ठीक है, कम्पाउन्डर्स जहां ९५४ चाहिएं वहां ८०० हैं सैनीटरी इन्सपेक्टर्स ३४५ की जरूरत है वहां हम २१५ ही प्रोवाइड कर सके हैं, ऑग्जीलियरी एण्ड हैल्थ सर्विसेज में ६९६ चाहिएं लेकिन हमारा आउट टर्न ३३९ का है।

जो डॉक्टर्स बाहर से अगर आ भी जायें तो ६-६ महीने तनख्वाह नहीं देते, कम्पाउन्डर्स को, कलर्क को तनख्वाह नहीं देते। उनके ग्रेड के रिवीजन पैन्डिग में हैं, जितना मिनिस्ट्रियल स्टाफ है उसके सारे रिवीजन आफ पे स्केल्स और सारे केसेज अण्डर कन्सीडरेशन में हैं और हम डाक्टरों को इम्पोर्ट करने की बात करते हैं। बाहर से डाक्टर इम्पोर्ट करके इस कमी को पूरा करना चाहते हैं। एक हॉस्पीटल हमने ६२-६३ में जरूर खोला टैगोर मैमोरियल के नाम से। पिछले दिनों जिस प्रकार से कॉलेजेज का एक्सटेन्सन किया गया वह हम सब को स्पष्ट है। जहां पहले ८० स्टुडेन्ट्स थे वहां अब १२० कर दिया है। इतने डॉक्टरों से क्या हम अपनी डिमाण्ड को मीट कर सकते हैं। बीकानेर में १०० स्टुडेन्ट्स के लिए कॉलेज खोला है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

२ मिनट-अरबन और रूरल वाटर सप्लाई के लिए जरूर कहूंगा। यह ऐसा मसला है कि जिसके लिए सरकार की नीति बडी दुर्लक्षपूर्ण है और विशेषकर रूरल एरिया के लिए। जिस क्षेत्र से मैं आया हूं यदि आप उस क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों पर जाने का आपको मौका मिले तो आप देखेंगे कि वहां पर पानी की कितनी समस्या है। लूणकरणसर को आप देख लीजिए। वहां शाम को या सुबह पानी की गाडियां आती हैं और

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

बीकानेर से पानी आता है। आज १२ साल हो गए हमारी सरकार ने लूणकरणसर में पानी का कोई इन्तजाम नहीं किया। आज वहां वही की वही स्थिति है। वहां हजारों बच्चे और औरतें इकट्ठी होती हैं और इस संबंध में फिसाद हो जाते हैं, झगडे हो जाते हैं। यही आज राजगढ़ मण्डी की हालत है। कहते हैं कि वहां का पानी खारा है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर एक बोरिंग हुआ था उसके अन्दर मीठा पानी निकला था। लेकिन लूणकरणसर के सेठ नहीं चाहते थे कि वहां पर मीठा पानी आये। वहां के एस० डी० एम० ने इन्क्वायरी की और इन्क्वायरी करके अपनी रिपोर्ट दी कि वहां पर मीठा पानी है। लेकिन वहां कोई कुआ नहीं खोदा गया।

इसके अलावा आप महाजन गांव का उदाहरण ले लें। पूरे महाजन में आपको एक टूटी नजर आयेगी और उसके आगे सैकडों घडे नजर आयेंगे और उन पर नम्बर होगा। वहां पर एक मीठा कुआ है उस पर राजा ने अपना कब्जा कर रखा है और उसमें से जो नल निकलता है वह पहले महाजन के राजा की कोठी में जाता है और फिर गांव में आता है। जब चुनाव होते हैं तो महाजन का राजा अपने यहां कोठी में नल को बन्द कर देता है, जब गांव वालों को उन्हें दबाना होता है तो नल का मुंह बन्द कर दिया जाता है और सैकडों घडे नल के सामने पडे रहते हैं। यह स्थिति है रूरल वाटर सप्लाई की।

मैं अर्ज करूं कि रातानगर क्षेत्र में हजारों मजदूरों को देखो जो राजस्थान कैनाल के अन्दर काम कर रहे हैं। आज ही रिपोर्ट दी है मेडिकल डिपार्टमेन्ट ने कि सूरतगढ में एक मोबाइल हास्पीटल खोला गया है जो कि सूरतगढ क्षेत्र में फिरेगा। यह हजारों किसान जो राजस्थान का भविष्य बना रहे हैं उन लोगों के लिए कोई मेडिकल ट्रीटमेन्ट नहीं है उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। जिस क्षेत्र में वह कार्य कर रहे हैं उसमें दस-दस और पन्द्रह-पन्द्रह मील से पानी लाकर पीना पडता है। मैं अर्ज करूं कि नारे वाले, राजोरी यह वह पंचायतें हैं, आर० ए० सी० के बोर्डर की पोस्टों पर पानी नहीं है। हमारे गृह मंत्रीजी गये थे और उन्होंने खुद भी देखा कि एक पोस्ट से चार-चार पोस्टों पर पानी ले जाया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना कह कर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। आशा है कि आपके कान के कीडे निकले होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पोहूमल।

श्री पोहूमल ईश्वरदास (अजमेर सिटी, पश्चिम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मांग संख्या १६, चिकित्सा के लिए ३ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। पहला प्रस्ताव होमियोपैथी अस्पताल में दिये जाने वाले ग्रान्ट और सरकारी होमियोपैथी अस्पताल में पूरी व्यवस्था नहीं होने के बारे में है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आजकल जनता होमियोपैथी इलाज के लिए तरस रही है और प्रति दिन लाखों की तादाद में होमियोपैथी इलाज के लिए अस्पताल में आते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ संस्थायें सेवा के क्षेत्र में ऐसी हैं कि जिन्होंने यह इलाज होमियोपैथी का उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल खोले हैं। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पडता है कि सरकार की तरफ से उनके योग्य जो ग्रान्ट मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पा रही है। इसके साथ ही जितने सरकार की तरफ से होमियो-पैथिक अस्पताल खोले गये हैं उनमें न तो

(श्री पोहूमल ईशरदास)

क्वालिफाइड डाक्टर हैं न कम्पाउन्डर हैं और आवश्यक दवाइयां भी नहीं होती हैं और मैं उसके लिये एक उदाहरण पेश कर रहा हूं।

अजमेर में कस्तूरबा अस्पताल मदारगेट पर है उसमें एक होमियोपेथिक इलाज का सेक्शन खोला गया है । डाक्टर तो ठीक रखा गया है लेकिन तमाशा यह है कि उसको कम्पाउन्डर एक भी नहीं दिया गया है। मैंने उस डाक्टर को आंखों से देखा है कि वह हर समय बिजी रहता है, वह खुद एक एक मरीज को देख कर दवा लिखता है और दवाइयों की पुड़ियां भी खुद ही देता है अपने हाथ से बांध कर । नतीजा यह होता है कि जो लोग वहां पर दवाई के लिये आते हैं उनको पूरा समय नहीं मिलता है इसलिये वे निराश होकर चले जाते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से नम्र निवेदन करूंगा कि जहां पर होमियोपेथिक अस्पताल खोले जायें ; वहां पर डाक्टर, कम्पाउन्डर और दूसरी ऐसी आवश्यक बातें हैं उनकी व्यवस्था करने का ख्याल रखें और जो संस्थाएं सरकार की मदद कर रही हैं और इलाज जनता के लिये उपलब्ध कर रही ह उनको काफी तादाद में जैसे आयुर्वेदिक औषधालयों को दिया जाता है वैसी ग्रान्ट दी जाय । इस बारे में मैं सरकार से नम्र निवेदन करूंगा कि वह एक सलाहकारी होमियोपेथी बोर्ड बनावे जिससे कि डाइरेक्टर ऑफ आयुर्वेद को होमियोपेथी के बारे में सही सलाह मिल सके ।

मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव सरकार के एलोपेथिक अस्पतालों में जो दवाइयां दी जाती हैं वे पूरी नहीं दी जाती हैं उसके बारे में है । उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर में मैंने देखा है कि दो नये पैसे की टिकिया के लिये या २८ पैसे की पैनिसिलिन के इन्जेक्शन के लिये भी कई बीमारों को केमिस्ट की शाप तक दौड़ना पड़ता है । ऐसी हालत में बीमार को दुःख होता है और उसके रिश्तेदार केमिस्ट के पास जाते हैं उनको भी दुःख होता है । सवाल यह है कि आज जितनी बढ़ी हुई संख्या में बीमार आते हैं उतनी ही तादाद में अस्पतालों में दवाइयां देनी चाहिये क्योंकि दवाइयों के सिवाय कोई बीमार अच्छा नहीं हो सकता । यह कोई मन्दिर मस्जिद नहीं है जहां आशीर्वाद या झाड़ फूंक से मरीज अच्छा हो सकता है । यहां तो दवाइयां ही आवश्यक हैं और ब्लड का तो नाम ही मत पूछो । कोई गरीब बीमार आता है तो कहते हैं ब्लड खरीद सकते हो । खरीदे कैसे वगैर पैसे के । न पैसा है न ब्लड दिया जाता है । नतीजा यह होता है कि बीमार राम राम सत हो जाता है ऐसी हालत में उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि बीमारों की बढ़ती हुई संख्या को देख कर उतनी मात्रा में ही वहां दवाइयां व ब्लड गरीबों को मुफ्त में उपलब्ध करे तो जनता को सहायता होगी ।

तीसरा मेरा कटौती प्रस्ताव अजमेर में मेडिकल कॉलेज न खोलने के बारे में है । उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ कहा जाता है कि हमारे यहां डाक्टरों की कमी है और दूसरी तरफ डॉक्टर को पढ़ाने-सिखाने के लिये कॉलेज खोलने के लिये इन्कार है । यह तो अजीब तमाशा दिखता है । उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जब कोई सदन में युनिवर्सिटी का सवाल आता है तो उसके लिये जोधपुर और उदयपुर उपयुक्त स्थान है । जब कोई एग्रीकल्चर

(श्री पोहूमल ईशरदास)

कॉलेज खोलना चाहते हैं तो उसके लिये भी उदयपुर ही अच्छी जगह मानी जाती है और अजमेर के साथ सौतेली मां का सा व्यवहार करते हैं । मैं कहता हूं कि अजमेर का महत्व खत्म करने के लिये यह सरकार बैठी है । अभी मेडिकल कालेज खोलने के लिये कई बार सवाल आया लेकिन वहां भी लडाई हो रही है, यह जोधपुर में खोलें या अजमेर में । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेडिकल कालेज क लिये जो आवश्यक चीजें होनी चाहियें वे सब अजमेर में मौजूद हैं । वहां बहुत बडा अस्पताल है बहुत बेड्स हैं, मैं कहता हूं कि जोधपुर से ज्यादा हैं, जनाना अस्पताल है, टी० बी० अस्पताल है सब कुछ है पर अल्ला जाने क्या है कि जो अजमेर इससे वंचित रखा जाता है क्यों नहीं वहां मेडिकल कॉलेज खोला जाता है ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं दो मिनिट और लूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा दिखता है कि जो मंत्री बैठे हैं वे आपस में बैठ कर हर चीज का बंटवारा करते हैं……

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री): अजमेर के तीन मंत्री हैं ।

श्री पोहूमल: दुर्भाग्य से अजमेर के जो तीन मंत्री हैं उनको भी छोडने वाला नहीं हूं । वे, मैं जानता हूं जैसा कि जनता, अजमेर की जनता कहती है कि वे अपनी कुर्सी की सुरक्षा के लिये बैठे हैं, अजमेर की जनता को भूल गये हैं, वे अच्छी तरह से अजमेर का ख्याल नहीं करते, अजमेर की मांग नहीं रखते । यही वजह है कि अजमेर में मेडिकल कॉलेज नहीं खुलता है । यदि उन्होंने केवल कुर्सी की ही परवा की और ऐसे ही चले तो मैं उनको आपके द्वारा इत्तला देता हूं कि वह दिन आयेगा जब अजमेर की जनता उनसे बदला चुकायेगी । वित्त मंत्रीजी ने चुनाव की आम सभा में कहा था कि मेरे जीतने के बाद अजमेर में ५० परसेन्ट फायदा तो जिस दिन रिजल्ट आउट होगा उसी दिन हो जायगा । मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, उल्टे ५० परसेन्ट फायदा तो दूर रहा, कॉलेज नहीं खुला सो नहीं खुला लेकिन ज्यादा टैक्स लगा कर आपने अजमेर की जनता का २०० परसेन्ट घाटा किया है और सही बात, जो अजमेर की तरफ से मैं अकेला ही नहीं, वरन् अजमेर की जनता की तरफ से रख रहा हूं कि यदि मंत्रीजी और सरकार ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया तो मैं कहूंगा कि प्रजातंत्र का सही माने में अपघात किया जाता है, खून किया जाता है । इसलिये मुझे और कुछ नहीं कहना पडेगा । यदि हैल्थ मंत्रीजी ने पूरा जवाब नहीं दिया तो मुझे यही कहना पडता है:

> "लाख बार मेम्बर चिल्लाये तो क्या
> होता है, होता वही जो मंजूरे मंत्री
> होता है" ।

श्री देवीलाल (सराडा सु०): सभापति महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव तहसील सराडा ग्राम चावंड में सेकन्ड्री हैल्थ सेन्टर खोलने के बारे में है । सराडा सलूम्बर और खेरवाडा के बीच में सराडा तहसील है । उस तहसील में सेकन्ड्री हैल्थ सेन्टर खोला जाना अति आवश्यक है । यहां पर आदिवासियों की घनी आबादी तो है ही उसके साथ साथ दूसरे गरीब लोगों की आबादी भी है । जहां

(श्री देवीलाल)

से साल भर में कई मरीज उदयपुर या अन्य स्थानों पर ले जाने पडते हैं तब काफी खर्चा उनको उठाना पडता है और ऐसी स्थिति में गरीब जो हैं वहां पर नहीं जा सकते उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे कई व्यक्ति टी० बी० के मरीज हैं। कई औरतें जो वहां पर प्रसूति गृह की व्यवस्था नहीं होने की वजह से मौत के घाट उतर जाती हैं। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि वहां पर सैकन्ड्री हैल्थ सेन्टर की व्यवस्था होनी चाहिये।

मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव है रिषभदेव में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोला है उसके बारे में। अभी अभी सरकार ने इसकी मंजूरी दी है लेकिन वहां पर डॉक्टरों की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है और ना कोई दूसरी व्यवस्था की गई है इसलिये मेरा निवेदन है कि यहां पर भी यह व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र कराई जावे।

हमारे यहां डाक्टर भी नहीं हैं काफी अर्से से नर्स भी नहीं हैं। नर्स की भी व्यवस्था होनी चाहिये। दूसरे, सराडा का पुराना अस्पताल है, उसमें भी दवाओं की बहुत कमी हैं। कई मरीजों को दवाइयां नहीं मिलती है और इन्जेक्शन भी दूसरी जगह से उन्हें खरीद कर लाने पडते हैं। तो यह व्यवस्था आदिवासी क्षेत्र में कम से कम गरीब लोगों के लिये व्यवस्था की जानी चाहिए कि अगर एक-दो इन्जेक्शन्स की जरूरत पडे तो अस्पतालों में ही उनकी व्यवस्था हो जाय। दूसरे यह है कि यदि उन्हें इन्जेक्शन खरीदने के लिए कही जाय तो इन्जेक्शन की सही कीमत क्या है, यह उन्हें बता दिया जाय। तीसरे मैं डॉक्टरों की फीस के बारे में कहना चाहता हूं कि गरीब आदमियों के लिए यह खास व्यवस्था होनी चाहिए कि उनसे फीस नहीं ली जानी चाहिए। इसके अलावा वहां पर आयुर्वेदिक औषधालय हों, जिससे जो आदिवासी जनता है, उसके पंचायत क्षेत्र में औषधालय हो तो वे वहां से दवा ले सकें यह भी व्यवस्था नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वे उस क्षेत्र में यह व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री चन्द्रसिंह बर्फा।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाडा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पहला कटौती प्रस्ताव डिमान्ड नम्बर १६, मेजर हैड २७–मेडिकल पर है:

"to discuss on purchasing Scheme of medicines and surgical Equipments & Instruments."

सैकिन्ड मेरा कट मोशन है:

"Demand No. XVI, Major Head 29-Medical be reduced by rupee one(to discuss on Accommodation and diets for patients in Hospitals).'

उपाध्यक्ष महोदय, जैसी कि हमारे भारतवर्ष की और राजस्थान की परम्परा रही है उस परम्परा के आधार पर हमारी जनता शासकों के प्रति सदैव और आज भी वफादार है और वफादार रहेगी, ऐसा मान कर हम चलते हैं; परन्तु इस वफादारी को समाजवाद के साथ में जोड कर जब इस हाउस के अन्दर या और कहीं बाहर भी हमारी सरकार यह नारा लगाती है और यह बडे गौरव के साथ कहती है कि समाजवाद पनप रहा है। मैं

(श्री चन्द्रसिंह बर्फा)

कहता हूं कि समाजवाद नहीं पनप रहा है, यह हमारी वफादारी का नतीजा है, यह हमारी वफादारी है कि इनके साथ जुट कर, कन्धे से कन्धा मिला कर काम करने के लिये बैठे हैं। लेकिन यह जो वफादारी है इस वफादारी को हम कब तक करते जायेंगे ? आज से दस साल के पहले के और आज के रेवेन्यू के आंकडों का अनुपात देखें, तो हम जो गांवों में रहने वाले किसान हैं, खेती करने वाले किसान हैं, जो भारत के अन्नदाता हैं, वे जो रेवेन्यू दे रहे हैं उसका अनुपात उपाध्यक्ष महोदय, लगायें तो मालूम होगा कि यह अनुपात कितना बढता गया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात का विश्वास दिलाऊं कि जिस बारानी जमीन, नहरी जमीन या चाही जमीन पर आज से दस साल पहले बीगोडी थी, पांच साल पहले बीगोडी थी, उससे आज ड्योढी और दुगुनी वसूल करते हैं फिर भी हमारे वित्त मंत्री महोदय ने बडी कुशलता, बडी दक्षता के साथ बजट पेश करते समय पर फिर टैक्स लगाये हैं। उसके बाद सरकारी पक्ष की ओर से बडी दक्षतापूर्ण तरीके से यह समझ कर भाषण दिये गये कि अगर हम टैक्सेज नहीं लगायेंगे तो विकास नहीं कर पायेंगे और विकास योजनायें किसी तरह नहीं चल सकेंगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उदाहरण आपके सामने है, मैं यह कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, जैसा कि माननीय वित्त मंत्री ने भी अपने भाषण में कबूल किया था, मैं उनके दो अल्फाज आपके सामने पढ कर सुना दूं 'तफसीली व्यौरा आंकडों का गोरख धंधा है।' उन्होंने स्वयं ने आंकडों का गोरख धन्धा माना है और आंकडों के गोरख धन्धे के आधार पर हमारे वित्त मंत्री महोदय ने कोई इस बात का अनुमान नहीं लगाया है कि कहां पर क्या होना चाहिए, जनता को क्या सुविधा मिलनी चाहिए। आज देश की संकटकालीन स्थिति का बहाना लेकर हमारे वित्त मंत्री ने हमारे सामने बजट प्रस्तुत किया है, मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने, मैं हास्पिटल्स और डिस्पेन्सरीज के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि ड्रग्स और मेडीशन्स पर १७ लाख ३० हजार का बजट रखा है और आपकी जो रिपोर्ट १९६१-६२ की है उसके अनुसार ऐसे हॉस्पिटल्स और डिस्पेन्सरीज का नम्बर ४९२ है। इसके अलावा एक प्रश्न के उत्तर में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उप-मंत्री महोदय ने यह जवाब दिया था कि अभी तक पांच सौ डाक्टरों की कमी है, ४९२ हॉस्पिटल्स में ५०० डाक्टरों की कमी है। अगर डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल्स बढें, सर्जिकल वार्ड, टी० बी० वार्ड बढें, इसकी क्या उम्मीद की जा सकती है।

दूसरी बात यह है कि जहां विज्ञान के इस जमाने में नये नये यंत्रों द्वारा इलाज ट्रीटमेंट जल्दी और सुविधा के साथ हो सकता है, उपाध्यक्ष महोदय, वहां इक्विपमेंट और इन्स्ट्रूमेंट के बजट में माननीय वित्त मंत्रीजी ने पांच हजार की कटौती की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां हम सरल और सुगम तरीके से स्वास्थ्य रक्षा करने के बारे में सोचते हैं और यंत्र द्वारा, एसे वैज्ञानिक यंत्र हैं, जिनकें द्वारा हमारा इलाज जल्दी हो सकता है, स्वास्थ्य सुधर सकता है वहां कटौती करना हमारे लिए और सरकार के लिए शोभाप्रद नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय अभी

(श्री चन्द्रसिंह वर्फा)

मेरी पार्टी के एक सदस्य बोले हैं, दूसरा नम्बर मेरा है । इसके अलावा कोई बोलने वाला नहीं है, इसलिए चेयर की ओर से जो व्यवस्था दी जा चुकी है····

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलिये, बोलिये ।

श्री चन्द्रसिंह वर्फा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपका ध्यान सरकारी पक्ष और सरकारी कर्मचारियों की मिली जुली नीति की ओर दिलाता हूं । आप देखिये १८ तो मिनिस्टर हैं और ९ हजार ड्रग्स और मेडीशिन्स का खर्चा है । तो पर मिनिस्टर ५०० रुपया प्रति वर्ष खर्चा आता है । इसके मुकाबले में जनता का अनुपात लगायें·········

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): मिनिस्टर ज्यादा बीमार होते हैं ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): चालीस रुपया एक मिनिस्टर पर आता है और बाकी का सैकडों का स्टाफ होता है उस पर होता है आप गलत क्यों कहते हैं ?

श्री विजयसिंह झाला: बीमार नहीं होते हैं तो भी दवा लेते हैं ।

श्री चन्द्रसिंह वर्फा: आप बोलें तो कह दें ।

तो जनता के लिए १९६१-६२ की रिपोर्ट के अनुसार इन्डोर पेशेन्ट के लिए २ लाख ११ हजार रखा था और १०५ हजार आउट डोर पेशेन्ट हैं, इस प्रकार पर हैड जनता, जो बीमार हैं, रोगी हैं, उन पर लगाये तो इस हिसाब से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो छः आदमियों पर एक रुपया सालाना खर्चा होता है । इस प्रकार किस प्रकार हमारे स्वास्थ्य की रक्षा हो सकती है । वर्तमान में कितना खर्चा होता है, मैं मानता हूं कि वित्त मंत्री जी अगर मेडिकल और स्वास्थ्य के ज्यादा आंकडे, जनता के लिए, देश के लिए रखते तो ज्यादा उपयुक्त होता क्योंकि वे स्वास्थ्य ठीक होने पर देश की रक्षा अच्छी तरह से कर सकते थे । इसी प्रकार मैं आपके सामने सेक्रेटेरियट के बारे में निवेदन करता हूं । सेक्रेटेरियट में कुल नियुक्तियां सब मिला कर······

श्री उपाध्यक्ष: आपका कटौती प्रस्ताव क्या है ? आप तो बजट पर भाषण कर रहे हैं ।

श्री चन्द्रसिंह वर्फा: मेडिकल रिलीफ दिया जा रहा है, उसके सम्बन्ध में निवेदन कर रहा हूं····

श्री विजयसिंह झाला: मिनिस्टरों को टॉनिक कितना लेना पडता है, यह अर्ज कर रहे हैं ।

श्री बरकतुल्ला खां (स्वास्थ्य मंत्री): I want to clear the point. No Minister has ever received any tonic from that scheme of re- imbursement.

श्री विजयसिंह झाला: That is only a presumption.

श्री बरकतुल्ला खां: आपको कोई आवश्यकता हो

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य जो पजेशन आफ फ्लोर हैं वे बोलेंगे । दूसरे माननीय सदस्य हस्तक्षेप न करें ।

श्री विजयसिंह झाला: यह तो प्रिजम्प्शन

(श्री विजयसिंह झाला)

है । यह क्लेरीफिकेशन होना चाहिये कि दवा नहीं लेते हैं तो क्या टॉनिक लेते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष: आप प्रारम्भ रखें ।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इनमें कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दवाई की लिस्ट बना कर एक जगह से खरीद लाते हैं, मगर जो गांवों के मरीज किसी हॉस्पिटल में जावें तो उन्हें नित नये इन्जेक्शन का खर्चा लगता है । डा० इन्जेक्शन लिख कर देता है और जिस समय वे लोग बाजार से इंजक्शन लावे तो उनका इलाज हो सकता है । अस्पतालों में जो गरीब लोगों के लिये इंजक्शन भेजे जाते है उनका क्या होता है यह पता नहीं लगता । वहां पर दवाइयों के पैसे खर्च किये जाते है उन दवाइयों का किस तरह से उपयोग होता है उसका तो लेखा जोखा करने वाले ही बता सकते हैं । उपाध्यक्ष,

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

अब मैं होस्पिटल्स के संबंध में कहूंगा कि जिस समय हॉस्पिटल खोलने का समय आता है तो सरकार की तरफ से कहा जाता है कि चन्दा दो, तो हॉस्पिटल खोले जा सकते हैं । हम चन्दा इकट्ठा करके हॉस्पिटल्स के लिये बिल्डिंग बनाते हैं मगर जब हाउस बन जाते हैं तो वहां के लिये डाक्टर और कम्पाउन्डर्स और नर्सेज की व्यवस्था नहीं हो पाती । हमें न तो वहां दवाइयें मिलती हैं न कोई व्यवस्था है । बिल्डिंग बने हुए पडे हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इसमें सुधार किया जाए । उधर टैक्सेज का बोझ बढ गया है और इस कारण राज्य के कर्मचारी और अधिकारी वेतन वृद्धि की मांग करेंगे..

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

चूंकि समय हो गया है, मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि गांव की तरफ हमारी सरकार का ध्यान जाना चाहिये और उनके यहां भी डॉक्टरों व दवाइयों का पूर्ण रूप से प्रबन्ध होना चाहिये ।

श्री लक्ष्मण प्रसाद (सिकराय) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है वह बसें जो मलेरिया दवाइयां छोडना, बुखार की गोली देना व खून टैस्ट करना व माता के टीके लगाने आदि पर फिजूल खर्च होता है उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिये चेष्टा करूंगा । मैंने इस संबन्ध में कई दफा हाउस में प्रश्न प्रस्तुत किये मगर कोई मेरी शंका का निराकरण सरकार की तरफ से नहीं हो रहा है । इसके अलावा मैं यह कहूंगा कि हमारे यहां पर डॉक्टर है वह इतना नशेबाज है कि हमेशा नशे में रहता है और हमेशा अपनी पिस्तोल को साथ लिये फिरता है और किसी का इलाज नहीं करता ।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा कि वहां से एक व्यक्ति का ११ दफे ट्रान्सफर किया गया । यह हमको कहने की जरूरत नहीं कि किस तरह से इतनी बार एक व्यक्ति की ट्रांसफर होती है और फिर वह वहीं आ जाता है । हम यह भी नहीं चाहते कि उसको वहीं रखा जावे । बार बार ट्रान्सफर उसी जगह पर होने से जनता को सन्देह पैदा होता है और उसका पैसा भी बरबाद होता है । इसके अलावा वहां पर डॉक्टर दवा फरोख्त करने वाले को भरतपुर से लाये हैं उनके लिये प्रतिदिन एक केस

(श्री लक्ष्मण प्रसाद)

मुलझाया जाता है और लोगों को उसके लिये बांदीकुई जाना पडता । लोगों को नुकसान होता है । यह संभवतः ठीक नहीं है ।

दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को मलेरिया के लिये काम करने के लिये रखा है वे अपना काम ठीक तरह से नहीं करते हैं । उनका काम यही है कि वे ऊपर के अधिकारियों के लिए अच्छा गांवों से घी, गुड़ आदि लाकर उनके मकान पर पहुंचा दिया करें । लेकिन यह नहीं सोचते कि जिस काम के लिये उन्हें सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है उसकी तरफ वे ध्यान नहीं देते । सिर्फ कुछ पुरुषों का खून ले कर, टैस्ट करके प्लेट बना कर भेज देते हैं । मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के फिजूल खर्चे को रोका जावे जब कि इससे कोई फायदा नहीं होता है ।

इसके अलावा जहां तक मेरी जानकारी है, मैं यह कहूंगा कि आयुर्वेद औषधालय भी सरकार ने उसी तरह से कायम रखे हैं जिस तरह से पुराने जिला बोर्ड के समय थे । मैं सरकार को यह बता देना चाहता हूं कि जो वैद्य जिला बोर्ड में रखे गये थे वे वहीं के रहने वाले थे और गांव २ में उनका दवाखाना था । उनका घर के घर में दवाखाना चल रहा है । मैं यह नहीं कहता कि वे सर्विस ठीक नहीं करते । मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आप उन वैद्यों को जो उसी गांव के रहने वाले हों उनको अपने गांवों में न रखें । पार्टी पोलिटिक्स और दूसरी कई बातें हैं उनको भी मैं मानता हूं । मैं यही कहना चाहता हूं कि जो वैद्य आप रखते हैं उनको उनके गांवों में न रखें जहां वे रहते हैं । क्योंकि वहां पर वे पार्टी पोलिटिक्स में पड जाते हैं और फिर लोगों की सेवा अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं और आयुर्वेद से जितनी दवाइयें उनको मिलती हैं वे सब ब्लेक मार्केट होती हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिये जितनी आयुर्वेदिक दवाइयें मिलती हैं उसका फायदा जनता को मिल सके । जब सरकार किसानों से टैक्स वसूल करती है और रेवेन्यू से भी आमदनी होती है तो मैं यह कहूंगा कि किसानों और गरीब लोगों के लिये हर पंचायत में एक एक आयुर्वेदिक औषधालय जरूर खोला जाय ।

एक माननीय सदस्य : Point of information Sir,

मेरा कट मोशन····

उपाध्यक्ष : मैं आपको सूचित कर दूं कि स्वतन्त्र पार्टी का समय समाप्त हो चुका है और कई माननीय सदस्यों के कट मोशन्स बाकी रहे हैं ।

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कुछ कटौती के प्रस्ताव कुछ गांवों में व शहरों में जल की व्यवस्था के संबन्ध में हैं । सबसे पहले मैं जल के संबन्ध में राजस्थान की जो स्थिति है उसके संबन्ध में निवेदन करूंगा । यह बहुत कटु सत्य है कि जो सरकार जनता केलिये साफ पीन को पानी का इन्तजाम नहीं कर सकती है वह सरकार दूसरी किन चीजों का इन्तजाम कर सकेगी । अगर राजस्थान में कांग्रेस सरकार लोगों को और कुछ नहीं दे सकती है तो सरकार को लोगों को कम से कम शुद्ध पानी पीने को अवश्य देना चाहिये । दो योजनाएं समाप्त हुई हैं, तीसरी पंच वर्षीय योजना में पानी का लक्ष्य रखा गया उसको ध्यान में रखें तो यह मान कर चलना होगा कि हम प्यासे लोगों को पानी नहीं दे सकते । हमने तीसरी पंच वर्षीय योजना में यह रखा कि १०

(श्री रामकिशन)

हजार से ऊपर की जनसंख्या वाले स्थानों पर पानी की व्यवस्था कर देंगे ।

राजस्थान में १० हजार से ऊपर की आबादी के १७२ नगर हैं अगर हम उनको पानी दे देंगे तो इस प्रकार १५ परसेन्ट लोगों को पानी की सुविधा पहुंचा सकेंगे । १० हजार से ऊपर की आबादी का लक्ष्य सरकार ने रखा है लेकिन उसको सरकार २० हजार कर सकती है। लेकिन होता क्या है कि जहां १० हजार की पापुलेशन है या उससे कुछ कम भी हो, जहां उसका राजनीतिक उद्देश्य सिद्ध होता है वहां नल का प्रबन्ध करती है। आज भी बहुत से ऐसे स्थान हैं जो २० या ३० हजार की आबादी के हैं मगर वहां पानी का इन्तजाम नहीं है और लोगों को पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान में पानी के प्रश्न को सबसे पहले लेना चाहिये और पहले उन इलाकों को पानी देने का प्रबन्ध करना चाहिये जो रेगिस्तान में हैं। अलवर और भरतपुर का सवाल है, अगर वहां भले ही आप पानी देर से पहुंचावें । अलवर भरतपुर की समस्या ऐसी नहीं है जैसी बीकानेर और जोधपुर डिवीजन की है और खास तौर से आदिवासी क्षेत्रों में इसका प्रबन्ध होना चाहिये। तो जो लोग शुद्ध पानी नहीं पीते उन्हें नाहरू रोग हो जाता है और जब नाहरू हो जाता है तो वे ही लोग जानते हैं जिनके वह निकलता है। आदिवासी लोग नाहरू रोग से परेशान होते हैं। यों तो सारा हिन्दुस्तान ही इस रोग से परेशान है और पीडित है, मगर आदिवासी लोग ज्यादे परेशान है। इसका कारण यह है कि उनको साफ पानी पीने को नहीं मिलता और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आदिवासियों की क्या हालत है। पिछली साल में मैं आयुर्वेद मंत्री के क्षेत्र में गया था। मैंने देखा कि वहां के लोग उन स्थानों में से, गड्ढों से पानी पीते हैं जहां भेड, बकरी और दूसरे जानवर पानी पीते हैं और पेशाव करते हैं। इसके लिये मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपके पास पैसा नहीं है तो जिस प्रकार सूडान की सरकार ने इस समस्या को हल किया है उसी प्रकार से आप भी करें। वह यही तरीका है कि हमारी भारतीय संस्कृति में दान की परम्परा है। आज हमारे बडे बडे लोग बम्बई, कलकत्ता आदि बडे बडे शहरों में रहते हैं। आप इसके लिये १ करोड का फन्ड बना लीजिये। वह फंड चाहे प्राइम मिनिस्टर के नाम से हो चाहे चीफ मिनिस्टर के नाम से हो बना लीजिये और लोगों से अपील आपको करनी चाहिये कि राजस्थान के लोगों को हम शुद्ध पानी देना चाहते हैं इसके लिये एक करोड का फन्ड रखा है। तो मुझे विश्वास है कि लोग रुपया देंगे। जब राजनीतिक दलों को वे सेठ-साहूकार रुपया देते हैं तो पानी के लिए तो अवश्य पैसा मिल सकता है। उस पैसे को जोधपुर, बीकानेर या आदिवासी क्षेत्र में लगावें तो काफी काम कर सकते हैं। इसलिए एक तो मेरा यह निवेदन है कि इसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिये और अगर हम प्रयत्न करें तो इस मामले को हल कर सकेंगे ।

पूर्वी राजस्थान में शुद्ध पानी का सवाल है, भरतपुर में पानी मिलने का सवाल नहीं है, शुद्ध पानी का सवाल है। वहां पानी फ्लड से खराब हो जाता है, वहां पानी को शुद्ध करने की दवाई आदि का प्रबन्ध कर दिया जाय मलेरिया को रोकने का इन्तजाम कर दिया जाय और इस सम्बन्ध में तृतीय पंच वर्षीय योजना में जो लक्ष्य रखा गया है उस पर दुबारा विचार कर के आगे बढाना चाहिये ।

(श्री रामकिशन)

मेरे कुछ मेडिकल चिकित्सा के सम्बन्ध में प्रस्ताव हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान ही ऐसा राज्य है जो आसाम के अलावा सब राज्यों से पीछे है, जहां दवाइयों की सुविधा नहीं, पानी की सुविधा नहीं। हम यहां दवाइयों पर जोर दे रहे हैं पर पश्चिमी देशों में इस बात पर जोर दिया जाता है कि रोगों को होने से रोका जाय रोग बढ़े नहीं। यहां दवाइयों पर ज्यादा जोर दिया जाता है, रोग बढ़े नहीं इस पर जोर नहीं दिया जाता। हमारे यहां टिटेनिस, तेज बुखार, ये रोग नये पैदा हुए हैं। तो ये रोग क्यों पैदा हो रहे हैं इनकी पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिये और इनको रोकने की सरकार को कोशिश करनी चाहिये।

मैं औषधियों और चिकित्सा के सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहूंगा कि यदि सरकार के पास पैसों की कमी है, सारे राजस्थान के लिये अच्छे अस्पताल नहीं दे सकती तो आयुर्वेदिक औषधालयों का, आयुर्वेदिक औषधियों का प्रबन्ध करना चाहिये। भरतपुर के औषधालय में ३ लाख मरीज आते हैं पर वहां औषधियां समय पर नहीं दी जातीं। सर्दियों में वहां कस्तूरी बटी नहीं पहुंचती और गर्मियों में कपूर बटी नहीं पहुंचती। सर्दियों में कस्तूरी बटी नहीं पहुंचने से लोग निमोनिया से मरते हैं और गर्मियों में कपूर बटी नहीं पहुंचने से लोग हैजे से मरते हैं। मैं नहीं कहता कि इसमें मन्त्री महोदय का हाथ है, या विभागाध्यक्ष का हाथ है पर समय पर आवश्यक औषधियां वहां पहुंचाई नहीं जाती हैं यह देखना उनका कर्त्तव्य है। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि मन्त्री महोदय इतनी दवाई खा गये पर मैं तो कहूंगा कि वे सोने की दवाई ले कर आते हैं जिससे कोई कितना ही हल्ला करो, पुकार करो, आलोचना करो, सुझाव पेश करो, इनका उन पर कोई प्रभाव नहीं होता और वे सब स्वीकार कर रहे हैं। गृह मंत्रीजी तो हर रोज आठ दस गोली खा कर आते हैं.. ..

एक माननीय सदस्य : रोज रोज हल्ला सुनते हैं, इसलिये असर नहीं होता।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : हम तो थ्री नॉट थ्री की गोली मारते जरूर हैं।

श्री रामकिशन : मुझे आयुर्वेद विभाग के बारे में सुझाव देना है। डूंगरपुर, बांसवाडा इलाके में मैंने देखा है, वहां के आदिवासियों ने जब मैं वहां गया तो मुझे बताया कि अस्थमा और कुक्कर खांसी की दवाई उनके पास है। अगर इन दवाइयों को प्रयोगशालाओं में भेज कर जांच कराई जाय तो इन दोनों रोगों से राजस्थान को ही नहीं हिन्दुस्तान को मुक्ति मिल सकती है। आयुर्वेद मंत्रीजी तो वहीं के हैं, उनके पिताजी तो खुद वह दवाई लेते होंगे, फिर क्यों नहीं परीक्षण करवाते। पर उनमें हिम्मत नहीं है कि इन औषधियों का परीक्षण करवायें। अगर परीक्षण करवायें तो राजस्थान ही नहीं सारे देश को इनसे लाभ मिल सकता है। पर हमारी सरकार ऐसी है कि पुरानी चीज सब निरर्थक, नई सब अच्छी।

एक निवेदन यह करना है कि भरतपुर में बडा अस्पताल है, सरकार के पास पैसा नहीं, डॉक्टर नहीं तो फिर इतना बडा अस्पताल किस मतलब का? मैं अपने लडके को भर्ती कराने गया तो वहां भर्ती की कोई व्यवस्था नहीं, वार्ड्स में जगह नहीं। मैं आरोप नहीं लगाता कि उदयपुर में औषधालय क्यों खोलते हैं औषधालय, कहीं भी करो, राजस्थान को लाभ होगा पर लोकतन्त्र में यह इस तरह की

(श्री रामकिशन)

प्रवृत्ति बहुत बुरी होती है। मैं निवेदन करूं जो स्वास्थ्य मंत्री होते हैं उनको खुद को टी. बी. के लिये ग्रान्ट देने का अधिकार दे रखा है। ५००० रु० की ३४ ग्रान्ट्स दी गई हैं उनमें से २८-२९ जोधपुर के लोगों को दे दी गई। टी. बी. के रोगी चाहे कहीं के हों, जोधपुर के हों या और कहीं के हों उनको ग्रान्ट मिलनी चाहिये पर इस प्रकार की प्रवृत्ति से लोगों में भ्रम फैलता है। इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि लोगों में किसी प्रकार का भ्रम नहीं फैले इस प्रकार की कार्यवाहियां करनी चाहिये।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजकीय वैद्य हैं उनको प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। इन्स्पेक्टर मैडिकल बोर्ड ने सुझाव दिया है कि वैद्य सर्टिफिकेट दे सकते हैं पर यह अधिकार उनको नहीं है। न वैद्यों का फिक्सेशन हुआ है और न ग्रेड तय हुआ है। साथ ही आयुर्वेदाचार्य वैद्य के लिये जो पद होना चाहिये वह प्रथमा वाले को दे दिया गया है। तो इन मामलों में मन्त्री महोदय को खुद को जांच करनी चाहिये। जितना आप पक्षपात के मामलों को नेग्लेक्ट करते जायेंगे, उतना ही आप में लोगों का विश्वास घटेगा।

मैंने तृतीय पंच वर्षीय योजना में सरकार का कुछ कार्यक्रम देखा है। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि ९०० नये नये बैड्स करेंगे, २० डिस्पेन्सरियां खोलेंगे, ८३ हैल्थ सेंटर खोलेंगे, ५ दांतों के क्लीनिक खोलेंगे और १५ टी. बी. के सेंटर खोलेंगे। सरकार का बहुत अच्छा लक्ष्य है। १९० परिवार नियोजन केन्द्र खोलेंगे, इसके बारे में मेरी एक राय है और सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। परिवार नियोजन हो पर परिवार बढ क्यों रहे हैं इसकी ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। हमारे यहां शारदा एक्ट बना हुआ है, छोटे बच्चे बच्चियों की शादियां नहीं हों, इसके लिये हमारे यहां कानून मौजूद है पर हम रोजाना देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों की शादियां होती हैं, हां स्वास्थ्य मंत्रीजी ने एक मिसाल पेश की है कि बडी उम्र में शादी होनी चाहिये। इसके लिये उन्होंने उदाहरण पेश किया है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आपकी एज तो बहुत ऊंची हो गई थी, इतनी ऊंची तो नहीं होनी चाहिये थी।

श्री रामकिशन (वैर) : तो मेरा निवेदन यह है कि जो कानून बना हुआ है, उसका सख्ती से पालन करायेंगे तो परिवार नियोजन होगा। आधुनिक औद्योगिक सभ्यता जैसे जैसे बढेगी त्यों त्यों संयुक्त परिवार टूटेंगे और इससे परिवार बढेंगे क्योंकि संयुक्त परिवार में अवसर कुछ कम मिलते हैं और अलग अलग और छोटे परिवारों में एकान्त का अवसर कुछ ज्यादा मिल जाता है स्त्री व पुरुष को एकान्त में रहने का। तो इससे कुछ अच्छाइयां आयेंगी तो बुराइयां भी आयेंगी। तो परिवारों के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण बन जाना चाहिये। पश्चिम के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट है, हिन्दुस्तान के लिये सुझाव दिये हैं, उन पर गम्भीरता से विचार करें। संयुक्त परिवार प्रणाली को जोर दे कर कायम रखें। इस पर यदि आप जोर दें तो दो मामले हल हो सकते हैं एक तो परिवार नियोजन होगा और दूसरा यह कि कम पैसों में ज्यादा सुविधा दे सकेंगे। आबादी भी नहीं बढेगी और कम पैसों में ज्यादा सुविधा भी दे सकेंगे, इससे यह दो लाभ होंगे पानी के मामले में निवेदन कर दिया पर फिर एक निवेदन और कर देता हूं, शायद मंत्री महोदय कहेंगे कि हमको रोग हो गया है हरिजन, आदिवासी और औरतों की

(श्री रामकिशन)

बात कहने का पर हरिजन, आदिवासी और औरतों को पानी के मामले में बडा दुख होता है। मैं उदयपुर गया था, नाम याद नहीं ऋषभदेव या कहीं मीटिंग थी, मामा बालेश्वर दयाल साथ थे। वहां की महिलाओं का गाना सुना, समझ में नहीं आया पूरा पर गाने का सार यह था कि मेरे हाथों में मेंहदी लगी हुई है और राजस्थान जैसे प्रदेश में पानी की वजह से तकलीफ होती है। तो ६० लाख करीब आदिवासी और हरिजन पानी की समस्या से परेशान हैं। इसी प्रकार ७० लाख के आस पास महिलायें पानी न मिलने के कारण परेशान हैं लेकिन आप सब ही जानते है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि कुओं से हरिजनों को पानी नहीं लेने दिया जाता। हरिजनों को पानी नहीं लेने दिया जाता है, औरतें पानी के बिना परेशान हैं। जोधपुर और उदयपुर में बताऊं, माननीय गृह मंत्रीजी शहर में आ गये हैं, बुजुर्ग हैं उनको मालूम है कि कितनी बडी बडी रस्सियां लेकर जाना पडता है, तो मंत्रीजी को पानी की व्यवस्था तो एक-दम हाथ में ले लेना चाहिये चाहे दूसरी चीज न ले सकें। सूडान की सरकार की बात कहता हूं।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) गृह मंत्रीजी से क्या सम्बन्ध है? हथकडी की बात ही तो बताइये।

श्री रामकिशन : जोधपुर से सम्बन्ध है। सूडान की सरकार ने क्या काम किये हैं वे मैं आपको बताऊं। पानी के सम्बन्ध में उन्होंने एक अन्तर्राष्ट्रीय फन्ड कायम किया है व सारे मुल्कों से दानस्वरूप पैसा लिया है। आप सारे मुल्कों से न लें किन्तु कम से कम हिन्दुस्तान के सारे प्रदेशों से इसके लिए दान स्वरूप राशि लेकर इस समस्या को हल करें। चम्बल वगैरा से आप नहरें निकालते हैं। मैं आपको तामिलनाड की एक बात कहता हूं। मैं तामिलनाड गया। तो वहां मि० नरसिंहम् हैं, उन्होंने एक बात पूछी कि आप जरा नहाओगे? उनका यह खयाल था कि राजस्थान में पानी नहीं होता है और वहां के लोग पानी न होने के कारण नहाते नहीं हैं तो उन्होंने मुझसे पूछा कि नहाओगे। मद्रास में बहुत पानी है। तो इस प्रकार की राजस्थान के बारे में देश में बातें फैली हुई हैं, उनको मालूम है कि वहां पानी नहीं है। इस प्रकार की बातों को दूर करना चाहिये।

स्वास्थ्य, चिकित्सा और पानी; ये तीन प्रश्न हैं और इनके लिए मामूली सुझाव हैं। कौन कौन से रोग ऐसे हैं जिनको कम किया जा सकता है। यूरोप के अन्दर मक्खी मार कर कुछ रोगों का अन्त कर दिया, मच्छर मार कर कुछ रोगों का अन्त कर दिया। इसी प्रकार हमारे यहां भी मलेरिया इरेडिकेशन विभाग बना हुआ है। आलोचना करने की बात नहीं है। भरतपुर के अन्दर भी इसके लिए स्टाफ है लेकिन मथुरा और आगरा में सैर-सपाटे करते हुए पायेंगे। गांवों की रिपोर्ट और ले लें। १५ साल पहले जो मलेरिया का स्वरूप था आज मलेरिया पहले से अधिक ही बढ रहा है। बरसात होती है तो मच्छर भी होते हैं और बने रहते हैं, लेकिन डॉक्टर समय पर पहुंचते नहीं हैं और उस समय पहुंचते हैं जब कि गर्मी का मौसम आ जाता है। गर्मी के दिनों में तो स्वत: ही मच्छर गर्मी के कारण से मर जाते हैं। इस तरह से जो सरकार पैसा खर्च करती है उसका उचित परिणाम नहीं निकल पाता। इस ओर सरकार गम्भीरता से विचार करे। समय कम है और मैं मर्यादा का पालन करने का आदी हूं इसलिए मैं इन शब्दों के साथ बैठता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

Page No 96

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कई कटौती प्रस्ताव इस मांग के सम्बन्ध में दिये थे जो औषधालय, चिकित्सा से सम्बन्धित हैं ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य को सूचित कर दूं कि उनकी पार्टी का टाइम अब केवल १० मिनट रहता है ।

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस पार्टी को भी समय मिलेगा या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : अब शायद सम्भव नहीं होगा ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : हम तो दो मिनट ही चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : Hon. Members (Congress) can talk it over with the Treasury Benches.

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से कटौती प्रस्ताव हैं जो जनरल नेचर के हैं, जिन पर माननीय सदस्यों ने हमारी पार्टी की ओर से विचार व्यक्त कर दिये हैं उन पर मैं समय नहीं लूंगा । मैं डाइरेक्टली कुछ समस्याओं या किन्हीं जगहों के बारे में जिक्र करना चाहूंगा ।

पहला, मैं सरकार का ध्यान कम्पाउन्डर थर्ड ग्रेड की समस्या के विषय में आकर्षित करना चाहता हूं । इन लोगों को, विशेष तौर पर जुलाई, १९५८ में एक स्कीम निकाल कर एक ट्रेनिंग दी गई और यह शर्त इनके साथ रखी गई थी कि ६ महीने बगैर किसी स्टाइपैन्ड लिये, ट्रेनिंग लेंगे इनको लाजमी तौर पर गवर्नमेन्ट सर्विस करनी पड़ेगी और यह भी शर्त थी कि पी. एन्ड आर. सी. की ट्रेनिंग जब गवर्नमेन्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी तब लेनी पड़ेगी । इन लोगों ने छः महीने तक कम्पॉउन्डर्स ट्रेनिंग ले ली इनका अपॉइन्टमेन्ट हो गया और थर्ड ग्रेड कम्पाउन्डर की तनख्वाह मिलने लग गयी । सरकार १९५९ में एक साल के बाद एक नोटिफिकेशन निकालती है जिनमें पी. एन्ड आर. सी. की ट्रेनिंग उन लोगों को प्रोवाइड करती है उनको तीन साल के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और यह प्रावधान किया गया कि ट्रेनिंग पीरियड में कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी और केवल ४० रु. स्टाइपैन्ड के रूप में मिलेगा । यह उन लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है । सन् १९५८ में जिन कन्डिशन्स में उन्होंने ट्रेनिंग में आना मंजूर किया, उनमें बहुत से लोग ऐसे थे जो टीचर्स थे जिनके साथ दूसरी कोई कन्डीशन नहीं थी पी. एन्ड आर. सी. की ट्रेनिंग दी जावेगी उस समय, आज उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी और ४० रु. स्टाइपैन्ड दिया जावेगा जब वे गवर्नमेन्ट की सर्विस में आगये थे तो उनको पूरी तनख्वाह मिलनी चाहिये । पी. एन्ड आर.सी. की ट्रेनिंग चाहे तीन साल करिये या पांच साल इससे कोई मतलब नहीं है । करीब ७५ लोग हैं उनके साथ यह अन्याय है । जो लोग नोटिफिकेशन निकलने के बाद आये हों उनके लिए गवर्नमेन्ट कोई बात करे तो सम्भव माना जा सकता है । पहले के लिए यह बात उचित नहीं मानी जा सकती ।

दूसरा मैं नोटिस में लाना चाहता हूं । अफसोस की बात है कि डॉक्टर लोग, आम तौर पर मरीजों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार की जनता के साथ अपेक्षा की जाती है उसमें विभाग में ऐसी शिकायतें मिली हैं कि अपने कर्मचारियों और खास कर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाय, घर पर इस तरीके का काम लिया जाय जैसे बरतन मंजवाना,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

रोटी बनवाना, कपड़े धुलवाना, इस प्रकार के काम करवाना, और उपाध्यक्ष महोदय, कोई कर्मचारी उसके खिलाफ आवाज उठाये कोई एतराज करे कि वे ऐसा काम नहीं करना चाहते, बजाय इसके कि गवर्नमेन्ट इस नाजायज बात को कोई करता है उसको रोकती, कर्मचारी को पेनेलाइज कर दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक पैथेटिक केस अलवर जिले का रखना चाहता हूं । वहां एक डाक्टर शुक्ला हैं एन्टी मलेरिया डिपार्टमेन्ट में । वहां जितने बेचारे चपरासी रहते हैं, रोते हैं । कितने ही छोड कर चले गये उनके व्यवहार की वजह से । एक कर्मचारी ने शिकायत करने की कोशिश की या घर का काम करने से इन्कार किया तो उसको मारा, मारने के बाद उसको नौकरी से निकाल दिया । घनश्याम नामक चपरासी है । उसको भूख-हडताल करनी पडी और माननीय मंत्री महोदय के बीच में हस्तक्षेप करने से उसने अपनी भूख-हडताल तोडी । जून महीने में उसको यह आश्वासन दिया गया था कि मामले को देख कर और अपाइन्टमेन्ट कर दिया जावेगा जो अब तक नहीं हुआ है । उस डॉक्टर के मामले के विषय में जब भूख-हडताल चल रही थी वहां के कर्मचारियों के बयान लिये जो दस्तखत शुदा कलमबन्द हैं । एक दो कर्मचारियों के बयान का हिस्सा में आपके नोटिस में लाना चाहता हूं :

"... ... ...मलेरिया विभाग में चपरासी हूं । २।। वर्ष हो गये । १९५९ से नौकर हूं । नौकरी पर लगा, आर. एन. शुक्ला की ड्यूटी पर हूं । तीन चार महीने दफ्तर में रहा । घर पर लगाया गया । वहां पर मुझसे बर्तन मंजवाना, कपड़े धुलवाना, रोटी बनवाना नाज सुधरवाना, कुट्टी वगैरा कुटवाना .."

श्री निरंजन नाथ आचार्य (उप मंत्री, शिक्षा) :On a point of order, Sir.

श्री निरंजननाथ आचार्य: आप जो किसी का स्टेटमेन्ट पढ रहे हैं उसकी इजाजत दें या न दें इस प्रश्न पर मुझे कोई आपत्ति नहीं । लेकिन हमारे रूल्स के अन्तर्गत हमारी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत किसी का स्टेटमेन्ट जो बाहर हुआ हो जो कटमोशन्स से संबन्धित नहीं वह स्टेटमेन्ट पढा नहीं जा सकता ऐसी परम्परायें हमारे यहां पर रही है । इन परम्पराओं के अनुरूप किसी पेपर का कटिंग भी नहीं पढा जा सकता । इसलिये यह स्टेटमेन्ट सदन के सामने नहीं पढा जाना चाहिये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल: इसका सीधा ताल्लुक मेरे कट मोशन से है । एक कर्मचारी को हटाया गया है और दूसरा कर्मचारी जो सर्विस में उसका व्यवहार उसके साथ किस प्रकार का है यह बयान यह जाहिर करता है । वह मैं अपने कथन के सबूत में पढ रहा हूं । आप चाहें तो टेबल ऑफ दी हाउस पर रख सकता हूं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य: : Point of order, Sir, it cannot be placed on the Table of the House as it is a statement of a person, which is not connected with cut motion as relevant. And, therefore there is no question of documents.

श्री रामानन्द अग्रवाल : It is directly relevant with the cut motion.

Page No 98

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): उप मंत्री महोदय को इसमें क्या एतराज है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : But what is the objection if some matter which is serious enough is brought to your notice Why should you?

श्री निरंजननाथ आचार्य: I have no objection. I only speak of rulings. Our rules do not permit such documents executed by others as a matter of statement to be laid on the Table of the House or to be read over. Even paper cuttings are not to be read over. That has been our precedent.

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) :

X X X X

श्री निरंजननाथ आचार्य : On a pointof Privilege, Siri मेरे प्रिविलेज का पोइन्ट यह है कि मैं माननीय सदस्य की प्रतिष्ठा करता हूं; उन्होंने यह रिफ्लेक्शन डाला कि X X X मैं, उपाध्यक्ष महोदय आर बार निवेदन करूं कि इस तरह का रिफ्लेक्शन डालने की ऐसी परम्परा यहां चल पडी है जिसको उचित नहीं कहा जा सकता ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह परम्परा कल आपने ही डालनी शुरू की थी ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): माननीय सदस्य ने सवाल के तौर पर पूछा कि X X X X

X X X X

अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गये ।

श्री उपाध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों को हिदायत कर दूं कि इस प्रकार का रिफ्लेक्शन किसी भी माननीय सदस्य पर डालना सदन की परम्परा और विवेक के प्रतिकूल है । इस बात का माननीय सदस्यगण हमेशा ख्याल रक्खें, बिना किसी जरूरत के ही कोई ऐसी बात न कही जाय; खास तौर से जब कोई दूसरा सदन का माननीय सदस्य किसी बात को कह रहा हो और इन दी पर्जेशन ऑफ दी हाउस हो । इस प्रकार से रिफ्लेक्शन डालना यह सदन की परम्परा का भंग है ।

श्री चन्दनमल वैद (उप मंत्री, वित्त):

It should be taken as expunged.

श्री उपाध्यक्ष: Well, this will be expunged.

श्री रामानन्द अग्रवाल : "गाली गलोज से पेश आते हैं...

श्री उपाध्यक्ष: यह जो डोक्यूमेन्ट आप पढ़ रहे हैं आपके कट मोशन्स से किस प्रकार संबन्धित है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल: मैंने अपने कट मोशन में कहा है कि फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और उसी दुर्व्यवहार का शिकार एक फोर्थ क्लास कर्मचारी हुआ है । उसके सुबूत में मैं यह डोक्यूमेन्ट पढ रहा हूं । मैं इसके द्वारा यह पेश कर रहा हूं कि क्लास फोर्थ सर्वेन्ट्स जो सर्विस में हैं उनके साथ किस प्रकार का

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
व्यवहार हो रहा है, इसके कारण कई लोग नौकरी छोड़ कर चले गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष: यह उसका पत्र है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल: यह उसके बयान हैं ।

श्री सज्जनमल वैद: यह बयान लिये किसने हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल: यह बयान मेरे द्वारा कलमबद्ध किये गये हैं । एक कमेटी इसके लिये बनी थी जिसने इन्क्वायरी की थी ।

श्री उपाध्यक्ष Order please ! संभव हो सकता है, यह माननीय सदस्य को लिख कर भेजा हो ।

श्री रामानन्द अग्रवाल: कई आदमियों की मौजूदगी में इस तरह की इन्क्वायरी की गई थी कि इस तरह का व्यवहार था या नहीं । यह मेरे द्वारा कलमबद्ध किया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष : अगर आप इस का सार अपने भाषण में ले आयें तो सारा मकसद हल हो जायगा ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): ये बयान अटेस्टेड हैं या नहीं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल: मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस तरह से कितने ही लोग इस तरह के व्यवहार के शिकार हुए हैं और नौकरी छोड कर चले गये हैं । एक आदमी को जिसको हटा दिया गया था बावजूद आश्वासन के अभी तक उसको नौकरी में नहीं लिया गया ।

तीसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के भंग हो जाने के बाद ७०–७५ वैद्य ऐसे रह गये हैं जिनका फिक्सेशन अभी तक नहीं किया गया है । यह डिपार्टमेन्ट के गौर करने का है । काफी लम्बा अर्सा हो गया है अभी तक फिक्सेशन नहीं होना बहुत अनुचित बात है ।

एक बात और कहना चाहता हूं जहां तक आयुर्वेदिक औषधालयों का सवाल है उनके साथ न्याय का व्यवहार नहीं हो रहा है । रूरल एरियाज में जो ज्यादातर कार्य करते हैं खास तौर से सी. क्लास औषधालय उनको केवल ६०० रुपये की मेडिशन साल भर में दी जाती है जो ५० रुपया माहवार होती है और इस तरह से १ रु० १० आना की मेडिशन हुई । २५-३० मरीज ही रोज आये तो हर मरीज पर एक आने की दवा पड़ती है । यह बहुत ही कम है इसको कम से कम दुगुना किया जाना चाहिये ।

दूसरा जो आयुर्वेदिक औषधालय है ए० बी० क्लास के उनमें इन्डोर पेशेन्ट्स के लिये ज्यादा इन्तजाम किया जाना चाहिये । बड़े एलोपेथिक हॉस्पिटल्स बहुत इन्टीरियर में ले जाने में आप असमर्थ हैं और बहुत अर्से तक यह होना भी संभव नहीं है । ऐसी हालत में जब आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरियां हम प्रोवाइड करते हैं वहां इस सुविधा को वास्तविक रूप में प्रोवाइड करें ।

आयुर्वेदिक सिस्टम के साथ मुझे अफसोस है कि हमारी अपनी सरकार होते हुए भी लोकल संस्था होने के बावजूद इसके साथ स्टेप-मदरली ट्रीटमेन्ट किया जाता रहा है । जो आज इसको प्रोत्साहन मिलना चाहिये

Page No 100

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इसको विकास का मौका मिलना चाहिये वह सरकार नहीं दे रही है । इसकी पोटेंशियलीटी को सही रूप में न आंका जाकर इस आयुर्वेद सिस्टम के साथ ठीक तरह का व्यवहार नहीं कर रहे हैं । वैद्यों के पे-ग्रेड्स देख लीजिये उनकी पावर्स देख लीजिये, उनको जो सुविधायें मिलनी चाहिये ऐसा मालूम देता है कि इनको इनफीरियर स्टेटस के लोग मानते हैं । कोई वजह नहीं एक डाक्टर हैल्थ सर्टिफिकेट दे सकता है तो फिर एक वैद्य को इस प्रकार का अधिकार क्यों न हो–इसकी कोई वजह नहीं । डाक्टर को कन्सलटेशन करने का अधिकार है, कन्सलटेशन रूम बनाने का अधिकार है और डाक्टर को विलेज अलाउन्स मिले तो वैद्यों को क्यों न मिले । इस बारे में गवर्नमेन्ट विचार करेगी और अपने सिस्टम के साथ न्याय किया जायगा ।

इसके साथ साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा सरकार यह भी विचार करे कि होमियोपैथिक सिस्टम आफ ट्रीटमेन्ट को रिकगनाइज करने का विचार करे । इस सिस्टम आफ ट्रीटमेन्ट द्वारा बड़े बड़े रोगों का अच्छा इलाज किया गया है । इसमें भी बड़े बड़े फीजीशियन देखे हैं जो एलोपैथिक सिस्टम में फेल हो गये वे होमियोपैथिक सिस्टम से ट्रीटमेन्ट कराने पर सफल हो गये । डा० प्रीट को भी हमने देखा है जब उनका किसी रोगी पर एलोपैथिक सिस्टम फेल हो जाता वे मरीज पर होमियोपैथिक ट्रीटमेन्ट करते और उसके द्वारा मरीजों को ठीक किया है । अपने राजस्थान में काफी लोग प्राइवेट प्रेक्टिस करते हैं और नये जवान भी इस मैदान में आ रहे हैं । सरकार को चाहिये कि इस सिस्टम को रिकग्नीशन दे और इनकी डिग्रियों को मान्यता प्रदान कर इनको नौकरियों में स्थान दे ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनिट में समाप्त करना चाहूंगा । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले सदन में भी निवेदन किया था मैंने कि अलवर अलेग्जेन्डर अस्पताल में पिछले साल से कोई भी पेड सर्जन नहीं है । डाक्टर शर्मा रिटायर्ड ही अभी तक काम कर रहे हैं । इस तरीके से अगर इस कमी के आधार पर सरकार यह कहे कि हमारे पास डॉक्टर नहीं हैं, तो बहुत से ऑनरेरी रिटायर्ड हैं, हमें कुछ पैसा वे दे सकते हैं वे कहें हमको रख लो तो हम काम करने को तैयार हैं तो फिर आप उनको भी रख लें । इस तरीके से सरकार को यह बात कोई शोभा नहीं देती । डॉक्टर शर्मा अपने वक्त के काफी मशहूर डॉक्टर रहे हैं, इसमें शक नहीं, पर आखिर उम्र का भी तकाजा तो होता ही है । तो लोगों को भी नुकसान है, पैसा नहीं मिला तो घर पर देख कर अपनी आर्थिक स्थिति को पूरा करना चाहते हैं । इससे मरीजों को नुकसान पहुंचता है । तो निवेदन करूंगा कि वहां पर जल्दी से जल्दी किसी सर्जन को नियुक्त किया जाय ।

(समय–समाप्ति-सूचक घंटी)

ब्यावर के बारे में निवेदन कर दूं थोड़ा, १५० बैड्स का अस्पताल था, अब ७५ ही रख दिये, तो इसके बारे में भी आप कुछ प्रकाश डालें ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रविशंकर ।

श्री रविशंकर याज्ञनिक (पिंडवारा): मेरा प्रस्ताव है सरकारी अस्पतालों में ग्रामीण जनता जब जाती है तो उसके प्रति डॉक्टर

(श्री रविशंकर याज्ञनिक)
लोग बुरा बर्ताव करते हैं इसे ठीक किया जाना चाहिये।

सरकार के पास जब पैसा कम होता है तो टैक्स लगाने के लिये वह गरीब लोगों की तरफ जाती है और जब सवाल उसकी मदद का आता है तो सरकार उसे भूल जाती है और शहरों की तरफ ज्यादा जाती है।

सिरोही के अस्पताल के बारे में मैं निवेदन करूंगा। इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के गांवों के लोग अपने इलाज के लिये जाते हैं तो उनको किसी भी वक्त अच्छी दवाई नहीं मिलती। एडमिशन भी नहीं मिलता। मेरे पास कई ऐसे केस आते हैं जिनमें डॉक्टर कहता है कि मुझे फुरसत नहीं, बात करने का वक्त नहीं।

हमारे यहां वैद्यक में धन्वन्तरि को भगवान का अवतार माना गया था। पर आज जब इन डॉक्टरों का यह हाल देखते सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो आज राक्षस हो गये हैं।

मेरा निवेदन है कि डॉक्टर जो उदासीनता ग्रामीणों के प्रति बरतते हैं वह न हो, वे उनको आराम पहुंचाने का प्रयत्न करें। उनकी पूरी पूरी मदद करें। उनका इलाज करें।

इन अस्पतालों में दवाइयां जो मिलती हैं वे चार किस्म के लोगों को मिलती हैं, जो गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स हैं उनको, जो बडे बडे अधिकारी हैं उनको, जो बडे बडे पैसे वाले हैं उनको और एल० आई० सी० के आफिस वाले जो हैं उनको, जो उनको इन्स्योरेन्स के कमीशन का पैसा दिला सकते हैं। मैं क्या अर्ज करूं आप से ? इन अस्पतालों की दवाइयां बाजारों में जाकर बिकती हैं और ब्लैक में बिकती है। इसके सुबूत हैं मेरे पास।

जिन बडे बडे अस्पतालों में पांच-सात डॉक्टर्स होते हैं, वहां से एक कम भी कर दिया जावे और उसे जहां देहात में डॉक्टर नहीं है वहां भेज दिया जावे तो गांव का काम चल जावेगा, और शहर का भी काम नहीं बिगडेगा। पर आप आज क्या करते हैं कि ऐसे छोटे गांवों में डॉक्टर के बदले एक कम्पाउन्डर भेज कर काम चलाते हैं। यह मेरा प्रस्ताव है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसिन्द): उपाध्यक्ष महोदय, थोडा समय और बढा दिया जावे।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): छोटी पार्टियों का समय अभी बाकी है।

श्री उपाध्यक्ष: टाइम तो काफी पार्टियों का रह जाता है हमेशा ही। इसमें I want help। सरकारी पक्ष।

श्री मानिकचन्द सुराणा: इसमें १५-२० मिनिट का समय बढाया जा सकता है बाद में।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र): उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने रूरल वाटर सप्लाई स्कीम के ऊपर यहां पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। टाइम की कमी के कारण और सुझाव न आ पाये, लेकिन जितने भी आये हैं उनके बारे में मैं आपको आगे चल कर निवेदन करूंगा।

जब से देश आजाद हुआ उस वक्त से सरकार ने यह प्रयत्न किया है कि जो भी जनता गांवों में रहती है उसको पानी की जो तकलीफ है उसको मिटाया जावे और इसके

(श्री हरिश्चन्द्र)

लिये ठोस कदम उन्होंने उठाये हैं। यह जरूर है कि जितनी आर्थिक कैपेसिटी हमारे प्रान्त की है उसको देखते हुए ही हम कदम उठा सकते हैं। कई ने, खास तौर से जो भरतपुर से आये हैं, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ग्रामीण जनता को पानी सप्लाई करने की व्यवस्था होनी चाहिये, उनको मिलना चाहिये। इससे हम सब सहमत हैं। पर हम उनकी उतनी ही सेवा कर पाते हैं जितने कि हमारे पास आर्थिक साधन हों। इसके अलावा तो करना बडा मुश्किल होता है।

लेकिन ताहम भी राजस्थान सरकार ने काफी अच्छा कदम उठाया और पहली योजना में १५० लाख का प्रोवीजन था, इसकी एवज में १५१.८४ लाख रुपया उसने खर्च किया और इसमें से भी ७,४४२ काम ऐसे किये जिससे कि गांवों के अन्दर कुए के मार्फत या और कोई तरीके से आदमियों को पानी मिल सके।

दूसरी योजना में प्रावधान रखा गया था वह करीब १६० लाख का था, उसके एवज में १७६.८४ लाख रुपये खर्च हुए। करीब ५ हजार ऐसे काम गांवों में लिये गये जिसके जरिये से ग्रामीण जनता को पानी अच्छा मिल सके।

राजस्थान एक इतना बडा विषद् प्रान्त है और इतनी डाइवर्सिटीज हैं कि यहां एक माप-दण्ड लेकर नहीं चल सकते। आप अगर कुएं की ऊंचाई को देखने जावें तो मैं बताऊं कि बीकानेर तथा और और जगह पर कुए बहुत गहरे हैं। कई गहरे कुओं का पानी भी खारा मिल जाता है, मीठा पानी भी नहीं मिल पाता। किन्तु उदयपुर, बांसवाडा की तरफ के इलाकों में पानी आपको ३० फीट पर मिल जावेगा; पर अगर उसको पी लिया जावे तो बहुत बार बाले की बीमारी शुरू हो जाती है। पांच-पांच, छ छः जगह देखा है कि बाले की बीमारी होती है। तो राजस्थान इतना बडा प्रान्त है और उसकी डाइवर्सिटीज इतनी हैं कि एक माप-दण्ड लेकर नहीं चला जा सकता। तो जो प्रयास सरकार की ओर से किया गया है वह यह है कि जितना सम्भव हो सके गांवों में पानी उपलब्ध कराया जावे।

इसके साथ साथ अरबॅन एरिया में डिस्ट्रिक्ट हैड-क्वार्टरों पर वाटर वर्क्स का काम कई जगह कम्पलीट हो चुका है।

जो प्रोवीजन अर्बन वाटर सप्लाई का है तीसरी पंचवर्षीय योजना का उसमें ४.६० करोड का प्रोवीजन है। उस प्रोवीजन के तहत १९६१-६२ में ७५ लाख रुपया मिला था उसमें से एक्चुअल एक्सपेन्डीचर हुआ है वह ८४.८८ लाख है और १९६२-६३ में ८० लाख का बजट प्रोवीजन था उसके फल-स्वरूप जो एन्टीसिपेटेड एक्सपेन्डीचर है वह करीब १ करोड २४ लाख और ७७ हजार के करीब आकर पडता है और १९६३-६४ में जो बजट प्रोवीजन अर्बन वाटर सप्लाई का है वह करीब ६० लाख का रखा गया है। रूरल वाटर सप्लाई में जो टोटल प्रोवीजन है वह २०० करोड का है और उसमें से १९६१-६२ में ६४ लाख रुपया रखा गया था.........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर): २०० करोड है तो निहाल हो जायेंगे।

श्री हरिश्चन्द्र: आई एम सारी २०० लाख। उसकी एवज में १९६१-६२ में

(श्री हरिश्चन्द्र)

मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस बात से काम रुका है कि सैंक्शन नहीं है या उसमें ढिलाई है तो वह ढिलाई दूर की जायेगी और उनका काम जल्दी से जल्दी हो जायेगा । इसके अलावा उन्होंने एक बीजापुर स्कीम के लिए जोर दिया कि वह सैंक्शन हो गई है और शुरू नहीं हुई तो मुझे बताया गया है कि वह स्कीम गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया को भेजी गयी है कि जो पैसा एलोकेट होगा, उसके बाद में उस चीज को लिया जायेगा । ताहम भी अगर राजस्थान सरकार के पास धनराशि उपलब्ध होती है तो यह स्कीम भी उसके तहत ली जा सकती है । इसके अलावा लूणकरणसर के बारे में माननीय सदस्य जो रायसिहनगर से आये हैं उन्होंने यहां बहुत जोर से और शोर से अपने भाषण में कहा । तो उसके लिए मैंने तलाश किया है उससे मुझे यह मालूम हुआ है कि मुख्य मंत्री जी आपके कहने के पहले ही गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया को चिट्ठियां इसके बारे में लिख चुके हैं और उनके सामने दो सुझाव रखे गये हैं कि या तो ट्यूबवैल के जरिये पानी पहुंचाया जाये या कैनाल के जरिये वहां लिफ्ट करके पानी भेजा जाये । ये दोनों स्कीम्स गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया के विचाराधीन हैं और यह मैं जरूर आपसे कह सकता हूं कि इस मामले को सरकार पर्स्यू करके यह देखेगी कि किस तरह से यह मामला जल्दी से जल्दी हल हो सकता है । तो यह कहना कि सरकार बिल्कुल इधर तवज्जह ही नहीं दे रही है यह कहना तथ्य से बहुत परे है ।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ): महाजन का एक और है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर): महाजन गांव के अन्दर जो मीठिया कुआ है उसके संबंध में कहा था कि उसका कन्ट्रोल व्यक्तिगत आदमी के हाथ में है । क्यूं नहीं सरकार उसको अपने हाथ में लेती है ?

श्री हरिश्चन्द्र: उस पॉइन्ट को मैं एग्जामिन करवा रहा हूं । उसके लिए अभी मैं फ्लोर ऑफ दी हाउस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): तो एक प्रश्न युनीफार्म रेट्स ऑफ वाटर के करने के बारे में था । जो कट मोशन्स हैं वे सारे मूव्ड मानते हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र: युनीफॉर्म वाटर रेट्स के लिए कई माननीय सदस्यों ने इस सदन के अन्दर रखा है युनीफॉर्म वाटर रेट्स मैं समझता हूं करना बडा मुश्किल है । इसलिए मुश्किल है कि हर रीजन में अलग अलग परिस्थिति है । कहीं कहीं पानी इतना डीप है कि उठाने में खर्चा आता है और कहीं पर ऊपर ही है तो उसमें खर्चा कम आता है । इसलिए एकीकरण के पक्ष में अभी हम नहीं हैं । आप कोई और फार्मूला इवॉल्व कर सकें तो कन्सीडर करने में हमें ऐतराज नहीं हो सकता । लेकिन मैं अभी जो पोजीशन है उसको रख रहा हूं । कोस्ट ऑफ प्रॉडक्शन अलग अलग एरियाज में अलग अलग है । इस बिना पर अलग अलग रेट्स हैं । युनिफॉर्म रेट करने का प्रश्न नहीं है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन): लाखेरी नगरपालिका में जल-योजना की कार्यवाही चल रही है उसके बारे में जिक्र किया था ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्षजी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जो कट मोशन्स दिये गये हैं उनका जवाब तो देना चाहिये, ऐसी व्यवस्था दी जा चुकी है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): मैं एक प्रश्न पूछूंगा एक मिनिट में। भरतपुर में केवल २।। घंटे एक दिन में पानी मिलता है और उसके चार्जेज ८) रु. माहवार हैं जबकि अलवर में और दूसरी जगह राजस्थान की दूसरी सिटीज में २४ घंटे पानी मिलता है। उस जगह भी वाटर रेट कहीं ४) रु०, कहीं ५) रु० और कहीं पर ६) रु० है तो जहां पर २।। घंटे पानी मिलता है वहां पर ८) रु० कैसे है, इस पर भी विचार करना है।

एक माननीय सदस्य: माननीय सदस्य हिन्दी में बोलें समझ में नहीं आता।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): इसका जवाब नहीं दिया जाय क्योंकि हिन्दी में नहीं बोले।

श्री हरिश्चन्द्र: आपने जो पॉइन्ट उठाया है ऐसी कई जगह हैं जहां पर पानी दो-तीन घंटे या ६ घंटे मिलता है। ऐसी कम जगह हैं जहां पानी २४ घंटे मिलता है। रेट के बारे में आपने कहा कि भरतपुर में रेट ऊंची है, यह मुझे मालूम है। लेकिन कोस्ट ऑफ प्रॉडक्शन भी ऊंची है। लेकिन आपने जो पॉइन्ट रेज किया उसको मैं एग्जामिन करा सकता हूं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: जरूर कराइये।

श्री रामानन्द अग्रवाल: जोधपुर के वाटर वर्क्स के कर्मचारियों का फिक्सेशन यूनिफाइड पे-स्केल्स में नहीं हुआ है इसी तरह से बीकानेर वाटर वर्क्स के टेक्निकल कर्मचारियों की छुट्टियां का पेमेन्ट नहीं हुआ है। ये दोनों विशेष महत्व के कट-मोशन सं० २९ ३० पर हैं, उनका उत्तर दीजिये। कट-मोशन्स का उत्तर देने की चेयर से व्यवस्था भी की जा चुकी है। तमाम कट-मोशन्स मूव्ड माने जाकर मंत्रीजी उनका उत्तर देंगे ऐसी व्यवस्था चेयर से हुई थी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इनका उत्तर देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष: मैं समझता हूं मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा है उससे ये बातें कवर-अप हो चुकी हैं।

श्री हरिश्चन्द्र: माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है। I am supplying the information. बैठ कर बात कर लेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल: जोधपुर वाटर वर्क्स के कर्मचारियों का फिक्सेशन युनिफाइड पे स्केल्स का पेन्डिंग है।

श्री हरिश्चन्द्र: जोधपुर वाटर वर्क्स के कर्मचारियों का नोटिफिकेशन हो चुका है। उनसे ऑब्जेक्शन्स इन्वाइट किये जा रहे हैं। As soon as objections are received, final picture will be there.

श्री भीखाभाई (आयुर्वेद मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर चर्चा के दौरान में इस बात पर भी कुछ कटौती प्रस्ताव आये कि आयुर्वेद विभाग के अन्दर बहुत सी अव्यवस्था है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर जो माननीय सदस्य थे जिन्होंने कटौती प्रस्ताव के जरिये सरकार का ध्यान आकर्षित किया है उनमें से मुख्य इस प्रकार हैं जिनको दो तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है।

(श्री भीखाभाई)

पहला यह कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर जिस प्रकार औषधालयों की आवश्यकता है उतनी तादाद में औषधालय नहीं खोले जाते। दूसरा यह कि इनमें दवाइयों की जिस प्रकार आवश्यकता है उस प्रकार की दवाइयां प्राप्त नहीं होती। तीसरा यह कि जिस प्रकार उनमें खर्चे की आवश्यकता होती है उस प्रकार खर्चा सरकार की ओर से नहीं मिलता और जिस प्रकार का विकास यहां होना चाहिये उस प्रकार नहीं होकर सौतेला व्यवहार आयुर्वेद के प्रति होता है। इस प्रकार के कटौती प्रस्ताव हाउस के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं।

मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक राजस्थान का सवाल है, राजस्थान के इतिहास में आयुर्वेद हमेशा से रहा है और राजस्थान की भूमि जिस प्रकार भक्ति और वीरता के बारे में प्रसिद्ध रहा है उसी प्रकार हमेशा प्राचीन संस्कृति और आयुर्वेद के बारे में हमारी यह भूमि मशहूर रही है। कुछ इतिहास रहा है आयुर्वेद का और वह इस प्रकार का है कि यहां के लोग बाहर जाकर बाहर के लोगों को प्रशिक्षण दिया करते थे और बाहर के लोग यहां आकर शिक्षा प्राप्त करते थे। जैसे नालन्दा और तक्षशिला युनिवर्सिटी कही जाती है ठीक उसी प्रकार यहां की भूमि रही है। मैं निवेदन करूं कि राजस्थान में आयुर्वेद के जो विद्वान रहे हैं हमेशा उन्होंने उसी प्रकार का प्रशिक्षण दिया है। मैं इस बात को निवेदन करूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राजस्थान के वैद्य हिन्दुस्तान के कौने कौने में मौजूद हैं और वहां वे स्वास्थ्य के प्रहरी हैं।

यह माननीय सदस्य ने कहा था कि आज कल औषधालयों में दवाइयों की कमी है। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि ३ पैसों की दवाई के जरिये मरीज क्या अच्छा हो सकता है? मैं निवेदन करूं कि आयुर्वेद का मूल सूत्र यह नहीं है। मूल सूत्र है स्वास्थ्य :

"स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षानं"

इसका मतलब यह है कि मूल चीज स्वास्थ्य की रक्षा करना है, न कि उपचार।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय राजस्थान का निर्माण हुआ उस समय राजस्थान में ३४६ आयुर्वेदिक औषधालय थे, लेकिन आज राजस्थान में १,२७८ औषधालय हैं और हर एक जिले में वृद्धि हो रही है।

श्री रामकिशन (वैर) : औषधालय या डिस्पेन्सरीज।

श्री भीखाभाई : क्या फर्क है दोनों में? औषधालय और आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरीज में कोई अंतर नहीं है।

श्री रामकिशन : रिपोर्ट में लिखा है।

श्री भीखाभाई : कुछ भी लिखा हो, आपकी रिपोर्ट आपके पास है। मैं स्पष्टीकरण करके कहता हूं कि आयुर्वेद डिस्पेन्सरी कहें चाहे औषधालय कहें लेकिन है बात एक ही। इसलिये माननीय सदस्य को चिन्ता नहीं करनी चाहिए। माननीय सदस्य को एक बात की चिन्ता है कि भरतपुर में दवाई नहीं मिलती। आपने एक प्रश्न उठाया था कि कहीं दवाइयों की कमी है। हमने कहा कि दवाइयों की कमी नहीं है। हमने साबित किया

(श्री भीखा भाई)
कि उस औषधालय में ५ हजार की दवाइयां मिलती हैं।

श्री रामकिशन : उसके लिये धन्यवाद।

श्री भीखाभाई : मैंने उनकी शंका का समाधान अलग अलग तरह से किया और बताया कि गये साल लगभग १२,०००) रु० की औषधियां दी हैं और इस साल १३,०००) की दी है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : कस्तूरी भैरव भी दी है क्या ?

श्री भीखाभाई : मैंने मालूम किया तो पता चला कि १०० ग्राम दिया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : लक्कड हजम, पत्थर हजम चूर्ण भी दिया होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्य के पास पहुंच नहीं पाई।

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य के पास नहीं गई होगी उनको टॉनिक के रूप में जरूरत होगी। यहां इस तरह से कहते हैं कि मंत्री लोग टॉनिक चाहते हैं। लेकिन माननीय सदस्य ही इस तरह के टॉनिक के आदी हैं।

एक माननीय सदस्य : केशर कस्तूरी चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, हो रहा है और वह विकास ऐतिहासिक भूमि राजस्थान के अन्दर आयुर्वेद का क्रमिक विकास में भरा पडा है। और मैं निवेदन करूं कि राजस्थान बनने के बाद जो धन-राशि खर्च हुई है उससे मैं प्रमाणित करूंगा। ९ लाख का खर्चा था सन् ५० में और १३ लाख हुआ प्रथम वर्ष में। द्वितीय वर्ष में १८ लाख हुआ। द्वितीय पंच वर्षीय योजना में ५८ लाख का खर्चा था और ६२-६३ में ६२ लाख रुपये इस पर खर्च होने लगे। इसके साथ साथ औषधालयों के जो आंकडे हैं उनसे प्रमाणित करूंगा कि ३४६ औषधालय थे, पहली पंच-वर्षीय योजना में ७३ और खोले, दूसरी पंचवर्षीय योजना में ३२५ औषधालय खोले, तीसरी पंचवर्षीय योजना में जिला परिषद् से ३११ औषधालय आये और हमारी ओर से ३२५ औषधालय खोल दिये जायेंगे। तीसरी पंच वर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में १०० और खोल दिये हैं। इस प्रकार औषधालयों की संख्या बढी है, धनराशि बढी है और दूसरी तरफ.......

श्री रामानन्द अग्रवाल : मरीजों की संख्या भी बढ रही होगी।

श्री भीखाभाई : औषधि के संबंध में मैं निवेदन करूंगा कि जो औषधि की बात कही गई है उसको भी मैं आंकडों से प्रमाणित करना चाहूंगा। १९५७-५८ में जडी बूटियां खरीदीं ४ लाख ६४ हजार रुपये की और इक्विपमेंट और इन्स्ट्रूमेंट्स २० हजार रुपये के खरीदे और डाइट पर ११ हजार खर्च किये। १९५८-५९ में जडी बूटियां ३ लाख ८६ हजार की खरीदीं, इक्विपमेंट और इन्स्ट्रूमेंट्स पर २७ खर्च किये और डाइट पर .०७ खर्च किये। १९५९-६० में जडी-बूटियों पर ४.३९ लाख खर्च किये, इक्विपमेंट और इन्स्ट्रूमेंट्स पर .३६ खर्च किये और डाइट पर .०७ पर खर्च किये। १९६०-६१ में जडी बूटियों पर ६ लाख खर्च किये,

(श्री भीखाभाई)

इक्विपमेंट और इन्स्ट्रूमेंट्स पर .९६ खर्च किये और डाइट पर .०८ खर्च किये। १९६१-६२ में जडी बूटियों पर ९.२२ खर्च किये, इक्विपमेंट और इन्स्ट्रूमेंट्स पर १.१० खर्च किये और डाइट पर .२५ खर्च किये। उसके बाद १९६२-६३ में जडी बूटियों पर ९.१६ खर्च किये, इक्विपमेंट और इन्स्ट्रूमेंट्स पर .६५ खर्च किये और डाइट पर .२६ खर्च किये। और १९६३-६४ में जडी बूटियों के लिये ९.३१ हैं और इक्विपमेंट और इन्स्ट्रूमेंट्स के लिए .६८ हैं और डाइट के लिये .२८ है। यह आंकडे प्रमाणित करते हैं कि राजस्थान के अन्दर आयुर्वेद का किस तरह विकास हो रहा है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ माननीय सदस्यों ने सरकार की आलोचना करने की दृष्टि से कहा कि आयुर्वेद को आगे बढाने के लिये सरकार प्रयत्नशील नहीं है। उनकी बात से ऐसा लगता है कि आयुर्वेद के लिये सोफ्ट कोर्नर उनमें है, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन जहां तक सरकार का सवाल आता है, इस संबंध में आपका और हमारा एक मत है। मैं निवेदन कर दूं जहां तक एलोपैथी का सवाल है, एलोपैथी का बजट बढता जा रहा है लेकिन उसके साथ साथ आयुर्वेद का नहीं बढ रहा हो–ऐसी बात नहीं है। मैं निवेदन कर दूं कि राजस्थान का जो खून है, राजस्थान का जो इतिहास रहा है, प्रशासन रहा है, वह सब ऊपर से नीचे तक आयुर्वेदमय है। मैं कहना चाहता हूं कि आप भी आयुर्वेदमय हो जायेंगे। आपकी इच्छा है कि हम मिल कर काम करें और राजस्थान प्रान्त को आयुर्वेदमय बनाने का काम हो और इसलिये प्रयास करें। मैं आपको निवेदन करूं कि आयुर्वेद की मूल भावना है, आयुर्वेद द्वारा प्रतिपादित चिकित्सा है, मैं समझता हूं कि राजस्थान के लोग हैं, उनमें यह हेरीडिटरी चीज है। मैं यह समझता हूं कि इस सदन के अन्दर जो टीका-टिप्पणी हुई है उससे यह मालूम होता है कि आयुर्वेद के प्रति सोफ्ट कार्नर है। मैं निवेदन कर दूं, कि अर्वाचीन और प्राचीन चिकित्सा पद्धति हैं, ये दोनों पद्धति रहती हैं और विकास करती हैं तो उचित होगा क्योंकि हम तो एक्जिस्टेन्स की नीति को मानते हैं और यह जमाना को-एक्जिस्टेन्स का है। नेहरू जी की विदेश-नीति में को-एक्जिस्टेन्स को महत्व दिया गया है। उसी तरह हम मानते हैं कि एलोपेथी के साथ साथ जीवन के हर पहलू में, जीवन के हर क्षेत्र में एलोपेथी रहे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां जो कुछ कहा गया, मैं अधिक समय लेता तो उसके बारे में, बहुत कुछ बता सकता था लेकिन समझता हूं कि उन सब बातों में मुझे नहीं जाना चाहिए। मैं मुख्य मुख्य बातें ही कहना चाहता हूं। पहली बात तो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में हम आयुर्वेद की फेकल्टी खोल रहे हैं। अब तक जो एक्जामिनेशन होते थे, उनके लिए एक एक्जामिनेशन बोर्ड बना रखा था। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी में फेकल्टी खोलने के संबंध में तय कर लिया गया है, उसके लिये कुछ रुपये भेज दिये हैं। और युनिवर्सिटी में आयुर्वेद की फेकल्टी भी रहे, इसकी स्थापना करने का निर्णय हो चुका है।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक कालेज का सवाल है, हमारे यहां उच्चतर आयुर्वेदिक शिक्षा और आयुर्वेद अनुसंधान के लिये पांच कालेज हैं और आयुर्वेद

(श्री भीखाभाई)

शिक्षा की जो संस्थायें हैं हम उनको ग्रान्ट-इन-एड देना चाहते हैं। मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम राजस्थान में आयुर्वेद का विकास करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिये क्या काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम यह भी कर रहे हैं कि जो लोग प्राइवेट रूप से निजी ढंग से आयुर्वेदिक औषधियों का वितरण करने का काम कर रहे हैं और जो संस्थायें इस प्रकार का काम कर रही हैं, उन लोगों और संस्थाओं को ढाई लाख का प्रति वर्ष अनुदान देते हैं। उससे मालूम होता है कि आयुर्वेद के प्रति हम किस प्रकार की भावना रखते हैं। इसी प्रकार मैं अर्ज करूं कि राज्य सरकार की ओर से एक बोर्ड बना हुआ है, एक परामर्शदात्री बोर्ड, उसका गठन करने के बाद, मैं आपको निवेदन करूं कि········

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इसके चेअरमेन कौन हैं ?

श्री भीखाभाई : स्कालरशिप के लिये जितना प्रावधान रखा हुआ है, उसको हम फौरन देते हैं और आयुर्वेद शिक्षा के लिये प्रेरणा देते हैं····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस बोर्ड के चेअरमेन कौन हैं ?

श्री भीखाभाई : आयुर्वेद मंत्री। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था इस प्रकार उस बोर्ड का गठन किया गया है। हम सोचते हैं कि जहां हमारे यहां पर ए श्रेणी के औषधालय हैं तो जिस प्रकार जो अर्वाचीन पद्धति से चलने वाली डिस्पैन्सरी हैं और उनके एडवाइजरी बोर्ड बने हुए हैं उसी तरह उनके भी क्यों न बनाये जायं ? इस संबंध में सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे बोर्ड बनाए जाने चाहियें और वह एडवाइजरी बोर्ड जो एडवाइज करें दवा वगैरह के लिये व पूरी हो सके।

दूसरा मुद्दा उठाया गया, दवाई के बारे में। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि रसायनशाला कॉमर्शियल बेसिस पर चलाई जाय। मैंने जैसा पहले निवेदन किया था, एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि जो दवाइयां हमारी रसायनशाला में बनती हैं, उनकी कीमत और बाजार में मिलने वाली दवाइयों की कीमत का अनुपात १:३ है। हमारे यहां की दवाई की कीमत एक रुपया है तो बाजार में मिलने वाली दवाई की कीमत तीन रुपये हैं। इसी प्रकार जो ए. श्रेणी, बी. श्रेणी और सी. श्रेणी के औषधालय हैं, उनमें दवाइयों के वितरण की अलग अलग व्यवस्था है, जहां ए. श्रेणी का औषधालय है, वहां ५ हजार से २० हजार तक है, बी. श्रेणी के औषधालय में नौ सौ से बारह सौ तक है और सी. श्रेणी में ६००) से ९००) रु० तक दवा देते हैं। ये दवाइयां दी जाती हैं, उनके अन्दर श्रमिक खर्चा भी शामिल है, दूसरा खर्चा उसमें है। हमारी रसायन-शाला में बनी हुई दवा की कीमत आती है उससे बाजार में जो दवा मिलती है, उस दवा की कीमत तीन गुनी होती है। इसके अलावा बाजार की दवा से अच्छी होती है, इफैक्टिव होती है और सस्ती रहती है। इसके साथ ही मैं निवेदन कर दूं कि पहले जो जिला बोर्ड के औषधालय थे, पहले जमाने की इकाइयों के औषधालय थे, उनको सिर्फ दो सौ, ढाई सौ की दवा मिलती थी। इसलिये आज दवाइयों की शिकायत करना उचित नहीं।

श्री भीखाभाई : पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि दवाई कम आई, दवाई अच्छी नहीं आई, सडी गली दवाई आई। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जांच की जायगी।

अलवर से आने वाले और अजमेर से आने वाले माननीय सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि होमियोपैथी का भी विकास होना चाहिए। मैं इस बात को मानता हूं और इसे मानना चाहिए। इसलिये मानना चाहिए कि वह भी हमारी एक पद्धति है और उसमें सबसे बडी बात है, जिस चीज का जहर है, उसका जहर उसी के एण्टी जहर से दूर हो सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था उसमें है। हम चाहते हैं कि उसका विकास हो। इसके लिए एक बिल तैयार है और उसको हम इन्ट्रोड्यूस करने वाले हैं। इसके साथ ही मैं निवेदन करूं, इसको विकसित करने की चेष्टा की है और जो संस्थायें दवाखाने चलाती हैं, उनको हम अनुदान देते हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आयुर्वेद में पीलिया का इलाज है ?

श्री भीखाभाई : इसके अलावा यह कहा है कि सरकार औषधालय चलाये, तो होमियोपैथिक डिस्पेंन्सरी भी सरकार चला रही है..

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: आयुर्वेद में पीलिया का इलाज है क्या ?

श्री भीखाभाई : इसके अलावा यह कहा गया कि जिला बोर्ड से जो वैद्य आये हैं उनका फिक्सेशन नहीं हुआ है। मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, उनका फिक्सेशन हो रहा है और शीघ्रातिशीघ्र फिक्सेशन करने की कार्यवाही की जा रही है। वैसे २१० का फिक्सेशन हो चुका है। मैं समझता हूं कि इसके लिये ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है...

श्री रामकिशन (वैर): कितने थे ?

श्री भीखाभाई : उनसे योग्यता के प्रमाण-पत्र मांगे गये थे, सर्टिफिकेट्स मांगे गये थे, उनके प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जायं तो एक महीने-दो महीने में फिक्सेशन किये जायेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर): च्यवनप्राश का आयोजन करेंगे मंत्री महोदय ?

श्री भीखाभाई: एक माननीय सदस्य, जो रायसिंहनगर से आये हैं, ने इस बात पर जोर दिया है कि उनके यहां भी उसी प्रकार दवाइयों का प्रबन्ध किया जाय। मैं समझता हूं, यह उन्होंने कहा है कि औषधालयों की कमी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं मैंने औषधालय की संख्या बताई है और आपके यहां औषधालयों की संख्या है वह भी बता सकता हूं। जिस वक्त राजस्थान का निर्माण हुआ तो वहां ११ औषधालय थे, और अब औषधालयों में ४७ की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही मैं निवेदन करूं कि नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वहां पर दवाइयों की कमी है। मैं यह समझता हूं कि यह मैंने प्रश्न के उत्तर में बता दिया था कि दवाइयों की कमी नहीं है, जैसा रायसिंह नगर से आने वाले सदस्य ने कहा कि पहले वहां ११ थे, पहली पंचवर्षीय योजना में ६ खोले, दूसरी पंच वर्षीय योजना में २० खोले और तीसरी में १५ खोल रहे हैं। इस प्रकार औषधालय खोले गये हैं। इससे माननीय सदस्यों को संतोष होना चाहिए।

(श्री भीखाभाई)

एक यह भी कहा गया कि उदयपुर में ज्यादा औषधालय खोले गये हैं। मैं यह अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर में ज्यादा औषधालय नहीं हैं। पहले नम्बर पर, जिसमें ज्यादा औषधालय हैं वह है जयपुर और उसके वाद उदयपुर है। उदयपुर में जो औषधालयों की स्थापना हुई है वे पहले से ही हैं। मेरे पास जो कटौती के प्रस्ताव हैं उनके उत्तर तैयार हैं। और मैं यह नहीं चाहता कि माननीय सदस्य इसको प्रश्नोत्तर बना लें। मेरे पास सारा मैटीरियल है। इसलिये इसको मैं प्रश्नोत्तर कॉल नहीं बना कर यही निवेदन करूंगा कि जो मांग रखी है उसको पास करेंगे और आशा है कि जिन माननीय सदस्यों ने आयुर्वेद के संबंध में अपने कटौती के प्रस्ताव रखे हैं उन्हें वापिस लेंगे।

एक माननीय सदस्य : मेरे कटौती प्रस्ताव का जवाब नहीं आया। कितना अनुदान देते हैं।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष: Order please! Order!!

श्री बरकतुल्ला खां (स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जिस तरह से मैडिकल डिपार्टमैन्ट को ठीक करने और जन स्वास्थ्य को ठीक करने और लोगों को मैडिकल फैसिलिटी ज्यादा से ज्यादा दिलाने के सुझाव दिये हैं उसके लिये मैं अपना आभार प्रगट करता हूं। खास तौर से इसलिये कि माननीय सदस्यों ने ऐसे कान्क्रीट सुझाव रखे हैं और जिस शेप में रखे हैं उसके लिये आभार प्रगट करता हूं। जहां तक मैडिकल फैसिलिटी का प्रश्न है, उसमें दो राय नहीं हो सकती कि जनता को जितनी ज्यादा से ज्यादा सहायता मिले, मिलनी चाहिये और सभी पार्टीज के सदस्य इस बात को मानेंगे कि मैडिकल फैसिलिटी लोगों को ज्यादा से ज्यादा मिले, चाहे वे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हों, चाहे सोशियलिस्ट पार्टी के हों, चाहे जनसंघ के हों, चाहे स्वतंत्र पार्टी के हों और चाहे कांग्रेस के हों। सब यही चाहते हैं कि जो कोई भी हिन्दुस्तानी होगा वह यही चाहेगा कि लोगों को दवाइयां मिलें और उनका अच्छी तरह से इलाज हो और इसके लिय हमारे सामने पैटर्न मौजूद हैं। कोई भी सरकार यह नहीं चाहती कि वह अपने बीमार नागरिकों का इलाज नहीं करे। लेकिन इकॉनॉमी में हमको यह याद रखना होगा, जिस दौर से और जिस जमाने से हम गुजर रहे हैं उसको भी देखना होगा। यह नहीं होगा कि दूसरे मुल्कों ने काफी उन्नति की है और वे इस हद तक पहुंच गये हैं। मैं यह कहूंगा कि सैंकडों वर्षों तक काम करने के वाद वहां जाकर पहुंचे हैं। आज हम बगैर कोशिश किये हुए उसी जगह पर पहुंच जावें, यह मुमकिन कैसे हो सकता है। यह हो सकता है कि दूसरे मुल्कों ने बहुत ज्यादा काम किया है और ज्यादा समय लिया है और हम कम समय लें। लेकिन उस जगह पर पहुंचने के लिये महनत अवश्य करनी होगी।

जिस समय राजस्थान बना उस समय बडे बडे शहरों में अच्छे अच्छे और बडे बडे हॉस्पिटल्स थे और वे सहूलियतें शहर के लोगों को ही देते थे। उनसे देहात के लोगों को राहत नहीं मिलती थी। क्योंकि बडे बडे डाक्टर शहरों में ही रहते थे। इसलिये राजस्थान बनने के वाद यह कोशिश की गई कि जो फैसिलिटी शहरों में मौजूद है उसको देहातों में ले जाया जावे। इसमें हमें कई डिफिकल्टीज आई। शहरों में बडे बडे डाक्टरों के होने क

(श्री बरकतुल्ला खां)

कारण हर व्यक्ति अपना इलाज करा सकता है लेकिन देहातों में छोटी मोटी डिस्पैन्सरीज में एक एक डाक्टर होता है। हमने यह सोचा कि एक एक डाक्टर को हर डिस्पैंसरी में भेजेंगे, लेकिन हमारा जो प्रोग्राम था वह बढता गया। डाक्टरों की कमी थी, वह आपके सामने है। आप देखेंगे, यदि आप किसी दूसरे प्रदेश में आप चले जावें, किसी जगह ५० वर्षों से तो किसी जगह २० वर्षों से और कहीं १० या १५ वर्षों से मैडिकल कालेज खुले हुए हैं लेकिन हमारे यहां राजस्थान में जयपुर में सवाई मानसिंह मैडिकल कालेज के सिवाय नहीं है। जिस स्टेट में एक ही मैडिकल कालेज हो वहां कितने डाक्टर वहां के लिये पैदा हो सकते हैं। इसलिये इस कमी को पूरा करने लिये दो मैडिकल कॉलेज और खोलें। सरकार इसके अलावा यह इरादा रखती है कि तीन-चार कालेज खोलें····

एक माननीय सदस्य : कब खुलेंगे ?

श्री बरकतुल्ला खां : अभी मेरे दोस्त ने पूछा कि कब खुलेंगे। मैं बतलाना चाहता हूं कि सरकार सैन्टर से मदद लेकर कॉलेज खोलना चाहती है। कालेज के लिये ५३ लाख की बिल्डिंग, इंजीनिअरिंग में २० लाख। इस तरह से एक करोड की योजना बनती है। इसके अलावा उसके रेकरिंग एक्सपेन्सेज को बर्दाश्त करना पडता है। इसलिये यह गौर किया जाता है कि बडे बड़े कीमती स्ट्रक्चर हैं उनको बदला जावे।

हमारे यहां लोग यह सोचते हैं कि उस कालेज में एक कमरा २० फुट का है तो हमारे यहां वह कमरा १८ या १९ फुट का क्यों? जब यह खर्च सामने आता है तो सरकार ने सोचा कि भारत सरकार के पास हमारे रिप्रेजेन्टेटिव गये। मैंने पर्सनली जाकर देखा और रिपोर्ट को पढा। मैंने सोचा कि बिल्डिंग पर ज्यादा पैसा लगाना उचित नहीं। कैपिटल इन्वैस्टमैन्ट में लगाना ठीक नहीं होगा। इसलिये सरकार ने यह निर्णय लिया कि जो नया कालेज खुलेगा वह उस तरह के कालेजेज नहीं होंगे जिस तरह के हैं। अभी मैं दिल्ली गया था। मैंने इस संबंध में डिप्टी हैल्थ मिनिस्टर से बात की।

आप देख रहे हैं कि हमारे यहां डाक्टरों की कमी है। पिछले साल ४१२ डाक्टरों की कमी थी। उसमें से यह हुआ कि हमारे यहां बहुत सी डिस्पैन्सरीज थीं, छोटे-मोटे हॉस्पीटलस थे जहां चौकीदार और फोर्थ क्लास सवन्ट्स, कम्पांउडर कोई नहीं थे। लोगों को बडी तकलीफ रहती थी। इसलिये कहा कि या तो बिल्डिंग के ताला लगा दो या वहां पर आदमियों का इन्तजाम करो। इसलिये दिल पर जोर देकर, सीने पर पत्थर रख कर हमने यह किया कि जो १५ वर्ष के पुराने कम्पाउन्डर्स फर्स्ट क्लास थ उनको वहां भेज दिया गया ताकि देहात क लोगों को फायदा मिले।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): 'नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे इमान'।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): शहर में उनको क्यों नहीं रखा गया ?

श्री बरकतुल्लाखां : जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर में जहां मोडल कॉलेज हैं वहां पर पढाई और क्लिनिक वर्क के लिये अनुभवी डाक्टरों की आवश्यकता रहती है। इसके

(श्री बकतुल्ला खां)
अलावा ऑल इन्डिया मैडिकल कॉन्सिल यदि अच्छा पढाई का प्रवन्ध न हो तो सर्टिफिकेट को नहीं मानेगी।

(विराम)

इसलिये इस कमी को दूर करने के लिये यह कदम उठाया गया।

बहुत सी जगह के लिये यह कहा जाता है कि डाक्टर नहीं है और प्राइमरी हैल्थ सैन्टर्स पर आदमी मौजूद नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सदन को बता देना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि आपको यह जान कर खुशी होगी कि आज को तारीख में १५ हैल्थ सैन्टर्स हैं और आप यह नहीं कह सकते कि वहां पर कम्पाउन्डर या डाक्टर नहीं हैं। ज्यादातर अपाइन्टमैन्ट्स हो गए हैं और पहुंच गये होंगे।

एक माननीय सदस्य : लेकिन पहुंचे नहीं हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : जैसा मैं अर्ज कर रहा था कि राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ है कि जो रुपया खर्च किया जा रहा है वह शहरों के लिये किया जा रहा है। मैं यह कहूंगा कि जो रुपया खर्च किया जा रहा है वह बिल्कुल अर्बन के लिये खर्च किया जा रहा है, यह कहना मुनासिब नहीं है। बल्कि मेरे दोस्त, मैंने जो पोजीशन बताई है उसको देखते हुए कहेंगे कि वे कन्विन्स्ड हैं। क्या वे यह चाहेंगे कि ढाणी ढाणी में डिस्पैंसरी खोली जावे। यह तो हो नहीं सकता। जहां पर ज्यादा मरीज होंगे वहां पर खोले गये हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रपोर्शनेट होना चाहिये।

श्री बरकतुल्ला खां: प्रोपोर्शनेट तो हुआ ही है। मैं आपको इसके बारे में फिगर्स दूंगा जिससे आपको मालूम होगा कि पहले रूरल एरिया में कितने हास्पिटल्स थे। सन् १९५१ के अन्दर ५६ थे और १९६२ में ९० हैं।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) I move that the time be extended.

श्री उपाध्यक्ष: क्या सदन की यह मंशा है कि जब तक यह मांग पारित न हो जावे तब तक के लिये सदन का समय बढाया जावे ?

(स्वीकृत)

सदन का समय, जब तक मांग स्वीकृत नहीं हो जाती, बढाया जाता है।

(५.०० म.प.)

श्री बरकतुल्ला खां : तो, माननीय उपाध्यक्ष, रूरल एरिया में ५१ में ५६ अस्पताल थे वहां आज ६२में ९० अस्पताल हैं और ८५७ बेड्स हैं, जहां ५१ में ८० डिस्पेन्सरीज़ थीं आज १६८ हैं। प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स १३४ हैं, फेमिली प्लानिंग सेन्टर्स १०६ हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Order! Order please!!

माननीय सदस्य परस्पर वार्तालाप इतने जोर से न करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हैल्थ मिनिस्टर की हैल्थ के लिये कर रहे हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : मेरी हैल्थ की फिक्र मत कीजिए, मैं तो आपकी सूरत देख लेता हूं तो एक दम तन्दुरुस्त हो जाता हूं।

चाइल्ड एण्ड मैटरनिटी वैलफेअर सेण्टर्स पहले चार थे, आज ८ हैं। पर-केपिटा एक्सपेण्डीचर के फिगर्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। १९५१ में पर-केपिटा एक्सपेण्डीचर ६४ न. पै. मेडिकल पर खर्च होता था और ७ न. पै. पब्लिक हैल्थ पर। १९६२ में मेडिकल पर १.५८ न.पै. और पब्लिक हैल्थ पर ५६ न. पै.।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): ६१ में कितना खर्च होता था ?

श्री बरकतुल्ला खां : १९६१ में मैडिकल पर १.५५ न. पै. और ४६ न. प. पब्लिक हैल्थ पर।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कम हो गया न मैडिकल पर।

श्री बरकतुल्ला खां : पर-केपिटा बढ़ा है। इसी तरह मरीजों की तादाद भी बढ़ी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : हां, "मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की"।

श्री बरकतुल्ला खां : हंसी की बात नहीं। जो आज जनता के ठेकेदार बन कर हाउस में कहते हैं कि गांवों की जनता के लिये मेडिकल एण्ड हैल्थ की कोई व्यवस्था नहीं, अस्पतालों को जो बूचड़खाना कहते हैं, उन्हें बताऊं, ये फिगर्स बताते हैं कि गांवों की जनता जिसको शहरों के अस्पतालों में जाने की हिम्मत नहीं होती थी, आज देहाती भाई भी शहरों में आते हैं, यहां जो मैडिकल फेसिलिटीज हैं उन्हें वे अवल करते हैं, फायदा उठाते हैं। कहीं शहरों के अस्पताल में देख लीजिये, शहरों के ही नहीं उनमें आस पास के गांवों के लोग ज्यादा सेण्टर्स तादाद में मौजूद हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अजायबघर की हैसियत से देखने आते हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय उपाध्यक्ष, अजायबघर की हैसियत में देखने वे आते हैं, जिनको तलाश करके कुछ चुरा कर लाना होता है, यहां सदन में विस्फोट करने के लिये लाना पड़ता है। मरीज तो तमाशा देखने नहीं आते। तमाशा देखने और दिखाने वाले और ही होते हैं।

राजस्थान गवर्नमेंट यह कोशिश कर रही है कि और मैडिकल कॉलेज खोले जायं। वहां यह भी किया है कि कॉलेज में जो एडमिशन हो रहे थे उनको भी बढ़ा दिया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अजमेर में थर्ड प्लान में खोलने का प्लान था, उसको कट किया है या नहीं ?

श्री बरकतुल्ला खां : उपाध्यक्ष महोदय, यह तय नहीं था कि कहां खोलेंगे, तय यह था कि राजस्थान में खोलेंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कट किया है कि नहीं ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : हम चाहते हैं कि जोधपुर में पहले खोलें और ये चाहते हैं कि अजमेर में खोलें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इनको बीकानेर में खुलवाइये, पर यह बताइये कि कट किया है या नहीं ?

श्री बरकतुल्ला खां : आप कट करने की कह रहे हैं, हम तो दो मेडिकल कालेजेज खोलने की कोशिश कर रहे हैं । मैं एश्योर करता हूं कि थर्ड फाइव इयर प्लान खत्म होते होते एक मैडिकल कालेज राजस्थान में और खोलेंगे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जोश में आकर कुछ तो मतलब की बात कही ।

श्री बरकतुल्ला खां : मेडिकल का जो पहले हमारे यहां ५ साल का कोर्स होता था, वह करने के बाद एक साल के लिये फिर रखा जाता था तो उसको ५ साल के बजाय, साढ़े चार साल का कर दिया है और एक साल के बजाय ६ महीने तक डाक्टर बन कर डॉक्टर का काम करेंगे और कोई गलती यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं पाई गई तो डिप्लोमा दिया जायगा । इसी तरह से ऐज को भी रिलेक्स किया है । वे प्राइवेट डॉक्टर्स जो गवर्नमेंट सर्विस में आना चाहते हैं, ५० साल की ऐज तक के आ सकते हैं । ५० से ज्यादा ऐज के भी आना चाहते हों और व मैडिकली फिट हों तो उन्हें हम कण्ट्रक्ट बेसिस पर लेने को तैयार हैं । हायर ग्रेड भी उनको देंगे जो एम. बी. हैं या एफ. आर. सी. एस. हैं । यह कोशिश इसलिये की है कि राजस्थान का भविष्य बनाना सभी चाहते हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस फेसिलिटी के देने के बाद प्राइवेट डाक्टर्स आये हैं क्या ?

श्री बरकतुल्ला खां : अब शायद आयन्दा इसलिये आयेंगे कि जिनकी इंश्योरेंस की प्रेक्टिस थी, उनकी कम हो रही है, वे शायद आ जायें ।

तो जैसा कि मैंने अर्ज किया अलग अलग वक्त पर अलग अलग कदम उठाये गये हैं । बंगाल से डॉक्टरों को लाये । पहले तो वे हमारी जुबान नहीं समझते थे फिर जिस गांव में गये, वहां के लोगों ने कहा कि हमारी बोली नहीं समझते ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : बंगाली डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों के लिये क्यों दिये गये ? शहरों को क्यों नहीं दिये गये ?

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय उपाध्यक्ष, मैं समझा देना चाहता हूं माननीय सदस्य बहुत इन्क्विजिटिव हैं, उत्सुक हैं । जो नये डॉक्टर हैं, एकदम पी. एम. ओ., सी. एम. ओ. या हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट का चार्ज नहीं ले सकते, एक दम लेक्चरार नहीं बन जायें, कहीं न कहीं जाना पड़ेगा । तो शहरों में जिनको लिया जा सकता था उनको शहरों में लिया जिनको शहरों में नहीं लिया जा सकता था उनको गांवों में लिया गया । उनको लेंग्वेज की डिफिकल्टी रही और इस लेंग्वेज की डिफिकल्टी के जो डाक्टर आये व स्वयं भी खुश नहीं रहे और दूसरों को भी खुश नहीं रख सके ।

एक कोशिश यह की कि फाइनल इम्तिहान खत्म हो जाते थे और जो फेल हो जाते थे उनको दो इम्तिहान देने पड़ते थे, हमने डॉक्टरों की कमी को मद्देनजर रखते हुए और एमर्जेन्सी का ख्याल करते हुए यह कर दिया है कि ये तीन इम्तिहान दे पायेंगे और जब भी पास हो जायेंगे उनको डाक्टर ले लिया जायेगा ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेडिकल डिपार्टमेंट का two fold programme है

(श्री बरकतुल्ला खां)
प्रिवेण्टिव एण्ड क्यूरेटिव। प्रिवेण्टिव साइड में जैसा कि आपको मालूम है हैल्थ साइड में मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम था। अब ट्रिकोमा को भी लेने जा रहे हैं। टी. बी. का भी थोड़ा बहुत काम चल रहा है। हैल्थ साइड है, प्रिवेण्टिव साइड है, इसमें किस किस में कितना कितना काम हुआ यह शोर्ट में अर्ज कर देना चाहता हूं।

मलेरिया का बताऊं कि मलेरिया में हमारे यहां की यूनिट के बारे में गलतफहमियां थीं, उनको दूर करना चाहता हूं। आल इंडिया स्टेण्डर्ड हुआ है उससे अच्छा ही साबित हुआ है। वहां की रिपोर्ट देखें तो जाहिर होगा कि हमारे यहां का ओवर आल वर्किंग है, दूसरी स्टेटों ने रिप्रजेंण्ट किया है उससे कहीं अच्छा है। यह रिपोर्ट आई है, यह कोई राजस्थान की रिपोर्ट नहीं है। मलेरिया यूनिट विथड्रा किया जाता है तो राजस्थान का डायरेक्टर बैठ कर नहीं कहता। बाहर के लोग आते हैं, टेक्निकल, हैल्थ डिवीजन के एक्सपर्ट्स आते हैं और सर्वे करते हैं। सर्वे करने के बाद देखते हैं कि काम ठीक है तब तो यूनिट को विथड्रा करते हैं, जब देखते हैं कि ठीक नहीं है तो कहते हैं कि जारी रखो।

तो हमारे राजस्थान में पोजिशन यह है कि जितने यूनिट विथड्रा करने थे विथड्रा कर लिये हैं। डेढ़ बाकी रहा है। यह करीब करीब आल इण्डिया फिगर्स अर्ज कर रहा हूं, कहीं दो हैं, कहीं ढाई हैं, हमारे यहां डेढ़ हैं।

जो गलतफहमियां आम तौर पर लोगों के दिमाग में आती हैं-मलेरिया वाले मलेरिया के केसेज नहीं बताते हैं। ऐसी बात नहीं है। हर जगह फीवर के केस होते हैं, तो खून ले लेते हैं और खून ले लेने के बाद मलेरिया का ट्रिटमेंट साथ देते हैं, खून पहले ले लेते हैं, स्लाइड भेजते हैं ताकि उसको एग्जामिन किया जाय और जब एग्जामिन हो जाता है तब पता लगता है, पोजिटिव केस आफ मलेरिया है। अगर सीवियर केस आफ मलेरिया हो और उसका वक्त पर इलाज न हो तो दूसरे केसेज में वह आगे बढ़ता है। इसलिए पहले प्रिकॉशन ले लिया जाता है। दवा देते वक्त खून लिया जाता है, स्लाइड आती हैं और उसको टैस्ट करते हैं। दूसरी डिपार्टमेंट के बारे में जो गलतफहमी है वह भी दूर कर दूं। इरेडिकेशन ऑफ मोस्क्विटो नहीं है। जर्म लिये हुए मच्छर हैं उनको खत्म कर दिया और मच्छरों को खत्म करने का प्रोग्राम हो वह इसमें नहीं है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): मच्छर तो रात को सोने के वक्त भी भिन भिनाते हैं।

श्री बरकतुल्ला खां: उपाध्यक्ष महोदय, दो तरह के मच्छर होते हैं। एक किस्म का मच्छर तो वह होता है जो काटता है लेकिन बुखार पैदा नहीं करता है और एक तरीके का मच्छर वह है जो भिन-भिन करता है काटता है और बुखार पैदा करता है।

श्री मथुरादास माथुर: हीयर! हीयर!

(शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: दूसरी किस्म के मच्छर हैं।

श्री बरकतुल्ला खां: जो बुखार वाले मच्छर हैं उनको खत्म किया जा रहा है

(श्री बरकतुल्ला खां)

मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को खत्म किया जा रहा है लेकिन सारे मच्छरों को खत्म करने के लिए न तो रुपया है और न योजना हम कर सकते हैं।

मिसाल के तौर पर यह बताना चाहता हूं। १९५५ में मलेरिया सेप्लिन रेड ३६.८। Cluito pante rate १ पर्सेंट। और मलेरिया केस रेकार्डेड ८,३५,३७८। उसके मुकाबले में आज राजस्थान के अन्दर सेप्लिन केस १.९ पर्सेन्ट पर आये और Cluito pante rate १ पर्सेन्ट से हट कर ०.०४ पर्सेन्ट हो गया है।

१९६१ के अन्दर फीवर केसेज डिडक्टेड हुए ८,९९,२३० और उसके अन्दर मलेरिया के केसेज ९०२६।

१९६२ में १४,१९,४९३ केसेज फीवर के थे उसके अन्दर टोटल केसेज मलेरिया के डिडक्ट हुए ३३१२।

१९६३ के ३ मार्च तक १६७ केसेज अब तक सामने आये हैं।

दूसरा प्रोग्राम जो मैं कह रहा था वह था फेमिली प्लानिंग के बारे में। मेरे दोस्त ने कहा, डिपार्टमेंट को पूरी जानकारी होते हुए भी पूरी जानकारी नहीं कर पाये। ४२ वर्ष की उम्र में मैं खिदमात करूं, अब तक तो मुबुक दोश था। डाइरेक्टर साहब हैं उन्होंने शादी नहीं की और जो डिप्टी डाइरेक्टर इन्चार्ज हैं उन्होंने भी शादी नहीं की।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): आप यह बता दीजिये कि फेमिली प्लानिंग को आप मानते हैं या नहीं?

श्री बरकतुल्ला खां: मैं मानने वाला हूं। आपने भी मानना शुरू किया था करते रहे वर्षों तक लेकिन मुश्किल यह है कि आपसे भी एक गलती हो गई।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर): गलती हुई उनसे। गलती की गुन्जाइश अब है।

एक माननीय सदस्य: आपने सुना नहीं।

श्री बरकतुल्ला खां: जैसा मैं अर्ज कर रहा था फेमिली प्लानिंग के बारे में इमीजियेट रिजल्ट्स नहीं निकाल सकते हैं। पूरी दुनियां के अन्दर भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जिसने इसको ऑफिशियल लेवल पर लिया है। दूसरे देशों ने नहीं लिया है और उस मुल्क ने लिया है जिसके बारे में दुनिया को वह गलतफहमी थी कि यह मुल्क तो सुपरस्टीशियस है। इन तमाम चीजों के होते हुए भी हमारे लोगों ने बताया कि मुल्क की आवश्यकता होते हुए फेमिली प्लानिंग को अन्डरस्टेन्ड करते हैं। कोई यह सोचे कि रिजल्ट ५-१० वर्षों में निकल जायेगा, मुमकिन नहीं है। इसलिए मुमकिन नहीं है कि यह वेलफेयर प्रोग्राम है। जबरदस्ती नहीं है। किसी को कम्पेल नहीं किया जाता है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): **इसको जबरदस्ती से कब शुरू करने वाले हैं?**

श्री बरकतुल्ला खां: कांग्रेस सरकार चली जावेगी और दूसरी सरकार आ जायेगी वह कर देगी। कांग्रेस सरकार का अभी इरादा नहीं है। F mily planning is a way of l fe इसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेन्सेंज होते हैं। फेमिली प्लानिंग में सबसे पहली बात है

(श्री बरकतुल्ला खां)

ro educate the people उनको कीजिए जो देहात में बैठे हैं। जिनको सुविधा दे सकते हैं। शहरों के पढ़े-लिखे लोग हैं। फेमिली प्लानिंग के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्ज यूज करते हैं, कुछ लोग एडमिट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): बिजली लगाने के लिए देहात में ज्यादा जरूरत है।

एक माननीय सदस्य: आप समझे ही नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आप प्रारम्भ रखिये।

श्री बरकतुल्ला खां: उसे देहात में जाने के लिए यह प्रोग्राम किया कि शहरों में कॉन्ट्रासेप्टिव्ज यूज करके इसका प्लानिंग किया जाय। गांवों में यह संभव नहीं लगता है, इसलिए गोली खाकर जिससे उनको दिक्कत भी न हो, इसको कर रहे हैं।

१९६१-६२ में ४५० बांटी गई।

१९६२-६३ में २० बांटी गई।

फोम टेब्लेट्स १९६१-६२ में १९७०६ बांटी गई।

१९६२-६३ में ५०६६३ बांटी गई।

जेली: १९६१-६२ में १७६५ बांटी गई।

१९६२-६३ में ५४५६ बांटी गई।

इसी तरह से फेमिली प्लानिंग में ८६ डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी गई और १५०) रु० उनको स्टीपेंड दिया गया। लेडी हेल्थ डॉक्टर को ट्रेनिंग दी गई और १००) रु० उनको भी स्टीपेंड दिया गया। सोशियल वर्कर्स को भी ट्रेनिंग किया गया और ४०) रु० (व्यवधान) महीना दिया गया। ६० सोशियल वर्कर्स तैयार हुए हैं। महिला १० थीं और ५० जेन्ट्स थे।

फील्ड यूनिट्स बनाई गई। पंचायत समिति में यूनिट्स को रखा गया और जगह जगह गांव-गांव में सिनेमा दिखाये गये। इससे एक अन्दाजा लगाया गया। कोई यह कहे कि फेमिली प्लानिंग सौ फी सदी सक्सेस हुआ है; यह न था और न है। फेमिली प्लानिंग ने बुनियाद डाली है। जैसे जैसे लोग इन्ट्रेस्ट लेते जायेंगे पापुलेशन का कन्ट्रोल होता चला जावेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज

करना चाहता हूं कि लीडर ऑफ दी अपोजीशन ने कुछ कन्स्ट्रक्टिव सुझाव दिये और जिम्मेवारी उन्होंने मुझ पर डाली। वे इस समय सदन में नहीं हैं। मैं अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने मेडिकल डाइरेक्टोरेट के बारे में कहा कि डाइरेक्टोरेट में टॉप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। डाइरेक्टोरेट में एक डाइरेक्टर है जो सारे विभाग को ओवरआल कन्ट्रोल करता है। चार डिप्टी डाइरेक्टर्स हैं, ५ असिस्टेन्ट डायरेक्टर्स हैं। आप यह समझिये कि एक तो डिप्टी डाइरेक्टर हेल्थ का है, एक डिप्टी डाइरेक्टर मेडिकल का है, एक डिप्टी डाइरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन का है और एक डिप्टी डाइरेक्टर नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन डिपार्टमेंट है उसका है। इस तरह से यह कोई टॉप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लगता। अगर इसमें पब्लिक हेल्थ भी मिला देते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है। मेडिकल और

(श्री बरकतुल्ला खां)

हेल्थ दोनों को मिला देते हैं तो एफीशियेन्टली इसको डील विद नहीं कर पायेंगे । फिर भी अपोजिशन के माननीय नेता ने सुझाव दिया है, उसकी हम कद्र करते हैं । इसके अन्दर कुछ कमी हो सकती है तो करने की कोशिश करेंगे, मेरा माइन्ड इसके लिये फाइनली क्लोज नहीं ।

एक माननीय सदस्य: पचास फी सदी तो क्लॉज है ।

श्री बरकतुल्ला खां: इसी तरह से मेरे एक दोस्त ने कहा एन्टी रेबीज के इन्जेक्शन हर जगह मिलने चाहिये ताकि इसमें पीडित मरीजों का वहीं पर इलाज हो सके । हमारे यहां इसके लिये कॉन्सिल है जो लोग यहां इलाज करवाते हैं उनको दवाइयां महैया की जाती हैं । मैं माननीय दोस्त से यह उम्मीद करता था कि उनकी तरफ से यह सुझाव आयगा कि वे ऐसे आवारा कुतों को डेस्ट्रोय करने का सुझाव देंगे लेकिन यह सुझाव तो आया नहीं, उल्टा उनका यह कहना था कि एन्टी रेबीज के इन्जेक्शन हर गांव में हर डिस्पेन्सरी में उपलब्ध होने चाहिये । मेरा तो सुझाव है कि रेबीज से जितनी डैथ्स हो हो रही हैं उनको देखते हुए स्ट्रे डॉग्ज को डेस्ट्रोय किया जाय ।

श्री मानसिंह महार (आमेर): स्ट्रे डॉग्ज को मारने पर कौन मना करता है ?

श्री बरकतुल्ला खां: मना करती है । पब्लिक ओपीनियन मना करती है । ये सदस्य जिन्होंने यह कहा है, आज ही हुक्म दे दें तो आज ही कल ही उनकी तरफ से आन्दोलन शुरू हो जायगा....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) आप कुत्ते मत मारिये ।

श्री बरकतुल्ला खां: मैं कुत्तों को पालता हूं, मारता नहीं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: स्ट्रे डॉग्ज के काटे हुए का आप इलाज रखते हैं लेकिन आदमी किसी कुत्ते को काट जाय तो उसके लिये क्या करेंगे ?

श्री बरकतुल्ला खां: अखबार वालों को कहूंगा कि इसकी न्यूज बना दें ।

श्री विजयसिंह झाला: यह प्रश्न मैंने रखा था । आपके जहां प्राइमरी हेल्थ सेन्टर्स हैं उन जगहों पर तो एन्टी रेबीज इन्जेक्शन का प्रबन्ध कर दें । क्या यह अच्छा नहीं रहेगा ? इसके लिये एक्स्ट्रा यहां खर्चा नहीं करना पड़ेगा । वहां तो प्रबन्ध कर दें ।

श्री बरकतुल्ला खां: जैसा कि मैंने कहा इनको रेफरीजेटर में रखना पड़ता है । ऐसी जगह भी हेल्थ सेन्टर्स हैं जहां न तो बिजली और न रेफ्रीजेटर का इन्तजाम हो सकता है । अगर बिजली हो और कुछ देर के लिये बन्द हो जाय तो वे सारे इन्जेक्शन्स खराब हो जायं । अब आप ही देख सकते हैं कि आपका यह सुझाव कितना मौजूं है ।

एक बात मेरी लाखेरी विजिट के बारे में भी कही गई । मैंने माननीय सदस्य को ऑफिसियल इनफोरमेशन दी कि मैं फलां तारीख को आ रहा हूं, लेकिन माननीय सदस्य जब मैं वहां पहुंचा किसी इलेक्शन के सिलसिले में गये हुए थे । लाखेरी मैं गया और मैंने जाकर उसको देखा । ऊपर जो खड्डा है वह नीचे के पानी को कहीं खराब

(श्री बरकतुल्ला खां)
तो नहीं कर देता हूं । जब मैंने देखा गड्डे का पानी इतना ऊंचा कर दिया गया है कि नले का पानी कितना ही ऊंचा आजाय वह उस पानी को खराब नहीं कर सकता । जहां तक गन्दे नाले का सवाल है उसके लिये इतना बड़ा सोक पिट हो नहीं सकता । हम देखते हैं शहरों के अन्दर भी गन्दे नाले होते हैं वह भी आखिर जाकर कहीं गिरते हैं यह केवल लाखेरी की बात नहीं सारे राजस्थान में गन्दे नालों के बारे में हमेशा यही होता है कि गांव के बाहर या शहर के बाहर दूर किसी जगह पर जाकर गिराया जाता है । मैंने ऐसी कोई बात नहीं देखी कि लोग उसका पानी पीते हैं...

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन): यह जानकारी सदन को गलत दी जा रही है । वह नाला नहीं बरसाती-नदी है ।

श्री उपाध्यक्ष : order ! order !! माननीय मंत्री महोदय जो कुछ कह रहे हैं वे पूर्ण जिम्मेदारी से कह रहे हैं । कोई गलत या सही कहते हैं तो उसके लिये बाद में निष्कर्ष निकाला जा सकता है । इस समय उनको इन्टरप्ट करने की आवश्यकता नहीं ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : वह जिस नाले को शहर का गन्दा नाला कह रहे हैं वह नाला नहीं बरसाती नदी है ।

श्री उपाध्यक्ष : It is bad taste to inter polate like that. He is speaking on his own responsibility.

श्री बरकतुल्लाखां: मैं फिर रिपीट करता हूं कि वह गन्दा नाला है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : जनता उस नदी का पानी पीती है ।

श्री बरकतुल्ला खां: आपने देखा होगा, मैंने तो किसी को देखा नहीं पानी पीते । मैं जब वहां आया तो आप वहां मौजूद नहीं थे । मैं आपकी इन्तजार करता रहा ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वह बरसाती नदी है और उसका पानी लोग पीते हैं । इसकी मालमात करने के लिये किसी भी सदस्य को आप डेप्यूट करदें । उसका खर्चा मैं देने के लिये तैयार हूं । खाली बगैर जानकारी किये कह देने से तो कुछ हल नहीं निकलेगा ।

श्री बरकतुल्ला खां: इसी तरह से अस्पतालों में दवाई नहीं मिलती इसका भी जिक्र किया गया । अस्पतालों के लिये यह हिदायत है कि जितनी भी दवाइयां उपलब्ध हों उनके नाम लिख दिये जांय । आज हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं कीमती दवाइयां भी हमारे यहां पर आ रही हैं । कीमती दवाइयां का रिजल्ट इमीजियेट होता है । कीमती दवाइयां अस्पतालों में नहीं रखी जातीं, इसलिये सर्टेन केसेज के अन्दर दवाई लाना जरूरी हो जाता है । अस्पताल में जो दवाइयां होती हैं उनकी लिस्ट लिखी हुई रहती है । इसके लिये हमारा बजट भी कमजोर नहीं है । ड्रग्ज के ऊपर ५६,१४,५०० रु० है, इक्विपमेंट के ऊपर ५,४४,३०० रु० है, डाइट्स के ऊपर जो कहा गया उसके लिये २०,५५,५०० रुपया खर्च कर रहे हैं । प्लान और नॉन प्लान का हमारा यह बजट है । हमने दवाइयों और डाइट्स के लिये अच्छा पर्सेन्टेज रखा है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): पहले जो डाइट का सिस्टम था उसमें और अब में कोई चेन्ज हुआ है क्या ?

एक माननीय सदस्य : क्या डाइट्स में कुछ कमी कर दी गई है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): पेटर्न में चेन्ज हुआ है क्या ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : डाइट्स को चेन्ज करके बेहतर बनाने की कोशिश की गई है या बचत करने का ध्यान रखा गया है ?

श्री बरकतुल्ला खां: जहां पर वेस्ट होता है वहां बचत होगी ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो स्पेसिफिकेशन पहले देते थे उसके अन्दर पहले से कमी की है या उसको बढाया है ?

श्री बरकतुल्लाखां: It is definitely better; there is no question about that. It is much better system.

श्री कुमारानन्द (ब्यावर): ब्यावर में जो बेड्स की कमी कर दी है उसके बारे में क्या कहना है ?

श्री बरकतुल्लाखां: बेड्स में कमी नहीं हुई । जितनी व्यवस्था वहां के लिये थी वह पूरी है । ऐसा होता है कि यदि बिस्तर भरे हुए रहते हैं और कोई मरीज सीरियस आ जाता है तो ऐसा किया जाता है कि उसको तो जमीन पर नीचे उतार दिया जाता है और उसको जगह दे दी जाती है । एडजस्टमेन्ट के लिये ऐसा किया जाता है । ज्यादा लोग आजायें तो उन को बिस्तर के बिना महरूम न रहना पडे इसलिये यह सहूलियत कर रखी है । हो सकता है उसमें कुछ कमी हुई है । जैसे अस्पतालों में बेड्स हैं उनके बीच में कोई जगह खाली रहती है, उसमें भी बेड्स लगा देते हैं । एक कमरे में जहां टीप-टाप तरीके से १३ बेड्स आ सकते हैं वहां सहूलियत के लिये २० भी हो जाते हैं । लेकिन जरूरत मन्द निकल न जावे इसलिये जो मरीज ठीक हैं उसको जमीन पर ले आते हैं । ब्यावर के बारे में जो बुजुर्ग मेम्बर हैं उनकी मैं इज्जत करता हूं, उनसे अर्ज करूं कि जो सेंक्शन्ड स्ट्रेन्थ है बेड्स की उसमें कमी नहीं हुई । एक्स्ट्रा बेड्स जो लगते थे उसमें किसी प्रकार की कमी हुई है तो उसकी जानकारी करूंगा और समझा दूंगा कि बेड्स में कमी न करें । ओरीजनल स्ट्रेंथ तो मौजूद है लेकिन एडजस्टमेन्ट स्ट्रेन्थ में कमी हुई होगी तो देख लूंगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल: आपके डिपार्टमेन्ट की तरफ से एक पुस्तिका निकली है उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :

> "Rationalised scheme of staff diet and drugs in the hospitals and dispensaries in Rajasthan has been approved by the Government."

क्या यह रेशनेलाइज्ड स्कीम्स के अनुसार इकोनॉमी की है या ज्यादा सुविधा देने की कोशिश की है ?

श्री बरकतुल्लाखां : ज्यादा सुविधा देने के लिये किया है ।

श्री बरकतुल्ला खां : इस तरह से मुझे शेक्सपीयर को कोट करने को जी चाह

(श्री बरकतुल्ला खां)
रहा है, पर मेरे सोशयलिस्ट साथी बैठे हैं, अंग्रेजी में बोलूं तो वे नाराज हो जावें।

श्री रामकिशन : शेक्सपीयर की भाषा तो आप बोल सकते हैं, अपनी नहीं कहें उसे।

श्री बरकतुल्ला खां : कहा गया हास्पिटल बूचड़खाने हैं। हॉस्पिटल का नाम बूचड़खाना रख दिया। तो बकौल शेक्सपीयर के मैं निवेदन करूं कि गुलाब को किसी नाम से पुकार लीजिये, वह गुलाब ही रहेगा। बूचड़खाना बूचड़खाना रहेगा, अस्पताल अस्पताल रहेगा। नाम के फेर बदल से कुछ नहीं होता।

जहां तक कमी का सवाल है तो बातें कही गई, मैं फिर जिम्मेदारी से कहता हूं कि अभी माननीय सदस्य ने जो जिक्र किया उन बातों की पूरी जानकारी करूंगा और इसरार करूंगा कि गंगानगर अस्पताल की शिकायत डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर के पास नहीं आई, डिप्टी मिनिस्टर के पास नहीं आई और मेरे पास भी नहीं आई। आज पहली बार आपसे सुनी है। अगर ऐसी शिकायत पहले आती तो बहुत इन्फोर्मेशन में इसके बारे में लेकर आता और जितनी भी जानकारी कर सकता था करता। पर अब भी जो जानकारी करनी होगी वह करूंगा और सारी बात का पता लगाऊंगा। इसमें क्या खामियां हैं, कितनी हैं; उसके बारे में भी पता लगाऊंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर) : जो प्राइवेट प्रेक्टिस करते हैं उनके बारे में? यह गंगानगर का अस्पताल तो वाकई में बूचड़खाना है, इसे गुलाब मत कहिये।

(अनेक सदस्यों के बोलने पर शोरगुल में)

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सदन की परम्परा कभी नहीं रही है कि बिना किसी पोइण्ट आफ आर्डर या क्लैरिफिकेशन के यों ही बीच में बातचीत जारी कर दें। इससे सदन की प्रतिष्ठा न्यून होती है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : (नसीराबाद) On a point of clarification., Sir.

मैं जानना चाहूंगा कि रिएम्बर्समेंट अफसरों की दवाइयों का होता है, इसके बारे में भी कोई नई नीति सरकार अख्तियार करेगी क्या?

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक रिएम्बर्समेंट का सवाल है यह जी. ए. डी. से ताल्लुक रखता है। वैसे जनरल जानकारी दे दूं, पर वह ऑथेण्टिकेटेड नहीं होगी।

इसी तरह से मेरे दोस्तों ने जो बातें कहीं, बूचड़खाने के बारे में गंगानगर की तकलीफें जाहिर कीं, मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ रही, जिस तरह से बेबसी की हालत कही, बड़े आंसू बहाये, वे आंसू तो देखे नहीं, पर जो जोश था वह मेरे दिल तक पहुंचा और उनके दिल के असर ने मेरे दिल पर भी असर किया और मेरे भी आंसू निकलने को आये, पर उनके आंसू रुकते देखा तो मेरे भी रुक गये। पर यह उनका कहना मुनासिब नहीं कि वहां अस्पताल बढ़े ही नहीं, ६० में वहां ६ अस्पताल थे अब सात हैं, ६७ डिस्पेन्सिरियां थीं, अब १०३ हैं। तीन फेमिली प्लानिंग के सेण्टर्स थे, अब ५ हो गये हैं। तो ऐसा नहीं कि उनको इग्नोर कर दिया गया हो।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर) : On a Point of information, Sir

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

मैंने तो डाक्टरों की करप्ट प्रैक्टिसेज़ के बारे में भी कहा, उसका क्या जवाब है ?

श्री **बरकतुल्ला खां** : हमारी यह मंशा है और हम बराबर इस मंशा को सामने रख कर चल रहे हैं कि मुल्क के लोगों की तन्दुरुस्ती अच्छी हो, अच्छी बुद्धि उनकी हो, काम के लिये यह जरूरी है कि दिल व दिमाग मजबूत हो, साफ हो और वे देश की हर स्थिति का मुकाबला करने को तैयार रहें । इस कोशिश में आज सदन ने अपने सुझाव देकर जो मेरा हौसला बढ़ाया है और जिस तरीके से मेरा साथ दिया है और जिन्होंने कहा है कि इसके लिये और रुपया मिलना चाहिए और जो भावनाएं दिखाई यह तो हमारी जोइण्ट रेस्पोन्सिबिलिटी है । लेकिन जिस तरीके से जोश दिलाया और हमदर्दी दिखाई उनका सबका में आभार प्रकट करता हूं ।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : On a point of information, Sir, दो कट मोशन्स थे ।

(एक अन्य सदस्य के खड़े होने पर)

श्री **उपाध्यक्ष** : One at a time please !

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : There were two specific cut motions

श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : On a point of clarification, Sir,

कम्पाउण्डर थर्ड ग्रेड को ४०) रु० का ग्रेड देने का जवाब नहीं दिया । फोर्थ क्लास के बारे में भी नहीं बताया तथा घनश्याम नामक कर्मचारी को हटा दिया था और दुबारा रखने का आश्वासन दिया था उसके बारे में भी कुछ प्रकाश डालने की कृपा करें ।

श्री **बरकतुल्ला खां** : अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो जिक्र किया वह टेम्पोरेरी एम्पलोयी था, मलेरिया इरेडिकेशन में था । इस के बाद उसका ट्रांसफर कोटपूतली कर दिया । उसने ट्रांसफर पर जाने से इन्कार किया । उसने मलेरिया यूनिट के डाक्टर के खिलाफ शिकायत की । इसकी एन्क्वायरी पी. एम. एच. ओ. ने की । उसका आरोप जो लगाया गलत साबित हुआ । फिर कहा गया कि ट्रांसफर पर जाओ । वह नहीं गया । तो उस को नोटिस दिया गया । नोटिस उसने नहीं लिया । डाक के जरिये उसे भेजा गया । इसके बाद भी वह ट्रांसफर पर नहीं गया । दफ्तर के सामने धरना देकर बैठ गया और कहने लगा तुम्हारे दफ्तर के सामने बैठूंगा और यहां तनखा लूंगा । तो इस तरह की इनडिसिप्लिन करके कोई यह तय कर ले कि ट्रांसफर पर नहीं जाना है तो फिर इसका दूसरों पर असर बुरा पड़ेगा, इस तरह से ट्रांसफर रोक दें तो एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा नहीं । फिर आप ही इसको गवर्नमेंट नहीं कहेंगे, पोपाबाई का फिर यह राज जरूर हो सकता है । हरएक आदमी अपने ट्रांसफर को कैन्सिल कराने के लिये भूख हड़ताल पर जाने लगेगा ।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : आपने आश्वासन दिया था या नहीं कि भूख हड़ताल तोड़ दो नहीं भेजेंगे ट्रांसफर पर ।

श्री **उपाध्यक्ष** : Order please ! जो कटौती प्रस्ताव यहां प्रस्तुत हुए हैं, प्रश्न यह है कि……

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : दूसरे कम्पाउण्डरों के विषय में ?

श्री उपाध्यक्ष : काफी एक्सप्लेनेशन हो गया है।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : There were two cut motions

(एक माननीय सदस्य खड़े हुए)

श्री **उपाध्यक्ष** : Order please order! Let there be no talklike that. इस प्रकार तो कोई व्यवस्था नहीं रहेगी।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : इस चेयर से यह व्यवस्था दी जा चुकी है कि जो इम्पोर्टेण्ट हैं उनको जवाब दिया जावेगा। उनको रेफर भी किया है। तो जो इससे इफेक्टेड हैं उस बारे में गवर्नमेंट की क्या नीति है, यह बता दें।

श्री **मथुरादास माथुर** (गृह मंत्री) : व्यवस्था यह थी कि कट मोशन का जवाब देंगे और जवाब दिया है। अगर कोई इण्डिविजुअल केस रह जावे तो लिखित रूप से जवाब दे देने का प्रावधान भी रूल्स में है। एक-दो पोइण्ट्स रह जावें तो मंत्रीजी लिख कर जवाब दे देंगे।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : लिखित की कोई बात नहीं थी, क्या दिक्कत है इसका जवाब देने में ?

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा On a point of information Sir. मेरा आर. ए. सी के डाक्टर के संबंध में एक है।

श्री **उपाध्यक्ष** : रूल्स में कई प्रकार के प्रावधान हैं जिनसे आप कई प्रकार की सूचनाएं ले सकते हैं। सदन का समय इस तरह से खराब करने से कोई अर्थ नहीं है Order please !

प्रश्न यह है कि जो मांग यहां प्रस्तुत हुई हैं उन पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए हैं उनको वापिस लेना शायद सब चाहेंगे ?

श्री केसरीसिंह (पाली) : In view of the assurance given by the Minister I will withdraw my cut-motion

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : I don't want to withdraw my cut motion.

मैंने डाक्टर कल्ला के बारे में रखा है उसको साइड ट्रैक करने की कोशिश की गई है।

श्री **ज्वालाप्रसाद शर्मा** (नसीराबाद) : We are ready to vote.

श्री **उपाध्यक्ष** : Order please ! प्रश्न यह है कि जो अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस नहीं लेना चाहते हों वे कृपया खड़े हों।

(कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए)

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : मैं बीकानेर के करप्शन के मामले के कट मोशन को विथड्रा करने की बात नहीं मानना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री उपाध्यक्ष : There are three cut motions which have not been taken back. All other cut motions will be considered as taken back.

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १६ एवं १७ स्वीकार की जाएं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : When the cut motion is there, you should take vote on the cut motion first and then put the demand to vote.

श्री उपाध्यक्ष : It is also the procedure that when voting is taken on the demand itself, the cut motions are automatically dropped.

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १६ एवं १७ स्वीकार की जायें।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १६ एवं १७ स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४० स्वीकार की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४० स्वीकार की गई।

(विराम)

सदन की कार्यवाही कल म. पू. ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ५ बज कर ४२ मिनट पर २१ मार्च, १९६३ के म. पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त विवरण
(बुधवार, दिनांक २० मार्च, १९६३)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक

स्थगित प्रश्न
(१२-३-६३)

विशेषाधिकार प्रश्न

अधिक अनुदानों की मांगें, १९५८-५९ को विलम्ब से पेश करने संबंधी श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य विधान सभा के विशेषा-

स्कम्भ

धिकार-प्रश्न को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदान नहीं की गई।

आय-व्ययक, १९६३-६४

द्वितीय अवस्था—अनुदानों की मांगों पर मतदान

(१) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३४९२ २९—चिकित्सा

(२) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०—जन-स्वास्थ्य

श्री बरकतुल्लाखां, स्वास्थ्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत की गई।

(३) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ६४—जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत

श्री हरिश्चन्द्र, सार्वजनिक निर्माण मंत्री द्वारा प्रस्तुत की गई।

स्कम्भ

उपरोक्त मांगों पर कुल ७० कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

सरकार की ओर से श्री हरिश्चन्द्र, सार्वजनिक निर्माण मंत्री, श्री भीखाभाई, आयुर्वेद मंत्री एवं श्री बरकतुल्ला खां, स्वास्थ्य मंत्री ने उत्तर दिया।

तत्पश्चात् उपरोक्त तीनों मांगें सदन द्वारा स्वीकार की गई।"

सदन की बैठक ५ बज कर ४२ मिनट पर गुरुवार, दिनांक २१ मार्च, को १९६३ प्रातः काल ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।

सभा भवन, जयपुर, दिनांक २० मार्च, १९६३ — अनोपसिंह, सचिव।

गुरुवार, २१ मार्च, १९६३ की ३६५८

कार्य-सूची

मांग संख्या १२—पुलिस

मांग संख्या ११—कारागार।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४८३ का उत्तर देखिये)

सूची स्थान जहां लूट व डकैती की घटनाएं घटीं

क्रमांक	स्थान
डकैती	
१	ढानी बिश्नोईयांन ग्राम रणजीतपुर।
२	ग्राम खिलेरिया, ग्राम बेरा वाला, ग्राम मोटोलाई और कान्वोलाई।
३	ग्राम सीणेवाला
४	ग्राम मोडायत।
५	मोहल्ला धोबी तलाई बीकानेर शहर।
६	ग्राम पलाना।
७	ग्राम गिरासर।
८	ग्राम जियोंवाली।
९	ग्राम मुरोवाला।
लूट	
१	ग्राम चारणवाला।
२	ग्राम बुढावाली।
३	खोला नागणोचेजी बीकानेर।
४	ग्राम घडसीसर।
५	ग्राम जप्तरासर।
६	मोहल्ला सुनारान, बीकानेर।
७	ग्राम करम वाला।
८	ग्राम बकडा।
९	रोही मौजा कबक।
१०	कुंआ महम्मद रोही सतासर।
११	ग्राम मेघाप्त।
१२	ग्राम बरजू।
१३	ग्राम खराला।
१४	सडक आम पेट्रोल पंप पब्लिक पार्क बीकानेर बहार बीकानेर।
१५	रोही ग्राम सांखडा।
१६	रोही ग्राम रामपुरा।
१७	ग्राम चारणवाला।
१८	रोही ग्राम पारवा।
१९	रोही ग्राम पाखा।
२०	ग्राम नगरासर।
२१	मोहल्ला सोनगिरी कुंआ के पास बीकानेर।
२२	मा० चौखूंटी, बीकानेर।
२३	ग्राम सादुलाई।
२४	गुवाड रानासर भाटियान।
२५	रोही मौजा बिदासरिया।
२६	मोहल्ला चौखूंटी बीकानेर।

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ४८८ का उत्तर देखिये)

ANNEXURE—I

1. The percentages of increase or decrease in production are as under:—

(+) Increase and (—) Decrease.

Crops		I Five Year Plan (over 50-51)	II Five Year Plan (over 55-56)	1961-62 (over 1960-61)	1962-63 (Anticipated over 61-62)
Food-grains	..	+42	+8	+20	+4
Oil Seeds	..	+227	—32	+48	+7
Cotton ..	..	+22	—20	+14	+15
Sugarcane	..	—14	+114	—26	+20

2. The percentages of increase or decrease in area are as under:—

Food-grains	..	+22	+11	+3	+2
Oil Seeds ..	..	+54	+2	+19	+3
Cotton ..	..	+61	—18	+18	+9
Sugarcane	....	+51	+55	—20	+6

3. The percentages of increase or decrease in yield per acre are as under:—

Food-grains	..	+17	—3	+16	+2
Oil Seeds ..	..	+65	—33	+24	+3
Cotton ..	..	+19	—3	—3	+5
Sugarcane	..	—43	+38	—8	+13

(+) Increase.

(—) Decrease.

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४६४ का उत्तर देखिए)

नगरपालिका, रतनगढ़ को सन् १६५७-५८ मे १६६१-६२ तक दी गई सहायता व ऋण की सूची:—

वर्ष	ऋण
१६५९-६०	तारीख २८-३-६० को १०,००० रु० ट्रेक्टर खरीद के लिए ऋण दिया गया ।

सहायता

वर्ष	जनरल सहायता	डवलपमेंट हेतु	एडहाक डी.ए.	सड़कों हेतु	व्हील वैरोज हेतु	अन्य कार्यो के लिये
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
१६५७-५८	८६७	१,७४०	३४०	४,०००	—	—
१६५८-५६	५,७१४	११,४३०	५,६००	३,०००	—	—
१६५६-६०	५,७१४	११,४३०	५,६००	—	५,०००	५,००० हरिजन बस्ती में बिजली विस्तार हेतु ।
१६६०-६१	—	—	५२०	५,०००	—	—
१६६१-६२	—	१०,०००	५,०००	—	—	—

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५०६ का उत्तर देखिये)

सूची नगरपालिकाएं, जो गन्ने पर आक्ट्राय वसूल करती हैं:—			सूची नगरपालिकाएं जिनसे सूचना प्राप्त नहीं हुई हैं:—		
१. अजमेर	..	२. केकडी	१. सरवाड	..	२. चोमूं
३. पुष्कर	..	४. कोटपूतली	३. फुलेरा	..	४. खन्डेला
५. चाकसू	..	६. सूरजगढ	५. मन्डावा	..	६. मुकुन्दगढ
७. पिलानी	..	८. टोंक	७. उदयपुरवाटी	..	८. बिसाऊ
९. निवाई	..	१०. टोडारायसिंह	९. गंगापुर	..	१०. देवली
११. अलवर	..	१२. राजगढ (अलवर)	११. धौलपुर	..	१२. बाडी
			१३. बीकानेर	..	१४. नोखा
१३. भरतपुर	..	१४. राजगढ (चूरू)	१५. देशनोक	..	१६. चूरू
			१७. छापर	..	१८. रतननगर
१५. तारानगर	..	१६. डूंगरगढ़	१९. सूरतगढ	..	२०. भादरा
१७. गंगानगर	..	१८. गर्जसिंहपुर	२१. फलोदी	..	२२. सोजत
१९. नोहर	..	२०. मेडता	२३. जैसलमेर	..	२४. पोकरण
२१. डीडवाना	..	२२. नावां	२५. भिन्डर	..	२६. सागवाडा
२३. मकराना	..	२४. बाली	२७. प्रतापगढ	..	२८. बडीसादडी
२५. जालोर	..	२६. बाडमेर	२९. शाहपुरा	..	३०. बॉसवाडा
२७. बालोतरा	..	२८. निम्बाहेडा	३१. कुशलगढ	..	३२. कोटा
२९. गंगापुर (भीलवाडा)		३०. बूंदी	३३. केशोरायपाटन	..	३४. झालावाड
३१. लाखेरी	..	३२. भवानीमन्डी	३५. झालरापाटन	..	

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक २० मार्च, १९६१)

स्तम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
३४११, ३४१६, ३४१७, ३४१८, ३४१९, ३४७६,	क्रमशः ५, ४, ११, १७, २४	मिर्था	मिर्धा
३४१३	१ व ८	श्री रघनाथ	श्री रघुनाथ
३४१८	११	श्री भरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
३४२०	११	श्री जयनाराद्दण	श्री जयनारायण
,,	२४	हल्ले	पहले
३४२१	२१	(अ ुपस्थित)	(अनुपस्थित)
३४३०	१८	परिशिष्टी	परिशिष्ट १
३४३२	७	माल	रूमाल
३४३६	१७	गृह मंत्री श्री मथुरादास माथुर	गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर)
,,	२६	प्रेड मं	प्रेड में
३४३७	अन्तिम	संतष्ट	संतुष्ट
३४३८	शीर्षक	प्रश्नोर	प्रश्नोत्तर
,,	२४	मिर्धा खास:	मिर्धा : खास
३४४०	९	बुलाऊंव यों	बुलाऊं क्यों
३४४१	१७	श्री सतीश-चन्द्र आवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
३४४२	१२	First	First
,,	२८	कृपया	कृपया
३४४६	२३	सरण	सारण

१	२	३	४
३४४७	२३	मैंरोंसिंह	श्री मैंरोंसिंह
३४५२	स्कम्म	४३५२	३४५२
"	अन्तिम से ४	सप्लीमेन्टी	सप्लीमेन्ट्री
३४५८	२७–२८	हैं विलेज की	विलेज की
३४६५, ३५०३, ३५१७	शीर्षक	माच	मार्च
३४६८	२५	श्री अब्दुल जब्बार खां	श्री अब्दुल जब्बार
३४६९	२५	इन्टेस्टेड	ईन्ट्रेस्टेड
३४७४	१९	hoüse	House
३४७५	१०	के। जो	के जो
"	अन्तिम पंक्ति	डिफीज	डिक्रीज
३४७६	६३	कृषि मंत्री श्री नाथूराम मिर्धा	कृषि मंत्री(श्री नाथूराम मिर्धा)
३४७७	अन्तिम से २	श्री माकिचन्द्र	श्री मानिकचन्द
३४७८	२७	सर्कमटान्सेज	सर्कमस्टान्सेज
३४८१	शीर्ष	(श्री सतीतचन्द्र अगवाल)	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
"	अंतिम से २	साख बाईलाज सेंक्शन हुए	सारण: बाईलॉज सेंक्शन हुए
३४८२	१	अप्रवाल	अग्रवाल
"	२६	ससेप्बिलिटीज	ससेप्टिबिलिटीज
३४८३	१५	समे	इसमें
३४८६	२३	श्री सतीशचन्द	श्री सतीशचन्द्र
३४८९	१	अपंहत	अपहृत
३४९१-९२	शीर्षक	मांग संख्या १६, १७, ४० चिकित्सा आदि पर पूंजी की लागत	ले. एवं मु. सा. विभाग विषयक जांच अधिकारी की नियुक्ति
३४९३	५	शोषंक	शीर्षक
"	१२	कटौती	[कटौती
३४९८	२६	to discuss	(to discuss
३५००	स्कम्म	३५०	३५००
"	३	reduecd	reduoe
३५०१	२६	to discuss in suff cient	(to discuss insufficient
३५०३	१३	People	(People)
३५०५	२	हेतु) ।	हेतु) ।]
३५१६	अन्तिम से २	मुस्तफिल	मुस्तकिल

१	२	३	४
३५१८	१५	घाला	झाला
३५२३	१	श्री समापति	श्रीमती सभानेत्री
,,	२	ज्वाला प्रशाद	ज्वालाप्रसाद
३५२५	शीर्ष	,,	,,
,,	अन्तिम पंक्ति	मको	हमको
३५३४	९	श्लाइटली	स्लाइटली
३५३६	३१	सजिकल	सर्जिकल
३५३८	जहां कहीं.	श्री समापति	श्रीमती समानेत्री
से	भी आया		
३५४८	है		
३५४०	शीर्षक	पंजी	पूंजी
३५४८	२४	जानता हूं	जानती हूं
३५५५-५६	शीर्षक	२ मार्च	२० मार्च
३५५७	१	डावरिया	ढावरिया
,,	३	शर्शा	शर्मा
३५६८	१५	करले	करने
३५७८,	१६	ईशरदास	ईसरदास
३५७९,	शीर्ष.		
३५८१	,,		
३६०४	अन्तिम से ६	out.	Cut.
३६०५	४	Objec tion if	Objection f
,,	२१	S ri	Sir,
३६१०	१३	ो	तो
३६१८	१५	nformation	info m tion
३६४१	शीर्ष	(श्री वरतुल्ला खां)	(श्री बरकतुल्ला खां)
३५४२	८	एक मानीय सदस्य	एक माननीय सदस्य
३६४३	१	ro educate	to educate
३६४६	१७	श्री बरकतुल्लाख :	श्री बरकतुल्ला खां :
३६४७	अन्तिम से २	श्री बरकतुल्लाखां :	श्री बरकतुल्लाखां :
३६४९	शीर्षक	२० माच,	२० मार्च
३६५३	२३	Ple se !	Please !
३६५५	२३	श्री रामान्नद अग्रवाल	श्री रामानन्द अग्रवाल
३६६२	८	ारा	द्वारा